बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 198

सर्वोच्च न्यायालय की सही सीख

वर्ष 2024 के लोक सभा चुनावों के दौरान राजनीतिक बढ़त हासिल करने की हताश कोशिश में दोनों प्रमुख राजनीतिक ताकतों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेसनीत 'इंडिया' गठबंधन ने विभाजनकारी राजनीतिक भाषणों के जरिये देश की विविधता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया जब उसने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई। यह फटकार नायडू के इस आरोप के लिए लगाई गई कि प्रदेश की पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नायडू को 'ईश्वर को राजनीति से दूर रखना चाहिए', खासकर ऐसे समय में जब मामले की जांच चल रही है और परीक्षण की जो रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं वे प्रथम दृष्टया ऐसा संकेत नहीं देती हैं कि लड्डुओं में पशुओं की चर्बी है। परंतु लाखों हिंदुओं की गहरी धार्मिक आस्थाओं से जुड़े एक मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत का पर्यवेक्षण जल्दी शांत नहीं होगा। इस विवाद ने विश्व हिंदू परिषद की उस पुरानी मांग के लिए आग में घी का काम किया है जिसके तहत वह चाहती है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। अब उसने इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ने की बात कही है। संयोग से यह विवाद उस समय सामने आया है जब हरियाणा तथा जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द चुनाव होने हैं।

राजनेताओं के लिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और नफरती भाषणों तथा धार्मिक और जातिवादी बातें करना एकदम आम हो चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता के पहले बिंदु में कहा गया है, 'किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए कि जो विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा करे, आपसी नफरत को बढ़ावा दे या पहले से मौजूद तनावों को और बढ़ाए।' इस बिंदु में यह भी कहा गया है, 'वोट हासिल करने के लिए जातियों या संप्रदायों से किसी तरह की अपील नहीं की जानी चाहिए और मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य उपासना स्थलों को चुनावी प्रचार का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए।'

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 123 (3) में कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट चुनावी आचरण में आता है। आरपीए की धारा 8 (ए) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है या छह साल के लिए मतदान करने से भी रोका जा सकता है।

जैसा कि 2024 के लोक सभा चुनाव प्रचार अभियान से सामने आया, लगभग सभी राजनीतिक विचारधाराओं के कई प्रमुख राजनेताओं ने आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून के सिद्धांतों का भरपूर उल्लंघन किया। बीते तमाम वर्षों के दौरान न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग ने ऐसी राजनीति पर अंकुश लगाने की कोशिश अवश्य की लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी।

सन 1980 के दशक में एक अहम घटना हुई थी जब निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे को नफरती भाषण फैलाने के कारण छह वर्षों तक मतदान करने से रोक दिया था। हालिया लोक सभा चुनाव में जब निर्वाचन आयोग को प्रमुख राजनेताओं के विभाजनकारी भाषण देने की शिकायतें मिलीं तो उसने उन नेताओं के बजाय उनके पार्टी प्रमुखों को नोटिस भेजा। उसका कहना था कि यह प्रमुख तौर पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रत्याशियों के आचरण की जिम्मेदारी लें, खासतौर पर अपने स्टार प्रचारकों की हरकतों की। निर्वाचन आयोग को इसके लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा लेकिन यह प्रकरण इस बात को भी रेखांकित करता है कि देश के बहुलतावादी लोकतंत्र को और अधिक दूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी प्रमुख तौर पर न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारों की नहीं बल्कि उसके शीर्ष राजनेताओं की है।

बिनय सिन्हा

एमपीसी: लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी मिली सफलता?

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को अपनी शुरुआत के बाद से ही देश में मुद्रास्फीति पर काबू में रखने में कई बड़ी बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बता रहे हैं जनक राज

भारत में मुद्रास्फीति को तय दायरे में लाने के लिए लचीली (एफआईटी) व्यवस्था तैयार करने के मकसद से 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया। देश में मौद्रिक नीति के इतिहास में यह महत्त्वपूर्ण मौका था क्योंकि इसके साथ ही मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले छह सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लेने शुरू कर दिए। समित में तीन आंतरिक और तीन बाहरी सदस्य होते हैं।

इससे पहले मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास था। हालांकि रिजर्व बैंक ने जुलाई 2005 में तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) बना दी थी मगर समिति को संविधिक समर्थन नहीं था। एमपीसी का गठन अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों में देखे गए प्रचलन के अनुरूप किया गया था, जिसके साथ ही मौद्रिक नीति के निर्णय समिति को सौंप दिए गए। किंतु अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम या यूरो क्षेत्र में यूरोपियन सेंट्रल बैंक में फैसले सामूहिक होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहां एमपीसी (ब्रिटेन की तरह) मतदान के जरिये फैसले होते हैं, जिसमें समिति के सभी सदस्यों के पास एक-एक वोट होता है। मतों की बराबरी की स्थिति में गवर्नर का वोट निर्णायक माना जाता है।

एमपीसी को मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें प्रतिशत कमीबेशी स्वीकार्य है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य पांच वर्ष में एक बार तय किया जाता है। सवाल यह है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में एमपीसी का प्रदर्शन कैसा रहा है? जवाब देने से पहले यह समझना चाहिए कि 4 प्रतिशत लक्ष्य का यह मतलब नहीं है कि मुद्रास्फीति को हमेशा इसी स्तर पर रखा जा सकता है। किसी बाहरी झटके से मुद्रास्फीति लक्ष्य से बेपटरी होती है तो एमपीसी को वक्त के साथ धीरे-धीरे उसे लक्ष्य पर लौटाना होता है।

मुद्रास्फीति की ऊंची दर को तेजी से लक्ष्य तक वापस लाने के लिए कोई भी प्रयास करते समय एमपीसी को नीतिगत दरें तेजी से बढ़ानी होती हैं, जिससे वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ सकती है। इस तरह मुद्रास्फीति लक्ष्य को मध्यम अवधि में हासिल करना चाहिए, जिससे एमपीसी को वृद्धि की चिंता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने का मौका मिल सके। यह लचीलापन विचलन दर (टॉलरेंस बैंड) में ही शामिल होता है।

अक्टूबर 2016 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति औसतन 5 प्रतिशत रही है, जबकि इसका लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इस बीच 94 महीने में से 67 महीने में सीपीआई मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर रही। जनवरी-मार्च 2022 से जुलाई-सितंबर 2022 की लगातार तीन तिमाही में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के अधिकतम स्तर से ऊपर रही। रिजर्व बैंक अधिनियम के मुताबिक अगर लगातार तीन तिमाही तक औसत मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के अधिकतम स्तर से ऊपर या 2 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से नीचे जाती है तो इसे मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने में नाकामी माना जाएगा। ऐसे मामलों में केंद्रीय बैंक को एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार को (1.) मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने में नाकामी के कारण, (2.) इसे सुधारने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए उपाय और (3.) मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने के लिए अनुमानित समयसीमा बतानी होती है। रिजर्व बैंक ने इस सिलसिले में नवंबर 2022 में केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट जमा की थी।

किंतु एफआईटी व्यवस्था के दौरान मुद्रास्फीति के रिकॉर्ड को ठीक से समझना होगा। एफआईटी को अपनाने से पहले लगभग पांच वर्षों (जनवरी 2012-सितंबर 2016) में सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 7.3 प्रतिशत रही। इस 57 महीनों में से 8 महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत या उससे अधिक रही थी और 20 महीनों में 9 प्रतिशत से अधिक रही। नवंबर 2013 में यह 11.5 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके विपरीत एफआईटी व्यवस्था अपनाने के बाद मुख्य मुद्रास्फीति 94 में से 10 महीनों में 7 प्रतिशत या उससे अधिक रही और अप्रैल 2022 में यह 7.8 प्रतिशत के शीर्ष स्तर तक गई।

इस प्रकार एफआईटी के तहत मुद्रास्फीति दर उससे पहले के पांच वर्ष की तुलना में काफी कम थी। इससे पता चलता है कि परिवारों के लिए मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं बेहतर तरीके से थामी गईं, जो एफआईटी के दौर में तीन महीने बाद के लिए 7.9 से 11.9 प्रतिशत और एक वर्ष बाद के लिए 8.3 से 11.5 प्रतिशत तक हो गईं। इससे पहले के पांच वर्षों में यह तीन महीने आगे के लिए 8.8 से 12.8 प्रतिशत और एक वर्ष आगे के लिए 9.3 से 13.5 प्रतिशत रहीं।

यह भी अहम बात है कि पिछले आठ वर्षों में कुछ असाधारण घटनाएं घटित हुईं, जिनमें 2020-21 में कोविड-19 महामारी और फरवरी 2022 में शुरू होकर अब तक चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध प्रमुख हैं। कोविड महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह उलट दिया और रूस-यूक्रेन युद्ध ने वस्तुओं विशेष रूप से तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को आग लगा दी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक वैश्विक मुद्रास्फीति में अचानक वृद्धि से हक्के बक्के रह गए क्योंकि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में यह कई दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

उदाहरण के लिए अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़कर 9.1 प्रतिशत और ब्रिटेन में 11.1 प्रतिशत हो गई, जो दोनों देशों में पिछले 40 साल की सबसे ऊंची महंगाई है। यूरो क्षेत्र में तो यह 10.6 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर है और आज से पहले कभी नहीं देखी गई। ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति लगातार 42 महीने और ब्रिटेन तथा यूरो क्षेत्र में 38-38 महीने लक्ष्य से ऊपर रही है। किंतु इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति अब नीचे जा रही है और धीरे-धीरे लक्ष्य के करीब पहुंच रही है।

कुल मिलाकर भारत में एफआईटी लागू होने के बाद ज्यादातर समय सीपीआई मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही, जिसका कारण आपूर्ति से जुड़े कई गंभीर झटके मिलना था। किंतु भारत में मुद्रास्फीति को अच्छी तरह बांधा गया और एफआईटी से पहले के पांच वर्षों की तुलना में कुल सीपीआई मुद्रास्फीति दर कम रही। फिर भी मुख्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप रखना जरूरी है, जिससे एफआईटी व्यवस्था की विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी।

(लेखक सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस, नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं और रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं)

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई से जुड़ीं हकीकत

सामयिक सवाल

निवेदिता मुखर्जी

'**सवाल** ही नहीं उठता।' कुछ दिन पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ साक्षात्कार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जवाब दिया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की शर्तें नरम बनाई जा रही हैं। गोयल ने यह बात तब कही है, जब भारत महत्त्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है।

यह अलग बात है कि बहु-ब्रांड खुदरा में एफडीआई की इजाजत है, जो पिछले 10 वर्ष से कागजों तक ही सीमित है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने वर्ष 2012 में बहु-ब्रांड खुदरा नीति को हरी झंडी दिखाई थी और इसमें 51 प्रतिशत तक एफडीआई की इजाजत दे दी थी। इसके अंतरराष्ट्रीय खुदरा कंपनियां भारत में उतरने की तैयारी ही कर रही थीं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार सत्ता में आ गई। नई सरकार ने अगले कुछ वर्षों में खुदरा कारोबार की दशा-दिशा ही बदल दी। तब से बहु-ब्रांड खुदरा नीति दरकिनार कर दी गई है।

यह बात किसी से नहीं छिपी है कि राजग सरकार बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई के खिलाफ है। इसका कारण भी सबको पता है। मगर भाजपा के लिए महत्त्वपूर्ण वोट बैंक समझे जाने वाले किराना दुकानदार और स्थानीय कारोबारी बहु-ब्रांड खुदरा में एफडीआई के बगैर क्या वाकई खुश हैं? या गली-मोहल्ले की दुकानों को बहु-ब्रांड खुदरा में एफडीआई पर सरकार के रुख से वाकई फायदा मिला है?

लगता तो यही है कि देसी कारोबारी काफी नाराज हैं। इस सप्ताह के शुरू में कारोबारी एक श्वेत पत्र पर चर्चा करने जुटे, जिसमें बताया गया था कि फ्लिपकार्ट और एमेजॉन जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों का उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है। यह श्वेत पत्र कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने तैयार किया था और यह भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीआईआई) की उस रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें बताया गया था कि एमेजॉन और फ्लिपकार्ट द्वारा ई-कॉमर्स में एफडीआई के नियमों का कैसे उल्लंघन किया है। सीसीआई ने इस मामले की तहकीकात 2019 में शुरू की थी, जब कैट से संबद्ध दिल्ली व्यापार महासंघ ने उसके समक्ष याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने कुछ विक्रेताओं को दूसरे विक्रेताओं पर तरजीह दी है। इसी मामले में जुर्माना तय करने के लिए सीसीआई ने ई-कॉमर्स कंपनियों से वित्तीय जानकारी मांगी है।

भारतीय खुदरा कारोबारियों ने ई-कॉमर्स श्रेणी में विदेशी कंपनियों से पहली बार लोहा नहीं लिया है। इन वैश्विक कंपनियों के खिलाफ यह शिकायत लगातार बनी हुई है कि अपने पास मौजूद अथाह रकम का फायदा उठाकर वे ग्राहकों को भारी छूट देती हैं। ध्यान रहे कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां मार्केटप्लेस हैं क्योंकि ये केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह काम करती हैं, जहां वे विक्रेता अपना सामान बेचते हैं, जिनका कंपनियों से कोई वास्ता नहीं है। ऑनलाइन कंपनियों का दावा है कि वे एफडीआई नियमों का पालन कर रही हैं मगर यह बात दूसरे पक्ष के गले नहीं उतर रही।

कैट के संस्थापक और अब दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल का कहना है कि स्थानीय कारोबारियों में एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ बहुत गुस्सा है। पहले तथ्य देख लेते हैं। करीब 10 वर्ष पहले भारतीय खुदरा बाजार का आकार 500 अरब डॉलर आंका गया था, जो उद्योग के अनुमानों के मुताबिक 2024 में 1.3 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। खंडेलवाल खुदरा क्षेत्र में इस तेजी का श्रेय आर्थिक सुधारों, उपभोक्ता द्वारा अधिक व्यय, तकनीक क्षेत्र में प्रगति और ई-कॉमर्स के विस्तार को देते हैं। मगर जब बात एमेजॉन और फ्लिपकार्ट की आती है तो खंडेलवाल साफ कहते हैं कि इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका नुकसान भारतीय कारोबारियों को हुआ है।

खंडेलवाल भारत के करीब 9 करोड़ कारोबारियों (10 साल पहले करोड़) की तरफ से कहते हैं, 'विदेशी निवेश पाने वाली कंपनियों ने 'अनुचित कारोबारी तरीके' अपनाए हैं और 'नियमों एवं नीतियों का भारी उल्लंघन' किया है, जिसके कारण बाजार बिगड़ रहा है। असमान अवसरों के कारण ग्राहक परंपरागत कारोबारियों से दूर छिटक रहे हैं और उन्हें 'नुकसान' हो रहा है।' हालांकि खंडेलवाल मानते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियों के कारोबार में तेजी से ज्यादातर कारोबारियों को नुकसान हुआ है मगर इसके कारण छोटे कारोबारियों ने नए रास्ते तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। पिछले एक दशक में परंपरागत खुदरा कारोबारियों ने या तो डिजिटल रास्ता पकड़ लिया है या उन्हें खुदरा की बदलती तस्वीर के बीच होड़ में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। 'क्विक कॉमर्स' (ग्राहकों तक झटपट सामान पहुंचाने का नया कारोबार) का जिक्र करते हुए खंडेलवाल कहते हैं कि यह शहरों में परंपरागत खुदरा विक्रेताओं को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा।

बहु-ब्रांड खुदरा में एफडीआई का प्रभाव अलग कैसे रहेगा? खंडेलवाल कहते हैं कि इससे खुदरा दुकानों पर सीधा असर होगा क्योंकि ग्राहक किराना दुकानों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। राहत की बात केवल इतनी है कि भारत के खुदरा बाजार में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी अभी केवल 8-10 प्रतिशत है, इसलिए समूचे खुदरा बाजार पर असर अपेक्षाकृत कम ही रहेगा।

यह सब देखकर हमें मानना पड़ेगा कि ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स अब काफी तेज गति से आगे बढ़ेंगे और स्टोर खोलने वाली विदेशी खुदरा कंपनियों का भी खुदरा क्षेत्र पर वैसा ही असर होगा, जैसा ऑनलाइन कंपनियों ने डाला है। आज के दौर की तुलना 10 या 20 वर्ष पहले की स्थिति से नहीं की जा सकती।

आपका पक्ष

चीन से अलग भारत का विकास

लेख 'चीन से आगे निकला भारत मगर सीखने होंगे सबक' बहुत तथ्यात्मक और सही परिप्रेक्ष्य में किया गया विश्लेषण है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंडों में निवेश की दृष्टि से भले ही भारत चीन से आगे निकल गया मगर यह अभी शुरुआत है। इसके आगे का मार्ग बहुत लंबा और कठिन है। चीन के मॉडल से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती क्योंकि वहां एक साम्यवादी सरकार है और निर्णय लेने और उनका कार्यान्वयन करने में वहां किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। भारत समावेशी विकास और वैश्विक साझेदारी के साथ सतत गति से चीन के पीछे खड़ा है। भारत को औद्योगिक क्षेत्र में निर्णय पांच दशक पहले लेने चाहिए थे, उसके बजाय भारत चीन के विकास को अपने अनुकूल मानते हुए लगातार पिछड़ता रहा और अपनी प्रगति को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले अनुदानों और ऋणों से संतुष्ट होता रहा। आज चीन भारत की सीमा पर बैठा है और आंखें भी दिखा रहा है, यही परिदृश्य हमारी आर्थिक स्थिति के प्रतिकूल रहा है क्योंकि इसी भय से हमारा देश चीन के उत्पादों का बड़ा आयातक बना रहा। ऐसा नहीं है कि भारत में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल, शोध, नवोन्मेष, पूंजी, राजनीतिक इच्छाशक्ति और कारोबारियों की कोई कमी है। वैश्विक निवेशक भी भारत की राजनीतिक स्थिरता और इच्छाशक्ति, देश के औद्योगिक सामर्थ्य को अच्छी तरह समझ गए हैं और देश में विदेशी पूंजी निवेश खुलकर आ रहा है। भारत के लिए सबसे आवश्यक है कि चीन के उत्पादों विशेषकर सेमीकंडक्टर, फार्मा, सौर उपकरण, बैटरी के क्षेत्रों में चीन से अपनी निर्भरता समाप्त करे और चीन से लगी सीमा पर अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली और लंबी दूरी और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अनुरूप आयुधों से अपनी सेना को सुसज्जित करे। भारत की समृद्धि भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी है, दोनों को अलग नहीं कर सकते।

विनोद जौहरी, दिल्ली

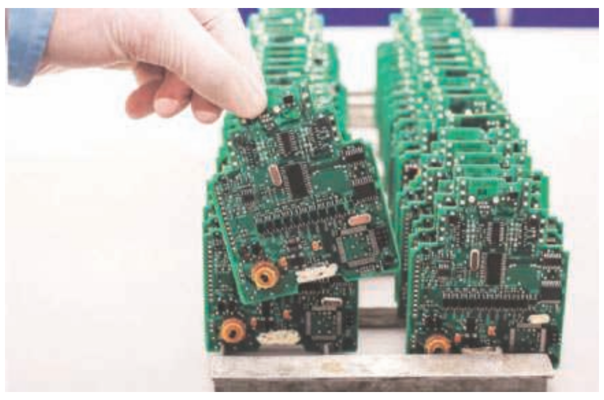

भारत के लिए सबसे आवश्यक है कि चीन के उत्पादों जैसे सेमीकंडक्टर, फार्मा, सौर उपकरण आदि से निर्भरता समाप्त करे

युद्ध और अशांति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

करीब ढाई साल से रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग के बाद अब इजरायल और ईरान में भी लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद जंग शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक और हाल ही में बांग्लादेश में सत्ता पलट की घटनाएं हो चुकी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक हमला कर दिया था। इसके बाद पलटवार में इजरायल की ओर से लगातार गाजा पट्टी पर हमास को खत्म करने के लिए हमला किया जा रहा है। हमास तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इजरायल हमास का युद्ध लेबनान, यमन से लेकर ईरान तक पहुंच गया है। ईरान के सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होने से तेल की कीमतों और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिरता के प्रति भी चिंता बढ़ने लगी है। विश्व में करीब एक तिहाई कुल कच्चे तेल की आपूर्ति इसी इलाके से होती है। ऐसे में तेल संयंत्रों या आपूर्ति के मार्गों पर हमले होने से कच्चे तेल की कीमतों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारियों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज सुबह 76 आरआर के आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। चर्चा की कि पिछले कुछ वर्षों में पुलिस व्यवस्था कैसे बदल गई है और साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियों से निपटना कैसे महत्त्वपूर्ण हो गया है।'

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिमत

रावल जी बहुत ही जिज्ञासु व नम्र व खुले विचारों के व्यक्ति थे। किसी भी मुद्दे की तह में जाने के लिए वे सवाल करते रहते थे, और दूसरों को सुनते रहते थे। वे एक पत्रकार की तरह खोज-बीन करते दिखते थे। और फिर अंत में किसी राय पर पहुंचते थे। उनकी एक छोटी लाइब्रेरी थी। कई पत्र-पत्रिकाएं आती थी। वे खासतौर पर पर्यावरण के मुद्दे पर अखबारों में छपी खबरों को चिन्हांकित कर काटते थे, उनको फाइल में सहेजकर रखते थे। जब कोई लेख लिखते थे, तो संदर्भ के लिए उन्हें देखते थे।

विकल्प खोजने वाले विचारक थे ओमप्रकाश रावल

■ बाबा मायाराम

मध्यप्रदेश में इंदौर जब भी जाना होता है, मेरा मन श्रद्धा व सम्मान से भर जाता है। इस शहर का मेरे जीवन में खास महत्व है, इसलिए नहीं कि मैंने वहां पढ़ाई की है और वर्षों रहा हूं। बल्कि इसलिए कि वहां मैं ऐसी हस्तियों से मिला, जिनका न केवल मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, प्रभावित किया, बल्कि बहुत स्नेह भी मिला। आज इस कॉलम में मैं ओमप्रकाश रावल जी के बारे में बताना चाहूंगा, जो एक शिक्षक, राजनेता, चिंतक और लेखक थे। वे कभी आदर्श, सिद्धांतों से नहीं डिगे, ईमानदारी और सादगी की मिसाल पेश की, और उन्होंने पर्यावरण के सवाल को न केवल सबसे पहले पहचाना, बल्कि उनके संघर्षों में शामिल भी रहे।

सोचता हूं उन पर कुछ लिखूं, फिर यह भी कि क्या? यह दोहराऊं कि उनका जन्म 4 जनवरी. 1928 को हुआ था। साल 1949 से स्कूलों में कुछ वर्षों तक अध्यापन किया था। वे इंदौर के परसरामपुरिया स्कूल के प्राचार्च थे, जेपी, लोहिया, गांधी से प्रभावित होकर मास्टरी छोड़ दी थी, मीसा में जेल गए थे, विधानसभा चुनाव में जीत गए थे, शिक्षामंत्री भी बने थे, लेकिन जल्द ही समझ गए कि व्यवस्था में एक व्यक्ति की सीमाएं हैं। शिक्षा में बुनियादी बदलाव न कर पाने के कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और मुख्यधारा की राजनीति से नाता तोड़ जन संगठनों और जन आंदोलनों से जुड़ गए थे।

रावल जी का जब मुख्यधारा की राजनीति से मोहभंग हुआ, तो वे एक नई वैकल्पिक शक्ति को खड़ा करने के लिए जुट गए। वे छोटे-छोटे संगठनों और समूहों को ताकत और समर्थन देने के लिए तत्पर रहने लगे। चाहे वह नर्मदा बचाओ आंदोलन की बड़े बांधों के खिलाफ लड़ाई हो या फिर भोपाल गैस पीड़ित संगठन की, चाहे वह छत्तीसगढ़ के खदान मजदूरों की लड़ाई हो या फिर होशंगाबाद व झाबुआ के आदिवासियों की, वहां अपना समर्थन देते, कार्यकर्ताओं की हिम्मत बंधाते और लौटकर उन मुद्दों पर अखबारों में लिखते, जिससे उन मुद्दों को लोगों को जानकारी मिलती और समूहों को ताकत भी। असल में रावल जी छोटे-छोटे जन संगठनों से ही एक वैकल्पिक शक्ति के निर्माण का सपना देख रहे थे। वे एक बेहतर का सपना देख रहे थे। इसी को वे रियल पॉलिटिक्स कहते थे।

रावल जी से मेरा परिचय साल 1988 में हुआ, उस समय मैं इंदौर में महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। इसके साथ ही अखबार में काम कर रहा था। मैंने उनसे हॉस्टल में एडमिशन की सिफारिश चाही थी, उन्होंने और उनकी पत्नी कृष्णा रावल जी ने मुझे उनके घर में रहने की अनुमति दी। इसके बाद में उनके घर दो साल तक रहा। इस बीच रावल जी से बहुत कुछ जाना, समझा, पढ़ा और सीखा।

लंबी कद काठी, खादी का सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर मोटी फ्रेम का चश्मा और स्मित मुस्कान ही उनकी पहचान थी। रावल जी की एक खासियत और थी, वे बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। सहज और मिलनसार तो थे ही। वे मितभाषी होते हुए भी दूसरों को लंबी-चौड़ी बातें सुनने का धीरज रखते थे। नपे-तुले शब्दों में कही गई उनकी बातें व टिप्पणी सीख की तरह होती थी।

रावल जी बहुत ही जिज्ञासु व नम्र व खुले विचारों के व्यक्ति थे। किसी भी मुद्दे की तह में जाने के लिए वे सवाल करते रहते थे, और दूसरों को सुनते रहते थे। वे एक पत्रकार की तरह खोज-बीन करते दिखते थे। और फिर अंत में किसी राय पर पहुंचते थे। उनकी एक छोटी लाइब्रेरी थी। कई पत्र-पत्रिकाएं आती थी। वे खासतौर पर पर्यावरण के मुद्दे पर अखबारों में छपी खबरों को चिन्हांकित कर काटते थे, उनको फाइल में सहेजकर रखते थे। जब कोई लेख लिखते थे, तो संदर्भ के लिए उन्हें देखते थे।

सुबह-सवेरे मैं रावल जी के साथ बैठकर चाय के साथ अखबार पढ़ता था। देश-दुनिया की घटनाओं पर उनसे बातें होती थीं। बड़े बांध और पर्यावरण पर उन दिनों उनकी खास नजर रहती थी। यह वह समय था जब नर्मदा बांध का मुद्दा उभरकर सामने आ रहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उभार इन्हीं दिनों हो रहा था।

रावल जी ने अपने लंबे राजनैतिक व सामाजिक जीवन के अंतिम वर्षों में पर्यावरण के सवालों को समझने में और उन्हे जनता के सामने लाने में लगाए। वे युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं में संभावनाएं देखते थे। उनके घर ऐसे लोगों का आना- जाना लगा रहता था। उन्होंने कई सामाजिक कार्यकर्ता बनाए और प्रशिक्षित किए। उनमंघ से कई पत्रकार व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

मुझे याद है उस समय कल्पवृक्ष संस्था के और पर्यावरणविद् अशीष कोठारी के नेतृत्व में नर्मदा का एक अध्ययन हुआ था। इसके लिए इन युवाओं ने नर्मदा की यात्रा की थी, तब रावल जी के सहयोग से एक पत्रकार वार्ता की गई थी, जिसमें उन्होंने नर्मदा की व्यथा गाथा व उनके अनुभव सबके सामने रखे थे। इसी तरह पर्यावरण पर उन्होंने कई कार्यक्रम करवाए।

इसी प्रकार, उनके साथ मुझे साल 28 सितंबर, 1989 में हरसूद रैली में जाने का मौका मिला। वहां कर्नाटक के साहित्यकार शिवराम कारंत, मेधा पाटकर और बाबा आमटे से लेकर सिने तारिका शबाना आजमी, स्वामी अग्निवेश जैसे लोग उपस्थित थे। घाटी के लोगों के लोगों का तो सैलाब उमड़ पड़ा था। नर्मदा पर बांध बनाने के खिलाफ यह बड़ी घोषणा थी। इस पूरे आयोजन से रावल जी बहुत उत्साहित थे।

नर्मदा बचाओ आंदोलन का इंदौर में एक समर्थक समूह था, जिसमें ओमप्रकाश रावल जी, महेन्द्र भाई (सर्वोदय प्रेस सर्विस के महेन्द्र भाई), कलागुरू विष्णु चिंचालकर जैसे दिग्गज लोग शामिल थे। इंदौर में मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोग आते रहते थे। नईदुनिया के संपादक राहुल बारपुते की पर्यावरण में गहरी दिलचस्पी थी, और उनके अखबार में ऐसी खबरों व लेखों को प्राथमिकता देते थे।

आज हम जब नेताओं के तामझाम, दिखावे, गाड़ी-बंगले वाली जिंदगी को देखते तो रावल जी याद आ जाती है। उनकी सादगी, ईमानदारी और गरीबों के प्रति गहरी संवेदना की मिसालें याद आ जाती हैं। वे न केवल स्वभाव में सहज थे, बल्कि व्यवहार में भी सरल थे। जनसाधारण से बहुत आत्मीय से मिलते थे। एक बार की बात है। उनके घर दूध देने वाला आया, वे बर्तन लेने घर के अंदर गए, और किसी और काम में व्यस्त हो गए। तब तक दूध वाला खड़ा रहा। जब उन्हें याद आया तो भाग कर आए, और दूध वाले से कई बार अपनी भूल के लिए कई बार माफी मांगी। मैं देखता ही रह गया।

इसी प्रकार, उनके पड़ोस में रूई धुनाई करने वाली एक महिला की दुकान जल गई, तो वे द्रवित व भावुक हुए और वे न केवल से उसे देखने कई बार गए, बल्कि उसकी मदद भी की।

वे वर्तमान की तामझाम व जीवनशैली के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित सतत चलने वाली विकास की पद्धति जो विकेंद्रित व्यवस्था एवं पर्यावरण के संरक्षण पर ही संभव है, यदि नहीं अपनाई गई तो मनुष्य जाति जिंदा नहीं रह सकेगी। शीघ्र ही नई पीढ़ी तथाकथित विकास के लंबरदारों से सवाल करेगी कि तुम्हें ऐशो-आराम के लिए भावी पीढ़ी की संपत्ति को लूट लेने और नष्ट-भ्रष्ट कर डालने का क्या हक है? इस प्रश्न को समझकर विकास की ऐसी वैकल्पिक नीति चलानी होगी जो हमेशा-हमेशा के लिए कायम रहे तथा जो पर्यावरण की भी रक्षा करे और सामाजिक न्याय भी स्थापित करें।

कुल मिलाकर, अब हमारे बीच रावल जी नहीं है। उनका निधन 3 फरवरी, 1994 को हो गया है। लेकिन रावल जी जैसी हस्तियों को न केवल याद रखने की जरूरत है, बल्कि आज उनके विचार और व्यक्तित्व से कुछ सीखकर आगे काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं?

मैं रावल जी के साथ बैठकर चाय के साथ अखबार पढ़ता था। देश-दुनिया की घटनाओं पर उनसे बातें होती थीं। बड़े बांध और पर्यावरण पर उन दिनों उनकी खास नजर रहती थी। यह वह समय था जब नर्मदा बांध का मुद्दा उभरकर सामने आ रहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उभार इन्हीं दिनों हो रहा था।

बीता सप्ताह

29 सितंबर
- केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ चुनावी बांड मामले में जबरन वसूली पर एफआईआर दर्ज करने का विशेष अदालत ने आदेश दिया।
- इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने आतंकवादी संगठन संस्थापक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा।
- स्वीडन इसरो के शुक्र आर्डिट मिशन में शामिल हो गया।
- भारत की मार्टिना देवी मैबाय ने आईडब्ल्यूएफ जुनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024 में दर्ज किए दो राष्ट्रीय रिकार्ड।

30 सितंबर
- अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) रवाना हुआ। नासा स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान दो एस्ट्रोनेट को लेकर रवाना हुआ।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए।
- बीसीसीआई ने बेंगलुरु में नई अकादमी का शुभारंभी किया।
- फिलीपींस के एक चार मंजिला इमारत में आग लग जाने से 6 लोगों की मौत हो गई।

1 अक्टूबर
- सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा कि राजनेता भगवान को सियासत से दूर रखें।
- अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के सम्मान देने की सूचना केंद्रीय प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की।
- एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी के सेवानिवृत्त होने पर एयर चीफ एपी सिंह ने वायु सेना के नए प्रमुख का कार्यभार संभाला।
- अमेरिका में तूफान हेलेन से 93 लोगों की जान गई।

2 अक्टूबर
- जम्मू-कश्मीर में तीसरे व अंतिम चरण में विधानसभा चुनाव में 56 फीसदी वोट पड़े।
- अभिनेता गोविंदा को गलती से किसी की गोली लगने से मामूली चोट आई। उन्होंने लोगों का आभार जताया।
- जापान की संसद ने सत्तारूढ़ लिबरन डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीएफ के नेता शिगेरू हशिबा को प्रधानमंत्री चुना।
- छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओडिशा राज्य में भी की जाएगी धान खरीदी।

3 अक्टूबर
- घारामल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर प्रतिबंध लगा दिया।
- गाजा में शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में तीन फिलीस्तीनी नागरिक की मौत हो गई।
- नेपाल में अंतरराष्ट्रीय 'नेपाल गुब्बारा' महोत्सव का आयोजन का निर्णय लिया गया. 24 दिसंबर से 1 जनवरी।
- डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस एडनाय छेब्रेयसस ने स्वच्छ भारत मिशन योजना पर पीएम मोदी की तारीफ की।

4 अक्टूबर
- पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान कादिर ने 31 साल की उम्र में पाकिस्तान क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा की।
- जूनियर विश्व चैंपियनशिप में खुशीने 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन (3 पी) में कांस्य पदक जीता।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा कि जाति के आधार पर कैदियों को काम देना असंवैधानिक।
- हरियाणा विधान सभा चुनाव का प्रचार आज थमा। कल मतदान

हरियाणा में बैकफुट पर बीजेपी!

हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। आखिरी दो दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार में नहीं जाने को लेकर ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अंतिम चार दिन हरियाणा में ही डेरा जमाए रखा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और बलात्कार एवं हत्या के केस में सजायाफ्ता राम रहीम को पैरोल पर रिहा करवाकर चुनाव जीतना चाहती है? आखिर जो भाजपा राम के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकी, वह राम रहीम के भरोसे कैसे चुनाव जीत सकती है? वस्तुत: राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के चुनाव प्रचार को अपने हाथ में लेकर भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है।

भाजपा के पिछले दस साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के आखिरी दो दिन प्रचार करने के लिए नहीं गए। नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए खासे मशहूर हैं। लोकसभा और विधानसभा तो क्या, नगरपालिका के चुनाव में भी वह प्रचार करने में संकोच नहीं करते हैं। जब तक चुनाव प्रचार चलता है, वे कतई प्रधानमंत्री नहीं लगते, बल्कि नितांत भाजपा के नेता और आरएसएस के खांटी प्रचारक सरीखा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कभी आचार संहिता की चिंता नहीं की। जब चुनाव फंसने लगता है तो वह इमोशनल ड्रामा से लेकर सांप्रदायिक और नफरती बयानों पर उतर आते हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख से दो दिन पहले ही मैदान छोड़ दिया। जो नरेंद्र मोदी अंतिम कोशिश तक चुनाव जीतने के लिए लड़ते रहे हैं, वे हरियाणा का कुरुक्षेत्र छोड़कर अन्यत्र व्यस्त हैं। यह भी अपने आप में अनूठा उदाहरण है। अब सवाल यह है कि मोदी और शाह द्वारा बनाई गई दूरी के कारण और इसके मायने क्या हैं? क्या मोदी और शाह ने हरियाणा में हार को देखते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है? दरअसल, भाजपा के पास हरियाणा में ना तो कोई चेहरा है और ना ही एजेंडा। मनोहर लाल खट्टर हों या नायब सिंह सैनी, कोई भी जीत की गारंटी नहीं है। बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड नरेंद्र मोदी भी अब जीत की गारंटी नहीं रहे हैं। कांग्रेस का किसान, जवान, पहलवान के साथ भारतीय संविधान का एजेंडा इतना भारी हो गया है कि नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व कार्ड फीका पड़ गया। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हरियाणा का मैदान छोड़कर दिल्ली दरबार में रहना मुनासिब समझा।

एक सवाल यह भी है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के आखिरी चार दिन हरियाणा में ही क्यों जमे रहे। दरअसल, हरियाणा कांग्रेस में अंतर-विरोध की खबरें आ रही थीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुमारी शैलजा की नाराजगी की चर्चा के कारण हरियाणा में 20.17 प्रतिशत दलित मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। जबकि लोकसभा चुनाव में दलितों के वोटों के कारण ही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पांच सीटें हराने में कामयाब रही। इसके पीछे संविधान बचाने की राहुल गांधी की मुहिम थी। फिलहाल, राहुल गांधी ने इस बात को महसूस कर लिया है कि हरियाणा में स्थानीय क्षत्रपों के बीच मनमुटाव और तनाव की खबरें कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए राहुल गांधी ने आखिरी चार दिन विजय संकल्प रैली में लगाए। प्रियंका गांधी उनके साथ रहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को यह हुआ कि चेहरों की लड़ाई राहुल गांधी के आने से खत्म हो गई।

पिछले दो साल में राहुल गांधी ने अटूट परिश्रम, निष्ठा और निर्भय नैतिकता से जन सामान्य में जो विश्वसनीयता हासिल की है, इसका सीधा फायदा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ हरियाणा के स्थानीय मुद्दों को भी बड़े पैमाने पर उठाया है। हरियाणा के स्थानीय मुद्दों में बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी, महिला पहलवानों का अपमान तथा बढ़ती हुई नशाखोरी की लत को राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक अंदाज में उठाया। इन समस्याओं के लिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खूब घेरा। नरेंद्र मोदी ने अपने कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थानीय रोजगार छीन लिया। यहां तक कि जो छोटे-मोटे लघु और मध्यम उद्योग थे, लगभग खत्म हो गए। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का गुड़गांव; बेंगलुरु और हैदराबाद की तरह ही आईटी का हब है। बहुत सारी देशी-विदेशी कंपनियों के बड़े ऑफिस हैं। लेकिन हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार लगातार घटता चला गया। इस वजह से नौकरी की तलाश में नौजवानों को डंकी बनकर अमेरिका और यूरोप मजबूर होकर जाना पड़ा। अमित मान के जरिए राहुल गांधी ने बेरोजगारी के दंश और यातना भरी यात्रा को बेहद मार्मिक अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। अमेरिका में अमित मान से मुलाकात और फिर करनाल में उसके परिवार से मिलने का वीडियो को जारी करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगार परिवारों के घरों की स्थितियों का भावुकतापूर्ण वर्णन किया। यह राहुल गांधी का नया अंदाज है। वह ऐसी घटनाओं को सामने लाकर पूरे समाज के सच को बयां कर रहे हैं। यह लोगों से सीधा कनेक्ट करने का बेहतरीन तरीका है। इसी तरह से हरियाणा के करीब एक दर्जन जिलों में बढ़ती नशाखोरी की लत को मोदी और अडानी से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने इस समस्या को बेपर्दा किया। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 3400 किलोग्राम हीरोइन और कोकीन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के पोर्ट पर हीरोइन की जब्ती के गुनहगारों को क्यों नहीं पकड़ा गया? इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मात्रा में ड्रग्स देश में कहां-कहां पहुंचाई गई होगी। करोड़ों नौजवानों को यह जहर बेचा जा रहा है। क्या इसकी सटीक जानकारी मिल ही नहीं सकती है? ड्रग्स के जरिए भारत के नौजवानों को भीतर से खोखला और अपाहिज किया जा रहा है। नशा उन देशों में ज्यादा तेजी से पैर पसारता है जिस समाज में बेरोजगारी या नौजवानों के बीच कुंठा पसरी हो। मोदी के भारत में, ये दोनों ही चीजें साफ पसरी हुई हैं। ऐसे में व्यापारी हो या नेता; अगर सत्ता और लाभ हासिल करने के लिए नौजवानों तक यह जहर पहुंचाया जाता है तो उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्या आने वाले समय में ड्रग्स माफिया, कॉरपोरेट और राजनीतिकों के बीच की इस दुरभि-संधि को खत्म करके गुनहगारों को सजा दी जाएगी? राहुल गांधी के सामने यह बड़ी चुनौती होगी।

प्रो. रविकांत

पिछले दो साल में राहुल गांधी ने अटूट परिश्रम, निष्ठा और निर्भय नैतिकता से जन सामान्य में जो विश्वसनीयता हासिल की है, इसका सीधा फायदा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ हरियाणा के स्थानीय मुद्दों को भी बड़े पैमाने पर उठाया है। हरियाणा के स्थानीय मुद्दों में बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी, महिला पहलवानों का अपमान तथा बढ़ती हुई नशाखोरी की लत को राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक अंदाज में उठाया।

दुनिया को रहने योग्य बनाने के लिए फिर लौटना होगा गांधी की ओर

2 अक्टूबर को हमने फिर गांधी को याद किया। यह आश्वस्त करने वाली बात है कि कम से कम उन्हें याद करने की परंपरा जारी है। हम आशा करें कि इस परंपरा की सहायता से अहिंसा की फिलॉसफी किसी दिन मानवता की प्रकृति बन जाएगी। 2022 तक यह तर्क दिया जाता था कि युद्ध कम हो गए लेकिन सशस्त्र संघर्ष बढ़ गए थे। फिर रूस-यक्रेन युद्ध आरंभ हुआ और राष्ट्र संघ के अनुसार सिर्फ 2022 में संघर्ष से संबंधित मामलों में नागरिक मौतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। फिलीस्तीन पर इजरायली हमलों और बमबारी ने इस वैश्विक स्थिति को बदतर बना दिया है। अब हमारे पास फिलिस्तीनी लोगों की मृत्यु एवं दुखों का एक अंतहीन सिलसिला है। युद्ध के दुख के अतिरिक्त अन्य तरीकों और साधनों से भी हिंसा होती है जिसे मोटे तौर पर 'संघर्ष' के रूप में ब्रांडेड किया जाता है।

संघर्ष अब निरंतर, अंतहीन और सामान्य होते जा रहे हैं। उन्हें कभी-कभी इस अर्थ में कम घातक माना जाता है जब अक्सर दो पूर्ण या समान रूप से शक्तिशाली देशों के बजाय घरेलू समूहों के बीच हिंसा होती है। अनसुलझे क्षेत्रीय तनाव, कानून-व्यवस्था के भंग होने, सरकारी या सहकारी संस्थानों की अनुपस्थिति, अवैध आर्थिक लाभ तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या के कारण संसाधनों की कमी संघर्ष के प्रमुख कारण बन गए हैं। इसके अलावा राष्ट्र संघ ने यह भी नोट किया है कि 'तकनीकी प्रगति ने घातक स्वायत्त हथियारों तथा साइबर हमलों, बॉट्स और ड्रोन के सशस्त्रीकरण एवं चरमपंथी हमलों के टीवी पर सीधे प्रसारण ने भी चिंताएं बढ़ाई हैं।' इसके साथ ही 'डेटा हैक और रैंसमवेयर (किसी उपभोक्ता या संगठन के कम्प्यूटर सिस्टम में घुसकर उसके डेटा हैक कर संबंधित व्यक्ति से मोटी रकम की मांग करना) जैसी आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग की गतिविधियां तनाव में हैं जो सभी रूपों में संघर्ष व हिंसा की रोकथाम तथा समाधान की वैश्विक क्षमता को कम कर रहा है।'

ग्लोबल पीस इंडेक्स- 2024 में कहा गया है कि इस समय 92 देश संघर्षों में शामिल हैं। गाज़ा और यूक्रेन संघर्ष वैश्विक शांति में गिरावट के प्राथमिक कारण हैं। पिछले साल केवल संघर्षों के कारण लगभग 162,000 मौतें हुईं। अमेरिकी सैन्य क्षमता चीन की तुलना में तीन गुना अधिक है। संघर्ष के कारण 2023 में वैश्विक जीडीपी पर 13.5 प्रश या 19.1 ट्रिलियन डॉलर का असर पड़ा। प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण और नीतियों, विशेष रूप से अमेरिका-चीन मतभेदों को भी विभिन्न देशों के बीच और घरेलू संघर्षों की श्रृंखला का एक कारण माना जाता है।

एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं जबकि विश्व स्तर पर लिंग आधारित हमले बढ़ रहे हैं। सारे विश्व में यह माना जा रहा है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा सहित पारस्परिक हिंसा की घटनाओं से विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है।

गांधी आज भी दुनिया में इन घटनाओं के मूक गवाह बने हुए हैं। मानवता इस बात से अनजान है और भूल गई है कि प्रकट हिंसा और संघर्षों का गहरा संबंध है कि हम कैसे सोचते हैं, व्यवहार करते हैं और जीते हैं। अज्ञानता और बौद्धिक अहंकार व्यक्तिगत जीवन में संकट लाते हैं। ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा दांव पर हैं। लोभ और भोग की वजह से मानवीय गुणों की जगह विकारों ने घेर ली है। उच्चतम सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग शायद ही चरित्रवान होते हैं। यह एक बुनियादी संकट है।

गांधी जयंती का यह अवसर कुछ उदात्त विचारों की पेशकश करने या नैतिक आधार लेने के लिए नहीं है। हम यह स्वीकार करें कि देश और स्थान के बावजूद हमारा चरित्र सामूहिक रूप से हम सभी के सामूहिक व्यवहार में प्रकट होने के लिए जिम्मेदार है। एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आत्म-विनियमन और संभालने के लिए शिक्षित करना होगा जहां न्यूनतम संघर्ष और हिंसा हो।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने सामाजिक मानदंडों तथा देश के कानूनों की अनदेखी, उल्लंघन और तोड़-फोड़ करने वाले स्वेच्छाचारी व्यवहार को जन्म दिया है। गांधी ने 'हिंद स्वराज्य' में 19वीं सदी के जाने-माने जीवविज्ञानी और मानवविज्ञानी थॉमस हेनरी हक्सली को उद्धृत किया है- 'मुझे लगता है कि वह आदमी जिसे अपनी युवावस्था में इतना प्रशिक्षित किया गया है कि उसका शरीर उसकी इच्छा का तैयार सेवक है और आसानी और खुशी के साथ वह सब काम करता है, जो एक तंत्र के रूप में वह करने में सक्षम है; जिसकी बुद्धि साफ है, उसे स्वार्थहीन शिक्षा प्राप्त हुई है.., जिसका मन प्रकृति के महान और मौलिक सत्य एवं उसके संचालन के नियमों के ज्ञान के साथ संग्रहीत है .., जानता है कि जुनून को एक जोरदार इच्छा से पैरों तले आने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, एक संवेदनशील विवेक का सेवक .., सभी प्रकार की दुष्टता से घृणा करना और अपने समान ही दूसरों का सम्मान करना। मुझे लगता है कि उसे स्वार्थहीन शिक्षा मिली है क्योंकि वह प्रकृति के साथ सद्भाव में है। वह प्रकृति को और प्रकृति उसे सबसे अच्छा बना देगी।'

दुर्भाग्य से अगली पीढ़ी को उपरोक्त वर्णित भावना में शिक्षित करने में दुनिया भर की शिक्षा प्रणाली विफल रही है। हिंसा एक दिन में खत्म नहीं होगी। इसके लिए हमें अगली पीढ़ियों को शिक्षित करना है। गांधी ने साबित किया था कि शिक्षा शास्त्र और शिक्षा की फिलॉसफी मन, कर्म व बुद्धि को शिक्षित करने के क्रम में थी।

प्रचलित शिक्षा प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा और 'मैं पहले' की भावना को जन्म देती है। यह सहयोग, करुणा और प्रेम की भावना को खत्म करती है। प्रतियोगिता एक 'अच्छे जीवन' के लिए है। अच्छे जीवन को शारीरिक आराम और आनंद के रूप में देखा जा रहा है। यह व्यक्तियों को जीवन में खुशी की ओर ले जाने में समर्थ नहीं है। व्यक्तियों की वृद्धि और विकास का मापदंड भौतिक संसाधनों की असीमित मांग और उनकी निर्बाध आपूर्ति को माना जाता है और यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में परिलक्षित होता है।

अब यह समझा जाता है कि किसी देश के अंदर और देशों के बीच संघर्ष मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए होता है जो शारीरिक आराम और आनंद के लिए भौतिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। बेशक, एक वर्ग है जो दावा करता है कि यह प्रकृति को यथासंभव गहराई से जानने और पृथ्वी को समृद्धि के साथ सबसे अच्छा जीवित ग्रह बनाने के लिए सत्य की खोज है। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष व अनियंत्रित उपभोग के साथ-साथ चारित्रिक संकट ने तथाकथित उदार समाजों और देशों को बचाने एवं उन पर हमला करने के लिए धार्मिक कट्टरवाद को प्रेरित किया है।

जातीय हिंसक संघर्षों में भी अनिवार्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण होते हैं। संसाधनों पर कब्जे को सक्षम करने के लिए शक्ति तथा प्रभुत्व की वैश्विक भूख ने एक-दूसरे के प्रति नफरत को बढ़ावा दिया है। यह बहुत तार्किक नहीं लग सकता तथा राजनीतिक-आर्थिक शक्ति के खेल एवं बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद के बीच संबंध कमजोर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक गहरा प्रतिबिंब कनेक्शन को प्रकट करेगा। गांधीजी ने सौ साल से भी अधिक समय पहले आधुनिकता की नकारात्मक विशेषताओं पर अच्छी तरह से चर्चा की है जिसने कुछ पारंपरिक समाजों को धार्मिक कट्टरवाद का सहारा लेने, पुरातन विश्वासों के माध्यम से अपनी आबादी को गुलाम बनाने और धर्म-आधारित सभ्यता की स्थापना के नाम पर खूनी युद्ध करने के लिए उनका ब्रेनवॉश करने के लिए प्रेरित किया है।

यह मानवता के लिए शुभ संकेत नहीं है। नस्ल, आर्थिक असमानता, धर्म व नस्लीय पूर्वाग्रह प्रतिशोध के साथ वापस आ गए हैं एवं दुनिया में प्रकट और संरचनात्मक हिंसा को बढ़ावा देंगे। मानवता आखिर इससे कैसे बच निकलती है? गांधीजी ने एक जीवन जिया और उसे दिखाया। अपने जीवन के अंतिम दिन तक वे अपनी कमजोरियों पर चिंतन करते रहे और अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए उन्हें दूर करने की कोशिश की।

इस तरह गांधी अपना 'स्वराज' हासिल करने की राह पर चलते रहे। हम में से प्रत्येक को आत्मावलोकन, आत्म-परीक्षा और आत्म-सुधार के जरिए ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। विश्व के सभी देशों को नीति के रूप में सत्ता के राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण को अपनाना होगा। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण आरंभ हो सकेगा।

शूमाकर कॉलेज, डेवोन, (यूके) के संस्थापक सतीश कुमार के शब्दों में, 'आत्मा का पोषण करना, समाज में दूसरों से प्यार करना और धरती की देखभाल करना मानवता को अहिंसक दुनिया की ओर ले जाएगा।' वास्तव में यही महात्मा गांधी का संदेश है कि एक अहिंसक और रहने योग्य दुनिया का निर्माण किया जाए।

(लेखक महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)

डा. सुदर्शन अयंगर

इस तरह गांधी अपना 'स्वराज' हासिल करने की राह पर चलते रहे। हम में से प्रत्येक को आत्मावलोकन, आत्म-परीक्षा और आत्म-सुधार के जरिए ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। विश्व के सभी देशों को नीति के रूप में सत्ता के राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण को अपनाना होगा। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण आरंभ हो सकेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

संपादकीय

“ युद्ध एक विचारशील प्राणी के रूप में इन्सान की विफलता को दर्शाता है। - जॉन स्टीनबेक

युद्ध और तेल

पिछले कुछ वक्त से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन इस्राइल-हिजबुल्ला-ईरान संकट की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पर गहराता संकट भारत समेत दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं को बढ़ा रहा है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयातित तेल पर निर्भर हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ईरान ने जब इस्राइली ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई थीं, तभी कच्चे तेल की कीमत में कुछ तेजी दिखने लगी थी। लेकिन बाइडन के इस बयान के बाद कि इस्राइल ईरान के तेल के ठिकानों को निशाना बना सकता है, कच्चे तेल की कीमतों में करीब पांच फीसदी की वृद्धि हो गई, जिसमें पिछले चौबीस घंटों में कुछ और इजाफा हुआ है। हालांकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल व गैस विपणन कंपनियों ने अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन पश्चिम एशिया में हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, ऐसा होने की पूरी आशंका बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि ईरान दुनिया में तेल का सातवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो अपने तेल उत्पादन का करीब आधा निर्यात करता है। भारत ने पिछले कुछ समय से रूस से तेल के आयात को बढ़ाया जरूर है, लेकिन इसकी तेल व गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब भी पश्चिम एशिया से ही पूरा होता है। लिहाजा अगर इस्राइल और ईरान में युद्ध पूरी तरह से भड़कता है, तो लाल सागर और हारमुज की खाड़ी जैसे विश्व के प्रमुख तेल मार्गों में बाधा पहुंचेगी, जिससे कतर से होने वाले तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और रूस, इराक व सऊदी अरब से तेल के आयात में दिक्कतें आएंगी। ओमान और ईरान के बीच स्थित हारमुज की खाड़ी को वैश्विक तेल व्यापार का चौराहा कहा जाता है, और इसी वजह से यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अहम है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू स्तर पर भी तेल की कीमतें और तदनुरूप महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यह

देखते हुए कि हर बार तेल की कीमतों में उछाल हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देता है, वैश्विक समुदाय को पश्चिम एशियाई संकट का शांतिपूर्ण हल और वैश्विक आपूर्ति को सुरक्षित रखने की कोशिश तो करनी ही होगी, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देते हुए तेल पर निर्भरता के दौर से उबरने के प्रयास भी करने चाहिए।

युद्धों के पीछे के वैश्विक पैटर्न को समझें

इस्राइल के साथ हिजबुल्ला, हमास और ईरान की लड़ाई हो या रूस-यूक्रेन का युद्ध, इनके पीछे के पैटर्न को समझने के लिए हमें इन्हें उस व्यापक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा, जो आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शीतयुद्ध का स्थान लेते हुए दुनिया को दो धड़ों में विभाजित करने की दिशा में बढ़ रहा है।

इस्राइल द्वारा हिजबुल्ला पर किया गया विनाशकारी हमला क्यों और कैसे ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और यहां तक कि चीन के लिए भी दुनिया को हिला देने वाला खतरा बन गया है, यह समझने के लिए हमें इसको उस व्यापक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा, जिसने आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शीतयुद्ध का स्थान ले लिया है। पिछले वर्ष सात अक्तूबर को इस्राइल पर हमास के हमले के बाद मैंने कहा था कि अब हम शीतयुद्ध या शीतयुद्ध के बाद के दौर में नहीं हैं। हम 'शीतयुद्ध के बाद के दौर के बाद के युग' में हैं। इसमें सभ्य देशों के अस्थायी समावेशी गठबंधन और रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के नेतृत्व में एक 'प्रतिरोधी गठबंधन' के बीच संघर्ष चल रहा है।

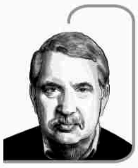

थॉमस एल. फ्रीडमैन

समावेशी गठबंधन में शामिल सभी देश लोकतांत्रिक नहीं हैं, पर अपने भविष्य को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सुरक्षित मानते हैं, जो जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को आर्थिक एकीकरण, खुलेपन और सहयोग के लिए प्रेरित कर रहा है। जबकि प्रतिरोधी गठबंधन में शामिल देशों का शासन क्रूर और अधिनायकवादी है, जो समावेशी दुनिया के प्रति अपने विरोध का उपयोग अपने समाजों के सैन्यीकरण को उचित ठहराने और सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए करता है। चीन दोनों खेमों में बंटा हुआ है, क्योंकि समावेशी गठबंधन तक पहुंच पर ही उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जबकि सरकार का नेतृत्व प्रतिरोधी गठबंधन की अधिनायकवादी प्रवृत्ति और हितों को साझा करता है।

यूक्रेन, गाजा और लेबनान में चल रहे युद्धों को इस वैश्विक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा। यूक्रेन यूरोप की समावेशी दुनिया में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। वह रूस के दायरे से आजाद होकर यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता था। इस्राइल और सऊदी अरब संबंधों को सामान्य बनाकर पश्चिमी एशिया में समावेशी दुनिया का विस्तार करने की कोशिश

कर रहे थे। रूस ने यूक्रेन को पश्चिम (यूरोपीय संघ और नाटो) में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया और ईरान, हमास और हिजबुल्ला ने इस्राइल को पूर्व (सऊदी अरब के साथ संबंध) में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो जाता है, तो यूरोप के 'संपूर्ण और स्वतंत्र' होने की समावेशी दृष्टि लगभग पूरी हो जाएगी और रूस में व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर इस्राइल को सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की अनुमति दी गई, तो इससे न केवल उस क्षेत्र में समावेशी गठबंधन का व्यापक विस्तार होगा, बल्कि यह ईरान और लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक में ईरान समर्थक शिया लड़ाकों के दुस्साहसी प्रतिनिधियों को लगभग पूरी तरह से अलग-थलग कर देगा, जो सभी अपने मुल्कों को विफल राष्ट्र में तब्दील कर रहे हैं। वास्तव में, यह कहना कठिन है कि हिजबुल्ला और उसके नेता हसन नसरल्ला, जो इस्राइली हमले में मारे गए, से लेबनान और सुन्नी व ईसाई अरब जगत के कई हिस्सों में लोग कितनी नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने लेबनान का अपहरण कर उसे ईरानी साम्राज्यवाद का अड्डा बना दिया था।

पिछले दिनों मैं ओरिट पेर्लोव से बात कर रहा था, जो इस्राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के लिए अरब सोशल मीडिया पर नजर रखती हैं। उन्होंने बताया कि लेबनानी लोग नहीं चाहते कि बेरूत को गाजा की तरह नष्ट कर दिया जाए और वे वास्तव में गृहयुद्ध की वापसी से डरते हैं। लेकिन नसरल्ला के अंत को लेबनानी, इस्राइली और फलस्तीनी लोगों के लिए स्थायी रूप से बेहतर भविष्य में तब्दील करने के लिए अभी बहुत सारे कूटनीतिक कार्य किए जाने बाकी हैं। बाइडन-हैरिस प्रशासन अस्थायी समावेशी गठबंधन को रणनीतिक महत्व देने के लिए एक नेटवर्क बना रहा है। पूरी परियोजना का मुख्य बिंदु इस्राइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का बाइडन टीम का प्रस्ताव है, जिसके लिए सऊदी अरब तैयार है, बशर्ते इस्राइल पश्चिमी तट में फलस्तीनी प्राधिकरण के साथ द्वि-राष्ट्र समाधान पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो। और समस्या यहीं पर आती है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण पर बारीकी से ध्यान दें, तो वह 'प्रतिरोधी' और 'समावेशी' गठबंधनों के बीच संघर्ष को अच्छी तरह समझते हैं। वास्तव में, यह उनके संयुक्त राष्ट्र भाषण का केंद्र बिंदु था।

उन्होंने अपने संबोधन के दौरान दो नक्शे दिखाए, एक का शीर्षक था 'आशीर्वाद' और दूसरा 'अभिशाप'। अगर आप 'अभिशाप' वाले नक्शे को ध्यान से देखें, तो इसमें इस्राइल तो दिखाया गया है, लेकिन गाजा और इस्राइली कब्जे वाले पश्चिमी तट के साथ कोई सीमा नहीं दिखाई गई है (जैसे कि इसे पहले ही जोड़ दिया गया हो, जो इस्राइल का लक्ष्य भी है)। और यही समस्या है। नेतन्याहू दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि ईरान और उसके समर्थक यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक फैले समावेशी दुनिया की मुख्य बाधा हैं। मैं इससे असहमत हूं। इस पूरे गठबंधन का आधार सऊदी-इस्राइल सामान्यीकरण है, जो इस्राइल और उदारवादी फलस्तीनियों के बीच सुलह पर आधारित है।

यदि इस्राइल अब आगे बढ़ता है और एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण, जिसने ओस्लो शांति संधि को पहले ही स्वीकार कर लिया है, के साथ दो राष्ट्रों पर बातचीत शुरू करता है, तो यह कूटनीतिक झटका होगा, जो इस्राइल द्वारा हिजबुल्ला और हमास को दिए गए सैन्य झटके को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में 'प्रतिरोधी' ताकतें पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाएंगी और उनकी झूठी ढाल छीन ली जाएगी कि वे फलस्तीनी मुद्दे के रक्षक हैं। ईरान, हमास, हिजबुल्ला एवं रूस और यहां तक कि चीन के लिए भी इससे बड़ा कोई झटका नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए नेतन्याहू को हिजबुल्ला, जिसे पार्टी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, के नेतृत्व को खत्म करने के सैन्य जोखिम से भी बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना होगा। 'समावेशी दुनिया' और 'प्रतिरोधी दुनिया' के बीच संघर्ष कई बातों पर आधारित है, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेतन्याहू लेबनान में 'पार्टी ऑफ गॉड' पर किए गए प्रहार के बाद इस्राइल में उनको समर्थन दे रही 'पार्टी ऑफ गॉड' के जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक संपूर्ण भू-भाग पर इस्राइली नियंत्रण के इरादों पर भी वैसा ही राजनीतिक प्रहार करें।

आर्थिकी

जटिलताएं पेश करता सीबीएएम

यूरोपीय संघ का सीबीएएम आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन शुल्क लगाता है, जो भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात के लिए जटिलताएं पेश कर सकता है।

वैश्विक व्यापार को नया आकार देते हुए यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) विकासशील देशों के लिए नई जटिलताएं भी पेश कर रहा है, विशेषकर भारत सरीखे विकासशील देश के लिए। सीबीएएम एक नियामक ढांचा है, जो यूरोपीय संघ में आयात पर कार्बन उत्सर्जन शुल्क लगाता है। सीबीएएम वर्ष 2026 से लागू होगा। इसमें 2023 से 2025 तक एक ट्रांजिशन यानी बदलाव कालीन चरण होगा। यह खास तौर से सीमेंट, लोहा, एल्यूमीनियम और स्टील जैसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन से बनने वाले सामान पर लागू होगा। सीबीएएम की वजह से यूरोपीय संघ के देशों में भारत द्वारा होने वाले निर्यात पर असर पड़ेगा। लोहा, स्टील और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं पर सीबीएएम के चलते कार्बन शुल्क 19.8 फीसदी से बढ़कर 52.7 फीसदी तक हो सकता है।

ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा थिंक टैंक एंबर ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यूरोपीय संघ के साथ सीबीएएम के अनुपालन के लिए भारत की रणनीतियों को रेखांकित करते हुए कहा है कि भारत के भारी उद्योगों के अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 17 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण से 2030 तक टाला जा सकता है। भारत के भारी उद्योगों को 2030 तक अपनी ऊर्जा खपत को पूरी तरह से डीकार्बोनाइज करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए 120 गीगावाट की समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमीनियम और अमोनिया क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उत्सर्जन-गहन 'भारी' उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन न केवल भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है। वर्तमान में, इन भारी उद्योगों में ऊर्जा की खपत का 11 प्रतिशत बिजली से आता है, जबकि बाकी जीवाश्म ईंधन-आधारित थर्मल ऊर्जा से आता है।

सीमा जावेद

उद्योग विकास अनुमानों के अनुसार, भारी उद्योगों के लिए बिजली की मांग में 45 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। इस बढ़ी हुई मांग को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने पर 18 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, जो नीदरलैंड के कुल वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। यदि नई प्रौद्योगिकियां और सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सफल होते हैं, तो 2050 तक औद्योगिक ऊर्जा मिश्रण में साफ बिजली का हिस्सा तीन गुना हो सकता है, और 73.7 करोड़ टन के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।

सीबीएएम नियमों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले सामान पर कार्बन उत्सर्जन के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना है। सीबीएएम को यह सुनिश्चित करना है कि आयात किए गए सामान का कार्बन मूल्य, घरेलू उत्पादन के कार्बन मूल्य के समान हो। साथ ही कार्बन उत्सर्जन पर कमजोर विनियमन वाले गैर-यूरोपीय संघ देशों में उत्पादन स्थानांतरित करने से कंपनियों को हतोत्साहित कर स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। एल्यूमीनियम, उर्वरक, सीमेंट इत्यादि जैसे कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिन्हें यूरोपीय निर्यात के मामले में संभवतः अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली की कल्पना करता है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पहली बार बड़े पैमाने पर कार्बन समायोजन की पहल है और इसलिए भविष्य में कई देशों के लिए यह परीक्षा की कसौटी बन सकता है।

एआई इन्सानों और मशीनों को करीब लाता है। यह इन्सानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाएगा। -रॉबिन बॉर्दोली

अगर आप एआई की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं, तो होना चाहिए। यह उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। -एलन मस्क

तुच्छ नहीं होती छोटी-छोटी शुरुआतें

जब विज्ञान को अपनी आजीविका बना लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन सभी बेमतलब की बातों और ईर्ष्याओं को पीछे छोड़ दिया है, जो मनुष्य की नैतिक प्रगति में बाधा डालती हैं। कुछ समय बाद मैंने अपने भीतर एक अलग तरह की उन्नति देखी।

मैं जीवनयापन के लिए पहले पुस्तकें बेचता था, जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी लंदन से बारह किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं की थी। छह महीने तक एक अप्रिय मालिक के यहां दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम किया। इस दौरान मैंने मनोरंजन के तौर पर रसायन विज्ञान और दर्शन की कई पुस्तकों से काफी कुछ सीखा और इस दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा हुई। मैं हमेशा से चुंबकीय-विद्युत पर निर्भर नए तथ्यों और विचारों की खोज का इच्छुक रहा हूं, न कि पहले से मौजूद शक्तियों की शक्ति को बढ़ाने की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद इसका पूर्ण विकास हो जाएगा।

माइकल फैराडे

जब मैंने पुस्तकें बेचने का काम छोड़ दिया और विज्ञान को अपनी आजीविका बनाया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन सभी बेमतलब की बातों और ईर्ष्याओं को पीछे छोड़ दिया है, जो मनुष्य की नैतिक प्रगति में बाधा डालती हैं। कुछ समय बाद मैंने अपने भीतर एक अलग तरह की उन्नति देखी। एक उन्नत व्यक्तित्व और समाज के लिए आत्म-शिक्षा जरूरी है। आत्म-शिक्षा वह बिंदु है, जिसमें मन को अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करना सिखाया जाता है। इसी आत्म-शिक्षा का परिणाम है कि मेरे अधीन कभी भी कोई ऐसा सहायक नहीं रहा, जिसने मेरी सहायता की हो।

जीवन धारा

मैंने हमेशा खुद से ही विचार करते हुए अपने प्रयोग किए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तब किसी कंपनी में काम कर सकता था या खुलकर सोच सकता था या अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता था। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा होता, तो अपने किसी सहायक के साथ घंटों और कई दिनों तक प्रयोगशाला में काम कर रहा होता या सफाई कर रहा होता। लेकिन आज मैं जो भी हूं, यह सब एकांत का परिणाम है। जीवन के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है अगर इसे समझा जाए, तो पाएंगे कि शिक्षा में मन के सुधार से संबंधित सब कुछ शामिल है, चाहे यह दूसरों से ज्ञान प्राप्त करके हो या स्वयं के प्रयासों से हो। यह हमें कभी भी किसी चीज की उपेक्षा करने की शिक्षा नहीं देती और छोटी-छोटी शुरुआतों को तुच्छ नहीं समझती है। कोई भी चीज इतनी अद्भुत नहीं है कि वह सच न हो सके, अगर वह प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो।

चैटजीपीटी से एक लेखिका की मुठभेड़

चैटजीपीटी ने लेखिका को पीछे छोड़ते हुए कहानी तो सिर्फ 17 सेकंड में लिख दी, लेकिन क्या उसमें वह भावनात्मक रस था, जो आपको भिगो दे।

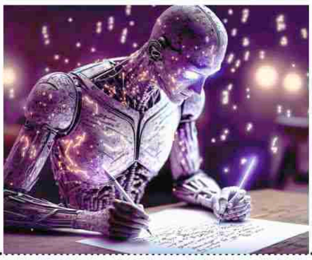

इमोशन एआई

इसे इमोशनल एआई या प्रभावशाली एआई भी कहते हैं। एआई के क्षेत्र में उभरती हुई इस इमोशन एआई तकनीक का उद्देश्य मानवीय भावनाओं का पता लगाना, उनका विश्लेषण करना और फिर उन पर अपनी प्रतिक्रिया देना है। मानवीय भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए यह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

कंपोजिट एआई

एआई ने बिजनेस के कई क्षेत्रों में विविधताओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अवसर बढ़े हैं, तो जटिलताएं भी हैं। इन्हीं जटिलताओं का समाधान करने और एआई की मदद के लिए एआई तकनीक में कंपोजिट एआई का प्रयोग किया जा रहा है। कंपोजिट एआई वह तकनीक है, जो कई तकनीकों की विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग कर बिजनेस में आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। कंपोजिट एआई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और नॉलेज ग्राफ के उपयोग से समस्याओं का हल करती है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि एआई अनुप्रयोगों में बड़े डाटा शीट की जरूरतों को पूरा करता है।

कर्टिस सिटेनफील्ड
उपन्यासकार

इन गर्मियों में, मैं एक अलग तरह के साहित्यिक प्रयोग का हिस्सा बनी। प्रयोग का विषय था कि एक इन्सान द्वारा रचित कहानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई द्वारा लिखित कहानी में क्या फर्क है? यह तय हुआ कि मेरे और चैटजीपीटी के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, यह देखने के लिए कि कौन बेहतर लिखता है। मैंने यह सोचकर प्रयोग के लिए हामी भर दी कि मशीन के साथ आमने-सामने की लड़ाई में हमें एआई के बारे में कुछ स्पष्ट जवाब मिल सकेंगे। प्रतियोगिता के आयोजकों के सामने अगली समस्या विषय के चुनाव की थी, जिसके बारे में यह निर्णय लिया गया कि पाठकों के बीच एक सर्वे आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिये ही विषय का चुनाव होगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं उन कई लेखकों में से हूं, जिनके उपन्यासों का उपयोग बगैर मेरी अनुमति के और बगैर मुझे मुआवजा दिए, चैटजीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। खैर, विषय तय हुआ और मुझे व चैटजीपीटी को प्रतियोगिता की शर्तें भी समझा दी गईं। हम दोनों ने कहानी लिखी। चैटजीपीटी की कहानी का 48 वर्षीय नायक बहुत शर्माता है और किशोरावस्था वाली पत्रिकाएं पढ़ता है। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन इतनी जल्दी कहानी का आकलन नहीं कर सकते। मैंने चैटजीपीटी की पूरी कहानी पढ़ी। मैं दावे के साथ कह रही हूं कि इतनी उबाऊ थी कि अगर प्रतियोगिता का सवाल न होता, तो शायद मैं कभी पूरी नहीं पढ़ती। कुल मिलाकर मुझे लगा कि वाक्य रचना की दृष्टि से तो चैटजीपीटी बेहद कुशल है, लेकिन मानवीय भावनाओं के स्तर पर बहुत उथला है। अगर आपको खूब पढ़ने की आदत है, तो चैटजीपीटी का लेखन आपको काफी घिसा-पिटा भी लग सकता है।

कुछ कमी है, जो आपको चैटजीपीटी की कहानी में लगेगी, जो मुझे भी लगी। मैं निष्पक्षता का दिखावा करते हुए इसकी तारीफ नहीं कर सकती। चूंकि प्रतियोगिता की थीम में यह शामिल था कि कहानी ऐसी हो, जो लोग समुद्र तट पर बैठकर पढ़ना चाहें, मैंने अपनी कहानी में कुछ चीजें जोड़ीं, लेकिन उन पर चैटजीपीटी ने ध्यान नहीं दिया।

- मैंने लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि जल्दबाजी से चीजों को बेहतर बनाने का मौका खोता है।
- मैं कई दिनों तक समुद्र तट पर टहलने गई, यह महसूस करने के लिए कि उस वक्त मनोविज्ञान किस चीज को पढ़ने की इच्छा करता है।
- मैंने अपनी कहानी के पहले ड्राफ्ट पर अपने भरोसेमंद मित्रों व परिवारजनों से फीडबैक लिया।
- कहानी जिस शहर की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, मैंने वहां जाकर उन जगहों को देखा और वहां के रेस्तरां की मेन्यू सूची भी देखी, ताकि मैं मौलिक ढंग से इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकूं।

एक चीज ऐसी है, जो मैंने की और जिसे चैट जीपीटी भी कर सकता था। चूंकि कहानी 1970 के दशक की है, मैंने सरकारी आंकड़ों की छानबीन की, ताकि मैं उस वक्त लोगों के नाम कैसे होते थे, यह जान सकूं। कहानी के चरित्रों के मैंने वैसे ही नाम रखे। एक चीज ऐसी जरूर थी, जो मैंने नहीं की और चैटजीपीटी ने की। चैटजीपीटी ने अपनी कहानी 17 सेकंड में लिखी, जबकि मुझे काफी वक्त लगा। एआई का यह गुण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इसकी कीमत भी हम चुकाते हैं। कहानी का नायक जब सोफे पर अपना हाथ रखकर कपड़े को महसूस करता है, या जब वह कॉफी का पहला घूंट पीता है और अपनी जीभ पर उसके स्वाद को फैलते हुए महसूस करता है, वह अनुभव जब कहानी में पाठक पढ़ते हैं, तो शब्द, चित्र बन जाते हैं। चैटजीपीटी की कहानी में ये अनुभव क्यों नहीं होते। मनुष्य और मशीन की लड़ाई में फिलहाल मेरा दांव तो मनुष्य पर ही है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 233 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

सम्पादकीय

दुनिया में चल रहे युद्ध पर भारत का अपना स्टैंड, त्रासदी के विरुद्ध शांति का पैगाम

पश्चिम एशिया में अब युद्ध का दायरा जिस तरह फैलने की आशंका पैदा हो रही है, उसका सिरा कहां तक जा सकता है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्वाभाविक ही भारत ने चिंता जताते हुए युद्ध में शामिल सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है और यह भी कहा कि अगर टकराव नहीं रुका तो कहीं ऐसा न हो कि युद्ध समूचे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले ले। दरअसल, हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो आक्रामक रुख अख्तियार किया, वह अब लेबनान और ईरान तक को अपने दायरे में ले रहा है और इसमें शामिल सभी पक्ष केवल खुद को सही और पीड़ित मान रहे हैं। मगर विचित्र है कि युद्ध के बजाय संवाद के जरिए समाधान का रास्ता खोजने के बजाय इजराइल, हमास, हिजबुल्ला या ईरान की ओर से युद्ध की घोषणा, हमला और उसके जवाब में उससे बड़ा हमला करके मसले का हल निकालने का दावा किया जा रहा है। सवाल है कि युद्ध का जो रास्ता खुद ही एक समस्या है, उसके जरिए किसी मसले का हल निकालने की कोशिश कहां लेकर जाएगी यह जगजाहिर हकीकत है कि मध्य-पूर्व में कई युद्धों ने उस समूचे इलाके में एक बड़ी त्रासदी खड़ी की। उससे उबरने में कई देशों को खासा वक्त लगा और अब वहां जब स्थितियां बेहतरी का रुख पकड़ रही थीं, तो अब फिर हालात चिंताजनक बन रहे हैं। स्वाभाविक ही उन इलाकों में रहने वाली आम आबादी के सामने जीवन तक की चुनौती खड़ी हो रही है। दरअसल, भारत की चिंता इस बात से भी जुड़ी हुई है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव ने बेलगाम युद्ध का रास्ता अख्तियार किया, तो उस समूचे इलाके में रहने वाले भारतीयों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसी से चिंतित भारत ने यह कहा है कि हम इस समूचे क्षेत्र में अपने नागरिकों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। मगर सच यह है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल पर जिस तरह भारी संख्या में मिसाइल दागे गए, उसके बाद अगर युद्ध की स्थितियां अनियंत्रित हुईं, तो उसमें चुनौतियां गहराएंगी। इसी के मद्देनजर भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को सतर्क रहने और गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। भारत ने हमेशा युद्ध के बजाय समस्या के हल का रास्ता शांति, संवाद और कूटनीति के जरिए निकालने की वकालत की है। भारत की चिंता इस बात से भी जुड़ी हुई है कि इजराइल और ईरान के बीच टकराव की नई तस्वीर में कहीं दुनिया के और कई देशों के उलझने की स्थिति न बने। दो देशों के बीच जंग से लेकर विश्व युद्धों तक के रूप में दुनिया ने देखा है कि युद्ध का हासिल क्या होता है। इतिहास से लेकर अब तक के तमाम उदाहरण यही साबित करते हैं कि संयम और संवाद के बजाय अगर युद्ध का रास्ता चुना जाता है तो उससे खुद वह मुद्दा भी और ज्यादा जटिल हो जाता है, जिसके हल के लिए ऐसा किया जाता है। अतीत में युद्ध की वजह से मानवता के सामने खड़े हुए त्रासद संकट से सबक लेने के बजाय अगर आधुनिक माने जाने वाले देश भी सैन्य टकराव को प्राथमिक उपाय मानते हैं, तो इसे कैसे देखा जाएगा?

विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने का क्रेज का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है

पिछले कुछ वर्षों से भारत से विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने की आकांक्षा का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2016 और 2021 के बीच 26।44 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए गए। एसोसिएटेड चेम्बरर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने 13.5 अरब डालर का खर्च किया। वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डालर यानि लगभग 2 लाख करोड़ रूपए रहा और रेडसियर स्टार्टेजी कन्स्लटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डालर यानि 7 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे।

अशोक भाटिया

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इससे देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है। इससे उद्योग-धंधों के लिए श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा, देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र फंसे तो नेताओं को पता चला कि इतने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक ने हैरानी जताई। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत से हरेक साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों में क्यों चले जाते हैं? यह सवाल कनाडा में जो भारत को लेकर हो रहा है उस रोशनी में पूछ जाना चाहिए। वहां जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे पहले ही भारतीयों के साथ हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय अधिक जाग चूका है और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि इजराइल में फिलहाल करीब 18 हजार भारतीय जबकि वेस्ट बैंक में करीब एक दर्जन और गाजा में तीन से चार भारतीय रह रहे हैं। जब यहाँ छात्र किसी कारण से फंसते है तो भारत सरकार को 'एयर -लिफ्ट 'का सहारा लेना पड़ता है जो परेशानी भरा होता हैं । केन्द्रीय मंत्री बी। मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया था कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4।44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए। एक अन्य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6।46 लाख थी, यानि 45 प्रतिशत की वृद्धि।

यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत से ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 के संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है। विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके माता-पिता अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर

इन युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गांवों में बड़ी मात्रा में विदेशों से धन आता था। विदेशों में पढ़ाई के इस क्रेज़ के चलते यह प्रक्रिया उलट हो गई है, यानि अब विदेशों से धन आने के बजाय विदेशों को धन भेजा जा रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2024 के अंत तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डालर पहुंच जाएगी, तो यह देश के लिए अत्यंत संकटकारी स्थिति का कारण बनेगा। गौरतलब है कि युवाओं का शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन, देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में पिछले दो-तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। यदि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो 1990-91 में जहां मात्र 49.2 लाख विद्याार्थियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया, यह संख्या वर्ष 2020-21 में 414 लाख तक पहुंच गई। मोटेतौर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्याार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुणा से भी ज्यादा हो चुकी है। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि वर्ष 2021 में देश में 1113 विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान, 43796 महाविद्यालय और अन्य स्वतंत्र संस्थान 11296 थे। इसी वर्ष देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 15.51 लाख शिक्षक कार्यरत थे। देश में कई विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और कई अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं और कई 'विश्वविद्यालय सम' यानि 'डीम्ड विश्वविद्यालय' हैं। देश में कई विश्वस्तरीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी वैश्विक कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं। जहां तक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों में फीस विदेशी संस्थानों में फीस से कहीं कम है और जिन विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत नीचा है। तो सवाल उठता है कि भारी भरकम राशि खर्च कर भारत के युवा विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश क्यों लेते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि विदेशों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश लेकर वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहां तक कि इंग्लैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि वहां रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय युवा यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि इन देशों में भी रोजगार की भारी कमी है। कई देशों में वहां के स्थानीय लोग भारतीय एवं अन्य देशों से आने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें भी देखने को मिल रही हैं।

देश से जाने वाले अधिकांश युवा विद्यार्थी वहां रोजगार प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं और उन्हें स्वदेश वापिस लौटना पड़ता है, जिसके कारण वे भारी कुंठा का भी शिकार हो रहे हैं। चूंकि व्यक्तिगत तौर पर विदेशों में जाने वाले युवा विद्यार्थी, पूर्व में विदेशों में जाने वाले भारतीयों की सफलता की गाथाओं से प्रभावित होकर विदेशों की ओर रूख कर रहे हैं। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे कि आज कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में, जहां वे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं, वे शिक्षा संस्थान स्वयं के आस्तित्व को बचाने हेतु भारतीय विद्यार्थियों को आसानी से अपनी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं भारतीय और अन्य देशों के अति इच्छुक विद्यार्थियों से भारी फीस ऐंठने हेतु शिक्षा की कई दुकानें भी खुल रही हैं, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
ऑफिस या घर में उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ेगा। जीवन को अधिक गंभीरता से लेंगे। नए संबंध स्थापित करने या काम के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शुभ अवसर के आयोजन के लिए समय अच्छा नहीं है।

वृष
सामाजिक समारोह, पर्यटन आदि के लिए जा सकते हैं। आप प्रफुल्लित रहेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे। अविवाहितों के लिए वैवाहिक योग है। सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए लाभ का दिन है।

मिथुन
पारिवारिक सदस्यों या सगे- संबंधियों के साथ मतभेद हो सकता है। आपकी बातचीत या व्यवहार के कारण गलतफहमी खड़ी हो सकती है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होने से चिंता बढ़ेगी। व्यर्थ के कार्यों में शक्ति बरबाद होगी।

कर्क
आज अत्यधिक धन खर्च की संभावना है, इसलिए संभलकर खर्च करने की सलाह दी जाती है। किसी के साथ आर्थिक व्यवहार करते समय काफी सावधानी बरतें। सामान्य बातचीत वाद-विवाद में परिवर्तित न हो जाये। शरीर में थकान, आलस और चिंता का अनुभव होगा।

सिंह
किसी के साथ संघर्ष न हो, इसका ध्यान रखें। आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति से मानसिक शांति मिलेगी। आज आपका मन चिंता के भार से मुक्त होगा। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। स्त्री मित्रों से विशेष लाभ होगा।

कन्या
शरीर में थकान, आलस और चिंता का अनुभव होगा। संतान के साथ मतभेद या मनमुटाव होगा। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ आपका वाद-विवाद होगा। राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नौकर और सहकर्मी आपके सहायक बनेंगे।

तुला
समय से भोजन करने में विलंब तथा अत्यधिक खर्च आपके मन को अस्वस्थ बनाएंगे। नौकरी-धंधा और व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपको लाभ ही लाभ है। इसके साथ मित्रों, सगे संबंधियों और बुजुर्गों से भी लाभ प्राप्ति का संकेत है।

वृश्चिक
नियमित आय में वृद्धि होने के साथ अन्य तरीके से आर्थिक लाभ होगा। दांपत्यजीवन में आनंद व्याप्त रहेगा। तन-मन से स्वस्थता का अनुभव होगा। किसी रमणीय पर्यटन स्थल की यात्रा से आपके आनंद में बढ़ोतरी होगी।

धनु
तबीयत खराब होने की संभावना होने के कारण खान-पान का ध्यान रखें। संक्षेप में कहा जाए, तो आज का दिन मध्यम रहेगा। आज का दिन आपके लिए शुभफलदायक होगा। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति निखर उठेगी।

मकर
धार्मिक कार्यों या धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखनें। कटु वचन या खराब व्यवहार के कारण झगड़े- विवाद होंगे। क्रोध और कामवृत्ति पर संयम आवश्यक होगा। आर्थिक लाभ की संभावना है।

कुंभ
मन दुविधा से मुक्त होने के कारण आप हिम्मत से काम कर सकेंगे और उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह निर्वाह कर सकेंगे। आर्थिक आयोजन सफलतापूर्वक कर सकेंगे। मौज-शौक की वस्तुएं और मनोरंजन के पीछे खर्च होगा।

मीन
परिवार में सुख- शांति का माहौल रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज तन-मन की अस्वस्थता और बेचैनी रहेगी, इस कारण आपको वाणी और व्यवहार में खूब सावधानी बरतने की जरूरत है। आंखों में दर्द होने की भी संभावना है। संतान के साथ मतभेद या मनमुटाव होगा।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

'सरल,सहज,सौम्य,सभ्य,शांत ये कोई शब्द नहीं बल्कि किसी के जीवांत व्यक्तित्व की शैली है शायद इसलिए ऐसे शब्दों में जीने वाले को तब भी याद किया जाता है जब वे कुर्सी पर नहीं होते'

नमस्कार साथियों हमारे आज शख्सियत कॉलम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं अनिल कुमार अग्रवाल का जो की निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर में अपनी निष्ठावान और गौरव में राजकीय सेवा पूरी कर हाल ही में सेवानिवृत हुए हैं । इनकी सरलता का क्या कहना,इनकी इमानदारी का क्या कहना सच में बेहद उम्दा व्यक्तित्व रहा है इनका। इतने सरल रहे हैं कि इन्हें कभी क्रोधित होते देखा ही नहीं जबकि इतने बड़े कॉलेज के प्राचार्य रहे लेकिन हमेशा तनावमुक्त रहकर खुद भी जिम्मेदारी संभाली और दूसरों को भी तनाव मुक्त ही रखा। इनका जन्म 6 अप्रैल सन 1965 को अलवर में हुआ उनकी स्कूली शिक्षा भी अलवर में हुई और सन 1986 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से यांत्रिक अभियंत्रिक की में स्नातक शिक्षा प्राप्त की थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला से गोल्ड मेडल से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की सन 2015 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की अपनी राजकीय सेवा की यात्रा राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से प्रवक्ता यांत्रिकी के पद से प्रारंभ की एवं प्रवक्ता के पद पर राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय अलवर में भी अपनी सेवाएं प्रदान की दोस्तों इनका व्यवहार और व्यक्तित्व बहुत सरल,निष्ठावान,आध्यात्मिक,गौरवमय, कर्तव्यनिष्ठ सद्भावी, मृदु भाषी और हमेशा मुस्कान बिखरने वाला रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगभग ढ़ाई दशक हो गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप इनको काफी करीब से जानता हूं और इनका व्यवहार सभी लोगों के साथ बहुत आनंदमय रहा है इसका सबसे बड़ा कारण शुरू से ही इन्हें संतों और आध्यात्मिक आबोहवाओं सानिध्य मिला। स्कीम नंबर एक में स्थित श्री हरि बाबा सत्संग भवन मंदिर से इनका काफी जुड़ाव रहा है आज भी यह इसी आध्यात्मिक वातावरण में अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को जीवांत बनाए

श्री अनिल कुमार अग्रवाल
(निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर)

हुए हैं। हाल ही में यह निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान जोधपुर से सेवानिवृत हुए हैं और बहुत सराहनीय प्रयास रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से ही अलवर शहर में एक राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं भिवाड़ी में में एक राजकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय इस बजट में स्वीकृत हुए हैं जो की अगले वर्ष से प्रारंभ हो जाएंगे। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु और सुखी जीवन व उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जय हिंद
रूपक शर्मा

आज का इतिहास

5 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- ईस्ट इंडिया कंपनी को 1676 में इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार मिला।
- फ्रांस की क्रांति के दौरान पेरिस की महिलाओं ने 1789 में वर्सेलिस तक मार्च किया।
- फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में 1793 को ईसाई धर्म विस्थापित हुआ।
- स्पेन ने 1796 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- कलकत्ता शहर में 1864 को चक्रवात से लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई।
- अलोंजो टी क्रॉस ने 1880 में पहले बॉल प्वॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
- पुर्तगाल में राजशाही खत्म हो गई और गणतंत्र की स्थापना 1910 में हुई।
- बुल्गारिया ने 1915 को प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया।
- फ्रांस में महिलाओं को 1944 में मताधिकार मिला।
- तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्क़ाबात में 1948 को हुए भूकंप से 110,000 लोगों की मौत।
- जेम्स बॉंड सीरीज की पहली फिल्म 'डॉ. नो' 1962 को रिलीज हुई।
- ब्राजील की संविधान सभा ने 1988 में संविधान को मंजूरी दी।
- मीरा साहिब बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी।
- तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को 1989 में मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
- आयरलैंड के कवि एवं साहित्यकार हीनी को 1995 में वर्ष 1995 के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा।
- राजधानी कम्पाला से नील नदी को 1997 को स्रोत जिन्जा में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेसतथा महेश भूपति ने जिम कूरियर तथा एलेक्स ओ ब्रायन को पराजित कर 'चाईना ओपन टेनिस टूर्नामेंट' का खिताब जीता।
- भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर होने वाली विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला 1999 में किया।
- यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मिलोसेविच के खिलाफ 2000 में विद्रोह।
- पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2001 में सेनाध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया।
- पश्चिम एशिया पर अरब देशों के प्रस्ताव का अमेरिका ने 2004 को विरोध किया।
- खुशमिजाजी में 2005 को भारत चौथे नंबर पर।
- नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच समझौता न हो पाने के कारण संविधान सभा के लिए 2007 को चुनाव रद्द हुआ।

विशेष आलेख

अंतर्राष्ट्रीय चिंतन : विश्व-युद्ध की पृष्ठभूमि में इजरायल, हमास लेबनान ईरान युद्ध

संजीव ठाकुर

अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी के अनुसार वैश्विक युद्ध की भूमिका वैसे तो इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध ने पहले से ही रख दी थी हिजबुल्ला लड़ाको ने इजराइल फिलिस्तीन हमास युद्ध के बीच कूद कर युद्ध में आग में घी का काम किया है। इसके अलावा लेबनान ने इस युद्ध में अपने को शामिल अपनी आहुति दे दी। इसराइल ने जिस तरह लेबनान में छिपे हिजबुल्ला के आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और उसमें कमांडर नसरूल्लाह की हत्या ने पूरे ईरान और शिया समुदाय को हिलाकर आक्रोशित कर दिया है। ईरान ने इसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर लगभग 300 टारगेटेड मिसाइल इसराइल पर दाग कर विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर दी है। यह अलग बात है कि इजरायल अब अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो गया अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी प्रतिबद्धता के कारण इसराइल को समर्थन दे रहे हैं। अब इसराइल बेलगाम होकर ईरान लेबनान और हमास के आतंकवादियों पर खुलकर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूत करने पर उतारू है । इसराइल के इस युद्ध में अरबो रुपए खर्च हो चुके हैं उधर ईरान ने भी लगभग 30 करोड़ की मिसाइल से अपना हमला कर इरादे साफ कर दिए हैं कि अब ईरान भी रुकने वाला नहीं है। इन सब युद्ध की गतिविधियों से विश्वयुद्ध की संभावनाएं बढ़ गई है और विश्व युद्ध वर्तमान की मानवीय सभ्यता के लिए एक गतिहीन अवरोध बन गया है। उधर अरबपति अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरस ने दावोस में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि दुनिया को इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें पूरे संसाधन झोंक देने चाहिए। वैसे भी रूस यूक्रेन युद्ध को दो साल से ज्यादा हो चुके हैं और युद्ध रोकने के जितने भी प्रयास है असफल हो चुके हैं वैश्विक सभ्यता को संरक्षित, पल्लवित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और संभवत एकमात्र तरीका रूस-यूक्रेन और इजरायल हमास, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान युद्ध को हर संभव तरीके से रोकना होगा होगा। यह हमला तीसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत कर सकता है और हमारी सभ्यता इसे झेल नहीं पाएगी और तहस-नहस हो जाएगी। दावा किया गया है कि पुतिन ने शी जिनपिंग को पहले से ही बता दिया था और दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी दोनों ने एक लंबा बयान जारी कर घोषणा की थी कि उन दोनों के बीच संबंधों की और सहयोग की कोई सीमा नहीं है। पुतिन ने सी जिनपिंग को यूक्रेन के विरुद्ध विशेष सैन्य अभियान की जानकारी भी दे दी थी। तब शी जिनपिंग ने पुतिन से ओलंपिक खेलों के होते तक सैन्य अभियान रोकने की बात कही थी। इसी बीच रूस के एक राजदूत ने इस्तीफा देकर पुतिन की इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया था और युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार ने भी रूस में अपना विरोध दर्ज किया है। पुतिन को अपनी गलतियों का अब धीरे-धीरे एहसास हो रहा है जब यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषा

के नागरिकों ने यूक्रेन पर हमले की घोर निंदा की है जबकि पुतिन को उनके समर्थन आशा थी जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुतिन को अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण करके एक बड़ी गलती की है। अब वह संघर्ष विराम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हैं जो वर्तमान संदर्भों में संभव नहीं है। क्योंकि विश्व समुदाय का रूस पर भरोसा खत्म हो चुका है। अब या तो पुतिन अपनी हार छुपाने के लिए चाइना की मदद विश्व युद्ध करेंगे या फिर अपनी हार स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा देकर पलायन कर जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध मैं आज तक कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अमेरिका सहित नैटो देश के सदस्य और अन्य यूरोपीय सदस्य लगातार यूक्रेन की आर्थिक तथा सामरिक मदद करते आ रहे हैं और इस स्थिति में रूस ही कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि रूस के तमाम कमांडर और सैनिकों का मनोबल अब लगातार गिरते जा रहा है, इसके पश्चात रूस के नागरिक भी इस युद्ध के अंदरूनी खिलाफ है जबकि यूक्रेन के नागरिक उसी हौसले और उत्साह के साथ अपने नेता जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। अब स्थिति यह है कि यूक्रेन के पास ना तो पैसे की कमी है ना ही हथियारों की,वह लगातार रूसी सैनिकों तथा कमांडरों का जमकर विरोध कर रहा है। ये अलग बात है कि मारियोपोल मैं इमारतों के मलबे के निकालने के पश्चात अलग-अलग जगह से चार पांच सौ दबे हुए शव को निकाला गया है। जिससे वहां जनता के बीच हाहाकार मच गया है। इस युद्ध की विभीषिका से यूक्रेन के लगभग एक करोड़ नागरिक यूक्रेन छोड़कर पोलैंड एवं अन्य देशों में शरण लेकर शरणार्थियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यूरोपीय देश इन शरणार्थियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प हैं और उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वैश्विक राजनीति में चीन और रूस सर्वथा अलग-थलग पड़ गए हैं। ताजा स्थिति के अनुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत में टोक्यो सम्मेलन में चीन के बढ़ते औपनिवेशिक वाद के खतरे को भांपते हुए प्रशांत महासागर एवं तीन पेसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए गठजोड़ कर लिया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मुस्कान से आसान होती है मुश्किलें

-ललित गर्ग

प्रत्येक अक्टूबर के पहले शुक्रवार को यानी इस वर्ष 6 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस है। आज मनाए जाने वाले विश्व मुस्कान दिवस के पीछे वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स के एक अमेरिकी वाणिज्यिक कलाकार हार्वे बॉल के दिमाग की उपज थी। प्रतिष्ठित स्माइली फेस 1963 में उनके द्वारा बनाया गया था। तब से, इसने सभी के सामूहिक आनंद को कैद कर लिया है। 1999 में पहला स्माइल डे बिना किसी बाधा के उत्साह और धूमधाम से मनाया गया था, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक समस्याओं एवं परेशानियों के हल समाये होते है। 2001 में, हार्वे के निधन के बाद, स्माइली निमार्ता को श्रद्धांजलि के रूप में हार्वे बॉल वर्ल्ड स्माइल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। इस दिन को स्थापित करने वाले मैसच्यूसेट्स के आर्टिस्ट हार्वे बाल के अनुसार हम सभी को हर साल एक दिन पूरी दुनिया में मुस्कुराने और दयालु बनने के लिए समर्पित करना चाहिए। क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी भी राजनीतिक, भौगोलिक और धार्मिक बातों को नहीं जानता। सिर्फ आज के दिन मुस्कुराने की बजाय आप रोज मुस्कुराने की आदत बनाइये। इससे ना केवल आपकी मुश्किलें आसान होंगी बल्कि आपके चाहने वाले भी आपको देखकर खुश रहेंगे।

अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं समग्र विकास के लिये मुस्कान जरूरी है। आज के तनाव, अशांत, चिन्ता एवं परेशानियों के जीवन में मुस्कान की तीव्र आवश्यकता है। क्योंकि हँसना और मुस्कुराना सभी के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायक है। मुस्कान हमारे जीवन की सफलता की चाबी है, वह अनेक समस्याओं का समाधान भी है। मुस्कान दुखी दिल के घावों को भरने वाला मलहम है। हमारे चेहरे का व्यायाम है और मन का आराम। शोध कहते हैं कि जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा मुस्कुराना कम हो रहा है। हम इसलिए कम नहीं मुस्कुराते कि हम बूढ़े हो गए हैं। हम बूढ़े ही इसलिए हुए कि हमने मुस्कुराना बंद कर दिया है। करूणामूर्ति मदर टेरेसा ने कहा, शांति की शुरूआत मुस्कुराहट से होती है। आपकी खुशी आपके होठों से शुरू होती है। इस वर्ष आप विश्व मुस्कान दिवस पर, अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ना न भूलें। यह संक्रामक होगा और आपके चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण तैयार करेगा।

सेहत का एक मंत्र यह है कि आप खुलकर मुस्कुरायें। हमें मुस्कुराना चाहिए और बात-बेबात मुस्कुराते रहना सफल एवं सार्थक जीवन का मंत्र हैं। पर कई बार पूरा पूरा दिन बिना मुस्कान के निकल जाता है। उदासी और बेचैनियों के बादल छाए रहते हैं, मुस्कान की धूप खिल नहीं पाती। मुस्कुराना-हंसना एक ऐसा सकारात्मक भाव है जो व्यक्ति के न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी स्वरूप को समृद्धिशाली एवं प्रभावी बनाता है। मुस्कान एक शक्तिशाली भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊजार्वान और संसार को शांतिपूर्ण बनाने की क्षमता हैं। यह व्यक्ति के विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब व्यक्ति समूह में मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान से सकारात्मक ऊर्जा सम्पूर्ण परिवेश में व्याप्त हो जाती है।

आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट व हँसी को भूलता जा रहा है, फलस्वरूप तनावजन्य बीमारियाँ, जैसे-उच्च रक्तचाप, शुगर, माइग्रेन, हिस्टीरिया, पागलपन, डिप्रेशन आदि को निमंत्रण दे रहा है। मुस्कुराने से ऊर्जा और ऑक्सीजन का संचार अधिक होता है। शरीर में से दूषित वायु बाहर निकल जाती है। हमेशा खुलकर मुस्कुराना शरीर के सभी अवयवों को ताकतवर और पुष्ट करता है। साथ ही शरीर में रक्त संचार की गति को बढ़ाता है। इसके अलावा पाचन तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करता है। इसलिये डॉक्टर भी हर बीमारी के रोगी के लिये मुस्कुराने को उपयोगी बताते हैं। क्योंकि जोर-जोर से कहकहे लगाने एवं मुस्कुराने से पूरे शरीर में प्रत्येक अंग को गति मिलती है। इससे शरीर में मौजूद हारमोन दाता प्रणाली (एंडोफ्राइन ग्रंथि) सुचारुरूप से चलने लगती है, जो कि कई रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है।

जो लोग हमें अपनी बातों से, अपने कार्यों एवं सोच से हमें मुस्कान देते हैं, वे हमारी स्मृतियों में रच-बस जाते हैं। हम किसी को पसंद या नापसंद कई कारणों से कर सकते हैं। पर लंबे समय तक हमारे प्रेम के हकदार वे लोग बनते हैं, जो हमें हंसाते हैं और हमारे चेहरे की मुस्कान लाते हैं। शायद इसीलिए विक्टर बोर्ग कहते हैं, ह्यहंसी दो लोगों के बीच की दूरी को पार करने का सबसे छोटा पुल है। हंसना-मुस्कुराना एक ऐसा बेशकीमती उपहार है, जो कुदरत ने केवल मनुष्य को ही बख्शा है। हास्य एवं मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है। इसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग से परे रहकर मानवता का समन्वय करने की क्षमता है। यह इंसान से इंसान को जोड़ने का उपक्रम है। मुस्कान एवं हंसी विभिन्न समुदायों को जोड़कर नए विश्व का निर्माण करने में सक्षम हैं। यह विचार भले ही काल्पनिक लगता हो, लेकिन लोगों में गहरा विश्वास है कि हंसी-मुस्कान ही दुनिया को एकजुट कर सकती है।

दुनिया में सुख एवं दुःख दोनों ही धूप-छाँव की भाँति आते-जाते हैं। यदि मनुष्य दोनों परिस्थितियों में हँसमुख रहे तो उसका मन सदैव काबू में रहता है व वह चिंता से बचा रह सकता है। मुस्कुराने से आत्मा खिल उठती है। इससे आप तो आनंद पाते ही हैं दूसरों को भी आनंदित करते हैं। हास-परिहास एवं मुस्कान पीड़ा का दुश्मन है, निराशा और चिंता का अचूक इलाज और दुःखों के लिए रामबाण औषधि है। हंसने-हंसाने-मुस्कुराने से तन-मन में उत्साह का संचार होता है और दिल से मुस्कुराना तो किसी दवा से कम नहीं है। मुस्कान एक उत्तम टॉनिक का काम करती है। प्रमुख विद्वान थैकर एवं शेक्सपियर जैसे विचारकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति अधिक जीता है। मनुष्य की आत्मा की संतुष्टि, शारीरिक स्वस्थता व बुद्धि की स्थिरता को नापने का एक पैमाना है और वह है चेहरे पर खिली प्रसन्नता। लंदन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सोफी स्कॉट कहती हैं कि, हंसी के द्वारा हमारा अवचेतन मन ये संकेत देता है कि, हम सुकून में हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जापान में भगवान बुद्ध के शिष्य थे होतेई। वह बड़े अलमस्त स्वभाव के भिक्षुक थे। वह बेहद निर्लिप्त और निरपेक्ष भाव से जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वह जिस कार्य को करते, उसमें पूरी तरह डूब जाते थे, तन्मय हो जाते। जापान में ऐसी मान्यता है कि एक बार होतेई मेडिटेशन करते-करते इतने रोमांचित हो गए कि ध्यानावस्था में जोर-जोर से हंसने-मुस्कुराने लगे। इस अद्भुत घटना के उपरांत ही लोग उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से संबोधित करने लगे। घूमना-फिरना, देशाटन करना, लोगों को मुस्कान व खुशी प्रदान करना लाफिंग बुद्धा का ध्येय बन गया। चीन में लाफिंग बुद्धा को पुताई के नाम से भी जाना जाता है। चीनी लोग उन्हें एक ऐसे भिक्षुक के नजरिए से देखते हैं, जो एक हाथ में धन-धान्य का थैला लिए, चेहरे पर खिलखिलाहट बिखेरे अपना बड़ा पेट और थुलथुल बदन दिखाकर सभी को मुस्कान देते हुए सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वे समृद्धि व खुशहाली का संदेशवाहक और घरों के वास्तुदोष निवारण का प्रतीक भी माने जाते हैं। जापान जैसे देशों में लोग अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हँसते-मुस्कुराते रहने की शिक्षा देते हैं, ताकि उनकी भावी पीढ़ी सक्षम एवं तेजस्वी हो। दुनिया के अधिकतर देश आतंकवाद के डर से सहमे हुए हैं, हर व्यक्ति के अंदर घबराहट और अशांति का कोहराम मचा हुआ है। ऐसे दौर में केवल मुस्कान ही दुनियाभर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर टेरीजा एमाबाइल ने कहा है कि, हँसते समय हमारा दिमाग सबसे अधिक क्रिएटिव होता है। हमें न केवल पारिवारिक परिवेश में बल्कि ऑफिस में हंसी-मजाक, मुस्कुराने को बढ़ावा देना चाहिए। ऑफिस का माहौल मेल-जोल और हंसी मजाक वाला हो, जिससे टीम के बीच काम के प्रति उत्साह का संचार हो सके। खूबसूरत चेहरे के लिए मुस्कान कारगर साबित हो सकता है। मुस्कुराने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। मेडिकल प्रयोगों में पाया गया है कि, 10 मिनट तक मुस्कुराते रहने से दो घंटे की गहरी नींद आती है।

मुस्कुराने वाले व्यक्तियों के कई सारे मित्र बन जाते हैं और इस प्रकार उनमें भाईचारा और एकता की भावना कब उत्पन्न होती है, पता ही नहीं चलता। डर, भय, असुरक्षा, आतंकवाद से हर इंसान सहमा हुआ है, तब मुस्कान दिवस की अत्यधिक आवश्यकता महसूस होती है। इससे पहले इस दुनिया में इतनी अशांति कभी नहीं देखी गई। इस व्यस्त, अशांत एवं तनावग्रस्त जिंदगी में लोग कम से कम एक दिन तो अपने लिए निकालें और जी भरकर मुस्कुरायें।

विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने का क्रेज का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है

अशोक भाटिया

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इससे देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है। इससे उद्योग-धंधों के लिए श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा, देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र फंसे तो नेताओं को पता चला कि इतने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक ने हैरानी जताई। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत से हरेक साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों में क्यों चले जाते हैं? यह सवाल कनाडा में जो भारत को लेकर हो रहा है उस रोशनी में पूछ जाना चाहिए। वहां जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे पहले ही भारतीयों के साथ हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय अधिक जाग चूका है और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि इजराइल में फिलहाल करीब 18 हजार भारतीय जबकि वेस्ट बैंक में करीब एक दर्जन और गाजा में तीन से चार भारतीय रह रहे हैं। जब यहाँ छात्र किसी कारण से फंसते है तो भारत सरकार को ह्यएयर -लिफ्ट ह्यका सहारा लेना पड़ता है जो परेशानी भरा होता हैं। बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत से विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने की आकांक्षा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2016 और 2021 के बीच 26।44 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए गए। एसोसिएटेड चेम्बरर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने 13.5 अरब डालर का खर्च किया।

वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डालर यानि लगभग 2 लाख करोड़ रूपए रहा और रेडसियर स्टाटेर्जी कन्स्लटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डालर यानि 7 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री बी। मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया था कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4।44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए। एक अन्य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6।46 लाख थी, यानि 45 प्रतिशत की वृद्धि। यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत से ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 के संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है।

विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके माता-पिता अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर इन युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गांवों में बड़ी मात्रा में विदेशों से धन आता था। विदेशों में पढ़ाई के इस क्रेज के चलते यह प्रक्रिया उलट हो गई है, यानि अब विदेशों से धन आने के बजाय विदेशों को धन भेजा जा रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2024 के अंत तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डालर पहुंच जाएगी, तो यह देश के लिए अत्यंत संकटकारी स्थिति का कारण बनेगा।

गौरतलब है कि युवाओं का शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन, देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में पिछले दो-तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। यदि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो 1990-91 में जहां मात्र 49.2 लाख विद्याार्थियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया, यह संख्या वर्ष 2020-21 में 414 लाख तक पहुंच गई। मोटेतौर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुणा से भी ज्यादा हो चुकी है। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि वर्ष 2021 में देश में 1113 विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान, 43796 महाविद्यालय और अन्य स्वतंत्र संस्थान 11296 थे। इसी वर्ष देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 15।51 लाख शिक्षक कार्यरत थे। देश में कई विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और कई अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं और कई विश्वविद्यालय सम यानि डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। देश में कई विश्वस्तरीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी वैश्विक कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं। जहां तक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों में फीस विदेशी संस्थानों में फीस से कहीं कम है और जिन विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत नीचा है।

तो सवाल उठता है कि भारी भरकम राशि खर्च कर भारत के युवा विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश क्यों लेते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि विदेशों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश लेकर वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहां तक कि इंग्लैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि वहां रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय युवा यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि इन देशों में भी रोजगार की भारी कमी है। कई देशों में वहां के स्थानीय लोग भारतीय एवं अन्य देशों से आने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें भी देखने को मिल रही हैं। देश से जाने वाले अधिकांश युवा विद्यार्थी वहां रोजगार प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं और उन्हें स्वदेश वापिस लौटना पड़ता है, जिसके कारण वे भारी कुंठा का भी शिकार हो रहे हैं।

चूंकि व्यक्तिगत तौर पर विदेशों में जाने वाले युवा विद्यार्थी, पूर्व में विदेशों में जाने वाले भारतीयों की सफलता की गाथाओं से प्रभावित होकर विदेशों की ओर रूख कर रहे हैं। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे कि आज कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में, जहां वे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं, वे शिक्षा संस्थान स्वयं के आस्तित्व को बचाने हेतु भारतीय विद्यार्थियों को आसानी से अपनी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं भारतीय और अन्य देशों के अति इच्छुक विद्यार्थियों से भारी फीस ऐंठने हेतु शिक्षा की कई दुकानें भी खुल रही हैं, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है।

ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को इस हेतु वास्तविकता से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे विदेशों में जाकर अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई को यूं ही न गवा दें। गौरतलब है कि पिछले लगभग दो दशकों से भारत के कई नागरिक एजेंटों के माध्यम से विदेशों में, खास तौर पर खाड़ी के देशों में रोजगार की तलाश में गए और वहां उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन युवाओं के पासपोर्ट तक एजेंटों के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह-तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए।इसी तर्ज पर देश के अनभिज्ञ युवा जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस हेतु आगे आना होगा। भारत में शिक्षा का स्तर आस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे देशों के बराबर बनाना होगा ताकि हमारे विद्यार्थियों को किसी अन्य देश में जाने की नौबत ही न आए!

विश्व-युद्ध की पृष्ठभूमि में इजरायल, हमास लेबनान ईरान युद्ध

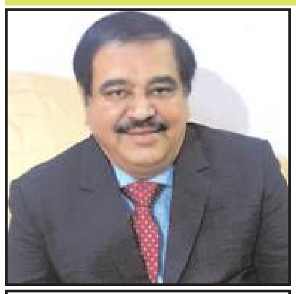

संजीव ठाकुर

अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के अनुसार वैश्विक युद्ध की भूमिका वैसे तो इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध ने पहले से ही रख दी थी हिजबुल्ला लड़ाको ने इजराइल फिलिस्तीन हमास युद्ध के बीच कूद कर युद्ध में आग में घी का काम किया है। इसके अलावा लेबनान ने इस युद्ध में अपने को शामिल अपनी आहुति दे दी। इसराइल ने जिस तरह लेबनान में छिपे हिजबुल्ला के आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और उसमें कमांडर नसरूल्लाह की हत्या ने पूरे ईरान और शिया समुदाय को हिलाकर आक्रोशित कर दिया है। ईरान ने इसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर लगभग 300 टारगेटेड मिसाइल इसराइल पर दाग कर विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर दी है। यह अलग बात है कि इजरायल अब अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो गया अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी प्रतिबद्धता के कारण इसराइल को समर्थन दे रहे हैं। अब इसराइल बेलगाम होकर ईरान लेबनान और हमास के आतंकवादियों पर खुलकर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूत करने पर उतारू है । इसराइल के इस युद्ध में अरबो रुपए खर्च हो चुके हैं उधर ईरान ने भी लगभग 30 करोड़ की मिसाइल से अपना हमला कर इरादे साफ कर दिए हैं कि अब ईरान भी रुकने वाला नहीं है। इन सब युद्ध की गतिविधियों से विश्वयुद्ध की संभावनाएं बढ़ गई है

और विश्व युद्ध वर्तमान की मानवीय सभ्यता के लिए एक गतिहीन अवरोध बन गया है। उधर अरबपति अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरस ने दावोस में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि दुनिया को इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें पूरे संसाधन झोंक देने चाहिए। वैसे भी रूस यूक्रेन युद्ध को दो साल से ज्यादा हो चुके हैं और युद्ध रोकने के जितने भी प्रयास है असफल हो चुके हैं वैश्विक सभ्यता को संरक्षित, पल्लवित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और संभवत एकमात्र तरीका रूस-यूक्रेन और इजरायल हमास, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान युद्ध को हर संभव तरीके से रोकना होगा होगा। यह हमला तीसरे विश्वयुद्ध की शुरूआत कर सकता है और हमारी सभ्यता इसे झेल नहीं पाएगी और तहस-नहस हो जाएगी। दावा किया गया है कि पुतिन ने शी जिनपिंग को पहले से ही बता दिया था और दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी दोनों ने एक लंबा बयान जारी कर घोषणा की थी कि उन दोनों के बीच संबंधों की और सहयोग की कोई सीमा नहीं है। पुतिन ने सी जिनपिंग को यूक्रेन के विरुद्ध विशेष सैन्य अभियान की जानकारी भी दे दी थी। तब शी जिनपिंग ने पुतिन से ओलंपिक खेलों के होते तक सैन्य अभियान रोकने की बात कही थी। इसी बीच रूस के एक राजदूत ने इस्तीफा देकर पुतिन की इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया था और युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार ने भी रूस में अपना विरोध दर्ज किया है। पुतिन को अपनी गलतियों का अब धीरे-धीरे एहसास हो रहा है जब यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषा के नागरिकों ने यूक्रेन पर हमले की घोर निंदा की है जबकि पुतिन को उनके समर्थन आशा थी जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुतिन को अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण करके एक बड़ी गलती की है। अब वह संघर्ष विराम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हैं जो वर्तमान संदर्भों में संभव नहीं है। क्योंकि विश्व समुदाय का रूस पर भरोसा खत्म हो चुका है। अब या तो पुतिन अपनी हार छुपाने के लिए चाइना की मदद विश्व युद्ध करेंगे या फिर अपनी हार स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा देकर पलायन कर जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध मैं आज तक कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अमेरिका सहित नैटो देश के सदस्य और अन्य यूरोपीय सदस्य लगातार यूक्रेन की आर्थिक तथा सामरिक मदद करते आ रहे हैं और इस स्थिति में रूस ही कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि रूस के तमाम कमांडर और सैनिकों का मनोबल अब लगातार गिरते जा रहा है, इसके पश्चात रूस के नागरिक भी इस युद्ध के अंदरूनी खिलाफ है जबकि यूक्रेन के नागरिक उसी हौसले और उत्साह के साथ अपने नेता जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। अब स्थिति यह है कि यूक्रेन के पास ना तो पैसे की कमी है ना ही हथियारों की,वह लगातार रूसी सैनिकों तथा कमांडरों का जमकर विरोध कर रहा है। ये अलग बात है कि मारियोपोल मैं इमारतों के मलबे के निकालने के पश्चात अलग-अलग जगह से चार पांच सौ दबे हुए शव को निकाला गया है। जिससे वहां जनता के बीच हाहाकार मच गया है। इस युद्ध की विभीषिका से यूक्रेन के लगभग एक करोड़ नागरिक यूक्रेन छोड़कर पोलैंड एवं अन्य देशों में शरण लेकर शरणार्थियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यूरोपीय देश इन शरणार्थियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प हैं और उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वैश्विक राजनीति में चीन और रूस सर्वथा अलग-थलग पड़ गए हैं। ताजा स्थिति के अनुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत में टोक्यो सम्मेलन में चीन के बढ़ते औपनिवेशिक वाद के खतरे को भांपते हुए प्रशांत महासागर एवं तीन पेसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए गठजोड़ कर लिया है। इसी तरह चीन के व्यापारिक फायदों को नुकसान पहुंचाने हेतु अमेरिका ने 13 देशों का एक आर्थिक समूह तैयार कर चीन को वैश्विक राजनीति और आर्थिक योजनाओं से अलग अलग कर दिया है। चीन अब क्वाड सम्मेलन को अपना विरोधी बताकर लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारियां भारत के विरुद्ध बढ़ाने में लग गया है। 13 देशों के आर्थिक समुदाय ने भी चीन को एक खुला संदेश देकर चुनौती दे दी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका तथा चीन के विरुद्ध आर्थिक क्षेत्र तथा सामरिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा मैदान में आ गई है। अमेरिका वैसे भी पूर्व से ही रूस का विरोधी रहा है अब अमेरिका चीन तथा रूसी गठबंधन को आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा मानते पूरे विश्व को इन दोनों के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। वैश्विक शांति और सभ्यता को नष्ट होने से बचाने के लिए इन दोनों देशों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक भी है।

हरियाणा में पिछड़ रही भाजपा मतदान से ठीक पहले मुश्किल स्थिति से कैसे उबर गयी?

इसमें कोई दो राय नहीं कि खट्टर से छुटकारा पाकर भाजपा ने हरियाणा में खुद को मुश्किल स्थिति से उबारने में सफलता पाई है। ऐसा लगता है कि यदि भाजपा ने मार्च में खट्टर को हटाने का फैसला नहीं लिया होता तो आज वह चुनावी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो चुकी होती।

हरियाणा में लगभग सवा नौ साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उपजी नाराजगी को भांप कर भाजपा नेतृत्व ने इस साल मार्च में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़वा कर और केंद्रीय मंत्री पद सौंप कर दिल्ली की राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया गया लेकिन खट्टर का मन हरियाणा में लगा रहा। भाजपा नेतृत्व को जब यह लगा कि खट्टर का नाम नुकसान पहुँचा रहा है तो पूरे चुनाव प्रचार अभियान से खट्टर का नाम और उनकी तस्वीर गायब कर दी गयी। हमने पाया कि भाजपा की हर चुनावी रैली अथवा जनसभाओं के दौरान मंच पर या उसके आसपास लगने वाले पोस्टरों, बैनरों और होर्डिंगों में खट्टर का नाम और तस्वीर नहीं थी। यही नहीं हरियाणा सरकार की जिन उपलब्धियों के सहारे भाजपा ने चुनाव लड़ा उसमें भी खट्टर की तस्वीर नहीं लगायी गयी। भाजपा ने साधारण लोगों की तस्वीरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार सामग्री में किया। जैसे युवाओं की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी गयी। किसानों की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि 24 फसलों का एमएसपी दे रही हरियाणा सरकार, महिलाओं की तस्वीरों के साथ लिखा गया कि तमाम योजनाओं का लाभ दे रही भाजपा सरकार। इसी प्रकार अन्य उपलब्धियों का बखान करते हुए भी प्रचार सामग्री तैयार करवायी गयी जिसमें आम लोगों की तस्वीरें प्रकाशित की गयी थी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि खट्टर से छुटकारा पाकर भाजपा ने हरियाणा में खुद को मुश्किल स्थिति से उबारने में सफलता पाई है। ऐसा लगता है कि यदि भाजपा ने मार्च में खट्टर को हटाने का फैसला नहीं लिया होता तो आज वह चुनावी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो चुकी होती। खट्टर से व्यक्तिगत रूप से लोगों की नाराजगी भाजपा को चुनावों में उसी तरह नुकसान पहुँचा सकती थी जैसे कि राजस्थान विधानसभा के 2018 के चुनावों में देखने को मिला था जब नारे लग रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा

तेरी खैर नहीं। हमसे बातचीत में भाजपा के भी कई समर्थकों और कार्यकताओं ने माना कि यदि खट्टर को हटाने का फैसला एक साल पहले लिया गया होता तो लोकसभा चुनावों में भी हम सारी सीटें जीत सकते थे।

इसके अलावा, 15 दिनों पहले जब हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार की कवरेज की शुरूआत की थी उस समय सब जगह कांग्रेस की हवा ही दिख रही थी लेकिन एक एक दिन बीतने के साथ यह हवा हमें धीमी पड़ती दिखी और अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो कहा जा सकता है कि हवा किसी एक के पक्ष में नहीं है बल्कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हरियाणा चुनाव के दौरान मुझे दिल्ली नगर निगम का पिछला चुनाव इसलिए याद आ गया क्योंकि उसमें भाजपा का सूपड़ा साफ होने की भविष्यवाणी की गई थी लेकिन जब परिणाम आये तो पार्टी नजदीकी मुकाबले में आम आदमी पार्टी से सिर्फ कुछ सीटों से पिछड़ गई थी। हरियाणा चुनावों में भी जमीनी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखी। ऐसा लगता है कि भाजपा को जब इस बात का अहसास हुआ कि वह चुनाव में कांग्रेस से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है तो उसने पिछले 10 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जनसभाएं कराई गयीं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने 70 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं कीं। जवाब में भाजपा ने 150 सभाएं और रैलियां कर माहौल को पूरी तरह बदल दिया।

हरियाणा में कांग्रेस ने जमीन तक इस बात को पहुँचाने में सफलता हासिल कर ली थी कि 'कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है'। भाजपा ने इस हवा की चाल को धीमा करने के लिए परिवारवाद को मुद्दा बनाया और भूपिंदर सिंह हुड्डा के पिछले शासन की याद दिलाई जिससे माहौल बदलने लगा। भाजपा ने जनता के बीच इस धारणा को मजबूत किया कि अगर कांग्रेस आई तो निश्चित रूप से हुड्डा को कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने भी बार-बार हुड्डा को ही कमान सौंपने के संकेत दिये जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान होता दिखा क्योंकि हुड्डा को अपने पिछले कार्यकाल में सिर्फ रोहतक का सीएम माना जाता था और उन पर अपने आलाकमान को खुश रखने के लिए प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप भी हैं। कई क्षेत्रों के लोगों का मानना है कि हुड्डा ने सिर्फ रोहतक में काम किया जिससे वहां की जमीनों के रेट ज्यादा हैं और उनके इलाके की जमीनों का रेट बहुत कम है।

इसके अलावा भाजपा ने जिस एकजुटता और रणनीति के साथ हरियाणा में काम किया उससे पार्टी मुकाबले में तेजी से वापसी करती दिखी। रैलियों, सभाओं और डोर टू डोर हुए प्रचार के बाद मिल रहे फीडबैक से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा और इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसलिए 3 अक्टूबर शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थमने तक भाजपा के प्रदेश के बड़े नेता, दूसरे राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री जनता के बीच लगातार पहुंचकर भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाने की अपील करते दिखे। भाजपा की रैलियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले लगभग एक महीने में प्रमुख नेताओं की 150 से अधिक जनसभाएं हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने रैलियों और रोड शो के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस को अनेक मुद्दों पर सफलतापूर्वक घेरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो एक दिन में 4 से 5 बड़ी रैलियां कीं। भाजपा के लिए हरियाणा में सघन प्रचार करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आदि शामिल रहे। हरियाणा भर में कोई शहर या गांव ना छूटे इसके लिए विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगायी गयी ताकि भाजपा की उपलब्धियों और पार्टी के संकल्प पत्र में किये गये वादों को जन-जन तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने विपक्षी नेताओं और उम्मीदवारों के प्रचार और उनके संबोधनों पर बारीकी से निगाह रखी। यदि किसी विपक्षी नेता ने कोई विवादित बयान दिया तो उसको सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया। बहरहाल, तमाम प्रयासों के जरिये भाजपा मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी से उबर पाने में तो सफल हुई। देखना होगा कि यह सफलता मतों में परिवर्तित होती है या नहीं? लोकसभा चुनावों के बाद हो रहे हरियाणा चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि भाजपा अपनी सरकार बचा लेती है तो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत पाने से चूकी पार्टी का मनोबल बढ़ जायेगा और यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो राहुल गांधी का कद और स्वीकार्यता राष्ट्रीय राजनीति में और बढ़ जायेगी।

-नीरज कुमार दुबे

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

भारत की जेलों में वर्षों से बंद विचाराधीन कैदी

भारत की जेलों में कैदियों की स्थिति चिंता का विषय है। हाल ही में जो आंकड़े आये हैं, उसमे भारत की जेलों में 76 फीसदी ऐसे कैदी बंद हैं, जिन पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। आरोप के आधार पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। यह कैदी बिना किसी दोष सिद्धि के जेलों में कई वर्षों से बंद हैं। भारतीय न्यायिक और कानूनी प्रणाली की खामियों की चर्चा अब विश्व स्तर पर होने लगी है। भारत में न्यायिक प्रणाली की धीमी गति, जांच में भारी विलंब, न्यायालय में विलंब से मुकदमा पेश होना, न्यायालयों में मामलों की सुनवाई और निपटारे में देरी, जमानत देने पर ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट की उदासीनता के कारण भारत की जेलों में लाखों लोग कई वर्षों से बंद हैं। भारत के नागरिकों को संवैधानिक मौलिक अधिकार मिले हैं। उनका भारत में कानूनी रूप से उलंघन हो रहा है। भारत की जेलों में बंद अधिकांश कैदी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनके पास वकील करने या जमानत राशि भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में देरी का खामियाजा निर्धन एवं गरीब मध्यम वर्ग के कैदियों को भुगतना पड़ता है। संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन भारत में हो रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मानव अधिकार के मामले में लगातार रैंकिंग घटती चली जा रही है। ऐसे कैदी, जो वर्षों से जेल में बंद हैं उनकी सुनवाई ट्रायल कोर्ट में भी पूरी नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत भी नहीं दी गई है। जेलों में बंद कैदियों के ऊपर दोष साबित नहीं हुआ है। इसके बाद भी जेलों में उन्हें वर्षों तक बंद रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुला हनन है। न्यायपालिका स्वयं नागरिकों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसके कारण अब कहा जा रहा है कि भारत की न्याय प्रणाली में अब सुधार की आवश्यकता है। भारत में सबसे पहले, जमानत प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने की जरूरत है। ताकि गरीब और कमजोर वर्गों को इसका लाभ मिल सके। जिन मामलों में गंभीर अपराध के आरोप नहीं हैं, उनमें तुरंत जमानत दिए जाने पर विचार होना चाहिए। जमानत को नागरिकों के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। जांच एजेंसी द्वारा एक निश्चित समय सीमा पर जांच करने की बाध्यता हो। निश्चित समय पर न्यायालय में चार्ज शीट पेश हो। अदालती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करके छोटे और गैर-गंभीर मामलों का त्वरित निपटारा किया जाना चाहिए। जेल सही मायने में सजायाप्ता कैदियों के लिए होती है। या उन अपराधियों के लिए होती है, जो समाज के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। जेलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी हैं। जेलों में बंद कैदियों के लिए उचित चिकित्सा, भोजन, मानसिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जेलों को केवल सजा देने का स्थान नही माना जाना चाहिए। जेलों को सुधार केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए। कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज करना, न्याय व्यवस्था और मानवाधिकार दोनों के लिए आवश्यक हैं।

शिक्षक दुनिया को बेहतर बनाने में सहायता करें

वैसे तो शिक्षक का पद अत्यंत गरिमा पूर्ण होता है,क्योंकि "जिस प्रकार खेती के लिए बीज,खाद एवं उपकरण के रहते हुए,अगर किसान नहीं हैं,तो सब बेकार है। उसी प्रकार विद्यालय के भवन,शिक्षण सामग्री एवं छात्रों के होते हुए,शिक्षक नहीं हैं तो सब बेकार है।" एक शिल्पकार प्रतिमा बनाने के लिए जैसे पत्थर को कहीं काटता है,कहीं छांटता है,कहीं तल को चिकना करता है,कहीं तराशता है तथा कहीं आवृत को अनावृत करता है।

– **ललित गर्ग** –

विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है। इस दिन आध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिये सम्मानित किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, उस संयुक्त बैठक को याद करने के लिये मनाया जाता है, जिसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई थी और इसके लिये सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। अत: इसे 1994 के बाद से प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है और इस प्रकार वर्ष 2024 में यह 30वाँ विश्व शिक्षक दिवस होगा। 2024 में इस दिवस की थीम है 'शिक्षकों को सशक्त बनाना, लचीलापन मजबूत करना, स्थिरता का निर्माण करना।' यह थीम इस बात पर जोर देती है कि शिक्षकों को सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण जागरूकता विकसित करने में छात्रों का समर्थन करने के लिए आवश्यक संसाधन और जानकारी देना कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षक उस माली के समान है, जो एक बगीचे को अलग अलग रूप-रंग के फूलों से सजाता है। जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण एवं शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी सफलता के सशक्त माध्यम शिक्षक ही है और शिक्षकों को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। विभिन्न देशों में शिक्षक दिवस अलग-अलग तारीखों को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, चिन्तक, शिक्षाशास्त्री डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 5 सितम्बर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य 'सा विद्या या विमुक्तये' रहा अर्थात् विद्या वही है, जो मुक्ति दिलाए। आज शिक्षा का उद्देश्य 'सा विद्या या नियुक्तये' हो गया है अर्थात् विद्या वही जो नियुक्ति दिलाए। इस दृष्टि से शिक्षा के बदलते अर्थ ने समाज की मानसिकता को बदल दिया है। यही कारण है कि आज समाज में लोग केवल शिक्षित होना चाहते हैं, सुशिक्षित नहीं बनना चाहते। वे चाहते हैं कि ज्ञान का सीधा संबंध उनके अर्थोपार्जन से ही है। जिस ज्ञान से अधिक से अधिक धन और उच्च पद को ग्रहण किया जाए वही शिक्षा कारगर है। पर चिंता का विषय है कि भारत के शिक्षक ही आज इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है, मानो उनका लक्ष्य केवल बौद्धिक विकास ही है। अब शिक्षक के लिये शिक्षा एक मिशन न होकर व्यवसाय हो गयी है। इन स्थितियों से शिक्षकों को बाहर निकलने में नई शिक्षा नीति से बहुत अपेक्षाएं है। विश्व शिक्षक दिवस उन समर्पित शिक्षकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जो अगली पीढ़ी के दिमाग को आकार देते हैं और ज्ञान देते हैं। यह विश्वव्यापी उत्सव शिक्षकों को उनके अमूल्य प्रयासों और भावी पीढ़ियों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित करता है। इस दिन, हम रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करके बच्चों के दिमाग और भविष्य को विकसित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करते हैं। यह उन कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जिनका वे सामना करते हैं और अपनी विशेषज्ञता को साझा करने और खुद को विकसित करने के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाते हैं। अपनी प्रतिबद्धता और जुनून के माध्यम से, शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि मूल्यों को भी स्थापित करते हैं, जिससे पूरे समाज पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है।

आज की शिक्षा मिशन न होकर, व्यवसाय बन गयी है। तमाम शिक्षक एवं शिक्षालय अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु-शिष्य की परंपरा कहीं न कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा छात्रों एवं छात्रों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट एवं अनुशासनहीनता की खबरें सुनने को मिलती हैं। इसे देखकर हमारी संस्कृति की इस अमूल्य गुरु-शिष्य परंपरा पर प्रश्नचिह्न लगने लगे है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। विश्व शिक्षक दिवस एक अवसर है जब हम धुंधली होती शिक्षक की आदर्श परम्परा एवं शिक्षा को परिष्कृत करने और जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण करने की दिशा में नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत ठोस कार्य करें। 'गुरु' का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। महात्मा गांधी के अनुसार सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है- आत्मा, मस्तिष्क, वाणी और कर्म-इन सबके विकास में संतुलन बना रहे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सर्वांगीण विकास का अर्थ है- हृदय से विशाल, मन से उच्च और कर्म से महान। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षक आचार, संस्कार, व्यवहार और विचार- इन सबका परिमार्जन करने का प्रयत्न करते रहते थे। शिक्षकों पर इस दुनिया में सबसे प्रेरक काम और एक बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षक ज्ञान का भंडार हैं जो अपने शिष्यों को अपना ज्ञान देने में विश्वास करते हैं जिससे उनके शिष्य भविष्य में दुनिया को बेहतर बनाने में सहायता कर सकेंगे। इससे ऐसी पीढ़ी निर्मित होगी जो उज्ज्वल और बुद्धिमान हो तथा वह जो दुनिया को उसी तरीके से समझे जैसी यह है और जो भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और तथ्यों से प्रेरित हो।

वैसे तो शिक्षक का पद अत्यंत गरिमा पूर्ण होता है, क्योकिं "जिस प्रकार खेती के लिए बीज, खाद एवं उपकरण के रहते हुए, अगर किसान नहीं हैं, तो सब बेकार है। उसी प्रकार विद्यालय के भवन, शिक्षण सामग्री एवं छात्रों के होते हुए, शिक्षक नहीं हैं तो सब बेकार है।" एक शिल्पकार प्रतिमा बनाने के लिए जैसे पत्थर को कहीं काटता है, कहीं छांटता है, कहीं तल को चिकना करता है, कहीं तराशता है तथा कहीं आवृत को अनावृत करता है, वैसे ही हर शिक्षक अपने विद्यार्थी के व्यक्तित्व को तराशकर उसे महनीय और सुघड़ रूप प्रदान करते हैं। हर पल उनकी शिक्षाएं प्रेरणा के रूप में, शक्ति के रूप में, संस्कार के रूप में जीवंत रहती हैं।

महान् दार्शनिक आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में -'व्यक्तित्व-निर्माण का कार्य अत्यन्त कठिन है। नि:स्वार्थी और जागरूक शिक्षक ही किसी दूसरे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है।' हमने सुपर-30 फिल्म में एक शिक्षक के जुनून को देखा। इस फिल्म में प्रो. आनन्द के शिक्षा-आन्दोलन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुति दी गयी है, जो विश्व परिप्रेक्ष्य में उपयोगी है। विश्व शिक्षक दिवस का उद्देश्य मानवता को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने और भविष्य के नेताओं को तैयार करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना है। यह शिक्षकों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने और दुनिया भर में शिक्षकों के लिए अधिक धन, तैयारी और सम्मान के लिए दबाव बनाने का अवसर है। आज शिक्षक एवं शिक्षा का महत्व ज्यादा है। जैसाकि महात्मा गांधी ने कहा था-एक स्कूल खुलेगी तो सौ जेलें बंद होंगी। पर आज उल्टा हो रहा है। स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ जेलों के स्थान छोटे पड़ रहे हैं। जेलों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। स्पष्ट है- हिंसा और अपराधों की वृद्धि में वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षक भी एक सीमा तक जिम्मेदार है। अशिक्षित और मूर्ख की अपेक्षा शिक्षित और बुद्धिमान अधिक अपराध कर रहे हैं। वह अपने पापों और दोषों पर आवरण डालने हेतु अधिक युक्तियां सोच सकते हैं। इस स्थिति के लिये शिक्षक ही जिम्मेदार है।

स्वतंत्र भारत में मानसिक स्वाधीनता भी अत्यंत आवश्यक ?

– **संजीव ठाकुर**

'**पराधीन** सपने हूं सुख नाही'। यह लोकोक्ति हर स्वाभिमानी आदमी और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति को याद रहती है। स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर सकता है, इसके लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत में स्वाधीनता के मायने कितने लोग समझ पाते हैं और कितना इसका सही और सटीक प्रयोग कर पाते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा और साक्षरता का उस देश और काल को समझने का एक कारगर हथियार हो सकता है पर भारत में मानसिक स्वाधीनता को समझना भी एक बड़ी समस्या है यह अशिक्षा जनित समस्या बहुत ही विकराल है। हम अभी भी पश्चिमी जगत की शिक्षा, कार्यशैली, विज्ञान एवं चिकित्सा पर संपूर्ण रूप से निर्भर हैं केवल एक शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जो स्वतंत्र भारत के नागरिकों को स्वाधीनता के महत्व को समझने में सक्षम होगा। अत: स्वाधीन भारत के स्वतंत्र नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्र नागरिक बनाकर देश के प्रति सजग और सचेत किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता केवल मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है। एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता के अनुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति सातवें दशक के प्रारंभ के बाद ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुशहाली की स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि 'एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं', पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 78 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, वह कर्जे से डूब गया है और अपने देश में खर्चा चलाने के लिए पूरी दुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने का एवं उधार की जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज, स्पेस रिसर्च में पूर्णता आत्मनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन किसी भी देश की प्रगति विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविषा है जिससे वह संघर्ष कर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताबें लिखने का का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त कर सका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा एवं परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त कर उसे स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर मेहनत कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। हमारा देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रेषित हुआ आज स्थिति यह है कि वह विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तमाम महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है। महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 'दैव दैव आलसी' पुकारा है, तब जाकर उनकी जिंदगी पटरी पर आई और हमें परिश्रम कर आत्म निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनता हमारा आत्मविश्वास सृजनशीलता सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है, आत्मनिर्भरता की कमी हमें किंकर्तव्यविमूढ़ बना देती है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला व्यक्ति जीवन के अक्षय आनंद से वंचित रहता है। खुद के परिश्रम श्रम से आगे बढ़ने वाला देश या व्यक्ति या समाज सदैव प्रफुल्लित आत्म विश्वासी तथा विकास की ओर सदैव अग्रसर रहता है। हमें सदैव अपने अंदर के आत्मविश्वास, छिपी हुई क्षमताओं मनोबल का सहारा लेकर आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कविता

दर्द

पेन यदि गुम हो जाए
मन बेचैन हो जाता है
आमदनी कई गुना हो
और सोच की दूसरा
खरीद लेंगे
मगर अपनापन
तो अपनापन ही
रहता।

कितने शब्द तरासे
कितना ही लेखा
जोखा लिखा
ता उम्र तक पेन ने
संग तुम्हारे दु:ख सुखों
के संग
वो तुम्हारा मर्म जानती
मगर कह नहीं पाती।

वो विचारों से करती
रहती संघर्ष
जैसे स्त्री ससुराल की
उत्पीड़न को
कभी नहीं बताती
अपने बाबुल को
झूठी हंसी लिए खुश
रहती।

गुम होने का तो दर्द
पूछा जा सकता
मगर डूबने का दर्द
किस्से छिपाए
डूबने -गुम हो जाने
का दर्द समान होता
मगर गुम हुई चीजे
अक्सर मिल जाती
डूबी हुई की केवल
मिलती है यादें
और मिलते वेदना के
स्वर
जो बाटे जाते है एक
कहानी की तरह
एक पीढ़ी से दूसरी
पीढ़ी में।

संजय वर्मा 'दृष्टि'
(125 बलिदानी भगतसिंह मार्ग, मनावर जिला धार, मप्र)

भारतीय पारंपरिक आहार जो मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं,उनमें मुख्य रूप से साबुत अनाज,दालें,मेवे,सब्जियाँ,फल,मसाले,जड़ी-बूटियाँ,डेयरी उत्पाद और किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल हैं,जिन्हें स्वयं 'कार्यात्मक' माना जा सकता है,क्यों कि इनमें विभिन्न पोषक तत्वों की क्षमता वाले कई फाइटोकेमिकल्स शामिल होते हैं। आज कई कारकों के कारण भारतीय आबादी की आहार संबंधी आदतों में बदलाव आया है,खासकर महानगरों में।

फास्ट फूड के बढ़ते चलन से बदलती भारतीय खाद्य जीवनशैली

– **सुनील कुमार महला**

भारत 55 करोड़ से अधिक युवा आबादी के साथ आज दुनिया का सबसे युवा देश है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से आज अधिकतर भारतीय युवा आबादी लगातार परंपरागत खाद्यान्न से अब विदेशों में अपनायें जाने वाले फास्ट फूड की ओर लगातार अग्रसर हो रही है। सच तो यह है कि रहन-सहन के साथ ही आज भारतीय युवाओं की खाद्य शैली में भी आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। भागम-भाग और दौड़-धूप भरी इस जिंदगी में कामकाजी महिलाओं के साथ ही गृहणियों के पास भी आज इतना समय नहीं बचा है कि वे परंपरागत भारतीय खाद्य पदार्थों को अपनी रसोई का हिस्सा बनाएं। हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय रसोईयों में परंपरागत खाद्य पदार्थ आज नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ आज हम हमारे परंपरागत खाद्य पदार्थों से दूर होते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता में अपनाएं जा रहे खाद्य पदार्थों पर हमारा ध्यान कहीं अधिक हो गया है। आज दादी-नानी और हमारे बुजुर्गों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यंजनों खीर, चूरमा, हलवा, पुरी, जलेबी व विभिन्न पेय पदार्थों छाछ, लस्सी, दूध, दही पर हमारा ध्यान कम ही है। आज से बीस पच्चीस साल पहले घरों में ज्वार, बाजरा, मकई, रागी का खूब व भरपूर इस्तेमाल होता था, आज बहुत कम है। हम गन्ना नहीं खाते, गन्ने का जूस पीने को वरीयता देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम गुड़ या शक्कर या इसके व्यंजनों को भारतीय रसोईयों में पहले की तुलना में कम इस्तेमाल में ला रहे हैं और चीनी की खपत घरों में बढ़ने लगी है। सच तो यह है कि घरों में आज फास्ट फूड की खपत बढ़ने लगी है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज भारत में सभी आय वर्गों में फास्ट फूड की खपत बढ़ रही है और यह इस देश में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की बढ़ती प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वैश्वीकरण, बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती आय से सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन तो आए ही हैं, इससे हमारे घरों की रसोई विशेष तौर पर प्रभावित हुई है। कभी हमारे यहां खाद्य पदार्थों और व्यंजनों की एक समृद्ध विरासत थी, आज इस विरासत को पाश्चात्य संस्कृति लगातार छीन रही है। हम फास्ट फूड संस्कृति में रम और बस गए हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय में फास्ट फूड समाज के सभी वर्गों के आहार का एक अभिन्न और अति महत्वपूर्ण अंग बन गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों में फास्ट फूड की अधिक खपत आज हो रही है। फास्ट फूड खाने वाली गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बच्चे मोटापे से ग्रस्त होने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसा कि ये उच्च वसा और उच्च चीनी आहार होते हैं। इनमें कालेस्ट्राल, कैलोरी और नमक की मात्रा भी काफी उच्च होती है। बर्गर, पिज्जा, चिकन, नूडल्स, स्प्रिंग रोल, पाव भाजी, सैंडविच, टिकिया, हैमबर्गर, होटल डोग, डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज, पाश्ता मोटापे, हमारी स्मृति, भूख न लगना, पाचन संबंधी समस्याओं, अवसाद, अपर्याप्त विकास और वृद्धि समेत अनेक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। दरअसल, फास्ट फूड वह होता है, जिसे हम किसी रेस्टोरेंट, ठेले या किसी दुकान विशेष से ऑर्डर करते हैं और हमारा यह ऑर्डर कुछ ही मिनट में हमें आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। वास्तव में इन खाद्य पदार्थों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जो हमारे अवलोकन में हमें जल्द से जल्द तेजी से उपलब्ध हो जाए। आज के समय में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, खिचड़ी, सलाद, फल और दही या छाछ का पेय प्राचीन काल की तुलना में कम ही रसोई घरों का हिस्सा रहा है। आज ढ़ोकला, पोंगल, लिट्टी चोखा, धाम, बिरयानी, रूगरा, छेना पोडा, दाल बाटी और चूरमा, अप्पम, भुट्टे का कीस, बाजरा खिचड़ी को हम लगातार भूलते चले जा रहे हैं और शायद यही कारण है कि हम अनेक बीमारियों के शिकार आज हो रहे हैं।

प्राचीन भारतीय शास्त्रों में 'अन्नं ब्रह्मम्' का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है भोजन ईश्वर है। परंपरागत रूप से भारत में भोजन को भगवान की प्रार्थना की तरह सम्मान दिया जाता है, लेकिन आज हमारी जीवनशैली पूरी तरह से बदल गई प्रतीत होती है। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थ न केवल शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देते हैं, बल्कि वे हमारे समग्र स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर बनाने के साथ ही बीमारियों को रोकने का लक्ष्य भी रखते हैं। भारतीय पारंपरिक आहार जो मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, उनमें मुख्य रूप से साबुत अनाज, दालें, मेवे, सब्जियाँ, फल, मसाले, जड़ी-बूटियाँ, डेयरी उत्पाद और किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिन्हें स्वयं 'कार्यात्मक' माना जा सकता है, क्यों कि इनमें विभिन्न पोषक तत्वों की क्षमता वाले कई फाइटोकेमिकल्स शामिल होते हैं। आज कई कारकों के कारण भारतीय आबादी की आहार संबंधी आदतों में बदलाव आया है, खासकर महानगरों में। हालांकि गांव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं और आज गांवों में हमें फास्ट फूड स्टॉल आसानी से मिल जाएंगी। जानकारी देना चाहूंगा कि फास्ट फूड का इस्तेमाल करने से अल्पकालिक, दीर्घकालिक और शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव पड़ते हैं और शायद यही वजह है कि आज पहले की तरह मनुष्य की औसत आयु में भी कमी आई है। पहले इंसान अस्सी से सौ बरस तक जिंदा रहता था लेकिन आज औसत आयु 60-65 वर्ष के आसपास ही रह गई है। भारतीयों में आज फास्ट फूड की तलब बढ़ी है और यह हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। प्रतिष्ठित पत्रिका डाऊन टू अर्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट यह बताती है कि फास्ट फूड बहुत ही घातक है और सालाना 1.61 करोड़ लोगों की मौत का कारण फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले नमक की ओवरडोज है। आजकल पैकेटबंद फास्ट फूड खाने का चलन तेजी से बढा है। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर लोग फास्ट फूड के पैकेट पर सोडियम की भ्रामक मात्रा देखे बिना ब्रांडेड कंपनियों के चिप्स-नमकीन, बर्गर-पिज्जा का उपभोग कर रहे हैं। इनमें मौजूद नमक की असंतुलित मात्रा, हमारी सेहत का संतुलन बिगाड़ रही है। जनरल आफ क्लीनिकल हाइपरटेंशन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक भारतीय प्रतिदिन औसतन 10 ग्राम नमक का सेवन कर रहे हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के मुताबिक प्रत्येक स्वस्थ्य व्यक्ति को एक दिन में पांच ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। जानकारी देना चाहूंगा कि जनरल आफ क्लीनिकल हाइपरटेंशन के मुताबिक पांच ग्राम से ज्यादा नमक खाने के कारण 1 करोड़ 65 लाख लोगों की हर वर्ष हृदय रोग के कारण हो जाती है। सच तो यह है कि जाने-

अनजाने हम आज के समय में नमक की तय मात्रा से दोगुना सेवन कर रहे हैं। नमक ही नहीं, फास्ट फूड में तेज मसाले, हाई कालेस्ट्राल, हाई कार्बोहाइड्रेट हमारे स्वास्थ्य का गणित लगातार बिगाड़ रहे हैं। यह बहुत ही हैरानीजनक है कि आज फास्ट फूड की आपूर्ति करने वाले तमाम बड़े ब्रांड भारत के छोटे शहरों से लेकर गांवों तक में अपनी पहुंच बना रहे हैं। हालांकि, यहां यह भी एक तथ्य है कि फास्ट फूड चेन भारत के फूड सर्विस मार्केट की अब भी पांच प्रतिशत से कम हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह करीब 20 प्रतिशत हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत को सचेतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारतीय खाद्य शैली लगातार बदल रही है।

(फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड)

– **पंकज सीबी मिश्रा**

अपने अँचरवा के शीतल बयरिया डाल हे ! मईया

ऋग्वेद के दशम मंडल के दशवें वें अध्याय के 125वें सूक्त की आठ ऋचाएं हैं जिन्हें देवी सूक्त कहा जाता है। जिसकी द्रष्टा महर्षि ब्रह्मज्ञानिनी वाक् थीं। वाक् ने प्रकृति की सर्जना शक्ति के साथ तादात्म्य कर देवी सूक्त उसी का उद्घाटन किया। इस सूक्त के अनुसार देवी ही इस सम्पूर्ण जगत की अधिष्ठात्री हैं। पितृ व्यवस्था भी देवी के ही अधीन है। गुरुवार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गया। शक्ति पीठों और देवी मंदिरो में भक्त माँ दुर्गा के नौ रूपों के पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। आज से देवी पंडालों में भी विराजेंगी जगह - जगह डीजे पर भक्ति संगीत फुल वॉल्यूम में बजेगा और फिर गुजरात का डांडिया और गरबा हमें हमारी संस्कृति की महत्वता का समरण कराएगा। देवी के नौ स्वरूपों की उपासना का त्योहारी उत्सव है नवरात्री। वाराणसी और आस पास के क्षेत्रों के लोक परम्परा में वर्षों पुरानी रामलीला भी चल रही। माटी की महक इन दिनों बदली है। सुबह और रात नम लगने लगे हैं। गांव दुआर पर सोने की प्रथा विलुप्त हो चुकी है पर अब छतो और बाहर खुले में सोने वाले लोग मड़ई और बरामदे में सोने लगेंगे। ओस रात को भिगो रही। कुल देवी, ग्राम देवी, अंचल देवी, पल्हना माई, चौकीयां माई, शीतला माता, विंध्यवासिनी देवी, शारदा मैया, कामाख्या देवी और अन्य देवी से लेकर भारत माता तक मातृ देवियों के आशीष, उनके द्वारा पोषित संतानों द्वारा लिया जा रहा। दैत्य संहार के पश्चात सिंहवाहिनी देवी लाल आँखों से देवगणों को सम्बोधित करते हुए कहती है - ।। अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम।। अर्थात मैं इस जगत के पितृरूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। देवी घोषित करती हैं कि %मैं ही अखिल भुवन में व्याप्त हूँ। यह जगत मेरी ही अभिव्यक्ति है। देवी के व्यापक स्वरूप को लोक पचरा में उद्धरित करता है जैसे निमिया के डरिया मईया नावेली झुलनवा होकि झूली झूली ना, और देवी मोरे अँगना पधारो शुभ पाँव से, मैंने झूला लगाया बड़े चाव से, मैया आशीष दें कर धन्य कीजिये, निमिया झूला लगायो बड़े भाव से।। माध्यम से लोक उनकी सहज उपलब्धि का बखान करता है। लोक परम्परा देवी से संवाद स्थापित करने की बात साक्षी है। यहां देवी घर आंगन और दुआरे में लगे नीम के पेड़ पर झूला डाल कर झूलती हैं इसलिए अब नौ दिन नीम की टहनी नहीं तोड़ी जाएंगी। प्रकृति संरक्षण का मैसेज देता यह नौ दिवसीय पर्व हिन्दू और वैदिक संस्कृति का बखान करता है। गांव की स्त्रियां माँ से पचरो के रूप में अपनी सहज बातचीत करती हैं, बात बात में वे अपने घर परिवार की समृद्धि का आशीष बड़ी चतुराई से मांगती हैं, माँ उन्हें पूरा करने का वचन भी देती हैं।लोक और शास्त्र दोनों की परंपरा में शक्ति की सर्वोच्चता है। जब देवगण असुरों से हारने लगते हैं तो वे माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। आनंद मंगल और न्याय के विजय का एकमात्र केंद्र माँ हैं। माँ का हर रूप संतानों के लिए कल्याणकारी है। ममता इस ब्रह्मांड का आधार है। माता का आदर पाने के लिए त्रिदेव शिशु रूप में आते हैं किंतु जब जब मातृत्व का अपमान होता है, जगतजननी महाकाली बनकर पापियों का रक्तपान करती हैं। उनके मुंडों से अपना श्रृंगार करती हैं। माँ सर्वव्यापी हैं। माँ के आशीर्वाद से जीवन चैतन्य और ज्योतिपुंज हो उठे। या देवी सर्वभूतेषु, मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।। हम अलसायी माटी के अद्भुत औलादें हैं।। पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया के नानावतारी पुरुषो पर बहत्तर के हूर चौहत्तर के जिन्न आसन जमाए हुए थे। जलेबी की खेती हो रही और साईं बाबा को बाबा के पद से हटाया जा रहा। और अब सस्ती लोकप्रियता के लिए दफली और राग का एकल हो रहे जिनका एक हो जाना भी एक गंभीर खतरा है, कत्तई नहीं होना चाहिए। यही हमारे आबो हवा की खूबसूरती है। पिछले दिनों कहीं परास के पत्तल में अपने बाप दादाओं पुरखों को नम आंखों से भोग लगाया जा रहा था, तो वहीं वृद्धाश्रम भी दिखे जहाँ जीते जी पानी तक पूछा नहीं जाता तो बाद में भोग रूपी अमृत पिलाने से क्या फायदा और कौन उसे स्वीकार करेगा ! ये बतौर लेखक मेरे विद्रोही स्वर है। हम तो बस हिम्मती हैं, फायदे नुकसान की अकल कभी हमारे लोक मान्यताओं की शकल बिगाड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। हम जिसकी बदौलत हैं उसके लिए एक दो नहीं पूरे नौ दिन उपवास करते है। उसी माँ नें सब दिया है। जानकी मैया जिस माँ भगवती के मंदिर में दर्शन कर अपने प्रभु के मुख की आभा निहार रही थी उसी पर कहा भी गया राम देखे सिया को सिया राम को दोनों अखियां लड़ी को लड़ी रह गई। उधर अब्दुल चचा रामजी का धनुष बना रहे हैं, दफाली लोग अपना बाजा कस रहे।बचपन में फुलवारी या रामजन्म के अगले दिन धनुष यज्ञ होता था जों अब भी यथावत थानागद्दी बाजार में जारी है। हाँ दुर्गा पूजा मेले का स्वरुप वीभत्स हुआ है और अब मेले मिलाप का संसाधन बन गए है। समाज से आपसी सौहार्द का रस गायब है केवल बचा है तो व्यापार का रिश्ता जों घातक और असहनीय है। जय माता दी।।

(पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक जौनपुर यूपी)

निगरानी और नागरिक स्वतंत्रता के बीच तालमेल जरूरी

डिजिटल युग के आगमन ने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति का युग शुरू किया है, जिससे हमारे रहने, काम करने और बातचीत करने के तरीके बदल गए हैं। जबकि ये नवाचार कई लाभ लाए हैं, इन्होंने गोपनीयता, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के क्षरण के बारे में भी गंभीर चिंताएं उठाई हैं। लेकिन निगरानी का बढ़ता सिलसिला हमारी आधुनिक दुनिया का एक अभिन्न अंग बन गया है। निगरानी, जो कभी केवल कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित थी, ने अब ऑनलाइन व्यवहार की ट्रैकिंग करने से लेकर भौतिक आंदोलनों की निगरानी तक कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल करने के लिए विस्तार किया है। सरकारें, कॉर्पोरेट और यहां तक कि व्यक्ति अब हमारे जीवन के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र कर सकता है, जिससे हमारे गोपनीयता के अधिकार की सीमा और दुर्व्यवहार की संभावना के बारे में प्रश्न उठते हैं। निगरानी कैमरे अब सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और स्टोरों से लेकर सरकारी भवनों तक में आम हो गए हैं। निःसंदेह, ये कैमरे अपराध को रोक सकते हैं और जांच में सहायता कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों की निगरानी किस हद तक की जानी चाहिए, इसके बारे में भी प्रश्न उठाते हैं। चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई है, जिससे अधिकारियों को वास्तविक समय में व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम बनाया गया है। जबकि यह तकनीक कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकती है, इसने इसके दुरुपयोग की आशंका को भी बढ़ाया है। अध्ययन से पता चला है कि चेहरे की पहचान के एल्गोरिदम कुछ जनसांख्यिकी के खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं, विशेष रूप से रंग के लोगों के खिलाफ। यह पूर्वाग्रह भेदभावपूर्ण परिणामों में ले जा सकता है, जैसे गलत गिरफ्तारी या निरोध। सार्वजनिक स्थानों में चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी और गोपनीयता के क्षरण के बारे में चिंताएं उठाता है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि निगरानी कैमरों का प्रसार एक ह्यपैनोप्टिकन प्रभावह्न पैदा करता है, जहां व्यक्ति लगातार देखा जाना और निगरानी महसूस करते हैं, जिससे अभिव्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। निगरानी फुटेज का भंडारण और प्रतिधारण डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं उठाता है। बेशक निगरानी के युग में जीवन और स्वतंत्रता को संतुलित करना एक जटिल चुनौती है। फिर भी निगरानी के लाभों और हानियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, स्पष्ट और लागू होने योग्य गोपनीयता कानून स्थापित करना आवश्यक है। इन कानूनों को निगरानी की सीमाओं को परिभाषित करना चाहिए, व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा का संग्रह और उपयोग नैतिक रूप से किया जाता है। सरकारों को भी अपनी निगरानी गतिविधियों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए।

कहानी सीताराम केसरी की

प्रेमकुमार मणि

नयी पीढ़ी सीताराम केसरी के नाम से अनभिज्ञ हो सकती है। जानती भी होगी तो नाम भर. लेकिन एक समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अत्यंत प्रभावशाली नेता थे। 1970 में कांग्रेस का जब समाजवादी कायाकल्प हुआ तब बिहार कांग्रेस में तथाकथित ऊंची जातियों के दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग हो गए। पिछड़े वर्ग के नेताओं का कद कांग्रेस में थोड़ा ऊँचा हुआ। केसरी को भी ऐसे में अवसर मिला। 1973 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बाद के दिनों में लम्बे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहे। संसदीय जीवन में लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य लंबे अरसे तक रहे। केन्द्रीय मंत्री भी रहे। 1996 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जहाँ वह 14 मार्च 1998 तक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से वह बेआबरू होकर निकले। उसकी अपनी कहानी है, जिस पर चर्चा करेंगे।

सीताराम केसरी का जन्म बिहार के दानापुर में एक टुटपुंजिया केसरवानी बनिया परिवार में 1919 में हुआ। पढाई-लिखाई भी व्यवस्थित नहीं हुई। दानापुर पटना के निकट एक छोटा-सा नगर है, जो व्यावहारिक तौर पर आजकल पटना शहर का ही हिस्सा हो गया है। यहाँ आर्य-समाज का अच्छा असर था और कहते हैं एक बार दयानन्द सरस्वती यहां आए थे। 1857 के सिपाही विद्रोह में दानापुर छावनी के 2500 सिपाहियों ने एक साथ विद्रोह कर दिया था। बीसवीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन का जब गांधी युग आरम्भ हुआ, दानापुर के अनेक लोगों ने उस में हिस्सा लिया। कहा जाता है सीताराम केसरी 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में शामिल हुए। वह संभवतः कांग्रेस सेवा दल के ड्रम-पार्टी के हिस्सा थे। उसके बाद वह कई बार जेल गए। आजादी मिलने पर वह कांग्रेस की राजनीति से जुड़े रहे।

बिहार की कांग्रेस राजनीति उस समय भी जात-पात से भरी थी। भूमिहारों और राजपूतों का बोलबाला था। तीसरे पायदान पर कायस्थ थे और चौथे पर ब्राह्मण. पूना पैक्ट के कारण दलितों को जो आरक्षण मिला था,उस के कारण दलितों के कुछ नेताओं को जगह मिल जाती थी। आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा कांग्रेस में शामिल जरूर किये गए, किन्तु 1963 में कुछ ही रोज उपमुख्यमंत्री रह कर हटने के लिए मजबूर कर दिए गए। इन सब के बीच पिछड़े वर्ग के नेताओं की कांग्रेस में कोई जगह नहीं थी। पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ कर राजनीति करते थे। हालांकि वहां भी घाघ द्विज नेताओं का जमघट था। ये समाजवादी द्विज बोली-वाणी में तो क्रांतिकारी रहते थे,लेकिन आंतरिक व्यवहार में कम जातिवादी नहीं थे।

ऐसी स्थिति में भी कुछ नेता थे जो कांग्रेस से जुड़े थे। सीताराम केसरी उसमें एक थे। इन नेताओं को शायद कभी बदलाव की उम्मीद थी। ऐसा एक बदलाव 1963 में आया जब कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब कुल ग्यारह सदस्यीय कैबिनेट में तीन पिछड़े वर्ग, एक दलित, एक पिछड़ा और एक अगड़ा मुसलमान और एक आदिवासी मंत्री बनाए गए। सामान्य कहे जाने वाले द्विजों के मुख्यमंत्री सहित कुल चार मंत्री बने थे। किसी जाति का दो मंत्री नहीं था।

इन परिस्थितियों से रु-ब -रु होते केसरी 1973 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मुश्किलों के बीच उनकी राजनीति चलती रही। 1977 में कपूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने, तब गैर द्विज जातियों की राजनीति में एक जोश आया। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस अब कुछ अधिक द्विजवादी हो गई थी। 1980 से 1990 तक कांग्रेस का बिहार में राज रहा और उस ने इस बीच पांच मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन केवल दो ऊँची जातियों के पाँचों थे। केसरी चुपचाप कांग्रेस में बने रहे। कांग्रेस की राजनीति दमघोंटू थी। लेकिन उसी में बने रहना उन्होंने बेहतर समझा।

1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू किये जाने के बाद वह उत्साहित हुए। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस में भी कुछ बदलाव होगा। जब नरसिंह राव की सरकार बनी तो वह सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री बनाए गए। इस बीच उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संभव कार्य किये। उत्तर भारतीय राजनीति में पिछड़ों के उभार से वह उत्साहित थे। मुलायम, लालू, नीतीश सब के प्रति उनकी शुभेच्छा रही। इसी बीच 1996 में वह कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। ऐसा लगा कि कांग्रेस में एक नया युग आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1996 और 1997 में दो वर्षों के भीतर दो सरकारें बनीं और बिखरीं। देवगौड़ा के बाद गुजराल आए। इस सरकार में डी एम के भी शामिल थी। डी एम के पर राजीव गांधी की हत्या में शामिल लिट्टे नेताओं से मिलीभगत के सबूत मिले और इस आधार पर केसरी ने मांग की कि डी एम के मंत्री को हटाया जाए। गुजराल ने इस्तीफा देना बेहतर समझा। नतीजतन 1998 के आरम्भ में चुनाव हुए और कांग्रेस को 1996 से केवल एक सीट अधिक मिली। तथ्य यह भी है कि इस चुनाव में प्रचार की कमान सोनिया गांधी ने संभाल ली थी। केसरी लगभग नजरबंद थे। कांग्रेस नेताओं की दलील थी कि केसरी को अंग्रेजी नहीं आती और दक्षिण में उनका प्रभाव नहीं हो सकेगा।

कायदे से अपेक्षित सफलता न मिलने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी की होनी चाहिए थी किन्तु ठीकरा अध्यक्ष केसरी पर फोड़ा गया। 14 मार्च 1998 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष की फजीहत की गई। प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव किया और बिना किसी विमर्श के हंगामे के बीच उसे पारित घोषित कर दिया गया। उद्देश्य केवल नया अध्यक्ष चुनना नहीं था। केसरी को अपमानित करना भी था। सभ्य कही जाने वाली इस पार्टी के सभ्य लोगों ने केसरी की धोती खोल दी। उन्हें जूतों से पीटा गया। नंगा कर के बाथरूम में बंद कर दिया गया। पूरे दफ्तर पर कब्जा कर लिए जाने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली। केसरी ने चूँ तक नहीं किया। अपमान पी कर चुप्पी बांधे रहे।

9 मई 1998 को फिर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर को कांग्रेस से निकालना था, क्योंकि इन लोगों ने सोनिया पर सवाल उठाए थे। एक बार फिर केसरी को उसी तरह अपमानित किया गया। उन्होंने लाख मिन्नत की। हनुमान की तरह कलेजा फाड़ कर दिखलाने का समय तो नहीं था, लेकिन जितना गिड़गिड़ा सकते थे किया। लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस का आंतरिक द्विज-संस्कार इस पिछड़े नेता का जी भर फजीहत करना चाहता था कि फिर कभी कोई ऐसा स्वर न उठा सके।

केसरी बिहार से थे और लालू प्रसाद पर उन्हें कुछ भरोसा था। जब उन्हें चारा मामले में आरोपित किया गया था तब लालू के प्रति केसरी की हमदर्दी थी। उन्हें जब जेल जाना पड़ा तब शायद केसरी की ही सलाह थी कि और किसी को नहीं, राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाइये। लालू उन्हें चाचा कहते थे। लेकिन इस मुसीबत में जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता जाने लगी तब उन्होंने लालू से सहयोग की अपेक्षा की। लालू सोनिया गांधी के मूड-मिजाज को समझते थे। उन्होने सहयोग से साफ इंकार कर दिया। इन्हीं सब अपमान और उपेक्षा के बीच वह बीमार हुए। कहते हैं उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। इन चौतरफा घुटन के बीच दिल्ली एम्स में 24 अक्टूबर 2000 को वह दिवंगत हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने केसरी के इस अपमान-प्रसंग को चुनावी भाषण का विषय बनाया कि कांग्रेस में पिछड़े वर्ग के नेताओं की क्या स्थिति थी।

केसरी की कहानी न केवल कांग्रेस बल्कि हमारी राष्ट्रीय राजनीति के चरित्र और संस्कार को भी सामने लाता है। अपने मध्यकालीन इतिहास में हमने देखा है कि हेमचन्द्र, जिसने मुगलों को लगभग खदेड़ दिया था, को बनिया-बक्काल कह कर राजपूतों ने सहयोग नहीं किया और जब मुगल आए तब उनके लिए पलक-पाँवड़े बिछा दिए। केसरी को भी कांग्रेस की दिल्ली लॉबी बनिया-बक्काल ही कहती थी। वह कोई असाधारण व्यक्तित्व नहीं थे। उनमें कमजोरियां होंगी। मसलन अंग्रेजी नहीं आती थी। लेकिन इतना तो कहा जाएगा कि राजनीति में उन्होंने अपना घर लुटाया, बनाया नहीं। आर्थिक ईमानदारी के मामले में उन पर कभी ऊँगली नहीं उठी, न ही परिवार के किसी व्यक्ति को कभी राजनीति में आगे किया। उनका दोष बस इतना था कि वह पिछड़े वर्ग से थे और यह भी सच है कि कांग्रेस का मण्डलीकरण करना चाहते थे। लेकिन इसकी उन्हें जो सजा मिली वह बहुत अधिक थी।

शायद यही वजह थी कि कुछ वर्ष पूर्व जब अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनाने केलिए जोर दिया गया तब उन्होंने साफ इंकार कर दिया। वह सीताराम केसरी दूसरे नहीं बनना चाहते होंगे।

विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने का क्रेज

अशोक भाटिया

(वरिष्ठ समीक्षक)

वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डॉलर यानि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रहा और रेड सियर स्ट्रेटजी कंसलटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डॉलर यानि 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बी। मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया था कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4।44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए। एक अन्य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6।46 लाख थी, यानी 45 प्रतिशत की वृद्धि। यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत से ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 के संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है।

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इससे देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है। इससे उद्योग-धंधों के लिए श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा, देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र फंसे तो नेताओं को पता चला कि इतने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक ने हैरानी जताई। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत से हरेक साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में क्यों चले जाते हैं? यह सवाल कनाडा में जो भारत को लेकर हो रहा है उस रोशनी में पूछ जाना चाहिए। वहां जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे पहले ही भारतीयों के साथ हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय अधिक जाग चुका है और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि इजराइल में फिलहाल करीब 18 हजार भारतीय जबकि वेस्ट बैंक में करीब एक दर्जन और गाजा में तीन से चार भारतीय रह रहे हैं। जब यहाँ छात्र किसी कारण से फंसते है तो भारत सरकार को ह्यएयर -लिफ्ट ह्यका सहारा लेना पड़ता है जो परेशानी भरा होता हैं। बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत से विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने की आकांक्षा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2016 और 2021 के बीच 26।44 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए गए। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने 13.5 अरब डालर का खर्च किया।

वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डॉलर यानि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रहा और रेड सियर स्ट्रेटजी कंसलटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डॉलर यानि 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बी। मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया था कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4।44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए। एक अन्२य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6।46 लाख थी, यानी 45 प्रतिशत की वृद्धि।

यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत से ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 के संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है।

विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके माता-पिता अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर इन युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गांवों में बड़ी मात्रा में विदेशों से धन आता था। विदेशों में पढ़ाई के इस क्रेज के चलते यह प्रक्रिया उलट हो गई है, यानी अब विदेशों से धन आने के बजाय विदेशों को धन भेजा जा रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2024 के अंत तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डॉलर पहुंच जाएगी, तो यह देश के लिए अत्यंत संकट का कारण बनेगा।

गौरतलब है कि युवाओं का शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन, देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में पिछले दो-तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। यदि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो 1990-91 में जहां मात्र 49.2 लाख विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया, यह संख्या वर्ष 2020-21 में 414 लाख तक पहुंच गई। मोटे तौर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुणा से भी ज्यादा हो चुकी है। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि वर्ष 2021 में देश में 1113 विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान, 43796 महाविद्यालय और अन्य स्वतंत्र संस्थान 11296 थे। इसी वर्ष देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 15।51 लाख शिक्षक कार्यरत थे।

देश में कई विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कई अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं और कई ह्यविश्वविद्यालय समह्न यानी ह्यडीम्ड विश्वविद्यालयह्न हैं। देश में कई विश्वस्तरीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी वैश्विक कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं।

जहां तक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों में फीस विदेशी संस्थानों में फीस से कहीं कम है और जिन विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत नीचा है।

तो सवाल उठता है कि भारी भरकम राशि खर्च कर भारत के युवा विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश क्यों लेते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि विदेशों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश लेकर वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहां तक कि इंग्लैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि वहां रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय युवा यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि इन देशों में भी रोजगार की भारी कमी है। कई देशों में वहां के स्थानीय लोग भारतीय एवं अन्य देशों से आने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें भी देखने को मिल रही हैं। देश से जाने वाले अधिकांश युवा विद्यार्थी वहां रोजगार प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं और उन्हें स्वदेश वापिस लौटना पड़ता है, जिसके कारण वे भारी कुंठा का भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को इस हेतु वास्तविकता से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे विदेशों में जाकर अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई को यूं ही न गवा दें। गौरतलब है कि पिछले लगभग दो दशकों से भारत के कई नागरिक एजेंटों के माध्यम से विदेशों में, खास तौर पर खाड़ी के देशों में रोजगार की तलाश में गए और वहां उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन युवाओं के पासपोर्ट तक एजेंटों के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह-तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किय.. इसी तर्ज पर देश के अनभिज्ञ युवा जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हरियाणा चुनाव

कांटे की टक्कर

हरियाणा चुनाव में कांटे की टक्कर है। भाजपा-जजपा गठबंधन टूटने तथा कांग्रेस विद्रोहियों ने अनिश्चितता बढ़ाई है। 5 अक्टूबर, 2024 को चुनाव में हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य जबरदस्त टकराव तथा गठबंधनों में बदलाव से परिभाषित हो रहा है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी-भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसने 2019 में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी-जजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी, पर अब वह अकेले चुनाव मैदान में उतरी है। भाजपा-जजपा गठबंधन टूटने से भाजपा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसे चुनाव तक अल्पमत सरकार चलानी पड़ी है। अपने पूर्व सहयोगी जजपा के अलग होने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। वह जनता को गिना रही है कि उसने ढांचागत विकास, शिक्षा तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। लेकिन पार्टी को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जहां कृषि सुधार जैसे मुद्दों पर भारी विरोध था। कांग्रेस स्वयं को भाजपा के मुख्य विकल्प के रूप में पेश कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जाट मतदाताओं में व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है और वह भाजपा सरकार के प्रति कथित असंतोष का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।

दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी का अलग विमर्श बनाने के लिए स्वयं की भाजपा की नीतियों से दूरी बना रहे हैं तथा 'किसान-हितैषी सुधारों' की पैरवी कर रहे हैं।
हरियाणा में पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी-'आप' अनिश्चितता और बढ़ा रही है। 'आप' पड़ोसी पंजाब में मिली सफलता यहां दुहराना चाहती है। पार्टी मुख्यत: शहरी मतदाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्यरक्षा, शिक्षा और भ्रष्टाचार-विरोधी कदमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। पिछले वर्षों में मजबूत पार्टी रही भारतीय राष्ट्रीय लोकदल-इनेलोद ने अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी-बसपा से हाथ मिलाया है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र केन्द्रीय मुद्दा बना हुआ है। यह नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध प्रदर्शनों से पैदा हुआ जिनको अब वापस ले लिया गया है। लेकिन सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और जजपा इसका प्रयोग कर ग्रामीण मतदाताओं को लामबंद करने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भारत की सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। भाजपा और कांग्रेस ने इसे हल करने का वादा किया है। भाजपा जहां अपनी औद्योगिक पहलें गिना रही है, वहीं कांग्रेस नई रोजगार नीतियों का प्रस्ताव कर रही है। इन सबके साथ ही राज्य में 'जातीय राजनीति' का दबदबा है जो सत्ता का निर्धारण करती है। परंपरागत जाट-गैर जाट विभाजन हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य परिभाषित करता है। भाजपा को परंपरागत रूप से गैर-जाट समुदायों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन उसके सामने इस जनाधार को मजबूत करने की चुनौती है। जजपा और कांग्रेस मुख्यत: जाट मतदाताओं पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। जातीय गणित हमेशा हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण रही है। इसने मतदाताओं के व्यवहार और चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। हरियाणा की जनसंख्या में 25-30 प्रतिशत जाट सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक जाति समूह हैं। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस जाट तथा गैर-जाट के बीच खाई पाटने के लिए शहरी-ग्रामीण विकास योजनाओं पर ध्यान दे रही है, लेकिन उसे विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। 'जातीय गणित' का प्रबंधन करने वाले दल को ही राज्य में सत्ता मिलेगी।

एकात्म मानववाद : आदर्श एवं चुनौतियां

भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्यय की 108वीं जन्म जयंती मना रही है। उसके सामने 'एकात्म मानववाद' के आदर्शों तथा आधुनिक प्रशासन के बीच संगति बैठाने की चुनौतियां हैं।

के.एस. तोमर
(लेखक, राजनीति विश्लेषक हैं)

भारतीय जनता पार्टी -भाजपा आजकल दीनदयाल उपाध्यय की 108वीं जन्म जयंती मना रही है। उसके सामने 'एकात्म मानववाद' आदर्शों तथा आधुनिक प्रशासन के बीच संगति बैठाने की चुनौतियां हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा 'एकात्म मानववाद' की अवधारणा व आदर्श पेश करने वाले स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती है कि वह इस दूरदर्शी आदर्श के अनुकूल स्वयं को कहां तक ढाल पाती है और इसे लागू करने में कहां तक सफल होती है। दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' दर्शन में विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें मनुष्य की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी संस्कृति, आत्मनिर्भरता तथा नैतिक प्रशासन पर जोर दिया गया है।

हालांकि, भाजपा ने इन सिद्धान्तों को अवधारणात्मक रूप से स्वीकार किया है, पर उनको दिन-प्रतिदिन के शासन-प्रशासन में स्थापित करना व्यावहारिक रूप से कठिन चुनौती है। इस अवधारणा को लागू करने के लिए आर्थिक आदर्शों को आधुनिक नीतियों के साथ रख कर देखना जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों की भारत की वर्तमान स्थितियों से सामंजस्य बैठाना जटिल है। वर्तमान 'वैश्वीकृत' दुनिया में भारत की नीतियां पूंजी-संचालित अर्थनीति पर आधारित हैं। इन नीतियों का प्रारंभ 1990 के दशक में अपनाये गए उदारीकरण सुधारों से हुआ था जिनके केन्द्र में 'उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण'-एलपीजी नीतियां थीं।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐसी आर्थिक नीतियों पर ध्यान केन्द्रित किया है जिनसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई, मुक्त बाजार सुधारों तथा निजीकरण को बढ़ावा मिले। आलोचकों का तर्क है कि इनका दीनदयाल उपाध्याय की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की अवधारणा से टकराव है क्योकि इसमें ग्रामीण व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन, जमीनी स्तर पर रोजगारों के सृजन तथा विदेशी पूंजी पर निर्भरता घटाने को केन्द्र में रखा गया है। सरकार ने स्वदेशी संस्कृति और वैश्वीकरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण तथा प्रोत्साहन की पैरवी की थी। हालांकि, इसके साथ देश की आधुनिक प्रगति को भी जोड़ा गया था। इनके बीच संतुलन बनाना भाजपा के लिए आसान काम नहीं है।

राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रवाद तथा परंपरागत मूल्यों पर जोर देती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने विश्व मंच पर आयुर्वेद व योग जैसी पहलों को बढ़ावा देने के अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। लेकिन आधुनिक जीवनशैली प्रवृत्तियों के उभार तथा तकनीकों के विकास के कारण भारत विश्व अर्थव्यवस्था से तेजी से जुड़ रहा है। ऐसे में उन गहरी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रभाव पड़ सकता है जिनकी पैरवी दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। भाजपा द्वारा विशिष्ट 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के विकास पर भी अनेक आलोचक सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि इससे दीनदयाल उपाध्याय के 'समावेशी दृष्टिकोण' से ध्यान हट सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष नैतिक प्रशासन को बढ़ावा देने तथा शासन-प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करने की कठिन चुनौती है। दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में नैतिक प्रशासन पर जोर दिया गया था जिसके प्रमुख तत्व निष्ठा, ईमानदारी तथा जनता की सेवा है। हालांकि, पिछले दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार तथा भाजपा व राजग की राज्य सरकारों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ा है और मोदी समेत सभी भाजपा नेता स्वयं को 'स्वच्छ प्रशासन' का पैरोकार मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आलोचकों तथा विपक्षी दलों ने पार्टी पर भ्रष्टाचार, दरबारी पूंजीवाद तथा बड़े निगमों का पक्ष लेने के आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप मुख्यत: भूमि अधिग्रहण नीतियों तथा निजीकरण के बारे में हैं। इनसे दीनदयाल उपाध्याय के नैतिक आदर्शों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर भी आलोचक सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, विपक्ष भाजपा के खिलाफ ऐसे आरोपों को अदालतों में पुष्ट नहीं कर सका है।

भाजपा के समक्ष समावेशी समाज बनाने की चुनौती भी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय ने समावेशी समाज बनाने की पैरवी की थी जिसका अर्थ सभी समुदायों की आवश्यकतायें पूरी करना तथा सामाजिक व धार्मिक विभाजनों से ऊपर उठ कर सामंजस्य व सद्भावना सुनिश्चित करना है। भाजपा का दावा है कि उसने अपनी विभिन्न विकास योजनाओं में सामाजिक व धार्मिक विभाजनों पर ध्यान नहीं दिया है, पर आलोचकों का आरोप है कि भाजपा विभाजनकारी नीतियां, खासकर धार्मिक आधार पर अपना रही है। हिंदुत्व-संचालित नीतियों तथा समावेशन व सामाजिक सामंजस्य के विचारों के बीच संतुलन बैठाना भाजपा के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। इसका संबंध कथनी और करनी में अंतर से भी है।

दीनदयाल उपाध्याय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 'अंत्योदय', यानी समाज के अंतिम व्यक्ति की प्रगति था। अंत्योदय का उद्देश्य समाज के सर्वाधिक हाशियाकृत की प्रगति सुनिश्चित करना है। भाजपा ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान दिया है। 'पीएम उज्जवला योजना' से ग्रामीण परिवारों को एलपीजी, 'पीएम आवास योजना' से गरीबों को सस्ते मकान तथा 'स्वच्छ भारत अभियान' से सफाई में सुधार के काम किए गए हैं। भाजपा ने अनेक अभियानों के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम किया है जिनमें विश्व स्तर पर 'योग दिवस' मनाना, भारतीय भाषाओं का विकास तथा भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों को उजागर करना शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में 'राजनीतिक विकेन्द्रीकरण' का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रशासन को लोगों के निकट लाना सुनिश्चित करना है। भाजपा ने 'सहयोगी संघवाद', जीएसटी तथा नीति आयोग के गठन जैसे कदम इस दिशा में उठाए हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण-डीबीटी तथा जनधन योजना ने नागरिकों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों को हटाया है। इससे सब्सिडी तथा कल्याणकारी योजनायें सीधे लोगों तक पहुंची हैं।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय शुरू की गई 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय के आत्मनिर्भरता सिद्धान्त पर जोर दिया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय विनिर्माण तथा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार 'मेक इन इंडिया' पहल दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप है। इसके माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक अर्थव्यवस्था का वैश्वीकृत चरित्र है। इसे देखते हुए पूर्णत: ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना बहुत कठिन तथा चुनौतीपूर्ण है जिसका विश्व अर्थव्यवस्था तथा दूसरे देशों से कोई संबंध न हो।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा महान भारतीय दार्शनिक दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को जमीन पर उतारने का प्रयास जारी है। दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को जमीन पर उतारने के प्रयास में सत्तारूढ़ भाजपा को अनेक सफलतायें मिली हैं, पर उसके समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। हालांकि, भाजपा को राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता तथा अंत्योदय को बढ़ावा देने में अनेक अभूतपूर्व व असाधारण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, पर उसे सच्चा आर्थिक विकेन्द्रीकरण लाने, शासन-प्रशासन को पूर्णत: नैतिक बनाने तथा सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने में काफी बाधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आधुनिक प्रशासन की जटिलतायें, वैश्विक आर्थिक एकीकरण तथा राजनीतिक रणनीतियां अक्सर भाजपा को दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से थोड़ा विचलित करती हैं। लेकिन 'एकात्म मानववाद' के आदर्श पार्टी के समक्ष प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जिससे वह दार्शनिक आदर्शों तथा समकालीन यथार्थ के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर बेहतर भारत बनाने का प्रयास कर रही है।

वैश्विक व्यवस्था का पुनर्संतुलन

"इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते मिसाइल हमले पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।"

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भारत के विस्तारित पड़ोस में बढ़ते हालात क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। हाल ही में इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडरों को मार गिराया जाना, खास तौर पर इसके शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह की हत्या, और इजरायली क्षेत्र पर ईरानी मिसाइलों की बारिश से पश्चिम एशिया में संकट बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की संवेदनशीलता को समझा और तुरंत अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया।

भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायल को संदेश था कि क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई बेहद जरूरी है, आतंकवाद के किसी भी रूप और अभिव्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है और भारत शांति और स्थिरता की जल्द बहाली का समर्थन करने के लिए तैयार है। पिछले महीने न्यूयॉर्क में फ्यूचर समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। बैठक के बाद जारी एक प्रेस बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री ने इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की समय-परीक्षित सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया और युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल दो राष्ट्र समाधान ही क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है।

यह याद करते हुए कि भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए भारत के निरंतर समर्थन से अवगत कराया। जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे, तब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नवनियुक्त प्रमुख मुहम्मद यूनुस को पश्चिमी नेताओं से बहुत जरूरी प्रशंसा मिल रही थी। यूनुस ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिकी विदेश मंत्री, कनाडाई प्रधानमंत्री, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, विश्व बैंक और एडीबी के प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असामान्य रूप से गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और क्षेत्रीय निकाय सार्क को पुनर्जीवित करने की इच्छा व्यक्त की। भारत के लिए, ये संबंध संभावित रूप से पाकिस्तान और चीन को बांग्लादेश के साथ इस नए-नए दोस्ताना संबंध का उपयोग भारत के खिलाफ अपने विध्वंसक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

लगभग उसी समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अपने भाषण में वैश्विक व्यवस्था को फिर से संतुलित करने पर बात की। उन्होंने कहा, वैश्विक व्यवस्था को फिर से संतुलित करना, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के 51 संस्थापक सदस्यों से हुई थी, जो पिछले आठ दशकों में चौगुनी हो गई है, जहां आपके पास न केवल दुनिया में अधिक स्वतंत्र देश हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के व्यक्तिगत सदस्यों का आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक कि जनसांख्यिकीय भार भी स्थानांतरित हो गया है, एक ऐसे बिंदु पर स्थानांतरित हो गया है जहाँ हममें से कई लोग मानते हैं कि आज हम वास्तव में एक मोड़ पर हैं, मंत्री ने विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित करने की कोशिश करते हुए एक ही संबोधन में बहुध्रुवीयता और बहुलवाद को सावधानी से लाया।

उन्होंने कहा, आज, हम वास्तव में एक वैश्विक परिदृश्य को देख रहे हैं जो बहुत अधिक क्षेत्रीय है, जो, जैसा कि मैंने कहा, उन देशों द्वारा अधिक विशेषता है जिनके अपने मजबूत हित हैं और जो उस हित को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए हम दुनिया के संदर्भ में जो कुछ भी देखते हैं, वह वास्तव में यह है कि दुनिया की अभिसरण की राजनीति वास्तव में कैसे होती है। और एक तीसरा शब्द जो मेरे दिमाग में आता है वह है बहुपक्षीयता। यह एक बहुत ही भद्दा शब्द है, लेकिन यह एक तरह से द्विपक्षीय संबंधों से परे एक ऐसी दुनिया का वर्णन करता है, जो बहुपक्षीय से कम है।

वह जहां देश इन अभिसरण और ओवरलैप के आधार पर संयोजन बनाते हैं, जिनके बारे में मैंने बात की है। और आपके पास वास्तव में देशों के समूहों की यह घटना है जो अक्सर एक सीमित एजेंडे के लिए एक साथ आते हैं, कभी-कभी अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक सहमत थिएटर में।

हाल की वैश्विक घटनाएं और इनमें से कई पर भारत का मापा हुआ रुख वही दर्शाता है जिसके बारे में विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में बात की थी, और एक पुनर्संतुलन चल रहा है।

आप की बात

नशे का व्यापार

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 562 किलो कोकेन पकड़ी जो अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है और जिसकी कीमत 6.5 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। भारत में नशे के व्यापार और अवैध उपयोग पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद आए दिन नशीले पदार्थ बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं और यह व्यापार अरबों रुपए का हो गया है। स्पष्ट है कि इसके लिए बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है। नशे के व्यापार का काफी पैसा आतंकवादियों की जेब में जाता है जिससे देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। रेव पार्टी के नाम पर युवकों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग का पूरा अमला लगा हुआ है जिसे विभिन्न एजेंसियों का सहयोग मिलता है। इसके बावजूद युवकों में नशाखोरी बढ़ती जा रही है। कई युवा इतने ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं कि नशे के लिए पैसा जुटाने हेतु आपराधिक गतिविधियां करने लगते हैं। इनके कारण चोरियों व अन्य आपराधिक घटनायें बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए नशे का व्यापार जिम्मेदार है। सरकार अपना काम कर रही है मगर नौजवानों को नशाखोरी की लत से बचाने के लिए परिवार तथा समाज को भी अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा।

-**सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

जातिगत भेदभाव

विडंबना है कि 78 साल की आजादी के बाद भी देश के कुछ राज्यों में ऐसी कारागार नियमावली है जहां जाति के आधार पर बैरक आबंटित की जाती है और काम दिया जाता है। इन कारागार नियमावलियों के अनुसार बंदी या हिरासती की जाति का उल्लेख जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में देश के 11 राज्यों में जारी भेदभाव पर आधारित जेल नियमावली को निरस्त करने का आदेश दिया है। उसने तीन महीने में आवश्यक संशोधन का आदेश भी दिया है ताकि औपनिवेशिक काल के जातिगत भेदभाव वाले इन प्राविधानों को समाप्त किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है और इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि देश में अब भी अनेक ऐसे औपनिवेशिक कानून मौजूद हैं जिनको तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। जातिगत भेदभाव के सभी रूपों तथा अश्पृश्यता की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए शासन-प्रशासन और न्यायपालिका के साथ ही राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों को पहल करनी चाहिए। जातिगत भेदभाव वाले ऐसे सभी प्राविधानों को समाप्त करना विकसित भारत तथा स्वस्थ समाज बनाने हेतु अनिवार्य है।

- **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

युद्ध का विस्तार

हिज्बुल्ला प्रमुख के मारे जाने के बाद ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। इजरायल भी पूरी मजबूती के साथ हमलों का जवाब दे रहा है। उसका कहना है कि वह इस समय सात दुश्मनों से एक साथ लड़ रहा है और वह सबको तबाह करके रहेगा। अमेरिका तथा पश्चिमी देश इस युद्ध में इजरायल के साथ हैं, लेकिन वे भी अनेक कारणों से युद्ध का विस्तार नहीं चाहते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध जारी रहने तथा पश्चिम एशिया में युद्ध का विस्तार होने से विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो पहले से ही अनेक संकटों का सामना कर रही है। अमेरिका में अगले महीने होने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से भी डेमोक्रेट व रिपब्लिकन किसी प्रकार इजरायल व यहूदियों के समर्थन से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन युद्धविराम करवाना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आसान नहीं है। एक साल पहले इजरायल पर हुआ हमला द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यहूदियों के नरसंहार के बाद सबसे बड़ा हमला था। इजरायल की जनता तथा सरकार इस बार अपने दुश्मनों का इस सीमा तक सफाया कर देना चाहते हैं कि वे उसके लिए निकट भविष्य में खतरा न बन सकें। वर्तमान स्थिति अत्यन्त जटिल है।

- **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पैसे की गुलामी

फिल्मी गीत-ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया बहुत मशहूर हुआ था। आज के समय में भी यह पूरी तरह प्रासंगिक है और शायद भविष्य में भी रहेगा। पैसा ही सब कुछ हो गया है और पैसे के लिए अनेक लोगों ने अपनी विश्वसनीयता व नैतिकता की लक्ष्मण रेखा तोड़ दी है। एक अस्पताल की नर्स ने महज 5100 रुपए का नेग न मिलने पर एक नवजात शिशु की जान ले ली। इसी तरह दो युवकों ने डेढ़ लाख रुपए के आईफोन मंगवाकर डिलीवरी ब्वाय की हत्या कर दी। बहुत अफसोस की बात है कि रुपए पैसों के आगे इंसान की कीमत घास के तिनके से भी गई बीती हो गई है। कहा जाता है कि पहले हमारे देश में दया, करुणा व विश्वास की संस्कृति थी, लेकिन अब पैसे की गुलामी के चलते उसकी हत्या हो रही है। हालांकि, अब भी लोगों के खोए पैसे उनको तलाश कर लौटाने तथा पैसे के लालच में न पड़ कर अपरिचित लोगों की सेवा और उनकी रक्षा करने वाले लोग हैं, पर ऐसी सकारात्मक खबरें अक्सर खो जाती हैं। हमें ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए।

-**हेमा हरि उपाध्याय,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भाषाओंका सम्मान

भारत बहुआयामी देश है और इसका परिवार भी बड़ा है। सभी भाषाओंका समृद्ध इतिहास है, जो क्षेत्रीय संस्कृतिका भी प्रतिनिधित्व करती है। इन भाषाओंका सम्मान भारतीय संस्कृतिकी विविधताका सम्मान है। विविधतामें एकता भारतकी विशिष्टता है, जो भाषा-भाषियोंको जोड़कर रखती है। यह हमारी भाषाई और सांस्कृतिक एकताका परिचायक है। इस सन्दर्भमें केन्द्र सरकारने गुरुवारको मंत्रिमण्डलकी बैठकमें पांच भारतीय भाषाओंको शास्त्रीय भाषाका दर्जा देनेका निर्णय किया है, जो स्वागतयोग्य है। इन भाषाओंमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला शामिल है। इन भाषाओंको शास्त्रीय भाषाओंका दर्जा मिलनेसे देशमें शास्त्रीय भाषाओंकी संख्या बढ़कर अब ग्यारह हो गयी है। इस श्रेणीमें पहलेसे संस्कृत, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और उड़िया शामिल हैं। केन्द्र सरकारके इस निर्णयसे इन भाषाओंको बढ़ावा मिलेगा। यह बात अलग है कि मराठी भाषाको ऐसे समय शास्त्रीय भाषाका दर्जा दिया गया है, जब महाराष्ट्रमें विधानसभाका चुनाव सन्निकट है। इसे राजनीतिके चश्मेसे देखनेकाकोई विशेष अर्थ नहीं है। वैसे भाषा और राजनीतिके बीच सम्बन्ध बहुत प्राचीन है और देशके कई राज्योंमें भाषा राजनीतिको प्रभावित करती है। वस्तुत: देशकी सभी भाषाएं सम्मानकी पात्र हैं और इनका सम्मान होना भी चाहिए। केन्द्र सरकारने अक्तूबर २००४ में शास्त्रीय भाषाओंके रूपमें भाषाओंकी एक अलग श्रेणी बनानेका निर्णय किया था, जिसमें तमिलको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया और शास्त्रीय भाषाओंके लिए मानदण्ड भी निर्धारित किये गये। किसी भी भाषाको इस श्रेणीमें लानेके लिए उस भाषाका कमसे कम हजार सालके दौरान रिकार्ड किये गये इतिहास या शुरुआती ग्रंथ बेहद प्राचीन होने चाहिए। भाषाका एक प्राचीन साहित्य या ग्रंथोंका संग्रह हो, जिसे कई पीढ़ियां मूल्यवान मानती हों। भाषाकी साहित्यिक परम्परा भी मौलिक हो, किसी अन्य भाषासे उधार नहीं ली गयी हो। इस श्रेणीमें तमिलके बाद २००५ में संस्कृत, २००८में तेलुगू, २००८ में कन्नड़, २०१३ में मलयालम और २०१४ में उड़ियाको शास्त्रीय भाषाका दर्जा दिया गया। केन्द्रमें नरेन्द्र मोदीकी सरकार बननेके बाद पहली बार पांच भाषाओंको शास्त्रीय भाषाकी श्रेणीमें शामिल किया गया है। यह अच्छा प्रयास है। शास्त्रीय भाषाएं भारतकी गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासतकी संरक्षकके रूपमें कार्य करती है। भविष्यमें इस श्रेणीमें और भाषाओंको न केवल शामिल किया जाय, बल्कि उसको प्रोत्साहित करनेका भी प्रयास किया जाय। इससे भाषाई एकताको भी प्रोत्साहन मिलेगा।

जानलेवा डिजिटल अरेस्ट

पूरी दुनियामें जिस तेजीसे साइबर अपराध बढ़ रहा है, वह गम्भीर चिन्ताका विषय है। विकास पथपर आगे बढ़नेके लिए जहां एक ओर नयी-नयी तकनीकका सहारा लिया जा रहा है वहीं शातिर दिमाग अपराधी साइबर ठगीके नये-नये तरीके ईजाद करनेमें पीछे नहीं हैं। एक अध्ययनके अनुसार दुनियाके ९७ देशोंमें साइबर अपराध होते हैं जिनसे भारत भी अछूता नहीं है। भारतमें धोखाधड़ी और डाटा चोरीकी घटनाएं अधिक होती हैं जो सरकारके समक्ष बड़ी चुनौती है लेकिन इससे बड़ी चुनौती साइबर ठगीका नया तरीका डिजिटल अरेस्ट बनता जा रहा है, जो जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसा ही एक हैरान कर देनेवाला मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेशके आगरामें सामने आया है जिसमें एक सरकारी स्कूलकी महिला शिक्षिकाकी जान चली गयी। इसमें साइबर ठगने पुलिस अधिकारी बनकर महिला शिक्षिकाके ह्वाट्सऐपपर काल करके बेटीको सेक्स रैकेटमें पकड़े जानेकी जानकारी देते हुए १५ मिनटमें एक लाख रुपयेकी मांग की। ऐसा न करनेपर बेटीका वीडियो वायरल करने और जेल भेजनेकी धमकी दी। साथ ही ठगने उसकी बेटीसे बात भी करायी। बेटीसे बात करने बाद शिक्षिकाकी तबियत बिगड़ गयी। यह कुछ फर्जी ड्रामा था। बेटी अपने कालेजमें सुरक्षित मिली लेकिन तबतक बहुत देर हो चुकी थी। मां सदमेको बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी हृदयघातसे मौत हो गयी। डिजिटल अरेस्टकी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं लेकिन इससे मौतकी यह पहली घटना सामने आयी है जो अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्तिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसपर पूरी तरह अंकुश लगानेकी जरूरत है। इसके लिए विशेष उपाय और रणनीति बनानेकी आवश्यकता है, तभी इसे रोका जा सकता है।

लोक संवाद

मामला मिलावटखोरीका

महोदय,-अयोध्यामें २२ जनवरीको हुई प्राण-प्रतिष्ठाके लिए तिरुपति तिरुमाला मंदिरसे भेजे गये लड्डुओंमें सूअरकी चर्बी, बीफ-टैलो और फिश ऑयलकी मिलावटखोरीका मामला सुर्खियोंमें है। खाद्य पदार्थोंकी बिक्री करनेवाले प्रतिष्ठानोंपर मालिकों एवं सेवादारोंके विषयमें जानकारी सार्वजनिक करनेका दूसरा मामला भी मिलावटसे ही जुड़ा है। इन दोनों मामलोंमें राजनीति जमकर हो रही है। समस्या दूर करनेके बदले राजनीतिक कार्यकर्ताओंके बीच आरोप-प्रत्यारोपका दौर जारी है। इस मामलेमें सुप्रीम कोर्टने कहा है कि राजनीतिसे भगवानको दूर ही रखें। देशमें मिलावटखोरीका गोरखधंधा बेखौफ चल रहा है। इसमें आस्थाका तड़का लगनेसे व्यंजन जायकेदार हो गया है। अपना देश दुग्ध उत्पादनके मामलेमें दुनियाभरमें सभीको पीछे छोड़ चुका है। औसतन १५ करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन पशुओंसे होता है। इतनी ही मात्रा मिल्क पाउडरसे बने दूधकी है। लेकिन प्रतिदिन दूधकी खपत ६५ करोड़ लीटर होती है। इससे स्पष्ट है कि आधीसे ज्यादा खपत नकली दूधकी है। आस्थाके नामपर मिलावटखोरीके खिलाफ उद्वेलित वर्ग इस सचाईसे पहलेसे ही वाकिफ है। इस सक्रियताके कारण यदि मिलावटके इस गोरखधंधेसे देशको मुक्ति मिले तो बड़ी उपलब्धि मानी जायगी। राजनीतिक जमात और धर्माचार्योंका यह समीकरण देशको मिलावटी खाद्य पदार्थोंसे मुक्ति दिलायेगा अथवा ध्रुवीकरणकी राजनीतिका यह अगला पैंतरा साबित होगा, इसपर दावेसे कुछ कह पाना आसान नहीं है। खाद्य पदार्थों एवं दवाइयोंमें मिलावटकी समस्या लगातार बढ़ रही है। धीमे जहरके इस कारोबारपर रोक लगानेके लिए सात दशक पहले कानून बनाया गया था। फिर इसमें संसद कई संशोधन भी करती है। आज इस अपराधके दोषियोंके लिए छह महीनेकी कैद एवं एक हजार रुपयेका जुर्माना भी वसूलनेका प्रावधान है। असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्योंमें मिलावटखोरीके अपराधियोंके लिए उम्र कैदकी सजाका प्रावधान किया गया है। परन्तु कठोर कानूनसे मिलावटका यह धंधा इन पांच प्रदेशोंमें बंद हो गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बात अवश्य हुई कि इन मामलोंमें प्रशासनकी उगाही बढ़ी है। लोक समाजकी सक्रियताके बिना कानून और प्रशासनके बूते इस समस्यासे पार पाना मुमकिन नहीं है। विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानममें दर्शनके लिए औसतन ८७ हजार भक्त प्रतिदिन आते हैं। इन्हें प्रसादके रूपमें लड्डू दिया जाता है। इसके लिए प्रतिमाह ४२ हजार किलो शुद्ध देसी घी खरीदा जाता है। देवस्थानमने ३१९.८० रुपये प्रति किलोग्रामकी दरसे शुद्ध देसी घीकी सप्लाई करनेवाली कम्पनी एआर फूड सप्लाई प्राइवेट लिमिटेडके विरुद्ध कानूनी काररवाई की है। वैदिक घीके नामसे केसरिया फर्म इसे ६९९ रुपये प्रति किलो एवं पतंजलि आयुर्वेदा गाय घी ६६५ रुपये प्रति किलोकी दरसे बाजारमें आज बेच रही हैं। गांवके किसान ७५० रुपयेसे ८०० रुपये प्रति किलोकी दरसे देसी घी बेच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा आज भी कई जगहसे २० से ३० रुपये प्रति लीटरकी दरसे गाय और भैंसका दूध खरीदा जा रहा है। क्या इन्हें पता नहीं है कि यह श्रद्धालु और भक्तके स्वास्थ्यके साथ खिलवाड़ है। यदि इन प्रतिष्ठित मठों-मंदिरोंमें यह पाप स्वीकार्य नहीं होता तो इतनी शीघ्रतासे शुद्धिकरणका मार्ग भी नहीं निकल पाता। चुटकी बजाते ही समस्या छूमंतर करनेवाले धर्माचार्योंने बड़ी आसानीसे गंगा जलसे धो-पोंछकर समस्या दूर कर दी है। शुद्धिकरणका मार्ग प्रशस्त करनेवाले इन धर्माचार्योंने इस गोरखधंधेमें अप्रत्यक्ष सहमति व्यक्त की है। आंकड़ोंसे स्पष्ट है कि ऐसे शुद्ध देसी घीका प्रयोग कर बनाये गये लड्डुओंके प्रसादका इस्तेमाल तिरुपति देवस्थानममें धड़ल्लेसे हो रहा है। क्या श्रद्धालुओं और भक्तोंकी अप्रत्यक्ष सहमतिके बिना ऐसा संभव है। यहां गौर करनेकी बात है कि आस्थाके इस कारोबारमें लगे धर्माचार्य तो भक्तोंको मुक्तिका मार्ग बताते हुए त्रिशंकु बनानेसे भी नहीं चूकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) दूध और दुग्ध उत्पादोंकी तत्काल जांचके लिए इलैक्ट्रानिक किटके इस्तेमालको प्रोत्साहित करते हैं। इन उपकरणोंकी मददसे उपयोगसे पहले ही आसानीसे गुणवत्ता परीक्षण मुमकिन है। लेकिन औने-पौने दामपर खरीद करनेवाले ऐसा करनेके लिए नैतिक रूपसे समर्थ नहीं हैं। इसलिए किसी सप्लायरकी अपेक्षा मंदिरके प्रबंधक जिम्मेदार होते हैं। इस केसमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानमसे बड़ा दोषी कोई सप्लायर नहीं माना जा सकता। तिरुपति मंदिरका प्रबंधन राज्य सरकार करती है। देशभरमें हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका प्रबंधन राज्य सरकारके अधीन है। जिन मंदिरोंमें राज्यकी कोई दखलअंदाजी नहीं है, उनकी दशा भी ऐसी है। मिलावटखोरोंको धर्माचार्योंकी मददसे ईश्वरकी कृपा प्राप्त हो रही है। धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले आचार्य अब मिठाइयोंके बदले फल और मेवा प्रसादके रूपमें प्रयोग करने लगे हैं। **-कौशल, वाया ईमेल।**

आतंकवादीसे हमदर्दीके मायने

लेबनानमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाहकी इसरायली हमलेमें मौत हो गयी। इसरायली सेनाने हिजबुल्लाहके साथ उसके सभी कमांडरों और ऑपरेटिव्सको भी मार गिराया। जब नसरल्लाह मारा गया, तब जम्मू-कश्मीरमें चुनाव चल रहा था। एक आतंकीकी हत्याके विरोधमें कश्मीर घाटीमें सैकड़ों लोग सड़कोंपर क्यों उतरे।

❐ **डा. ओ.पी. त्रिपाठी**

विभिन्न राजनीतिक नेताओंने नसरल्लाहकी हत्याकी निन्दा की और श्रीनगरसे लोकसभा सदस्य आगा रूहुल्लाह, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और पूर्व मंत्री इमरान अंसारीने हत्याके मद्देनजर अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया, क्योंकि नसरल्लाहको 'शहीद' कर दिया गया। श्रीनगर, बडगाम, कारगिलमें व्यापक स्तरपर मातम मनाया गया। काले कपड़े पहनकर एक भीड़ने अपनी छाती पीटकर स्यापा किया। लोग बिलख-बिलख कर रोते नजर आये। कश्मीर घाटी और लद्दाखके कारगिलके विभिन्न हिस्सोंमें शिया समुदायके सैकड़ों लोगोंने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियोंने इसरायल और संयुक्त राज्य अमेरिकाके खिलाफ नारे लगाये। रैनावारी, आलमगरी बाजार, लाल बाजार, पट्टन, बडगाम और कारगिलके कुछ इलाकोंसे विरोध प्रदर्शन की खबरें आयीं। भीड़के हाथोंमें नसरल्लाहकी तस्वीरें थामी गयी थीं। लोग ईरानके सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेईके जिन्दाबादके नारे भी लगा रहे थे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्तीने सोशल मीडियापर एक पोस्टमें लिखा, 'लेबनान और गाजाके शहीदों, खासकर हसन नसरल्लाहके साथ एकजुटतामें कल अपना अभियान रद कर रही हूं। हम इस दुख और अनुकरणीय प्रतिरोधकी घड़ीमें फिलिस्तीन और लेबनानके लोगोंके साथ खड़े हैं।' रूहुल्लाहने लिखा, 'अपना अभियान बंद कर रहा हूं।' पट्टनसे चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री इमरान अंसारीने लिखा, एक शेर शहीद हो गया, उसकी दहाड़ अब भी बाकी है। हर धड़कनमें उसका संघर्ष कायम है। मैं शहीद सैयद हसन नसरल्लाके सर्वोच्च बलिदानको सम्मान देनेके लिए सभी प्रचार गतिविधियोंको स्थगित कर रहा हूं।' पीपुल्स कॉन्फ्रेंसके प्रमुख सज्जाद लोनने लिखा, 'शहीद सैयद हसन नसरल्लाहकी सर्वोच्च शहादतपर शोक व्यक्त करता हूं। अल्लाह उनकी आत्माको शांति दे और हमें अत्याचारियोंके खिलाफ उनकी विरासतको आगे बढ़ानेकी शक्ति प्रदान करे।' हुर्रियत प्रमुख मीरवाइज उमर फारूकसे जुड़ी संस्था मीरवाइज मंजिलने भी नसरल्लाहको श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'शहीद मरते नहीं। वे प्रेरणाके रूपमें हमारे दिलोंमें जीवित रहते हैं।' सोनावारीसे एनसी उम्मीदवार हिलाल अकबर लोनने भी अपना अभियान रद करते हुए कहा, 'सैयद हसन नसरल्लाहकी शहादतके कारण कलके हमारे कार्यक्रम रद कर दिये गये हैं। हमारा दिल टूट गया है।' इस वक्त भारत बड़े खतरनाक दौरमें है। हिन्दू और मुसलमानमें विभाजन गहराता जा रहा है। मुसलमानको दूसरे मजहब और समुदायकी चिन्ताओं और दुरावस्थाओंसे कोई सरोकार नहीं है। कई राज्योंमें मंदिर बनाम अवैध मस्जिदके विवाद उग्र होते जा रहे हैं। हालात यहांतक सांप्रदायिक हो गये हैं कि हिजबुल्लाहका घोषित, घोर आतंकी सरगना नसरल्लाह भारतके मुसलमानोंको अपना 'भाई', 'दिलोंका राजा' लगता है। छोटे-छोटे बच्चोंके मुंहसे नारे बुलवाये गये- 'एक नसरल्लाह मारोगे, हर घरसे नसरल्लाह निकलेगा।' अमेरिकाको आग लगा दो' 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे भी गूंज रहे थे। यह सिलसिला कश्मीर घाटीसे उत्तर प्रदेशके लखनऊ और सुलतानपुरतक और छत्तीसगढ़की राजधानी रायपुरतकमें जारी रहा। भीड़ हाथोंमें मोमबत्तियां जलाये मार्च निकालती दिखाई दी, मानो भारतका अपना कोई देशभक्त या सैनिक 'शहीद' हो गया है! नसरल्लाह न तो भारतीय था और न ही किसी धर्मयुद्धका योद्धा था, जिसके मारे जानेपर ऐसा मातम मनाया जा रहा है! मासूम बच्चोंको क्या पता कि उसकी मौत क्यों और कैसे हुई? उन्हें नफरतकी घूंट पिला दी गयी, लिहाजा वे नसरल्लाहके अभिनन्दनमें नारे लगाने लग पड़े। नसरल्लाह तो 'इस्लामी जेहादी' भी नहीं था, लेकिन दुनियामें असंख्य हत्याओंका सूत्रधार जरूर था। भारतमें एक घोषित, घोर आतंकी के हमदर्द रहे हैं, यह कई मामलोंमें सामने आया है-याकूब मेमनसे अफजल गुरुतक। भीड़ बुरहान वानी सरीखे आतंकियोंके जनाजे और सुपुर्द-ए-खाकके दौरान इस कदर इकट्ठा होती रही है मानो किसी क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानीकी 'अंतिम संस्कार यात्रा' हो! मुसलमान पहले इस्लामी और मुसलमान हैं, बादमें भारतीय हैं। अभिव्यक्तिकी आजादी, ऐसे प्रदर्शनोंकी आजादी और सबसे बड़े लोकतंत्रने हिन्दू-मुस्लिम विभाजनको लगातार गहरा किया है। मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षताके गलत मायने निकाले जाते रहे हैं। पड़ोसी देश बंगलादेशके मौजूदा हालात सामने हैं। वहां असंख्य हिन्दुओंकी हत्या ही नहीं की गयी, बल्कि उत्पीड़न इतनी पराकाष्ठातक पहुंच चुका है कि हिन्दुओंको बंगलादेश छोड़कर चले जानेका वक्त तय कर दिया गया है। बंगलादेशकी यूनिवर्सिटीसे दो हिन्दू प्रोफेसरोंको नौकरीसे निकाल दिया गया है। हिन्दुओंकी पूजा और पर्व मनानेपर पाबंदी थोप दी गयी है। बंगलादेश 'इस्लामीस्तान' बन गया लगता है। इन हालातपर भारतीय मुसलमान, खासकर नसरल्लाह जैसोंके हमदर्द, न तो मातम मना रहे हैं और न ही प्रतिक्रियामें कोई सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें हिन्दुओंसे कोई सरोकार नहीं है, जबकि वे भारत मूलके ही हैं। क्या हिन्दुओंके साथ 'भाईचारा' महज दिखावटी और बयानबाजीका ही है? दुनियामें मुसलमानोंकी दूसरी सबसे बड़ी आबादी, करीब २१ करोड़, भारतमें रहते हैं। वे कई मायनोंमें एक ताकतवर वोट बैंक हैं। यदि ऐसे देशमें मुस्लिम आबादी घोषित आतंकवादी नसरल्लाहके मारे जानेपर मातम मनाती है तो उसके कई संकेत हो सकते हैं। महज चुनावके लिए इतने आयोजन नहीं किये जा सकते। यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सरीखी पार्टियां ही ऐसे मातमी प्रदर्शन आयोजित कराती हैं तो यह देशद्रोह भी है। सवाल है कि क्या इतने बड़े समुदायको नियंत्रित किया जा सकता है? छोटे-छोटे मुद्दोंपर हंगामा बरपने लगता है। मुस्लिम बहुसंख्यक होनेकी धमकियां दी जाती हैं। ये भारतके लिए 'खतरनाक संकेत' हैं, क्योंकि उसकी आबादीके दो प्रमुख घटकोंके बीच ही तनावकी स्थितियां हैं। इनपर सरकारको गम्भीरतासे मंथन करना होगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको भी पूरी तरह नकेल देनी होगी। कश्मीर घाटीमें रोज कहीं न कहीं आतंकवादियों और पुलिसकी मुठभेड़ें हो रही हैं। इनमें आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं और हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। आखिर कब यह आतंक खत्म होगा। राजनीतिक दलोंको दहशतगर्दोंके समर्थनसे बाज आना चाहिए। देश आज विकासके रास्तेपर आगे बढ़ रहा है तो कई लोगोंके पेटमें दर्द हो रहा है। किसी दहशतगर्द या आतंकीका समर्थन किसी भी सूरतमें जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी हरकतें देशके अमन और चैनके लिए खतरेका संकेत हैं। वहीं ये हरकतें सोचनेको भी मजबूर करती हैं कि इन सबके पीछे कोई वोट बैंककी राजनीति है या फिर देश तोड़नेकी कोई गहरी बाहरी और आंतरिक साजिश। जो भी ऐसी घटनाओंकी गहरी छानबीन और पड़ताल होनी चाहिए। देशके अन्दर बैठकर किसी गैर-मुल्कके आतंकीका समर्थन करनेवाली भीड़ अपने देशके प्रति कितनी वफादार होगी ये बात सोचने वाली है। देशकी एकता बनी रही इसका प्रयास सबको करना चाहिए और गलतका साथ देनेकी आदतसे दूरी बनाये रखनी चाहिए।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादको भी पूरी तरह नकेल कसनी होगी। कश्मीर घाटीमें प्रतिदिन आतंकवादियों और पुलिसकी मुठभेड़ होती है। इनमें आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं। आखिर कब यह आतंक खत्म होगा। राजनीतिक दलोंको दहशतगर्दोंके समर्थनसे बाज आना चाहिए। देश विकासके रास्तेपर अग्रसर है तो कई लोगोंके पेटमें दर्द हो रहा है। किसी दहशतगर्दका समर्थन किसी भी सूरतमें जायज नहीं है। ऐसी हरकतें देशके अमन-चैनके लिए खतरेका संकेत हैं। ये हरकतें सोचनेको भी मजबूर करती हैं कि इन सबके पीछे कोई वोट बैंककी राजनीति है या फिर देश तोड़नेकी गहरी साजिश।

बेहतर नीतियोंकी आवश्यकता

दुनियामें हर क्षेत्रमें लगातार विकास हो रहा है। यह विकास कई तरहकी समस्याओं और संकटोंको आमंत्रित कर रहा है वहीं, कई समस्याओंको हल करनेमें भी अहम रोल अदा कर रहा है। लेकिन नये विकाससे समस्याओंका दौर भी चलता है।

❐ **अखिलेश आर्येन्दु**

दुनियामें हर क्षेत्र में विकास लगातार हो रहा है। यह विकास जहां कई तरहकी समस्याओं और संकटोंको आमंत्रित कर रहा है वहींपर समस्याओंको हल करनेमें भी अहम रोल अदा कर रहा है। लेकिन दुनियामें नये विकासकी वजहसे समस्याएं और संकटोंका दौर लगातार चलता रहा है। इसलिए इसपर शिद्दतसे गौर करनेकी जरूरत है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचरकी लिविंग प्लैनेट शीर्षकसे प्रकाशित रिपोर्टके मुताबिक आदमीके संसाधनोंकी मांग नेचरकी भरण-पोषण क्षमतासे बहुत ज्यादा है। दुनियामें जबसे मल्टीनेशनल कम्पनियों और न्यू बाजारवादी शक्तियोंका उदय हुआ, उसके बादसे ही नेचुरल रिर्सोसेसके बेतहासा इस्तेमाल होनेकी प्रवृति बढ़ी है। नेचुरल रिर्सोसके बेतहासा दोहनकी वजहसे नये तरहके आसन्न संकट दिखायी पड़ने लगे हैं। साथ ही पलूशनका संकट विश्वव्यापी संकटके रूपमें सामने आने लगा है। इसके बावजूद प्राकृतिक संसाधनोंके बेतहासा दोहनके प्रति किफायत बरते जानेकी प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। प्राकृतिक संसाधनोंके बेतहांसा दोहनके कारण जलवायु परिवर्तन और ऋतुचक्रमें अमूलचूल बदलावका होना यह बताता है कि प्रकृतिका छेड़छाड़ इनसानके लिए भारी पड़ सकता है। ग्लेशियरोंके पिघलने, सुनामी, बर्फीले तूफान, अकाल और बिना मौसम बरसातकी समस्या इसके साफ संकेत हैं।

पिछले तीन दशकोंसे वैज्ञानिक इस बातको लेकर चिंतित रहे हैं कि नेचर रिर्सोसेसके खत्म होनेके बाद इनके विकल्पके रूपमें किन चीजोंका इस्तेमाल किया जायगा और प्रकृतिमें हो रहे बदलावोंका असरके गम्भीर परिणामको क्या रोक पाना मुमकिन हो पायगा। संयुक्त राष्ट्र संघ प्राकृतिक संसाधनोंके बढ़ते अंधाधुंध दोहनकी वजहसे खासा चिंतित है। कोयला ज्यादासे ज्यादा दो सौ साल, पेटोलियम पदार्थ पचास साल, पानी पचास साल और खनिज पदार्थोंका भण्डार पचास सालसे ज्यादा चलनेवाले नहीं हैं। पानीकी विकट समस्याके कारण भविष्यमें 'जल-युद्ध' युद्ध छिड़ सकता है। खास कर पश्चिम एशियामें जहां पानीकी बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। प्राकृतिक सम्पन्नताके नजरियेसे देखा जाय तो भारत सबसे ज्यादा मालामाल है। नेचुरल संसाधनोंका बेतहासा दोहन कई तरहकी समस्याएं और संकटकी तरफ इशारा करते हैं। गौरतलब है जल, जंगल और जमीनपर आया संकट इसीका हिस्सा है। इस बाबत जागरूकता फैलानेकी कोशिशें भी की जाती रही हैं, बावजूद लोगोंमें जागरूकता नहीं आयी है। पानीके बेतहासा इस्तेमालसे मुल्कके हजारों गांवों और शहरोंमें अननेचुरल जल संकट पैदा हो गया है। गौरतलब है देशके कई इलाकोंमें तो सालके बारह महीने सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। पानीके अलावा खादान्नकी कमीका रोना सरकार आये दिन रोती रहती है और इसका आड़ ले विदेशोंसे खादान्न आयात किया जाता है। लेकिन खादान्नकी समस्याका कारण पैदावारकी कमी नहीं, बल्कि प्रबंधनकी खामीकी वजहसे विचौलियों द्वारा पैदा किया हुआ आर्टीफिशियल संकट है। देशकी हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है। इसको सुधार कर तिलहन और दलहनकी समस्यासे निजात मिल सकती है। केन्द्र और राज्य सरकारें तिलहन और दलहन फसलोंकी पैदावार बढ़ानेके लिए कई योजनाएं शुरू कर चुकी हैं, लेकिन उन योजनाओंके बाद भी तिलहन और दलहन कमीको पूरा किया जा सका है।

बिहार, असम और पूर्वोतरके कई राज्योंमें प्रबंधनकी विफलताकी वजहसे हर साल बाढ़से जन-धन बेतहासा नुकसान हो जाता है। बाढ़से खेतोंकी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियोंके जरिये समुदरमें पहुंच जाती है। इससे पैदावारपर भी जबरदस्त असर पड़ता है। बाढ़की वजहसे हर साल मेढ़बंदी करना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। पूर्वोत्तरसे पलायनकी वजह बाढ़ और सूखा भी है। बिहारकी सड़कोंकी खस्ता हालातकी एक वजह बाढ़ भी है। बिहारमें जल प्रबंधनकी बहुत जरूरत है। यदि यहां जल प्रबंधन हो जाय तो पीनेके साफ पानीकी किल्लत दूर हो जायगी, वहींपर खेती और रोजमर्राकी तमाम जरूरतें पूरी हो सकेंगी। नेचुरल रिर्सोसका मनमाना दोहनकी वजहसे कई राज्योंमें ये खत्म हो गये हैं या खत्म होनेके कगारपर हैं। केन्द्र और राज्य सरकारोंका जल, जंगल, जमीन और दूसरे नेचुरल रिर्सोसके संरक्षण दावा खोखला साबित हो रहा है। गौरतलब है, ग्लोबलाइजेशनके बाद उदारीकरण और निजीकरणके नामपर केन्द्र और राज्य सरकारोंने मल्टीनेशनल कम्पनियोंको नेचुरल रिर्सोसके दोहनकी खुली छूट दी। उसका नतीजा है, देशका बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गया या खत्म होनेके कगारपर है। इसके अलावा राजनेताओं और भू-माफियोंके जरिये संसाधनोंपर जो डाका डाला जा रहा है, वह तो अत्यंत भयावह है। जमीन और खदान माफियोंकी मिलीभगतसे धरतीका बहुत बड़ा हिस्सा झील और पोखरमें तबदील होता जा रहा है। जमीनसे कीमती पत्थर, रत्न, बालू, रेत और तमाम रासायनिक वस्तुओंके बेतहासा दोहनसे पर्यावरण सहित कई समस्याएं पैदा हो गयी हैं। नेचुरल संसाधनोंके संतुलित इस्तेमालको लेकर आम आदमीमें संवेदना पैदा करना कारगर हो सकता है। इसमें केन्द्र, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आन्दोलनोंकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पश्चिमी जीवनशैली 'यूज एंड थ्रो' के अंधानुकरणसे बचना होगा और भारतीय अपरिग्रह वाली संस्कृति उचित उपयोग और सबका संरक्षण और 'नेचर इज माई मदर' की विचार धाराको हर फेमलीमें पहुंचानेकी जरूरत है। जाहिर है, आनेवाली पीढ़ीके लिए हमारा दायित्व क्या है हमें उसी तरह समझना होगा जिस तरहसे हमारे पूर्वज अपरिग्रहके सिद्धांतको पालन करते हुए हमें नेचरका अकूत भंडार हमारे लिए सुरक्षित छोड़ गये थे। नेचुरल संसाधनोंके दोहनकी प्रतियोगिता सभी देशोंमें छिड़ी दिखाई देती है। उसके असरको हमें समझनेकी बहुत जरूरत है। दरअसल सारी समस्या प्रबंधनकी जानकारी न होनेके कारण है। एक बेहतर जिन्दगीमें किस चीजकी जरूरत कितनी, किस प्रकार और कब होती है और इनका इस्तेमाल किस तरहसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और दूसरोंको हम इससे कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, इसपर गौर करनेकी जरूरत है। इसे जबतक हम बेहतर तरीकेसे समझेंगे नहीं, समस्याओंका समाधान नहीं हो सकता है। गांवोंकी धरोहर कही जानेवाले जलस्रोत, बगीचे, वन, झीलें और अन्य नेचुरल संसाधन लगातार खत्म किये जा रहे हैं। शहरोंमें तो तकरीबन खत्म हो गये हैं। ऐसेमें हम पूरी तरह आर्टीफिशियल संसाधनोंपर निर्भर होनेके लिए मजबूर हो गये हैं। यहांतक कि हवा, पानी और ऊर्जाके हर स्रोतको हम कृतिक ढंगसे बनाकर या परिवर्तित-रूपमें इस्तेमाल करनेके लिए मजबूर हो गये हैं और यह आर्टीफिशियल लाइफ सोच हमारी जिन्दगीका हिस्सा बन गयी है। गौरतलब है आर्टीफिशियल लाइफस्टाइल और सोचने लगातार नयी-नयी समस्याओंको जन्म दिया है और जैसे-जैसे आर्टीफिशियल सोच बढ़ रही है वैसे-वैसे नयी-नयी समस्याएं पैदा हो रही हैं।

नवरात्रका संदेश

❐ **सलिल पांडेय**

नवरात्र पर्वके अवसरपर साधना-उपासना तथा व्रत आदिके विधानमें सनातन संस्कृतिके प्रणेता ऋषियोंकी उस व्यापक दृष्टिकी झलक मिलती है जिसके तहत मनुष्यको निरन्तर उन्नत जीवन जीते रहनेका अभ्यास करनेका विचार रहा है। नौ दिनोंके नवरात्र पर्वको वे नवप्रकाश पर्व भी कह सकते थे लेकिन इसमें रात्रि शब्द जड़नेका मतलब अंधकारपर विजय प्राप्त करनेका सन्देश निहित है। नवरात्रके नौ दिनको जन्म देनेवाली मांके गर्भमें नौ माह और नौ द्वारोंवाले मनुष्यके लिए दस दिशाओंसे युक्त भौतिक जगतमें आगमन और उसपर विजय प्राप्त करनेके सन्दर्भसे भी लिया जा सकता है। मनुष्य परमानन्द स्वरूप ईश्वरका अंश है। गोस्वामी तुलसीदासने रामचरितमानसमें ईश्वर अंश जीव अबिनासी, चेतन, अमल, सहज, सुखरासी चौपाईमें इसका उल्लेख भी किया है। अध्यात्म-जगत सृष्टिके अविनाशी स्वरूपकी व्याख्या की है, जिसमें प्रथम बिन्दु-सृष्टि और द्वितीय नाद सृष्टि। नाद सृष्टिपर आधिपत्यके चलते ही मनुष्य धरतीके समस्त जीवों और जड़ पदार्थोंका अधिष्ठाता भी है। नवरात्रमें श्रीदुर्गासप्तशतीकी कथा भी मनुष्यको सजग और सतर्क रहनेकी प्रेरणा देती है। कथा है कि भगवान विष्णु योगनिद्रामें थे तब उनके एक कानसे मधु और दूसरेसे कैटभ निकला जो सृष्टिकर्ता ब्रह्माको मारनेके लिए उद्यत हुआ। मनुष्य ईश्वरका अंश है तो उसके दोनों कानोंसे निकलनेवाले मधु और कैटभ नामक दैत्योंपर विचार जरूरी है। मधु शब्दका आशय मिठास और कैटभका आशय कीटाणुसे है। मधु (शहद) जिस वृक्षमें होता है वहां कीटाणुके रूपमें मधुमक्खियोंका जमावड़ा रहता है। यदि मधु (शहद) के लिए सतर्कता नहीं बरती गयी तो मधुमक्खियोंका आक्रमण भी हो जाता है। शहद पानेके लिए विशेष तरीका अपनाना पड़ता है। इस प्रसंगको भौतिक जगतकी मिठासके रूपमें देखा जाय तो जन्मके पूर्व मांके गर्भमें प्रेम-स्नेह, करुणा, आह्लादके बीच पला शिशु सृष्टिमें आनेके बाद जब बड़ा होकर भौतिक मिठासके लिए कीटाणुओं जैसा आचरण करने लगता है तब वह संकटमें पड़ जाता है। दस वर्षतकके बच्चोंको भगवान स्वरूप कहा है। इसीलिए नवरात्रमें देवीके रूपमें दस वर्षकी कन्याओं एवं भगवान गणेशके रूपमें बालकोंकी आराधनाका विधान किया है। स्पष्ट है कि इस उम्रके बाद बच्चोंको विशेष संस्कार दिया जाना चाहिए तथा नकारात्मकताके कीटाणुओंसे बचानेके लिए सजग रहना चाहिए। जब घरके अभिभावक नवरात्रमें खुद नकारात्मक प्रवृत्तियोंसे दूर रहेंगे तभी बच्चोंपर इसका प्रभाव पड़ेगा। मनुष्यकी प्रवृत्तियां ही मां दुर्गा हैं जो किसी नकारात्मक दैत्य रूपी प्रवृत्तियोंसे युद्ध करती है। ऋषियोंकी मंशाकी गहराइयोंमें उतरकर जीवनको उन्नत एवं ऐश्वर्यपूर्ण बनानेका सन्देश देता है।

पशु भी चाहते हैं आजादी और प्रेमपूर्ण व्यवहार

❐ **चेतनादित्य आलोक**

बढ़ती जनसंख्या और घटती वन-संपदाने जिन कुछ प्रमुख समस्याओंको जन्म दिया है, उनमें सर्वाधिक चिन्तनीय और घातक समस्या वन्य पशुओंका लगातार बढ़ता हुआ आतंक है। उत्तर प्रदेशके सीमावर्ती जिले बहराइचका प्रकरण सामने है, जहां मार्च २०२४ में शुरू हुए भेड़ियोंके खूनी हमलोंके सर्वाधिक शिकार इलाकेके छोटे-छोटे बच्चे हुए। इन हमलोंमें लगभग दस बच्चों समेत कमसे कम एक दर्जन लोगोंकी मौत हो चुकी है, जबकि ४० से अधिक लोग घायल हुए हैं। दुर्भाग्यसे घायलोंमें भी अधिकतर बच्चे ही हैं। वैसे देखा जाय तो भेड़िये ही नहीं, बल्कि बेहद खूंखार और भयावह वन्य पशुओंका मानव बस्तियोंमें अतिक्रमण और उनके द्वारा मनुष्यों, विशेष रूपसे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओंपर हमलेकी घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल देशभरमें जंगलोंकी बेतरतीव कटाईके कारण वन्य पशुओंका आशियाना दिनोंदिन उजड़ता जा रहा है। आज विश्वकी कुल जनसंख्या आठ अरब (आठ अरब साढ़े १७ करोड़) से भी अधिक हो चुकी है और प्रत्येक वर्ष इससे दो गुनासे भी ज्यादा लगभग १८ अरबतक वृक्षोंकी कटाई हो रही है। पेड़ोंकी इस अंधाधुंध कटाईकी भरपाई किये जानेका एक ही तरीका हो सकता है और वह है तीव्र गतिसे नये पौधोंका रोपण और उनकी देखभाल करना। हालांकि उन पौधोंके पेड़ बननेमें कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वास्तवमें पौधरोपणकी जो वर्तमान दर और गति है, उससे लगातार नष्ट किये जा रहे जंगलोंके एवजमें नये जंगल उगा पाना संभव नहीं है। जाहिर है कि वन्य पशुओंके प्राकृतिक रहवास और पर्यावरण दोनोंको बचानेके लिए पौधरोपणकी गतिको हमें इस हदतक बढ़ाना होगा कि जितने वृक्ष प्रत्येक वर्ष दुनियाभरमें काटे जाते हैं, कमसे कम उससे डेढ़ गुनातक पौधे तो अवश्य ही लगाये जायं, जबकि फिलहाल प्रत्येक वर्ष १८ अरब काटे जानेवाले वृक्षोंकी तुलनामें दुनियाभरमें मात्र पांच अरब पौधे ही लगाये जा रहे हैं। यह विडंबना ही है कि भारतमें भी वृक्षोंकी अंधाधुंध कटाई जारी है। लोकसभामें एक सवालके जवाबमें केन्द्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादवने २१ मार्च, २०२२ को बताया था कि वर्ष २०२०-२१ के दौरान भारतमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओंके निर्माण और विकासके लिए लगभग ३१ लाख पेड़ काट दिये गये। वन (संरक्षण) अधिनियमके अंतर्गत काटे गये पेड़ोंके बदलेमें प्रतिपूरक वनीकरणकी योजना चलाकर मोदी सरकारने ३५९ करोड़ रुपयेकी लागतसे ३.६ करोड़से अधिक पौधे लगाये, जो नाकाफी प्रतीत होते हैं, क्योंकि फिलहाल इससे संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि उनमेंसे कितने पौधे बचाये गये और कितने नष्ट होनेके लिए छोड़ दिये गये। फिलहाल वनोंकी अंधाधुंध कटाईके कारण दिनोंदिन वन्य पशुओंका प्राकृतिक रहवास सिकुड़ता जा रहा है, इससे इनके लिए भोजन-पानीकी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। इसीलिए वन्य पशु भोजन-पानीकी तलाशमें मानव बस्तियोंकी ओर पलायन करनेके लिए मजबूर हुए हैं। वैसे सारे भेड़िये आदमखोर नहीं होते। हालांकि ये स्वभावसे खूंखार और प्रतिशोध लेने वाले होते हैं। इसलिए ये अपने शत्रुओंसे चुन-चुनकर बदला लेते हैं। आजसे लगभग २५ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेशके जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलोंमें सई नदीके किनारे भेड़ियोंके हमलोंमें इलाकेके ५० से अधिक मासूम बच्चोंकी मौत हो गयी थी। उस समय पड़ताल करनेपर यह पता चला था कि कुछ इनसानी बच्चोंने भेड़ियोंकी एक मांदमें घुसकर उनके दो बच्चोंको मार डाला था, जिसके प्रतिशोध स्वरूप भेड़ियोंने बच्चोंको मौतके घाट उतार दिया था। उस दौरान वन विभागके अधिकारियोंने कुछ भेड़िये पकड़े भी थे, लेकिन उनके आदमखोर जोड़ा बदला लेनेके मिशनमें लगातार कामयाब भी होता गया। हालांकि बादमें उन्हें वन विभागके कर्मचारियों द्वारा गोली मार दी गयी और अंतत: भेड़ियोंका खूनी आतंक खत्म हो पाया था। गौर करें तो इस बार भी बहराइचकी घटनाओंमें भेड़ियोंका वही व्यवहार वही पैटर्न सफल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए इस आशंकासे इनकार नहीं किया जा सकता कि भेड़िये किसीके द्वारा अपने बच्चोंको नुकसान पहुंचाने या उनकी हत्या करनेका बदला ले रहे हों। बहरहाल दु:खकी बात यह है कि एक बार फिर इन आदमखोर भेड़ियोंकी जान खतरेमें आ गयी है, क्योंकि शासन-प्रशासनकी ओरसे इन्हें गोली मारनेका आदेश दे दिया गया है। वैसे भेड़ियोंके विरुद्ध की जानेवाली सरकारी काररवाइयोंपर गौर करें तो उनके जीवनका सर्वाधिक स्याह पक्ष अंग्रेजोंके समयका है, जब ब्रिटिश सरकारकी ओरसे भेड़ियोंको मारनेका बड़ा अभियान चलाकर ४० सालोंमें एक लाखसे भी अधिक भेड़ियोंको शिकारियोंने मार डाला था और ब्रिटिश राजकी तरफसे ईनाम भी प्राप्त किया था। देखा जाय तो मनुष्य और वन्य पशुओंके बीच जारी संघर्षोंका यह सिलसिला बेहद गम्भीर और चिन्ताजनक है। इसलिए समय रहते इसका हल ढूंढ़ना जरूरी है। अन्यथा यह समस्या अत्यंत विकराल रूप भी ले सकती है। ऐसेमें जरूरी है कि केन्द्र और राज्य सरकारें वन्य प्राणी विशेषज्ञोंकी सलाह लेकर वन्य पशुओंके प्राकृतिक आवासोंको संरक्षित करने तथा बड़े स्तरपर वनीकरण अभियान चलाकर वनोंके विकास करनेकी दिशामें कुछ ठोस और सकारात्मक कदम उठायें, ताकि हमारे वन्य साथी आजादीसे अपने घरोंमें बेफिक्र होकर रह सकें। संभव है कि इन प्रयासोंके फलीभूत होनेमें कई वर्ष लग जायं, लेकिन इस दौरान एक कार्य किया जा सकता है, वह है इन वन्य प्राणियोंके साथ प्रेमपूर्ण आचार और व्यवहार करना। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि इन वन्य पशुओंके विरुद्ध क्रूरताके बदलेमें दयाका भाव दर्शाया जाय और इनको लाड़-प्यार दिया जाय तो मनुष्योंके प्रति इनके हिंस्र व्यवहारोंमें भी परिवर्तन आ सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भविष्य के लिए संधि को मंजूरी

गैर-बराबरी और गरीबी का संबंध आर्थिक नीतियों से है, जिनमें परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर है। इसीलिए ये संधि व्यावहारिक रूप से कोई फर्क डाल पाएगी, इसकी उम्मीद नहीं जगी है। बहरहाल, सदिच्छाओं का भी अपना महत्त्व होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के लिए संधि को मंजूरी मिल गई है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस संधि में दुनिया को एकजुट करने की बात कही गई है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र ने विश्व हित की अपनी इच्छा जताई है। लेकिन विडंबना यह है कि आज दुनिया एकजुट होने के बजाय बंटती नजर आ रही है। जिस तरह का टकराव और कड़वाहट है, वैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही कभी दिखा हो।फिर भी, कहा जा सकता है कि प्रतिकूल स्थितियों में भी आशा और प्रयास को तिलांजलि नहीं दी जानी चाहिए। इस लिहाज से संयुक्त राष्ट्र की ताजा पहल प्रशंसनीय है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने 193 सदस्यों वाली महासभा को इस संधि को मंजूर करने के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि इस संधि से जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, गैर-बराबरी और गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए देशों के एकजुट होने का रास्ता खुला है, जिससे दुनिया के आठ अरब लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। रविवार को शुरू हुए दो दिवसीय भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान 42 पेज की संधि को अपनाया गया। संधि को अपनाने को लेकर महासभा की बैठक की शुरुआत तक संशय बना हुआ था। स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि महासचिव गुटेरेश ने तीन अलग-अलग भाषण तैयार किए थे- एक पारित हो जाने के लिए, एक नामंजूर हो जाने की स्थिति के लिए, और एक उस स्थिति के लिए जब परिणाम स्पष्ट न हो। अंततः उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। यहां तक सब ठीक है। लेकिन मुद्दा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं की वजह उपभोग बढ़ाने पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जिस पर समझौता करने के कोई देश तैयार नहीं है। ना ही समस्या से निपटने के लिए गरीब देशों को वित्तीय मदद देने का अपना वादा धनी देशों ने निभाया है। इसी तरह गैर-बराबरी और गरीबी का संबंध आर्थिक नीतियों से है, जिनमें परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर है। इसीलिए ये संधि व्यावहारिक रूप से कोई फर्क डाल पाएगी, इसकी उम्मीद नहीं जगी है। बहरहाल, सदिच्छाओं का भी अपना महत्त्व होता है।

योगी जी का नया फरमान

योगी जी ने पिछले दिन फिर आदेश निकाला है कि खान-पान वाले अपने मालिक और मैनेजर का नाम लिखेंगे । सभी कर्मचारियों के नाम भी घोषित होना चाहिए ? खाना बनाने वाले मास्क और दस्ताना पहनें । कुछ समय पहले कांवड़ के समय में योगी जी ने आदेश निकाला था कि सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले, यहाँ तक कि ढेले वाले भी नाम घोषित करेंगे । योगी जी का आरोप था कि बहुत से मुसलमान अपनी दुकान का नाम हिन्दू देवी देवताओं के नाम पर रख लेते हैं और इससे हिन्दू कांवड़िए मुसलमान की दुकान का खाना खा लेते हैं । अब हिन्दू धर्मशास्त्र के जानकारों का कहना है कि यह कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म वाले का दिया खाना खाने से कोई पथ भ्रष्ट हो जाता है । तब तो केवल ब्राह्मण के हाथ का बना खाना ही खाना चाहिए । सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी । स्वच्छता अच्छी चीज है, परन्तु इसे जाति या धर्म से जोडऩा ठीक नहीं है । कहते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के भगवान के कपड़े मुस्लिम महिलाएं सिलती हैं । अलमें भाजपा के कुछ लोग देश को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं । अब भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ । अब कुछ मुसलमानों के साथ तो हम नहीं रह सकते, फिर देश का विभाजन नहीं होता तो क्या दोनों सम्प्रदाय के लोग शांति से रह सकते थे । वीर सावरकर ने भी लिखा है कि हिन्दू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं हैं । असलियत यह है कि हिन्दू महासभा ने बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर प्रांतीय सरकार बनाई थी । असल में योगी जी साधु संत भी बना रहना भी चाहते हैं तो राजनीति भी करना चाहते हैं । देश की बहुत प्रतिष्ठित संस्था गोरखनाथ पीठ के वे अधिष्ठाता हैं । परन्तु साधु होने के कारण वे अपने पिता की मौत के बाद दाह संस्कार में शामिल नहीं हुए । अब यह दोहरी नीति कैसे चल सकती है । योगी जी दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं । अभी जो आदेश निकाला है वह पहले क्यों नहीं निकाला । असल में उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर उप चुनाव होने हैं । हिन्दी वोट साधने के लिए यह नया आदेश आया है, विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है । यह भी कहा जाता है कि वे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं । यद्यपि मोदी जी के बाद अमित शाह का ही नम्बर है । विपक्ष का यह भी आरोप है कि योगी जी और अमित शाह के बीच सम्बन्ध मधुर नहीं है । अभी कश्मीर में चुनावी भाषण देते हुए अमित शाह ने घोषणा की कि वे ईद और मोहर्रम पर फ्री गैस सिलेण्डर देंगे । असल में जम्मू कश्मीर में यदि भाजपा अपनी सरकार बनना चाहती है तो उसे कश्मीर को साधना पड़ेगा और कश्मीर में बहु संख्यक हिन्दू नहीं, मुसलमान है ।

अब राशन की चिंता से मुक्त हो रहे हैं प्रवासी मज़दूर

आरती कुमारी

देश में रोज़गार प्रमुख समस्या बनी हुई है. इसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में नज़र आता है. गांव में रहने वाली एक बड़ी आबादी रोज़गार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास करती है. ऐसे में इनके सामने अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती जन वितरण प्रणाली द्वारा मिलने वाला राशन होता है. जिसके लाभ से ये मज़दूर अक्सर वंचित हो जाते हैं. चूंकि राशन कार्ड गांव में बना होता था, ऐसे में प्रवास के कारण वह अन्य स्थान पर इससे मिलने वाला सस्ता राशन का लाभ उठा नहीं पाते थे. लेकिन केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना ने इन प्रवासी मज़दूरों की समस्या को दूर कर दिया है. अब यह मज़दूर अपने प्रवास स्थान पर भी अपने राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता अनाज खरीद कर परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देश भर में एक केंद्रीय डेटाबेस विकसित किया गया है, जिसमें हर पात्र व्यक्ति का डाटा संग्रहित होता है. यह योजना 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है. इसके माध्यम से श्रमिक अब जहां भी प्रवास करते हैं, वहीं अपने हिस्से के राशन का लाभ उठा रहे हैं. राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोकेश रविदास बताते हैं कि "मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला हूं और पिछले 20 वर्षों से परिवार के साथ काम की तलाश में राजस्थान सहित अन्य राज्यों में करता रहता हूं. जहां स्थानीय दुकानदार से राशन खरीद कर लाना पड़ता था. जो अक्सर महंगा होता था. लेकिन अब काम की जगह पर ही मेरे परिवार को पीडीएस के माध्यम से सस्ता राशन मिल जाता है. लोकेश बताते हैं कि मैं पिछले 2 साल से भीलवाड़ा के ईंट भट्टे पर काम कर रहा हूं, वहां मुझे अपना राशन स्थानीय राशन की दुकान से उपलब्ध हो जाता है." वह बताते हैं कि पहले लंबे प्रवास के कारण गांव के राशन लिस्ट से हमारा नाम भी काट दिया जाता था. जिसे दोबारा शुरू कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. लेकिन अब इस योजना के कारण हमें हमारे काम की जगह और गांव में भी राशन की सुविधा मिल जाती है. इसी ईंट भट्टे पर काम करने वाले बिहार के बांका जिले के प्रमोद मांझी बताते हैं कि पीडीएस से राशन प्राप्त करने के लिए अब हमें बार बार गांव जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम मजदूर यहीं काम करते हैं और पास के गांव से सस्ता राशन भी प्राप्त करते हैं, जिससे मेरे परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो गया है. वह बताते हैं कि पहले जब साल दो साल पर हम अपने गांव वापस जाते थे तो सरकारी राशन दुकान का मालिक कहता था कि दो साल से राशन नहीं लेने की वजह से तुम्हारा नाम काट दिया गया है. लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे. इससे हमें आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से परेशानी होती थी. लेकिन अब केवल कार्यस्थल के पास ही नहीं, बल्कि वापस गांव जाने पर भी सरकारी राशन से अनाज मिल जाता है. प्रमोद कहते हैं कि इस योजना ने रोज़गार के लिए अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले हम जैसे मज़दूरों के जीवन को आसान बना दिया है. हम पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी कम कर दिया है. वन नेशन, वन राशन योजना ने देश के कमजोर वर्गों को एक मज़बूत खाद्य सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति देश के भीतर किसी भी समय और कहीं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन प्राप्त कर सकता है. इस योजना से पहले खाद्य सुरक्षा वाले लाभार्थी केवल अपने पैतृक गांव में दर्ज राशन कार्ड से ही सस्ता अनाज खरीद सकते थे. वहीं उनके प्रवास के बाद लंबे समय तक राशन नहीं लेने के कारण गांव में दर्ज राशन लिस्ट से उनका नाम भी काट दिया जाता था. इतना ही नहीं,

पूरा सिस्टम ऑनलाइन और डिजिटल हो जाने के कारण अब इस योजना के माध्यम से राशन वितरण में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना भी कम हो गई है. इस संबंध में क्रय विक्रय सहकारी समिति धुंवाला, भीलवाड़ा के सदस्य सत्यनारायण शर्मा बताते हैं कि यह योजना वर्ष 2019 में शुरू हुई थी. इसके तहत सुविधा का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है. सबसे पहले इन मज़दूरों को सरकार द्वारा संचालित 'मेरा राशन एप' पर पंजीयन कराना होता है. जिसमें उन्हें अपने पैतृक गांव की डिटेल दर्ज करानी होती है. इसके बाद उन्हें अपने प्रवास स्थल का विवरण दर्ज कराने के साथ ही अपने फिंगर प्रिंट दर्ज कराने होते हैं. इस प्रक्रिया के पूरा होते ही उन्हें उस जगह के स्थानीय जन वितरण प्रणाली की दुकान से जोड़ दिया जाता है. वह बताते हैं कि चूंकि यह एक राष्ट्रीय योजना है और पूरी तरह से ऑनलाइन है इसलिए किसी भी मज़दूर को नए जगह नाम दर्ज कराने से पहले पैतृक स्थल से नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में वह जब वापस अपने गांव लौटते हैं तो वहां भी वह पहले की तरह ही राशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. सत्यनारायण शर्मा बताते हैं कि 'चूंकि मज़दूर कठिन परिश्रम करते हैं ऐसे में अक्सर उनके हाथों में छाले अथवा अन्य कारणों से फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो पाता है. इसीलिए राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों के फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं ताकि किसी भी सदस्य के फिंगर प्रिंट मैच कर जाने पर उन्हें राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. वह बताते हैं कि 'मेरा राशन एप' पर पंजीयन कराते समय राशन कार्ड धारकों के आंखों की पुतलियों के निशान भी लिए जाते हैं. लेकिन ज़्यादातर राशन दुकान पर इससे जुड़ी मशीन उपलब्ध नहीं होती है. इसलिए केवल फिंगर प्रिंट के आधार पर राशन वितरित कर दिया जाता है. वह बताते हैं कि प्रवासी मज़दूरों के हितों में लाभकारी होने के बावजूद इस सिस्टम में अभी भी कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है. इनमें मज़दूरों की उपस्थिति और उसी अनुसार राशन का स्टॉक रखना एक बड़ी समस्या है. अक्सर राशन स्टॉक आ जाने के बाद नए मजदूर पंजीकृत होते हैं, जिन्हें अनाज उपलब्ध कराना राशन डीलरों के लिए चुनौती बन जाती है. इसके अलावा कुछ दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी और डिजिटल प्रणाली का अभाव इस योजना की सफलता में बाधक बन रहा है. हालांकि, सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके बावजूद यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवासी मज़दूरों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है. केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है. माना जाता है कि इस योजना ने गरीबों के सामने भोजन की समस्या का हल कर दिया है. हालांकि इससे पहले भी देश में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और वंचित तबके को सस्ते में राशन उपलब्ध कराया जाता रहा है. लेकिन वन नेशन, वन राशन योजना ने न केवल लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की है बल्कि देश में एक एकीकृत और कुशल राशन वितरण प्रणाली स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इस योजना ने रोजगार के लिए पलायन करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया है.

विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने का क्रेज़ का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है

अशोक भाटिया

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इससे देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है। इससे उद्योग-धंधों के लिए श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा, देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र फंसे तो नेताओं को पता चला कि इतने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक ने हैरानी जताई। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि भारत से हरेक साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों में क्यों चले जाते हैं? यह सवाल कनाडा में जो भारत को लेकर हो रहा है उस रोशनी में पूछ जाना चाहिए। वहां जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे पहले ही भारतीयों के साथ हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय अधिक जाग चूका है और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि इजराइल में फिलहाल करीब 18 हजार भारतीय जबकि वेस्ट बैंक में करीब एक दर्जन और गाजा में तीन से चार भारतीय रह रहे हैं। जब यहाँ छात्र किसी कारण से फंसते है तो भारत सरकार को 'एयर -लिफ्ट 'का सहारा लेना पड़ता है जो परेशानी भरा होता हैं । बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत से विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने की आकांक्षा का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2016 और 2021 के बीच 26.44 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए गए। एसोसिएटेड चेम्बरर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने 13.5 अरब डालर का खर्च किया। वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डालर यानि लगभग 2 लाख करोड़ रूपए रहा और रेडसियर स्टार्टेजी कन्स्लटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डालर यानि 7 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री बी। मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया था कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4.44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने गए। एक अन्य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6.46 लाख थी, यानि 45 प्रतिशत की वृद्धि। यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत से ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 के संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है। पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है। विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके माता-पिता अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर इन युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गांवों में बड़ी मात्रा में विदेशों से धन आता था। विदेशों में पढ़ाई के इस क्रेज के चलते यह प्रक्रिया उलट हो गई है, यानि अब विदेशों से धन आने के बजाय विदेशों को धन भेजा जा रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2024 के अंत तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डालर पहुंच जाएगी, तो यह देश के लिए अत्यंत संकटकारी स्थिति का कारण बनेगा। गौरतलब है कि युवाओं का शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन, देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में पिछले दो-तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। यदि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो 1990-91 में जहां मात्र 49.2 लाख विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया, यह संख्या वर्ष 2020-21 में 414 लाख तक पहुंच गई। मोटेतौर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुणा से भी ज्यादा हो चुकी है। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि वर्ष 2021 में देश में 1113 विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान, 43796 महाविद्यालय और अन्य स्वतंत्र संस्थान 11296 थे। इसी वर्ष देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 15.51 लाख शिक्षक कार्यरत थे। देश में कई विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और कई अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं और कई 'विश्वविद्यालय सम' यानि 'डीम्ड विश्वविद्यालय' हैं। देश में कई विश्वस्तरीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी वैश्विक कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं। जहां तक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों में फीस विदेशी संस्थानों में फीस से कहीं कम है और जिन विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत नीचा है। तो सवाल उठता है कि भारी भरकम राशि खर्च कर भारत के युवा विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश क्यों लेते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि विदेशों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश लेकर वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहां तक कि इंग्लैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि वहां रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय युवा यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि इन देशों में भी रोजगार की भारी कमी है। कई देशों में वहां के स्थानीय लोग भारतीय एवं अन्य देशों से आने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें भी देखने को मिल रही हैं। देश से जाने वाले अधिकांश युवा विद्यार्थी वहां रोजगार प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं और उन्हें स्वदेश वापिस लौटना पड़ता है, जिसके कारण वे भारी कुंठा का भी शिकार हो रहे हैं। चूंकि व्यक्तिगत तौर पर विदेशों में जाने वाले युवा विद्यार्थी, पूर्व में विदेशों में जाने वाले भारतीयों की सफलता की गाथाओं से प्रभावित होकर विदेशों की ओर रूख कर रहे हैं। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे कि आज कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में, जहां वे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं, वे शिक्षा संस्थान स्वयं के आस्तित्व को बचाने हेतु भारतीय विद्यार्थियों को आसानी से अपनी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं भारतीय और अन्य देशों के अति इच्छुक विद्यार्थियों से भारी फीस ऐंठने हेतु शिक्षा की कई दुकानें भी खुल रही हैं, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को इस हेतु वास्तविकता से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे विदेशों में जाकर अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई को यूं ही न गवा दें। गौरतलब है कि पिछले लगभग दो दशकों से भारत के कई नागरिक एजेंटों के माध्यम से विदेशों में, ख़ास तौर पर खाड़ी के देशों में रोजगार की तलाश में गए और वहां उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन युवाओं के पासपोर्ट तक एजेंटों के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह-तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए।इसी तर्ज पर देश के अनभिज्ञ युवा जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस हेतु आगे आना होगा। भारत में शिक्षा का स्तर आस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे देशों के बराबर बनाना होगा ताकि हमारे विद्यार्थियों को किसी अन्य देश में जाने की नौबत ही न आए!

मेष राशिः आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है। जिसके लिये आपको ओवर टाईम करना पड़ेगा। आज अपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी, जिससे आपको काफी फायदा होगा। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बना कर खिला सकती है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवनसाथी से आज आपको कोई उपहार मिलेगा।

वृष राशिःआज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर-दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी। आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जायेंगे। छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगो को आज बड़ा मुनाफा होगा। पिता से आज आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा। आज कोई ऐसी पुरानी चीज आपके हाथ लग सकती है, जिसे पा कर आपको खुशी महसूस होगी।

मिथुन राशिःआज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आज आप अपने व्यापार को आगें बढाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। आज दोस्तों के साथ फोन पर बात कर के समय बितायेंगें। परिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में बड़े-बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग बैंक में कार्य करते है वह आज अपना काम बहुत जल्द निपटा लेंगें। लवमेटस आज साथ में समय बितायेंगे।

कर्क राशिःआज का दिन खुशियां लेकर आया है । बिजनेस में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच सकते है, लेकिन शुरू करने से पहले अपनों से बड़ों की सलाह जरूर ले लें। पारीवारिक मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे। आज आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। शाम का समय भाई बहनों के साथ हँसी-मज़ाक में बितेगा । जीवनसाथी आज आपको नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दें सकते है।

सिंह राशिःआज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। अपनी सकारात्मक सोच को सार्थक कामों में लगायें। जो लोग डांस सीखना चाहते है, वे आज सोशल मिडिया की मदद से सीखेंगे। आज घर पर किसी चीज की मरम्मत करानी पड़ेगी। महिलाओं को घर के कार्यो से राहत मिलेगी। आज बच्चे आपने माता पिता का ज्यादा ध्यान रखेंगें और उनकी बात भी मानेंगे।

कन्या राशिःआज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आज इस बात का खास ख्याल रखें की दूसरों से तभी दोस्ती करें जब उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें और उसे भली-भांति समझ लें। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पिता अपके बिजनेस में आपका सयोग करेंगें । लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। नवविवाहितों को आज घुमने जाने का मौका मिलेगा। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें।

तुला राशिःआज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको पहले किये गये छोटे-मोटे कार्यों से भी पॉजीटिव रिजल्ट मिलेगा। सफलतायें छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी। ऑफिस के कार्यो को करते समय फोकस बनायें रखें। आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे अपनी समझदारी से बखुबी निभायेंगें । जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं उनका काम अच्छा चलेगा और आपका रूका हुआ पैसा वापस मिलेगा।

वृश्चिक राशिःआज बच्चों को करियर के मामले में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें ग़ौर से सुनें, भविष्य में आपके लिये फायदेमंद रहेगी। युवाओ को बढ़िया नौकरी मिलने की सम्भावना बन रही है। कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हे पुराने किये गये कार्यो से वाहवाही मिलेगी।

धनु राशिःआज का दिन बढ़िया रहने वाला है। करीयर को बेहतर बनाने के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। संतान की सफलता के कारण, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। शाम को जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। बच्चे आज किसी जरुरी काम में अपनी माता की मदद मागेंगे। जिससे उनके काम पूरे होंगे। शारीरिक दृष्टि से आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ।

मकर राशिःकार्यक्षेत्र में आज आपको काफी हद तक सफलता हासिल होगी। पारिवारिक मामलों में आज आपको ठण्डे दिमाग़ से सोचेने की जरूरत है, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आज भाई अपने काम में आपकी मदद मांगेगे। समाज में आज आप अपने बढ़िया कार्यों के कारण पहचाने जायेंगे। मेडिकल की पढाई कर रहें छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा । घर के जरूरी कागजों का खास ख्याल रखें।

कुंभ राशिःआज कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर आपकी परफॉरमेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगें। आज सभी जरुरी काम आसानी से पूरा कर लेंगे। पिता के जरिए व्यापार में दी हुई जिम्मेदारियां आप आसानी से निभा लेंगें। इस राशि के जो लोग फर्निचर का व्यापार कर रहे है, उन्हें उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा । परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। बच्चे आज किसी खिलौने के लिए जिद्द करेंगे।

मीन राशिःआज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। जिम ट्रेनर को आज अच्छे ग्राहक मिलेंगे। आपके व्यावसायिक कौशल में तेजी आयेगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में खुद को आगे पायेंगे। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

शब्द सामर्थ्य -198

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. जीत, फतेह 3. राशन सामान बेचने वाली एक जाति, वैश्य 6. मुर्गी की जाति की एक पक्षी, आधा... आधा बटेर 7. कमल, पंकज, भारत के एक दिवंगत प्रधानमंत्री का नाम 8. नहाने का स्थान, स्नानागार 10. ख्वाब, स्वप्न 12. बुलावा, निमंत्रण 14. तबाही, बर्बादी 17. कत्ल, वध 18. क्षतिपूर्ति, मुआवजा 19. करार, चैन, आराम 21. दृष्टि, निगाह 23. नाश करने योग्य 24. लाडला, प्यारा 25. सीताजी, जनकनंदनी।

ऊपर से नीचे

1. शादी, ब्याह 2. अनाथ, निराश्रित 3. साल, वर्ष 4. दोस्ताना, यारी 5. सुर, देव, भगवान 9. मनुष्य, इंसान, आदमी 11. पाटा जाना, चुकता करना, बात तय करना 12. कार्यक्षेत्र, गोल घेरा, वृत्त 13. अधीनता, मातहती, अधिकार 15. नगर 16. गैरजरूरी 20. दृष्टांत, सुपुर्दगी, उदाहरण 22. धरती, भूतल, धरातल।

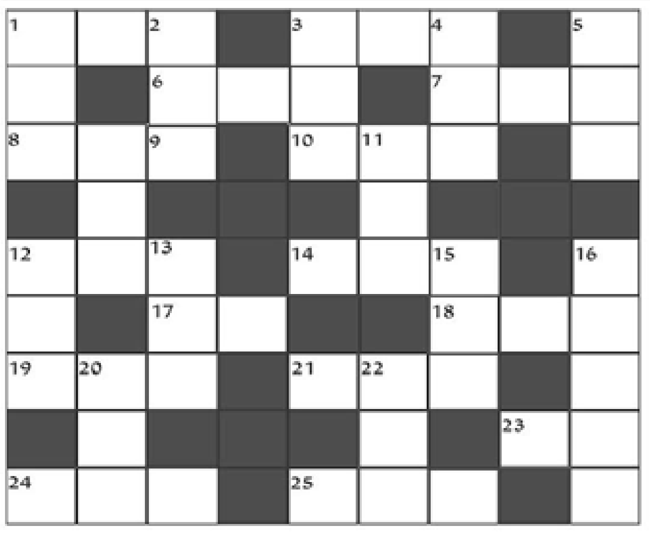

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 197 का हल

अं	त		म	री	ज			
ग	ह	न	ता		ब	र	ब	स
	की		धि	क्का	र		र	मा
	का		का		द	वा	खा	ना
प	त	वा	र		स्त	र		
ह						दा	मि	नी
ना		ए	ह	ति	या	त		लां
वा	च	क		हा			खू	ब
		ता	ब	ड़	तो	ड़		र

सूडोकु नवताल- 7209

★★★★☆ मध्यम

2	9		3	1			8	
3	6		2		7		9	
		7			6		2	1
	7		1					
1	3			4			7	2
					5		4	
6	2		4			9		
	5		6		9		1	8
	1			5	3		6	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7208 का हल

3	9	7	5	1	4	6	8	2
1	2	8	6	9	3	4	5	7
6	4	5	2	8	7	1	3	9
5	7	3	4	6	9	2	1	8
2	1	9	7	5	8	3	4	6
4	8	6	3	2	1	7	9	5
9	3	2	8	4	6	5	7	1
7	6	1	9	3	5	8	2	4
8	5	4	1	7	2	9	6	3

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

सोनम वांगचुक के साथ ऐसा बर्ताव क्यों?

लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के साथ कठोर व्यवहार कर मोदी सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? सोनम लद्दाखियों की मांगों को लेकर पहले महीना भर अनशन कर चुके हैं और अब दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सिंघु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। सवाल यह है कि सरकार सोनम वांगचुक से बात करने से क्यों बच रही है? सोनम न तो आतंकवादी हैं और न ही अलगाववादी। और न ही उनका आंदोलन अहिंसक है। सरकार उनकी मांगे माने न माने, लेकिन बात तो करे। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का बीते पांच सालों में कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे उससे पूर्ण राज्य का हिस्सा होने का लाभ भी छिन गया। सोनम यह पदयात्रा मुख्यो रूप से लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। लेह से 1 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा क़रीब एक हज़ार किलोमीटर लंबी है। सोनम को गांधी जयंती पर बापू की समाधि पर पहुंचना था। उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खुद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें हिरासत में लिए जाने जानकारी एक वीडियो पोस्ट में दी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। इसके लिए 100 पुलिस वाले हैं। कुछ का कहना है कि ये 1000 हैं।बकौल वांगचुक उनके साथ पदयात्रियों में 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग भी हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ कुछ दर्जन सेना से रिटायर्ड लोग भी हैं। वांगचुक ने आगे लिखा कि आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक सबसे शांतिपूर्ण मार्च पर थे। ध्यान रहे कि दिल्ली पुलिस ने पदयात्रा को देखते हुए 6 दिन के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को भी लागू कर दिया है। वांगचुक की इस यात्रा ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना वांगचुक से मिलीं और केन्द्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल को मिली मर्यादित शक्तियों की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि क्या लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक अधिकार मांगना ग़लत है? सोनम वांगचुक को रोकना तानाशाही है। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट किया कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाख के लोगों की हिरासत अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज़ उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? मोदीजी आपको लद्दाख की आवाज सुननी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि जो लोग शांति से डरते हैं वो लोग अंदर से डरे हुए होते हैं। उधर मोदी सरकार का का मानना है कि सोनम वांगचुक के आंदोलन के पीछे वामपंथी और कांग्रेस है। लद्दाख में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यह सोच हकीकत से मुंह छिपाने वाली है। लोगों की जायज मांगों को भी न सुनने का अर्थ है, लद्दाख में भी अलगाववादी गतिविधियों को हवा देना। लद्दाख के लोग अभी तक शांत ही रहे हैं। लेकिन केवल राजनीतिक स्वार्थ और अहंकार के चलते सोनम जैसे लोगों से बात भी न करना, नई मुसीबत को न्यौता देने जैसा है।

इसलिए जरूरी है 'एक देश, एक चुनाव' का विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार-बार चुनाव से विकास कार्य में बाधा आती है। किसी भी चुनाव की घोषणा होते ही अंतिम रिजल्ट नहीं आने तक कोई नया विकास कार्य शुरू ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि 'एक देश, एक चुनाव' के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। यहां तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था।

आरके सिन्हा

एक देश, एक चुनाव का सपना अब तो साकार होता नजर आ रहा है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमिटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। मतलब यह कि अब देश में 'एक देश, एक चुनाव' की राह का सारा व्यवधान सारा सस्पेंस दूर हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक वक्तव्य में साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 'एक देश, एक चुनाव' पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमिटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह देश मे एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। अब कमिटी की सिफारिशों पर देश की सभी राजनीतिक मंचों पर इस पर चर्चा की जाएगी। सभी नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से इस पर बात होगी। इसके बाद इसे लागू करने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार-बार चुनाव से विकास कार्य में बाधा आती है। किसी भी चुनाव की घोषणा होते ही अंतिम रिजल्ट नहीं आने तक कोई नया विकास कार्य शुरू ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि 'एक देश, एक चुनाव' के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। यहां तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था।

बेशक, एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रक्रिया की चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, क्योंकि कई चुनावों के लिए बार-बार तैयारी और कार्यान्वयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या आपको पता है कि कुछ माह पहले देश में हुए लोकसभा चुनाव में कितना खर्चा हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव पर 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब दोगुना से भी ज्यादा खर्चा आया। चुनावी खर्च पर रिपोर्ट जारी करने वाली गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अनुमान लगाया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल खर्च 55 से 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस तरह देखा जाए तो इस बार दोगुने से भी ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च किया गया है। अमेरिका ने भी साल 2020 में हुए राष्ट्रसपति चुनाव में करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए थे। क्या आपको पता है कि 1951-52 में भारत के पहले चुनाव के दौरान महज 10.5 करोड़ रुपये था? चुनाव खर्च का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया प्रचार पर खर्च किया जाता है। भारतीय राजनेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए असाधारण और नए-नए तरीके अपना रहे हैं। यह सबको पता है कि देश में बार-बार चुनाव होने से जनता और सरकारी अधिकारियों का समय और संसाधन बर्बाद होता है। एक साथ चुनाव कराने से यह सब नहीं होगा। एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता में सुधार आएगा।क्योंकि, सरकार को बार-बार चुनावों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक साथ चुनाव होने से प्रशासन पर भी काम का दबाव कम होगा और वे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 'एक देश, एक चुनाव' से कई मसलों का हल हो जाएगा। चुनावों की अवधि कम हो जाने से, शासन और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान बेहतर ढंग से केंद्रित किया जा सकेगा। यह जानना जरूरी है कि भारत में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। साल 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव साथ ही कराए गए थे, क्योंकि आज़ादी के बाद विधानसभा के लिए भी पहली बार ही चुनाव हो रहे थे। उसके बाद साल 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए थे। यह सिलसिला पहली बार उस वक़्त टूटा था जब केरल में साल 1957 के चुनाव में ईएमएस नंबूदरीबाद की वामपंथी सरकार बनी। साल 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभा जल्दी भंग हो गई और वहां प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने मनमाने ढ़ंग से राष्ट्रपति शासन लगा दिया।इसके अलावा साल 1972 में होनेवाले लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराए गए थे। साल 1967 के चुनावों में कांग्रेस को कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कई राज्यों में विरोधी दलों या गठबंधन की सरकार बनी थी। इनमें से कई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं और विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई। वैसे यह बात भी है कि अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इसके लिए मौजूदा संख्या से तीन गुना ज़्यादा ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन, वह तो एक बार ही होने वाला खर्च होगा।क्या बाकी देशों में भी 'एक देश, एक चुनाव' वाली व्यवस्था लागू है ? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि में 'एक देश, एक चुनाव' वाली स्थिति हैं। अमेरिका में हर चार साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। भारत की ही तरह फ्रांस में संसद का निचला सदन यानी नेशनल असेंबली है। वहां नेशनल असेंबली के साथ ही संघीय सरकार के प्रमुख राष्ट्रपति के साथ ही राज्यों के प्रमुख और प्रतिनिधियों का चुनाव हर पांच साल में एक साथ कराया जाता है। स्वीडन की संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव हर चार साल में एक साथ होते हैं। यहां तक कि नगरपालिका के चुनाव भी इन्हीं चुनावों के साथ होते हैं। वैसे तो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमंस के चुनाव हर चार साल में कराए जाते हैं, जिसके साथ कुछ ही प्रांत स्थानीय चुनाव को संघीय चुनाव के साथ कराते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जैस देश के लिए 'एक देश, एक चुनाव' का विचार बहुत ही उपयुक्त और आदर्श है। पर दिक्कत यह है कि हमारे विपक्षी दल इतने शानदार विचार की बिना सोचे समझे राजनीतिक स्वार्थ साधने के चक्कर में निंदा करने लगे हैं। उम्मीद कीजिए कि वे भी अंत में सरकार का ही साथ देंगे।

अध्यात्म

आत्मविश्वास ना खोएं, ऊँचाइयाँ पाओगे

एक बार एक युवक को संघर्ष करते- करते कई वर्ष हो गए लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह काफी निराश हो गया, और नकारात्मक विचारो ने उसे घेर लिया। उसने इस कदर उम्मीद खो दी कि उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। वह जंगल में गया और वह आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक सन्त ने उसे देख लिया। सन्त ने उससे कहा- बच्चे क्या बात है , तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया- मैं जीवन में संघर्ष करते - करते थक गया हूँ और मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। सन्त ने पूछा तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हों? युवक ने कहा मुझे दो वर्ष के लगभग हो गए, मुझे ना तो कहीं नौकरी मिली है, और ना ही किसी परीक्षा में सफल हो सकां हूँ। सन्त ने कहा- तुम्हे नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जायोगे। निराश न हो , कुछ दिन और प्रयास करो। युवक ने कहा- मैं किसी भी काम के योग्य नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। जब सन्त ने देखा कि युवक बिलकुल हिम्मत हार चुका है तो उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चे ने दो पौधे लगाये , एक बांस का, और एक फर्न (नागफनी , कैक्टस ,पत्तियों वाला) का, फर्न वाले पौधे में तो कुछ ही दिनों में पत्तियाँ निकल आई। और फर्न का पौधा एक साल में काफी बढ़ गया पर बाँस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन बच्चा निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष में भी बाँस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। लेकिन फर्न का पौधा और बढ़ गया। बच्चे ने फिर भी निराशा नहीं दिखाई। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष भी बाँस का पौधा वैसा ही रहा, लेकिन फर्न का पौधा और बड़ा हो गया। बच्चा फिर भी निराश नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद बाँस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते- देखते कुछ ही दिनों में बाँस का पेड़ काफी ऊँचा हो गया। बाँस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में चार पाँच साल लग गए। सन्त ने युवक से कहा- कि यह आपका संघर्ष का समय, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझे एवं निराश न हो। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत ,परिपक्व हो जाएँगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जायेगा। आप खूब फलेंगे, फूलेंगे, सफल होंगें और आकाश की ऊँचाइयों को छूएंगें। आप स्वंय की तुलना अन्य लोगों से न करें। आत्मविश्वास नहीं खोएं। समय आने पर आप बाँस के पेड़ की तरह बहुत ऊँचे हो जाओगे। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। बात युवक के समझ में आ गई और वह पुन - संघर्ष के पथ पर चल दिया। दोस्तों, फर्न के पौधे की जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं जो जरा सी तेज़ हवा से ही जड़ से उखड जाता है। और बाँस के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बड़ा सा बड़ा तूफ़ान भी उसे नहीं हिला सकता। इसलिए दोस्तों संघर्ष से घबराये नहीं। मेहनत करते रहें और अपनी जड़ों को इतनी मजबूत बना लें कि बड़े से बड़ी मुसीबत, मुश्किल से मुश्किल हालात आपके इरादो को कमजोर ना कर सके और आपको आगे बढ़ने से रोक ना सके।

जज्बा हो तो मिल ही जाती है मंजिल...

खोना से मिलता-जुलता शब्द है 'खो जाना', जो एक मानसिक स्थिति भी है। इंसान जब कुछ सोचते-सोचते गहराई में चला जाता है या कोई मनपसंद काम करते हुए उसमें डूब जाता है, तो यह स्थिति भी 'खो जाना' कहलाती है। मनपसंद काम में डूब जाने का अर्थ ही है, अपने काम में इतना तल्लीन हो जाना कि दिन-दुनिया का ध्यान ही न रहना। इसमें हमारे भीतर का जज्बा हमें बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। यही है खो जाने की स्थिति। यह ध्यान की एक मानसिक स्थिति है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। इस दौरान जब हमें कोई यह कहता है कि कहां खो गए, तब हमें आभास होता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे।

महेश परिमल

बचपन में हम सब एक खेल खेलते थे। खेल का नाम था- खो-खो। इस खेल में हम सब एक पंक्ति में विपरीत दिशा में चेहरा करके उकडू बैठ जाते थे। एक साथी पीछे से आकर हमें 'खो' कहता, हम दौड़ कर दूसरे साथी को छूने की कोशिश करते। जिसे हम छू देते, वह 'बाहर' हो जाता। यहां पर खो का आशय अपने स्थान से उठकर 'खो' कहने वाले को अपना स्थान देना। बात खो की हो रही है। इससे बनने वाले शब्दों में खोना और खो जाना भी है। खोना, यानी हमारे पास जो कुछ है, उसमें से कुछ हिस्सा हमसे अलग होना, जिसे अब हम प्राप्त नहीं कर सकते।

कई बार अपने प्रयास से यह भले ही हमें प्राप्त हो जाए, पर उसके खोने का दर्द हमें हमेशा सालता रहता है। वास्तव में किसी चीज को पाने के बाद हमें जितनी खुशी मिलती है, उसके मुकाबले अधिक दुख हमें उसके खोने से मिलता है। खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोता है। कभी माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त, रिश्तेदार- ये सभी कहीं न कहीं दिल से जुड़े होते हैं। कभी कोई शरीर का कोई अंग ही खो देता है, जैसे हाथ-पांव, आंख। ये भी अपने खोने के साथ इंसान को दुख दे जाते हैं।

समय के साथ कुछ के खोने पर हमें अफसोस होता रहता है, पर यह सब आगे चलकर भुला दिए जाते हैं। यह भी सच है कि जब भी हम कुछ खोते हैं, तो दूसरी ओर हम पाते भी हैं। हम क्या पाते हैं, इसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम खोने के गम से जुदा नहीं हो पाते। दरअसल, खोने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, उसका आनंद कुछ और ही होता है।

एक सज्जन दुर्घटना में अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठे। एक आंख की रोशनी जाने के बाद वे अवसाद में चले गए। कुछ समय बाद धीरे-धीरे वे सहज होने लगे। अपना दोपहिया वाहन भी चलाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका एक कान कुछ अधिक ही संवेदनशील हो गया है। पीछे से आने वाले वाहन की सरसराहट को वे आसानी से महसूस करने लगे। पहले एक तरफ से आने वाले वाहनों से अक्सर उनकी टक्कर हो जाती, पर धीरे-धीरे उन्हें अपने एक कान के अतिसंवेदनशील होने की जानकारी हुई, तो वे अब कुशलता से दोपहिया वाहन चलाने लगे हैं। ये है खोने के बाद पाने का सुख। इसीलिए कहा गया है कि अगर एक रास्ता बंद होता है, तो दूसरे कई दरवाजे खुल भी जाते हैं। हमें पूरे संयम के साथ दूसरे दरवाजों को देखना होगा। कौन-सा दरवाजा हमारे लिए उपयुक्त होगा, यह भी समझना होगा। तभी हम सफलता के द्वार को खोल पाएंगे।

खोना से मिलता-जुलता शब्द है 'खो जाना', जो एक मानसिक स्थिति भी है। इंसान जब कुछ सोचते-सोचते गहराई में चला जाता है या कोई मनपसंद काम करते हुए उसमें डूब जाता है, तो यह स्थिति भी 'खो जाना' कहलाती है। मनपसंद काम में डूब जाने का अर्थ ही है, अपने काम में इतना तल्लीन हो जाना कि दिन-दुनिया का ध्यान ही न रहना। इसमें हमारे भीतर का जज्बा हमें बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। यही है खो जाने की स्थिति। यह ध्यान की एक मानसिक स्थिति है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। इस दौरान जब हमें कोई यह कहता है कि कहां खो गए, तब हमें आभास होता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे।

इस तरह खोना एक अच्छी स्थिति है। खोने का आशय यह नहीं लेना चाहिए कि हमसे कुछ आखिरी तौर पर अलग ही हो गया। अगर अलग भी हुआ है, तो हमें कुछ देकर ही जाएगा। क्या देकर जाएगा, यह परिस्थितिजन्य है। परिस्थितियों के अनुसार हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो सकता है, जिसके जरिए भी हम अपना जीवन संवार सकते हैं। हेलन केलर का उदाहरण है, जिन्होंने बहुत कुछ खोया, पर उससे भी अधिक पाया। जो कुछ पाया, वह अप्रतिम है। उसके खोने का लाभ हम सबको मिला। सूरदास ने आंखें खोईं, हमें कृष्ण पर उत्कृष्ट साहित्य मिला। अरुणिमा ने अपने पांव खोए, मगर हमें हिमालय पर चढ़ने का जज्बा मिला। अगर यह सब अपने भीतर कुछ अलग या खो जाने पर अवसाद में ठहरे रहते, तो दुनिया को कुछ भी न मिलता। ऐसा अक्सर अपने आसपास भी कभी देखा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी दुख में डूबा रहता है, तो वह तब तक दुखी ही दिखता है, जब तक कि वह उस भाव से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही किसी खोई गई चीज का गम भुला कर वैसा नया बनाने का हौसला काम करना शुरू कर देता है, वह पहले की तरह सक्रिय हो जाता है, उसे नया कुछ हासिल होना शुरू हो जाता है।

इसलिए जब कुछ खो जाए, तो उसका गम करने की एक सीमा होनी चाहिए। खोने के बाद हमें जो कुछ भी नया मिल रहा है, उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। बैसाखी पर चलने वालों के लिए वह एक सहारा ही नहीं, बल्कि एक हथियार भी है, जीवन को जी पाने का। हमें किसी के खोने का दुख होना चाहिए, लेकिन उस दुख में इतना अधिक नहीं डूब जाना चाहिए कि उसके बाद के जीवन के अवसरों को हम भुला दें। खोने से आगे कुछ नया पाने का रास्ता भी है। इस रास्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, परिवार के साथ स्नेह बढ़ सकता है। किसी शुभ कार्य पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको पारिवारिक खुशी मिल सकती है।

वृषभ
कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

मिथुन
कुछ परेशानियों से भी घिर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। व्यापार के लिए समय अच्छा है।

कर्क
कर्क राशि वालों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है, साथ ही पिछले कुछ कार्य भी बनेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

सिंह
पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, बाद में धन कमाने की सोचें। किसी भी काम के अच्छे बुरे पहलु को परखे बिना कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में न करें।

कन्या
आप किसी शुभ कार्य पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको पारिवारिक खुशी मिल सकती है, यदि विद्यार्थी हैं तो कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे।

तुला
तुला राशि वालों को आज आर्थिक लाभ होने की संभावना है। साथ ही पिछले कुछ कार्य भी बनेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं।

वृश्चिक
आपके लिए यह दिन शुभ है। आपको आर्थिक लाभ होने की आशा है। माननीय लोगों से आपकी भेंट हो सकती है, साथ ही कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं।

धनु
आज धनु राशि वालों को आराम नहीं मिलेगा। कार्य का बोझ अधिक रहेगा। साथ ही कुछ अहम कार्य रुक सकते हैं, इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें।

मकर
आपके अधिकारियों से आपकी बहस हो सकती है। संचित धन में कमी आए सकती है और धन की समस्या भी हो सकती है। ध्यान दें कहीं, बेकार की बातों में कतई न उलझें।

कुंभ
आप किसी शुभ कार्य पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको पारिवारिक खुशी मिल सकती है, यदि विद्यार्थी हैं तो कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे।

मीन
आज का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा है लेकिन लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संवाद
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 5 अक्टूबर 2024

निवेशक न घबराएं

भारत की ग्रोथ है इसकी सबसे बड़ी ताक़त

पश्चिम एशिया में इस्राइल और ईरान के बीच लड़ाई तेज होने की आशंका का असर डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ा है। भारत में BSE और NSE के संवेदी सूचकांक (सेंसेक्स और निफ्टी) पर पिछले कुछ दिनों से दबाव बना हुआ है। शुक्रवार को भी इनमें भारी उतार-चढ़ाव बना रहा और इस दिन संवेदी सूचकांक 1% की गिरावट के साथ बंद हुए।

क्या हैं संकेत | भारतीय बाजार में जो हो रहा है, उससे आने वाले वक्त के बारे में संकेत मिलते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने गुरुवार को 15,243 करोड़ की बिकवाली की। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,914 करोड़ की खरीदारी। अगर घरेलू संस्थागत निवेशकों का सहारा नहीं मिला होता तो भारतीय बाजार में कहीं बड़ी गिरावट आती।

युद्ध की आशंका : बाजार लड़खड़ाया

FPI का मूड | दुनिया के बड़े बाजारों में भारतीय शेयर बाजार सबसे महंगा है, जबकि हाल ही में बड़े राहत पैकेज का एलान करने वाले चीन का बाजार वैल्यूएशन के लिहाज से काफी आकर्षक। इस वजह से विदेशी निवेशक कुछ पैसा भारत से निकालकर चीन में लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें आने वाले वक्त में वहां से बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। इस बीच, जापान में नए प्रधानमंत्री के आने के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो येन कैरी ट्रेड घटेगा। इससे भी बाजार पर बुरा असर पड़ेगा।

MF के पास काफी नकदी | इधर, इस्राइल-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से मार्केट का मूड और बिगड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगस्त के आखिर तक भारतीय म्युचुअल फंडों के पास 1.86 लाख करोड़ का कैश था। उन्होंने यह पैसा इसलिए बचाया हुआ है ताकि वैल्यूएशन कम होने पर वे खरीदारी कर सकें। इसलिए आने वाले वक्त में अगर मार्केट और गिरता है तो उनकी ओर से इसे सपोर्ट मिलेगा।

तेल की कीमतें बढ़ेंगी | लेकिन पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज होने से भारत के सामने कुछ मैक्रो चुनौतियां आ सकती हैं। पहली, अगर इस्राइल ने ईरान के तेल-गैस ठिकानों पर हमले किए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जो भारतीय इकॉनमी के लिए बुरी खबर होगी। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। साथ ही, संघर्ष तेज होने से भारत से एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है।

स्ट्रक्चरल तेजी | सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में स्ट्रक्चरल तेजी है। इसकी इकॉनमिक ग्रोथ दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेज बनी हुई है। जल्द ही यहां ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है, जिससे कंपनियों की दिलचस्पी कर्ज लेकर बिजनेस में निवेश करने में बढ़ेगी और कंस्यूमर्स की ओर से डिमांड बढ़ेगी। अगर ग्रोथ तेज बनी रही और घरेलू निवेशकों की ओर से पैसा आता रहा तो भारतीय बाजार में मजबूती आगे भी बनी रहेगी।

दो दूनी चार

फ्यूचर का सही ऑप्शन

रमेश तिवारी

इक्विटी यानी शेयरों में निवेश तो कोई एसआईपी के जरिये भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि बच्चों का खेल क्या खेलना। दिलदार वो है, जो इक्विटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में पैसा लगाए। ये भ्रम सिर पर सवार हो गया कि किस्मत साथ दे तो यही अमीर बनने का पासपोर्ट है। हालांकि इस सेगमेंट में ज्यादातर निवेशकों को भारी नुकसान होता रहा, फिर भी ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगातार तेज बढ़ोतरी देखी जा रही थी। इससे देश की इकॉनमी को नुकसान हो सकता है, तब सरकार और मार्केट रेगुलेटर काफी चिंता में आ गए। इकॉनमिक सर्वे से भी संकेत मिले कि ये कारोबार जुए सी फीलिंग दे रहा है। सर्वे के बाद आए बजट में इसके सौदों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी तय कर लिया कि अटकलबाजियों के बाजार को लगाम कसनी होगी।

असल में सेबी ने एक स्टडी कराई थी। इसमें पता चला था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 93 फीसदी आम निवेशकों को नुकसान हुआ। पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान ट्रेडर्स को 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इतने के बावजूद तीन चौथाई से ज्यादा ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़े रहे। एक ट्रेंड ये भी ध्यान देने वाला है कि इसमें यंग ट्रेडरों की भागीदारी बढ़ रही है। 30 से कम उम्र वाले ट्रेडरों की संख्या वित्त वर्ष 23 में 31 पर्सेंट थी, जो एक साल बाद बढ़कर 43 पर्सेंट हो गई। ट्रेडरों में आधे से ज्यादा लोग सिर्फ चार राज्यों के हैं- महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान।

जब निवेशकों को कोई निवेश पसंद आ जाए तो उन्हें रोका नहीं जा सकता है। लेकिन पसंद का हर निवेश फायदा दे, जरूरी नहीं। जब आम घरों की बचत किसी प्रॉडक्टिव इन्वेस्टमेंट में न जाए, अटकलबाजियों के हवाले हो जाए तो ये साफ है कि लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। कुछ साल पहले नैशनल सेंटर फॉर फाइनैंशल एजुकेशन ने एक सर्वे किया था। इसमें पाया गया कि देश में करीब एक चौथाई लोग ही वित्तीय मामलों में जानकारी रखते हैं।

इसी को ध्यान में रखकर सेबी के साथ स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य संस्थाओं ने हाथ मिलाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। बताया गया कि निवेश में लंबी अवधि का नजरिया अपनाना चाहिए। इस साल जून से फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट दिखने लगी। तब से शेयर बाजार नित नई ऊंचाई छू रहा है। हो सकता है कि गिरावट का डर देख खतरों के खिलाड़ी फिलहाल दूरी बना रहे हों। मौका पाकर वे फिर सक्रिय हो सकते हैं। इसी के कारण हाल में कुछ सख्त उपायों का ऐलान भी हुआ। इनमें सबसे अहम ये है कि एंट्री बैरियर बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया, जो कम आय वालों और छोटे शहरों के लोगों को रोक सकता है।

फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार जिम्मेदार तरीके से किया जाए, लंबी अवधि के लिए हो, तो पोर्टफोलियो को अच्छा लाभ दिला भी सकता है। लेकिन इसकी जटिलता को समझना रिटेल निवेशकों के लिए आसान नहीं है। लोग इसे ठीक से समझ सकें, इसके लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म हों, जहां मार्केट का डेटा सहज उपलब्ध हो। इसके लिए गाइड करने में ब्रोकर भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। निवेश में अनुशासन हो, उम्मीदें धरातल पर रहें, बार-बार खरीद बिक्री से बचें तो निवेश के बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।

ऑफ़ दि ट्रैक

AI से FIR

दिलीप लाल

कार चोरी जैसी घटना हो या मर्डर जैसा संगीन जुर्म, किसी भी आपराधिक वारदात में सबसे महत्वपूर्ण होती है FIR। इसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर तय होता है कि जांच आगे क्या रूप लेगी। यही रिपोर्ट फिर मुकदमे का आधार बनती है। क्या आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के जरिये FIR को बेहतर बनाया जा सकता है? अमेरिका के कैलिफोर्निया और कोलोराडो में कुछ शहरों की पुलिस फिलहाल इसी का जवाब तलाश रही है। वहां पुलिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दर्ज करने और अधिकारियों के रेस्पॉन्स के एनालिसिस के लिए AI का इस्तेमाल शुरू किया है। पुलिस के लिए खास कैमरा और टूल डिवेलप किया है Axon नाम की कंपनी ने। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचता है, तो शुरुआती पूछताछ के दौरान ही AI टूल रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। कंपनी का दावा है कि टेक्नॉलजी से 20% तक फोर्स की कमी की भरपाई हो सकती है। कंपनी ने अपने टूल को Draft One नाम दिया है। अभी तक के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। फोर्ट कॉलिन्स पुलिस के मुताबिक, एक रिपोर्ट लिखने में औसतन 23 मिनट लगते हैं, जबकि एआई से यह काम 8 मिनट में हो गया। इसी तरह, कैलिफोर्निया की Campbell पुलिस के मुताबिक, एआई ने एक महीने में उनके 50 घंटे बचाए। इस क्षेत्र में एक और कंपनी Truleo भी काम कर रही है। यह कंपनी एआई की मदद से पुलिसकर्मियों के बॉडीकैम की फुटेज का एनालिसिस करती है। हालांकि यह सब अभी प्रयोग के स्तर पर ही है।

देश में 90% मानसिक बीमारियों के पीछे ऑफ़िस के ख़राब माहौल का हाथ

जब काम करने में आए आनंद

डॉ. समीर पारिख

कामना छिब्बर

आम तौर पर किसी सामान्य व्यक्ति का सबसे ज्यादा समय वर्कप्लेस पर ही बीतता है। स्वाभाविक ही वर्कप्लेस का बिगड़ा माहौल बड़ी संख्या में लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। वर्कप्लेस के बिगड़े माहौल का मतलब उन हालात से है, जिनमें कर्मचारियों को लगातार दबाव में काम करना पड़ता है, काम की वजह से वे खुद को हमेशा तनाव में महसूस करते हैं। आम तौर पर इसके लिए काम लेने का दोषपूर्ण अंदाज जिम्मेदार होता है। भारत की ही कई हालिया रिपोर्टों में मानसिक तनाव के कारण कॉरपोरेट अधिकारियों पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर किया गया है।

असहजता का माहौल | हमारा ध्यान इस सवाल की तरफ जाना चाहिए कि कितने लोग वर्कप्लेस पर अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करने में सहज महसूस करते हैं। सचाई तो यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन की बातों और सुझावों को अपने सीनियर्स या बॉस के साथ साझा करने में संकोच करते हैं।

गलत समझे जाने का डर | ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है कि अपनी कोई समस्या उठाने पर उन्हें गलत ढंग से 'जज' किया जाएगा। इसके पीछे यह तथ्य भी है कि आम तौर पर सीनियर्स या बॉस कर्मचारियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे समस्या लेकर आने के बजाय उनके सामने सॉल्यूशन पेश करेंगे। स्वाभाविक ही, अपनी समस्या में उलझा कर्मचारी सहजता के साथ बॉस को अपनी हालत नहीं बता पाता।

पॉजिटिव नजरिया | वर्कप्लेस पर ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है, जिसमें

AI image

वर्कप्लेस पर पॉजिटिव माहौल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है

कर्मचारी बिना किसी अंदेशे के अपने विचार साझा कर सकें। ऐसा माहौल सबके लिए फायदेमंद होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें सहज माहौल में बातचीत के जरिए दफ्तरों में कई जटिल मसले आसानी से हल कर लिए गए। काम करने में आजादी महसूस करना भी पॉजिटिव माहौल के लिए जरूरी होता है। जब कोई कर्मचारी स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो वह अपना पूरा प्रयास लगाता है। ऐसे में उसका प्रदर्शन तो अच्छा होता ही है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी इसके फायदे मिलते हैं।

कैसा हो वर्कप्लेस

- काम करने में आजादी महसूस हो
- गलती होने पर जलील न किया जाए
- सुरक्षा और समरसता का माहौल हो

मनोवैज्ञानिक सुरक्षा | मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मतलब है, कर्मचारी वर्कप्लेस पर मानसिक रूप से अपने आपको हर हाल में स्वस्थ महसूस कर सकें। ऐसा सिस्टम विकसित करने की जरूरत है कि कर्मचारियों में किसी प्रकार का तनाव न हो। वे खुद को दबाव में न महसूस करें। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से आश्वस्त रहता है, तो उसमें अपमान या शर्म महसूस करने जैसी बात नहीं होती।

बातचीत में सम्मान | वर्कप्लेस पर कई बार कर्मचारियों से बुरा व्यवहार किया जाता है। उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे कर्मचारियों से तुलना कर उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास होता है। इनसे पॉजिटिव नतीजे मिलना मुश्किल है। इसके बदले बातचीत के जरिए गुणवत्ता में सुधार की तरफ ध्यान देना ज्यादा कारगर हो सकता है। सहज और सम्मानजनक बातचीत से कर्मचारी और मालिक के बीच एक जुड़ाव बनता है।

अनुभवों का आदान-प्रदान | समझने वाली बात यह है कि सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए जोर लगाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। कर्मचारियों के अनुभवों के आदान-प्रदान से बड़ी-बड़ी चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। 2021 में McKinsey Health Institute के एक सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि हर 10 में से 4 भारतीय कर्मचारी गुस्सा, तनाव, चिंता और अवसाद की समस्या का सामना करते हैं। 90% मामलों में इसके पीछे वर्कप्लेस का विषाक्त माहौल और बिगड़ा वर्क कल्चर जिम्मेदार पाया गया है।

डिप्रेशन और एंग्जाइटी | विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 2019 में काम करने वाले 15% वयस्कों में मानसिक विकार पाया गया। हर साल डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कारण लगभग 12 अरब वर्किंग डे काम प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में इससे पूरी दुनिया में सालाना एक ट्रिलियन डॉलर (8,396.78 अरब रुपये) का नुकसान हुआ।

अनुभव की कद्र | वर्कप्लेस पर जितना महत्व व्यक्तिगत अनुभव का है, उससे कम सिस्टम का नहीं है। ये दोनों बातें कर्मचारियों के तनाव को कम करने में मददगार हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे मानसिक प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़े। जैसे ही वह समझ लेता है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला कोई नहीं है, वहां काम करने का माहौल खुद ब खुद बन जाता है।

अच्छी टीम, अच्छा माहौल | वर्कप्लेस पर मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन टीमों का निर्माण करना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है सुरक्षित स्थान, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक समरसता और स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करना। यदि कंपनियों को अच्छे कर्मचारियों की तलाश है, तो उन्हें उन कर्मचारियों के लिए मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना होगा।

(डॉ. पारिख सीनियर सायकायट्रिस्ट और कामना सीनियर क्लिनिकल सायकॉलजिस्ट हैं)

घाटे में इस्राइल

युद्ध में उलझे इस्राइल की इकॉनमी अमेरिकी मदद के बावजूद चरमराने लगी है। अप्रैल और जून में GDP ग्रोथ महज 0.7% रही। क्या इस्राइल की अर्थव्यवस्था हिज्बुल्लाह और ईरान के साथ खुले युद्ध को झेल पाएगी, समझते हैं :

AI image

रक्षा खर्च का बोझ

मार्च में इस्राइली सेना ने 16 बिलियन डॉलर मांगे थे। यह जीडीपी का 3% है। युद्ध के बाद भी सेना को हर साल 8 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे ताकि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.1% हो चुका है।

निवेशकों में घबराहट

लड़ाई इस्राइल के व्यापारिक केंद्रों, तेल अवीव और यरुशलम तक पहुंच गई है। मई से जुलाई के बीच देश के बैंकों से दो अरब डॉलर निकालकर विदेश भेजे गए। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

लगातार बढ़ रहा कर्ज, रेटिंग घटी

जनवरी में इस्राइल का कर्ज GDP का 62% था, जो कि ज्यादातर अमीर देशों वाले OECD क्लब के औसत से कम है। हालांकि युद्ध लंबा चलने पर यह राहत नहीं बचेगी। रेटिंग एजेंसियां फिच और मूडीज इस साल एक बार इस्राइल की रेटिंग घटा चुकी हैं और फिर ऐसा कर सकती हैं।

कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर असर

पिछले साल हमास के हमले के बाद इस्राइल ने 80 हजार फिलिस्तीनी वर्कर्स के वर्क परमिट को रद्द कर दिया था। इनकी खाली जगह पर किसी को नहीं रखा गया। इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 40% तक घट चुकी है। यही हाल हाई-टेक कंपनियों और दूसरी फर्म्स का भी है।

इकॉनमी सिकुड़ी, महंगाई बढ़ी

अगस्त में महंगाई 3.6% की वार्षिक दर पर पहुंच गई थी। युद्ध जारी रहा तो इस्राइली मुद्रा शेकेल की कीमत गिर सकती है, बैंकों को अपने रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।

प्रस्तुति : **शैलेंद्र पांडेय**

भारत में चेस का यह गोल्डन टाइम है...

विमिन ग्रैंड मास्टर और इंटरनैशनल मास्टर तानिया सचदेव पिछले दिनों हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित चेस ओलिंपियाड में गोल्ड जीतने वाली भारतीय विमिंस टीम की सबसे अनुभवी सदस्य हैं। करीब छह साल की उम्र से शतरंज खेल रहीं दिल्ली की 38 वर्षीय तानिया को इस ओलिंपियाड में पांच गेम मिले। इनमें से दो उन्होंने जीते और तीन बाजी ड्रॉ खेल कर टीम में अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया। पिछले 32 बरसों से भारत में चेस की हमसफर रहीं तानिया से ***रूपेश रंजन सिंह*** *ने चेस ओलिंपियाड में भारत की ऐतिहासिक स्वर्णिम सफलता समेत खेल के कई अहम पहलुओं पर बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :*

सप्ताह का इंटरव्यू

तानिया सचदेव

> “सफलता बार-बार पास आकर दूर चली जा रही थी। खासकर चेन्नै में मिली हार को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था। लग रहा था कि अब ओलिंपियाड में मुझे मौका नहीं मिलेगा। उस समय मेरे लिए खेल से जुड़े रह पाना कठिन हो गया था। लेकिन, आखिरकार सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। इसके लिए हमने 16 बरस लंबा इंतजार किया है

■ **कितने साल का इंतजार रहा। कब से आप चेस ओलिंपियाड में भाग ले रही हैं?**

इंतजार तो काफी लंबा रहा, करीब 16 साल का। मैं छह साल की उम्र से ही चेस खेल रही हूं, लेकिन अपना पहला ओलिंपियाड साल 2008 में खेला। इन 16 बरसों के दौरान कई बार हम मंजिल के करीब पहुंचकर बहुत दूर रह गए, लेकिन बुडापेस्ट में हमने वह हासिल कर ही लिया, जिसके लिए मैं इस सफर पर निकली थी।

■ **सफर लंबा हो जाए तो कई बार थकावट भी महसूस होने लगती है। क्या इन 16 बरसों के दौरान कभी सफर से पीछे हटने का मन किया?**

जी, जब आप लगातार विफल होते हैं तो दिल छोटा हो जाता है, मनोबल भी टूटता है। थकान महसूस होती है। कई बार ऐसा ख्याल भी आया। मैंने 8 ओलिंपिक्स खेले। हम कभी चौथे स्थान पर रहे, कभी पांचवें पर। चेन्नै में सभी ने देखा कि कैसे लास्ट राउंड में गोल्ड हमारे हाथ से फिसल गया और हम तीसरे स्थान पर रहे। चेन्नै के बाद बहुत मुश्किल हो गई थी। उस हार के साथ एडजस्टमेंट करना आसान नहीं था। तब इस खेल के साथ जुड़े रहना मेरे लिए कठिन हो गया था। मुझे एकबारगी लगने लगा था कि चेन्नै में मैंने अपना आखिरी ओलिंपियाड खेल लिया, लेकिन शुक्रगुजार हूं कि मुझे एक और मौका मिला और आखिरकार मेरे लंबे करियर को एक मंजिल मिल गई।

■ **अब क्या ख्याल आ रहा है, इस मंजिल पर ही खेल को विराम देने का विचार है या फिर खेल जारी रहेगा?**

सच कहूं तो ऐसे विचार आते हैं। मैंने अपने जीवन के 31 साल चेस को दिए हैं और इसलिए जानती हूं कि मैं हमेशा चेस के साथ तो जुड़ी ही रहूंगी। चाहे वह ब्रॉडकास्ट कमेंट्री करियर के जरिये ही हो, जो कि मेरे करियर का बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। रही बात मेरे खेलने की, तो यह मेरा पहला प्यार है। आगे क्या होगा, इस पर फिलहाल जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं लेने वाली। सच तो यह है कि ऐसे खिताब आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं और आपकी भूख को और बढ़ाते हैं, लेकिन अगर मैं अगला ओलिंपियाड न भी खेल पाऊं तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा।

■ **कमेंट्री करियर के बारे में थोड़ा बताइए...**

चेस की कमेंट्री से जुड़ना मेरे लिए इस खेल से अपने रिश्ते को और भी गाढ़ा करने का जरिया बना। कमेंट्री मेरे लिए कोई काम नहीं है। जैसे मुझे चेस खेलना पसंद है, वैसे ही मुझे कमेंट्री भी बहुत पसंद है। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि चेस का भी टीवी पर प्रसारण हो, लाखों लोग इसे देखें, इस खेल के साथ लोग खुद को कनेक्ट करें। मैं कमेंट्री करते हुए मुझे नजर आता है कि लोगों का प्यार इस खेल को मिलने लगा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी लाइव व्यूअरशिप बहुत बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि इस बदलाव को लाने में एक खिलाड़ी के साथ-साथ कमेंटेटर के तौर पर भी मैं एक भूमिका निभा रही हूं।

■ **चेस की कमेंट्री में क्या चुनौतियां हैं? क्या सभी चेस प्लेयर्स के लिए यह करियर का विकल्प बन सकता है?**

चेस की कमेंट्री सचमुच बहुत कठिन है। बहुत सारे खेल में चुप रहना ही बेस्ट कमेंट्री होती है, क्योंकि वहां तस्वीरें ही बहुत कुछ बोल जाती हैं। लेकिन चेस में तस्वीरें बात नहीं करतीं। चेस में सारा ऐक्शन प्लेयर्स के दिमाग में चल रहा होता है और आपका काम होता है प्लेयर के दिमाग में चल रहे ऐक्शन को लोगों तक पहुंचाना। उन्हें बताना कि प्लेयर ने जो चाल चली है उसकी खूबसूरती और खासियत क्या है। जब तस्वीरें कुछ नहीं बोल रही हों तो भी उसे इंटरेस्टिंग बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। चेस की कमेंट्री ने भी एक लंबा रास्ता तय कर लिया है। 10 साल पहले जो कमेंट्री होती थी और आज जो कमेंट्री होती है उसमें बड़ा फर्क आ चुका है। इस खेल के साथ नए प्रशंसकों के जुड़ने के पीछे यह एक बड़ी वजह है।

■ **चेस को करियर के तौर पर अपनाना क्या जोखिम भरा फैसला हो सकता है? यदि शतरंज के खेल में कोई ज्यादा सफल नहीं हो पाता है तो फिर करियर में उसके लिए आगे क्या संभावनाएं होती हैं?**

देखिए, खेल में तो यह होता ही है। यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको उस खेल में शीर्ष पर होना होगा। यह किसी भी खेल के साथ है। अगर आप उस खेल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर करियर ग्राफ ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे अन्य खेलों में प्लेयर्स के पास कोचिंग का पसंदीदा विकल्प होता है, वैसे ही शतरंज में भी कोचिंग एक करियर विकल्प है। इसके अलावा, अब स्ट्रिमिंग और कमेंट्री भी बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं। मेरा मानना है कि इस खेल का पूरा इको सिस्टम बेहतर हुआ है। कह सकती हूं कि भारत में चेस का यह गोल्डन टाइम है और नई पीढ़ी इस खेल को और भी आगे लेकर जाने वाली है। इस खेल में बहुत संभावनाएं उभर रही हैं।

www.nbt.in

वह सफ़र दर्द से मुस्कान का

खुद अपनी आंख से

सरस्वती रमेश

बात कॉलेज के दिनों की है। एक एनजीओ से जुड़कर हम पास की बस्तियों में पढ़ाने जाते थे। उस एनजीओ में विभु नाम का एक लड़का भी काम करता था। वह एमएससी का छात्र था। उससे मेरी बातचीत होने लगी। हम जल्द ही दोस्त बन गए। वह बच्चों से तुरंत घुल-मिल जाता था, इसलिए बच्चे उसे पसंद करते थे। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद विभु ने कहा, 'मैं आमिर के घर जा रहा हूं। जाने क्यों आमिर चार-पांच दिनों से पढ़ने नहीं आया।'

'मैं भी साथ चलती हूं', मैंने कहा। हम दोनों आमिर के घर पहुंच गए। उसकी अम्मी घर के बाहर ही मिल गईं। घर क्या था, मिट्टी गारे की दीवार पर नीले तिरपाल की छत। बस इतना ही। 'आमिर पढ़ने क्यों नहीं आ रहा', विभु ने पूछा। 'उसकी तबीयत ठीक नहीं है', उसकी अम्मी ने बताया। विभु ने पूछा, 'डॉक्टर को दिखाया?' इस पर अम्मी भावुक हो गईं। बोलीं, 'हमारे पास पैसे नहीं हैं।' असल में कुछ समय पहले आमिर खेलते हुए गिर गया था। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। पैसों के अभाव में अच्छे से इलाज नहीं हो पाया। हकीम को दिखाकर कच्चा प्लास्टर बंधवा दिया था। हड्डी ठीक से जुड़ी नहीं और पैर में दर्द रहने लगा। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उसने पैर में रॉड डालने की बात कही।

हमने उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में दिखाने की बात कही। मगर इसमें भी अड़चन थी। आमिर के कई छोटे भाई-बहन थे, जिन्हें छोड़कर उसकी अम्मी अस्पताल नहीं जा सकती थी। आमिर के अब्बू दिनभर काम करते थे। उसी से घर का चूल्हा जलता था। समस्या बड़ी थी, पर विभु ने हार नहीं मानी। आमिर के माता-पिता से बातचीत कर अगले दिन हम उसे एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने कहा, 'आमिर के इलाज में बहुत खर्च आएगा। क्या आप इतने पैसे दे सकेंगे?' हालात को भांपकर डॉक्टर ने ही हमें एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का नंबर दिया और उनसे फोन पर हमारी बात करवाई। अब आमिर को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। विभु ने आमिर के अब्बू से कहा कि वह कुछ दिन काम पर न जाएं। घर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा।

अब सवाल था कि आखिर यह खर्च कहां से आएगा? एनजीओ से विभु को इतना भी नहीं मिलता था कि उसकी अपनी जरूरतें अच्छे से पूरी हो सकें। फिर भी वह आधी सैलरी आमिर के अब्बू को देने को तैयार था। थोड़ी-बहुत मदद हम दोस्तों ने कर दी। अगले दिन हम अस्पताल पहुंचे। बिस्तर पर लेटे हुए मासूम आमिर हमें टुकुर-टुकुर देख रहा था। शायद पैर के दर्द से परेशान था। हमने उसके अब्बू को एक कोने में बुलाकर उन्हें बारह सौ रुपये पकड़ा दिए। हमने उन्हें आमिर का इलाज ठीक से करवाने को कहा और वहां से चले आए। कुछ समय बाद आमिर फिर से पढ़ने आया। वह अब एकदम ठीक हो गया था। उसके अब्बू भी साथ थे। उन्होंने विभु की हथेलियां पकड़ कर कहा, 'आप कौन हो? सच-सच बताओ?' 'आपकी तरह ही एक इंसान', विभु ने सहजता से कहा। आमिर हमें देख मुस्कुरा रहा था और मेरी नजरें उसके मुस्कुराते चेहरे से हट नहीं रही थीं।

चलते-चलते...

अभी तक कहा जाता था कि कुर्सी पर सही ढंग से न बैठने से बैकपेन हो सकता है। अब एक नई स्टडी के मुताबिक, जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, अगर वे कुर्सी और सोफे से दूरी बना लें तो पीठ दर्द से राहत पा सकते हैं। University of Turku के रिसर्चर्स ने पाया कि दर्द से परेशान लोग अगर कुछ देर भी कम बैठते हैं, तो 6 महीनों में उन्हें काफी राहत मिल सकती है।

रीडर्स मेल

नशे का कारोबार

यह पत्र 4 अक्टूबर के संपादकीय 'कोकेन जब्ती के मायने' से संबंधित है। इंटरनैशनल नेटवर्किंग के जरिए भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों में पहुंचाई जा रही कोकेन का मामला बेहद संवेदनशील है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने हाल ही में कोकेन की बड़ी खेप पकड़ी है। बड़ी मात्रा में कोकेन का पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि हमारे देश में नशे के सौदागर अपने स्वार्थ और लालच में देश के नौजवानों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कोकेन का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि कई बार अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस इन अवैध कारोबारियों को तगड़ा झटका भी देती है। लेकिन जब तक नशे के कारोबार पर पूरी तरह शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक यही समझा जाना चाहिए कि हम सफल नहीं हुए हैं। नौजवान पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए हमें नशे के कारोबार की तह में जाकर समाधान ढूंढना होगा। साथ ही, लोगों को जागरूक भी करना होगा ताकि वे नशे की गिरफ्त में न आएं।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

तीसरे विश्युद्ध के आसार

वर्तमान समय में विश्व बड़े संकट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस्राइल और हमास युद्ध में जिस तरह से ईरान और लेबनान के हिज्बुल्लाह की एंट्री हुई है, उससे संघर्ष के फैलने की आशंका पैदा हो गई है। इस्राइल के साथ पहले से अमेरिका खड़ा है और रूस तथा चीन ईरान के साथ आने का संकेत दे रहे हैं। पिछले काफी समय से विश्व में दो युद्ध चल रहे हैं। इन युद्धों का दायरा भले सीमित रहा है, इसके प्रभावों से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। युद्धों के लंबा खिंचने के पीछे बड़ी शक्तियों का हाथ है। यूक्रेन-रूस युद्ध में अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। यही कारण है कि वह रूस के सामने लंबे समय से टिका हुआ है। दूसरी तरफ, रूस को चीन का साथ मिला हुआ है। ऐसे में अगर ईरान-इस्राइल युद्ध तेज हुआ तो तीसरे विश्वयुद्ध की नौबत भी आ सकती है। यह चिंता की बात है।

ललित शंकर, गाजियाबाद

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु. संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 5 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जिस त्याग से अभिमान उत्पन्न होता है, वह त्याग नहीं, त्याग से शांति मिलनी चाहिए, अंततः अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है

-विनोबा भावे

जातियों को मुक्ति मुश्किल

सुप्रीम कोर्ट का जाति के आधार पर कैदियों से भेदभाव को गंभीर मानना वाकई चिंता का सबब है। शीर्ष अदालत ने इस प्रथा को खत्म करने और जेल नियमावली में संशोधन करने की भी सलाह केंद्र सरकार को दी है। पीठ का मानना है कि जाति के आधार पर काम कराना उचित नहीं है, निचली जाति के कैदियों से सीवर टैंकरों की सफाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे नियमों को असंवैधानिक कहा। जेलों के अंदर जाति-आधारित भेदभाव के मामले को अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर ग्यारह राज्यों की कारागार नियमावली को निरस्त करते हुए तीन माह में रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ जारी संघर्ष में अदालत योगदान दे रही है और फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत गैर-भेदभाव के पहलुओं पर गौर किया गया। निःसंदेह अदालत ने यह फैसला मानवीय आधार पर तथा जातियों के प्रति घृणा-अवमानना को देखते हुए किया है। मगर असलियत में हमारे यहां होने वाली राजनीति व आरक्षण जैसी सुविधाओं में जातियों का प्रमुखता से प्रयोग होता है। लंबे अरसे से जनगणना में जातियों की गिनती की बात जोरदारी से उठाई जा रही है। सरकारी दस्तावेजों में जाति नाम चिह्नित करना अनिवार्य है। कानूनों में संशोधन कर इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने में सरकारें सकुचाती हैं। क्योंकि जाति आधारित राजनीति करने में वे माहिर हैं। इसलिए उनकी प्राथमिकताओं में अंग्रेजों के बनाए नियमों को सुधारने की बात ही नहीं उठती। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद हम अब तक जातियों के पूर्वाग्रह और अंतहीन जंजाल से निकलने में पूर्णतः असफल हैं। अपराधियों को सजा अदालत देती है मगर कैद के दौरान उनके साथ किया जाने वाला जेलाधिकारियों का बर्ताव भी कई दफा बहुत पक्षपाती होता है। जातियों में किसी भी तरह के ऊंच-नीच की बात करना भी असंवैधानिक ही माना जाना चाहिए। दुनिया हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की करती जा रही है, परंतु हम पीढ़ियों से चली आ रही संकीर्णताओं व रूढ़ियों की घुटन से बाहर निकलने को राजी ही नहीं हैं। यह वाकई बेहद सोचनीय मसला है। यह सलाह सिर्फ जेल नियमावली तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए। बल्कि इस तरह का सुधारवादी कदम पूरे समाज में सख्तीपूर्वक लागू किए जाने की जरूरत है। छुआछूत या जाति-आधारित भेदभाव से मुक्त स्वस्थ समाज की नींव डालने और नई पीढ़ियों को इस दलदल से मुक्त रखने की पहल हमें समय रहते करनी होगी।

नई पार्टी से उम्मीदें

बिहार में प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के दिन एक नई पार्टी 'जनसुराज' की घोषणा की है। यह वही प्रशांत किशोर हैं जो चुनाव विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं। अंततः किसी भी दल को मनोनुकूल न पाकर उन्होंने जनता की लामबंदी के लिए बिहार में करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए संगठन बनाया और एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। उनकी यह 'जनसुराज पार्टी' बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव जोर-जोर से लड़ने का मन बना रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार को बदलने का लक्ष्य सामने रखा है। यह एक सच्चाई है कि भारतीय जनता का एक बड़ा वर्ग मौजूदा राजनीतिक दलों की रीतियों और नीतियों से निराश हो चुका है। यह वर्ग मानता है कि इस समय चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अपेक्षित बदलाव लाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए जब कोई सार्वजनिक जीवन का चर्चित व्यक्ति नई राजनीतिक पहल करता है तो निराश जन-मन उससे जुड़ जाता है। अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी (आप) की घोषणा की थी और चालू राजनीति के स्थान पर एक नए प्रकार की जान सरकारी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देने की घोषणा की थी तो जनता ने उनमें उम्मीद की एक किरण देखी थी। लोग उनसे जुड़े अंततः वे दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन अब उनकी राजनीति वैकल्पिक राजनीति न होकर चालू राजनीति का ही हिस्सा मानी जा रही है। प्रशांत किशोर के संदर्भ में केजरीवाल और आप का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि किशोर भी कुछ-कुछ उसी तरह की उम्मीदें जगा रहे हैं। उन्होंने आप की सफलताओं-असफलताओं से और पार्टी के नेताओं के आचरण से निश्चित ही कुछ सबक सीखे होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं की बिहार की राजनीति अपने सारे अंतर्विरोधों के साथ किसी भी वास्तविक परिवर्तन की संभावनाओं पर विराम बन चुकी है। ऐसी स्थिति में किशोर का यह कदम उम्मीद जगाता है बशर्ते कि उनकी परिणति आप जैसी न हो। बहरहाल जनसुराज की भावी गतिविधियों को लेकर उत्सुकता बनी रहेगी।

कटाक्ष/ कबीरदास

राजनीति में घसीटने भी दो यारो

भाई ये तो भगवा भाइयों-बहनों के साथ सरासर चीटिंग है। बेचारों ने कितनी मुश्किल से, कितनी जान खपा-खपाकर, कितनी जुबान घिस-घिसकर, हरेक चीज में भगवान को घसीटने में महारत हासिल की थी। जब तक बेचारों की ट्रेनिंग चल रही थी, तब तो किसी अदालत ने नहीं रोका कि हरेक चीज में भगवान में खींचना मना है। पर अब जब वे हर चीज में भगवान को घसीटने में मास्टरर्स डिग्री कर के आ गए हैं, तो अचानक सुप्रीम कोर्ट की नींद खुल गई और जागते ही एलान कर दिया, कम से कम भगवान को राजनीति में नहीं घसीटा जाए।

यह भगवा भाई-बहनों के साथ धोखा ही तो है। बेचारों ने जान भिड़ाकर जिसकी पढ़ाई की, वही कोर्स के बाहर कर दिया। फिर बात सिर्फ भगवाइयों की नहीं है। बात राजनीति के अस्तित्व की है। अदालत ने यह तो आसानी से कह दिया कि भगवान को राजनीति में नहीं घसीटा जाए। पर यह नहीं बताया कि फिर राजनीति में किसे घसीटा जाए। जिस दिन से हमारे देश में खुले बाजार की आर्थिक नीतियां आई हैं, उसी दिन से आर्थिक नीतियों को राजनीति में घसीटने पर बैन लग गया था। संस्कृति को राजनीति में घसीटने पर तो पहले ही बैन था। शिक्षा को राजनीति में नहीं घसीटने की शिक्षा तो खैर आजादी के बाद से ही बच्चों को दी जा रही थी। खेलों को भी। सरकारी सेवाओं को राजनीति में घसीटने की हमेशा से मनाही थी, जब तक कि उन्हें आरएसएस में घसीटने की इजाजत नहीं दे दी गई। आरएसएस, राजनीति में नहीं न है जी! साहित्य, सिनेमा, समाज, किसी भी चीज को देखो, राजनीति में घसीटना मना है की तख्ती टंगी मिलेगी। अब भगवान को भी राजनीति में घसीटने पर रोक लग गई। तब राजनीति में करेंगे क्या? घुइयां छीलेंगे! बेचारे भगवाइयों को वह भी तो नहीं आता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, तिरुपति के लड्डू के सिलसिले में कहा है। लड्डू तिरुपति का ही सही, पर है तो लड्डू ही। वैसे प्यार से लड्डू गोपाल की भी आरती की जाती है, फिर भी लड्डू को भगवान नहीं कह सकते। लड्डू, लड्डू है, भगवान नहीं, तभी तो उसमें मिलावट हो सकती है। नायडू-पवन जोड़ी की हड़बड़ी ने खामखां में बात बिगड़वा दी। भगवाइयों की नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए।

भारी होता भारत का पलड़ा

सुरक्षा परिषद

प्रमोद भार्गव

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र निकाय के विस्तार की वकालत भी की है। मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को परिषद का स्थाई सदस्य होना चाहिए।

दो ऐसे देश भी होने चाहिए जिनकी अफ्रीका प्रतिनिधित्व के लिए अनुशंसा करे। दूसरी तरफ, पाकिस्तान से दोस्ती और भारत विरोधी रुख के लिए चर्चित तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को झटका दिया है। उन्होंने गाजा युद्ध को लेकर जम कर हमला बोला, लेकिन इस बार कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। इससे लगता है कि भारत की स्थाई सदस्यता के लिए सहमति बढ़ रही है। भारत के संयुक्त राष्ट्र में भारी होते पलड़े के संदर्भ में विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्किये ब्रिक्स का सदस्य देश बनना चाहता है। इसके लिए उसे भारत की मदद जरूरी है। भारत असहमति जता देता है तो उसे सदस्यता मिलना मुश्किल है।

ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। भारत इनमें प्रमुख सदस्य है। इस बीच खबर यह भी है कि तुर्किये को नाटो देशों के समूह से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए तुर्किये ब्रिक्स देशों की सदस्यता चाहता है। एर्दोगान ने कहा भी है, 'हम ब्रिक्स देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की उभरती आर्थिक शक्ति हैं। इसलिए हम उनके साथ संबंध मजबूत और विश्वसनीय बनाने के पक्षधर हैं।' एर्दोगान ने यह झटका तब दिया है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि महासभा में कश्मीर में हो रहे चुनाव का मुद्दा उठाया जाए और इस चुनाव प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताया जाए, परंतु दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे भारत का डंका विश्व की लोकतांत्रिक और मानवाधिकार हित की पैरवीकार संस्थाओं में बजता दिख रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की दलील है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की सुरक्षा परिषद् 21वीं सदी की लक्ष्य पूर्तियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा। भारत 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र की उच्च परिषद् में अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया था किंतु दुनिया का जो वर्तमान परिदृश्य है, उससे निपटने के लिए स्थाई सदस्यों की संख्या दुनिया का हित साधने के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। इसीलिए मैक्रों को कहना पड़ा, 'सुरक्षा परिषद् के कामकाज के तरीकों में

बदलाव, सामूहिक अपराधों के मामलों में वीटो का अधिकार सीमित करने और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी फैसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। अतएव जमीन पर बेहतर और बेहिचक तरीके से काम करने की दृष्टि से दक्षता हासिल करने का समय आ गया है।' मैक्रों की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रविवार 22 सितम्बर, 2024 को 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित करने के कुछ दिन बाद आई जिसमें मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार आवश्यक है।

उन्होंने कहा था, 'सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है।' वाकई इस समय संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता खोती दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने 15 सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद् को भी पुरानी व्यवस्था का हिस्सा बता कर आलोचना की। स्पष्ट कहा कि अगर इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो इस संस्था से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का गठन हुआ था। अहम मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से सुरक्षित रखना था। याद रहे चीन जवाहरलाल नेहरू की अनुकंपा से सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था। कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रहे शशि थरूर ने अपनी किताब 'नेहरू-द इन्वेंशन ऑफ इंडिया' में लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था। लेकिन उन्होंने इसे चीन को दे दिया। भारत का दो बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं।

तालिबान की आमद के बाद अफगानिस्तान में किस बेरहमी से विरोधियों और स्त्रियों को दंडित किया जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं रह गया है। इस्राइल और फिलिस्तीन और रूस एवं अमेरिका के बीच युद्ध एक नहीं टूटने वाली कड़ी बन गए हैं। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। दुनिया में फैल चुके इस्लामिक आतंकवाद पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत के आदेश को नहीं मानता। इसका उदाहरण अजहर जैसे आतंकियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर चीन का बार-बार वीटो का इस्तेमाल करना है जबकि भारत विश्व में शांति स्थापित करने के अभियानों में मुख्य भूमिका निर्वाह करता रहा है। बावजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी एवं सामुदायिक बहुलता वाला देश सुरक्षा परिषद् का स्थाई सदस्य नहीं है।

भारत में दुनिया की 18 फीसद आबादी रहती है। दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। साफ है, संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति निष्पक्ष नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मनवतावादी केंद्रीय भूमिका दिखनी चाहिए थी, लेकिन वह महामारी फैलाने वाले दोषी देश चीन के समर्थन में खड़ा नजर आया। अलबत्ता, सुरक्षा परिषद् की भूमिका वैश्विक संगठन होने की दृष्टि से इसलिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उसके एजेंडे में प्रतिबंध लागू करने और संघर्ष की स्थिति में सैनिक कार्रवाई की अनुमति देने के अधिकार शामिल हैं। इस नाते उसकी मूल कार्यपद्धति में शक्ति-संतुलन बनाए रखने की भावना अंतर्निहित है, लेकिन वह इन प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज कर रहा है, गोया संस्था के प्रति विश्वास का संकट गहराया हुआ है। नतीजतन, इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है।

(लेखक के निजी विचार हैं)

भारत में दुनिया की 18 फीसद आबादी रहती है। दुनिया का हर छठ व्यक्ति भारतीय है। साफ है, संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति निष्पक्ष नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मनवतावादी केंद्रीय भूमिका दिखनी चाहिए थी, लेकिन वह महामारी फैलाने वाले दोषी देश चीन के समर्थन में खड़ा नजर आया। अलबत्ता, सुरक्षा परिषद् की भूमिका वैश्विक संगठन होने की दृष्टि से इसलिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उसके एजेंडे में प्रतिबंध लागू करने और संघर्ष की स्थिति में सैनिक कार्रवाई की अनुमति देने के अधिकार शामिल हैं

पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है बांस

- बांस बहुपयोगी, मजबूत, नवीकरणीय, पर्यावरणानुकूल और पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है, जो अपने पूरे जीवन में 25 मीटर या उससे अधिक की लंबाई तक बढ़ता है
- इसे हर वर्ष पुनः लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तीन से पांच वर्ष के चक्र में स्थायी रूप से काटा जा सकता है
- -स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति डॉ. अरुण कुमार के मुताबिक, असम देश का सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य है। वहां बांस प्रौद्योगिकी पार्क भी है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

इस्राइल का अस्तित्व है तो अमेरिका के कारण और अमेरिका है कि इसे नरसंहार से रोक तक नहीं पा रहा, बल्कि कहना तो यह चाहिए कि बड़े स्तर पर हत्याओं में उसका अतिउत्साही साथी है। तो भारत को भाषण देना बंद करे। आपकी रिपोर्ट डस्टबिन में डालने लायक है।

-स्वाति चतुर्वेदी,पत्रकार

प्रगति की राह पर सरपट

यूपीआईटीएस | उमेश चतुर्वेदी

पिछली सदी के अस्सी के दशक में जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू कहकर उपहास उड़ाया जाता था, उसी यूपी में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का भव्य आयोजन होना मामूली बात नहीं है। राज्य के तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा शहर में 25 से 29 सितम्बर तक चले यूपीआईटीएस में देशभर की बड़ी कंपनियों का जुटान यह बताने के लिए काफी है कि राज्य में निवेश और कारोबार को लेकर भरोसा बढ़ रहा है।

चार दिनों तक चले यूपीआईटीएस का आयोजन 15 हॉल में किया गया था। वैसे तो अपने आप में सभी हॉल यूपी में आ रहे बदलाव और उसमें कारोबार और निवेश की दुनिया के दिग्गजों की दिलचस्पी की कहानी कह रहे थे, लेकिन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है, यूपी इन्वेस्ट का हॉल, जिसमें देश के तकरीबन सभी अहम क्षेत्रों की कंपनियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इनमें देश की अग्रणी अडानी, अंबानी, रिलायंस, लुलु हाइपर मार्केट, वाइब्स जैसी कंपनियां शामिल रहीं। इस आयोजन में एक पूरा और एक्सक्लूसिव हॉल इलेक्ट्रॉनिक्स का रहा, जिनमें देश के 100 से अधिक स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए और लोगों को अपनी तरक्की से प्रभावित किया। साल 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय उत्पादों को बाजार और पहचान मुहैया कराने के लिए 'एक जिला, एक उत्पाद' नाम से योजना शुरू की थी। जिसे संक्षेप में ओडीओपी के नाम से जाना जाता है। यूपीआईटीएस के इस आयोजन में ओडीओपी के लिए भी अलग से हॉल तैयार था, जिसमें राज्य के सभी 75 जिलों के 325 उत्पादक अपने स्थानीय विशेष उत्पादों के साथ मौजूद रहे। गौर करने की बात यह है कि इनमें काफी संख्या महिलाओं की रही। इस योजना के जरिए अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा रहे कुछ दिव्यांग कारोबारी भी इसमें शामिल थे। इस आयोजन में पशुधन विकास, दुग्ध उद्योग, मत्स्य पालन, कृषि उत्पाद और खाद्य संरक्षण की भी कंपनियां शामिल रहीं और अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इस आयोजन में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र फूड प्रोसेसिंग वाला हॉल रहा, जहां उत्तर प्रदेश के स्थानीय खाद्य उत्पादों और व्यंजनों को बतौर

नमूने प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन का 14 और 15 नंबर का हॉल निर्यातकों के लिए विशेष तौर पर आरक्षित था। जिसमें उत्तर प्रदेश के करीब सभी निर्यात होने वाले उत्पाद प्रदर्शित किए गए। ये हॉल विदेशी ग्राहकों को सबसे ज्यादा लुभाते दिखे। यहां यह भी बताना जरूरी है कि इसे देखने के लिए दुनियाभर से करीब 400 लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि कुछ विदेशी ग्राहक ऐसे भी थे, जो खुद यहां पहुंचे। विदेशी ग्राहकों और कंपनियों को यहां राज्य के उत्पादकों और निर्यातकों को कारोबारी बैठक के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिसका राज्य को फायदा भी हुआ और करोड़ों रुपए के ऑर्डर भी मिले। ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा, और रक्षा उत्पाद को भी इस हॉल में प्रदर्शित किया गया था। इस आयोजन में शिक्षा से जुड़ी तमाम संस्थाएं जिनमें कुछ बड़े विश्वविद्यालय भी शामिल थे, ने युवाओं को अपनी सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी। पांच दिनों तक चले इस आयोजन में पांच सत्रों का आयोजन किया गया, जो ई-कॉमर्स ट्रेंड्स और अवसर, नवाचार और स्टार्टअप्स, देश की निर्यात क्षमता, आदि पर आधारित थे। इस आयोजन की उपलब्धि ही कही जाएगी कि आयोजन के चौथे दिन उद्यमियों को अमेरिका, फ्रांस और जापानी कंपनियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए। इस दौरान बिरला एयरकॉन और सोनी के बीच जहां 50 करोड़ का करार हुआ, वहीं मदरसन कंपनी को 25 करोड़ के ऑर्डर मिले। इसी तरह आइसक्रीम की मशहूर कंपनी वडीलाल और जैन शिकंजी को 10-10 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। पूरे आयोजन में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।

यूपीआईटीएस 2024 का सहयोगी आयोजक वियतनाम रहा, जिसके राजदूत की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वियतनाम ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एवं आईटी के क्षेत्र में निवेश को लेकर उत्सुकता जाहिर की। बहरहाल यूपीआईटीएस के बीते आयोजन में राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को नई उड़ान मिली है। इस दौरान राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों की जबरदस्त खरीदारी हुई। इस आयोजन के दौरान 75 हजार कारोबारी निर्यात के ऑर्डर भी मिले। कभी उत्तर प्रदेश को भदेस और उसके उत्पादों को उपहास की नजर से देखा जाता था, लेकिन यूपीआईटीएस जैसे आयोजनों के चलते उत्तर प्रदेश की पहचान भदेस से निकल रही है और राज्य नए सिरे से ना सिर्फ अपनी पहचान हासिल करता दिख रहा है, बल्कि राज्य के हस्तशिल्प और दूसरे उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलता दिख रहा है।

नजर-ए-करम | संत राजिन्दर

नजर-ए-करम या सतुरु का दर्शन इतना प्रभावशाली क्यों होता है? इसका अनुभव वही लोग करते हैं जिन पर अपने सतुरु की नजर-ए-करम पड़ती है या फिर वो उस दृष्टि को पाने के लिए तरसता है। जब शिष्य उस नजर-ए-करम से जुदा हो जाता है तो उस समय वह अपने सतुरु के वियोग में विरह का अनुभव करता है। जिस किसी ने अपने सतुरु से जुदाई का अनुभव किया हो, वह जानता है हर पल, हर क्षण उनकी नजर-ए-करम के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। जैसे एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया जाए तो बच्चा तब तक रोता है, जब तक कि वह मां से नहीं मिल जाता। इसी तरह जब शिष्य के अंदर सतुरु से मिलने की इच्छा जागृत होती है तो उसका ध्यान बाहरी दुनिया के आकर्षणों से हटकर अंतर में दिव्य-प्रेम की खोज में लग जाता है और उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि वह अपने सतुरु की नजर-ए-करम प्राप्त नहीं करता। जब शिष्य सतुरु की प्रेम भरी नजर प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा को अंतर के मंडलों में उड़ान भरने के लिए उभार मिलता है। इसीलिए हजारों लोग दुनिया के कोने-कोने से एक संत-सतुरु से मिलने आते हैं और घंटों तक उनके दर्शन की चाह में इंतजार करते हैं क्योंकि उनकी आत्मा अपने सतुरु की नजर-ए-करम पाना चाहती है। एक शिष्य जब अपने सतुरु की नजर-ए-करम पाता है तो उसकी आत्म-जागृति हो जाती है। ऐसा शिष्य इस दुनिया की नश्वरता को अनुभव करता है। फिर वह अपने मन का कैदी नहीं होता तथा न ही इस संसार की किसी वस्तु की चाह रखता है क्योंकि वो अपनी आत्मा की असलियत को जानने लगता है। वो यह भी जान जाता है कि उसकी आत्मा पिता-परमेवर की अंश है और संत-सतुरु की नजर-ए-करम के जरिये ही वे प्रभु से मिल सकती है। वह जल्दी से जल्दी अपनी आत्मा का मिलाप पिता-परमेवर से कराना चाहता है। उसे इस बात की पूरी समझ है कि एक संत-सतुरु की नजर-ए-करम पाना कितना जरूरी है। नजर-ए-करम आत्मा के प्याले में मधुर अमृत को डालने जैसा है। यह एक ऐसी मिठास है जो हमारे रोम-रोम में समा जाती है और हमें ऐसी ऊर्जा से भर देती है जिससे कि हमारी आत्मा प्रभु की ओर अग्रसर होती है।

रीडर्स मेल

भारत को मिले स्थाई सदस्यता

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सभी देशों ने मिलकर मानवता को युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। उस समय इस संस्था में 51 सदस्य थे, जिनमें पांच देश अमेरिका, रूस,चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 191 हो चुकी है, लेकिन स्थाई सदस्यों की संख्या आज भी पांच है। रूस-यूक्रेन युद्ध एवं हमास - इस्राइल युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ बेबस और मूकदर्शक की भूमिका में है। इस युद्ध में मानवता शर्मसार हो रही है एवं यह तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन सीमित अधिकार की वजह से कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। बदलते दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव अनिवार्य हो चुका है। भारत जैसे शांतिप्रिय और सबसे अधिक आबादी वाले देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

नशाखोरी खत्म करनी होगी

इंटरनेशनल नेटवर्किंग के जरिये भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों में पहुंचाई जा रही कोकीन का मामला बेहद संवेदनशील है। बड़ी मात्रा में कोकेन का पकड़ा जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि देश में नशे के सौदागर अपने स्वार्थ, चंद पैसों के लालच और जल्दी अमीर बनने की लालसा में देश के नौजवानों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि निकट भविष्य में इस स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो कुछ लोग हमारी भावी पीढ़ी को मौत के गर्त में धकेलने में कामयाब हो जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों से भारत में कोकेन का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। पेरू, बोलिविया और कोलंबिया से देश में चोरी-छिपे कोकीन की धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही है। कई बार पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए कोकीन की बरामदगी कर लेती है, परंतु जब तक नशे के इस काले कारोबार पर पूरी तरह शिकंजा नहीं कसेगा तब तक इस कार्य में कामयाबी नहीं मानी जाएगी। नौजवान पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए हमें इसकी तह तक जाना होगा। कोकीन के उत्पादन पर रोक लगाने सहित समाज के लोगों को कोकीन के सेहत पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावो के बारे में जागरूक करना होगा। इसकी सप्लाई के नेटवर्क को तोड़कर भी काफी हद तक नशाखोरी से समाज को दूर रखा जा सकता है।

हितेंद्र डेढ़ा, दिल्ली

सरकार करे विचार

आयकर विभाग द्वारा हाल ही में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सहित कई एनजीओ पर की गई कार्रवाई; लोकतांत्रिक समाज में सरकारी अतिक्रमण और दमन के बारे में बड़ी चिंताएं पैदा करती है। क्या ये कार्रवाई वास्तव में कर अनुपालन के बारे में है या यह सिर्फ और सिर्फ असहमति को दबाने के लिए राजनीति से प्रेरित प्रयास है? 'विदेशी फंडिंग' पर ध्यान वैध निरीक्षण की तुलना में बलि का बकरा बनाने जैसा लगता है। क्या राज्य को लोकतांत्रिक संस्थानों को दबाने के बजाय उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 52
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय
संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

हिज्बुल्लाह : क्या आतंक खत्म होगा?

इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन हिज्बुल्लाह के नेतृत्व का एक के बाद एक सफाया कर दिया है। इजराइल के ताजा हमलों में हिज्बुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन और टॉप कमांडर अनीस के मारे जाने की खबर है। हाशिम सैफुद्दीन को नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद नया चीफ बनाया गया था। इससे पहले सीरिया पर किए गए हमले में नसरुल्लाह के दामाद के मारे जाने की खबर आई थी। हाशिम के मारे जाने के साथ ही यह अब साफ है कि लेबनान का हर अति सुरक्षित बंकर भी इजराइल की जद में है। इजराइल अपने दुश्मनों को दोजख तक पहुंचा कर ही दम लेता है। पिछले 4 साल में उसने हमास, ईरान, हिज्बुल्लाह के लगभग 40 टॉप लीडर खत्म कर दिए हैं। अपने दुश्मनों को चुन-चुनकर और खोज-खोजकर मारने के लिए उसकी गुप्तचर एजेंसी मोसाद बहुत माहिर है। दुनिया के नक्शे पर इजराइल को ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि आकार में वह बहुत छोटा देश है लेकिन उसके हथियारों, सुरक्षा तकनीक और जासूसी तंत्र की तारीफ पूरी दुनिया करती है। मजाल है कि कोई दुश्मन उसके निशाने से बच जाए।

इसी वर्ष 31 जुलाई को उसने हमास के सर्वोच्च राजनीतिक नेता इस्माइल हानिए को तेहरान में एयर स्ट्राइक कर मार डाला था। जुलाई में ही इजराइल ने बेरूत में बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें हिज्बुल्लाह के सैन्य प्रमुख फौद शुकर को उसने मार गिराया था। फौद शुकर को इजराइल ने द्रूज इलाके में हुए रॉकेट हमले के जवाब में मारा था। इस हमले में फुटबाल खेल रहे 10 बच्चों की मौत हो गई थी। शुकर को नसरुल्लाह का दाहिना हाथ माना जाता था। हिज्बुल्लाह के सैन्य संगठन में वह नसरुल्लाह के बाद दूसरी पंक्ति का कमांडर था। इजराइल ने 20 सितम्बर को बेरूत में किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया। अकील की भी हैसियत हिज्बुल्लाह की कमांड में दूसरे नंबर पर थी। वह नसरुल्लाह को सीधे रिपोर्ट करता था। अकील पर 1983 में हुए बम विस्फोटों के मामले में 70 लाख डॉलर (58 करोड़ भारतीय रुपये) का इनाम था। अकील के साथ हमले में एलीट राडवान फोर्स के कमांडर अहमद वहाबी भी मारा गया था।

> **इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इजराइल के कई दुश्मन हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ईरान का है। इजराइल और ईरान एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, जबकि इजराइल पर हमले करने वाले मिलिशिया ग्रुप को ईरान की तरफ से फंडिंग और हथियार मिलते हैं। ईरान के बाद लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, बहरीन के मिलिशिया संगठन इजराइल के दुश्मन हैं। इस तरह इजराइल सात मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। यद्यपि इजराइल लेबनान में घुसकर हिज्बुल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है, पर इस जमीनी जंग के साइड इफैक्ट भी दिखने लगे हैं। जमीनी लड़ाई में उसे भी अपने सैनिक गंवाने पड़े हैं।**

इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इजराइल के कई दुश्मन हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ईरान का है। इजराइल और ईरान एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, जबकि इजराइल पर हमले करने वाले मिलिशिया ग्रुप को ईरान की तरफ से फंडिंग और हथियार मिलते हैं। ईरान के बाद लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, बहरीन के मिलिशिया संगठन इजराइल के दुश्मन हैं। इस तरह इजराइल सात मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। यद्यपि इजराइल लेबनान में घुसकर हिज्बुल्लाह के ख़िलाफ लड़ रहा है, पर इस जमीनी जंग के साइड इफैक्ट भी दिखने लगे हैं। जमीनी लड़ाई में उसे भी अपने सैनिक गंवाने पड़े हैं। हिज्बुल्लाह भले ही इजराइल के हवाई हमलों का मुकाबला न कर पाए लेकिन जमीनी मुकाबला करने में वह पूरी तरह से सक्षम है।

हिजबुल्लाह का दावा है कि ओदाइसा और यारून इलाकों से उसके लड़ाकों ने इजराइली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, हिज्बुल्लाह ने इजराइली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजराइली सैनिकों को मारकर और कुछ इलाकों से खदेड़ने के बाद हिज्बुल्लाह आत्मविश्वास से लबालब भर गया है। 2006 के युद्ध में भी इजराइल देख चुका है कि लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग कितनी मुश्किल थी। उस जंग में 125 से अधिक इजराइली सैनिकों की मौत हुई थी और हिज्बुल्लाह लड़ाकों ने 20 से अधिक इजराइली टैंकों को तबाह कर दिया था। लेबनान चूंकि हिज्बुल्लाह का गढ़ है, इसलिए उसे एक-एक चीज की जानकारी है। इजराइली सैनिक यहीं मात खा जाते हैं और हिज्बुल्लाह के जाल में फंसते जा रहे हैं।

अमेरिका एक तरफ इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है। हर मोर्चे पर उसकी मदद कर रहा है लेकिन वह भी शांति की बात करता है। फिलहाल इजराइल और ईरान आपस में सीधे युद्ध से बच रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हिज्बुल्लाह का आतंक खत्म होगा? अगर यह युद्ध लम्बा खिंचा तो इसके घातक परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। अगर जंग शुरू हुई तो यह ईरान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि यह अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर और यूएई तक फैल जाएगी। यह ऐसे देश हैं जो भारत और अन्य देशों को बड़े पैमाने पर तेल की सप्लाई करते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और इसका असर भी पड़ना शुरू हो गया है। मौजूदा हालात भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती है क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं। भारत इजराइल की तरफ झुकेगा तो ईरान के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा और यह खाड़ी में रहने वाले भारतीयों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करेगा। ईरान में भारत के कई प्रोजैक्ट चल रहे हैं जो लटक सकते हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय लाखों डॉलर भारत भेजते हैं। युद्ध होने की स्थिति में इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। भारत का दोनों देशों में संतुलन बनाकर चलना अपने आप में बड़ी चुनौती है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

गोहाना की जलेबी पर विवाद क्यों?

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक
kapurakesh@gmail.com

बेशक भारत का लोकतन्त्र शोर-शराबे का लोकतन्त्र है मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि तथ्यहीन व तत्व विहीन मुद्दों को चुनावी विमर्श में खड़ा करने का प्रयास किया जाये। इसकी वजह यह है कि भारत की 90 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक लोग राजनीति में जमीनी मुद्दों की परख करना बखूबी जानते हैं। चुनाव प्रचार के अन्तिम चरण में सोनीपत के निकट के कस्बे में यहां की प्रसिद्ध जलेबी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो तजवीज पेश की उसे लेकर ही उनके विरोधी पक्ष के लोग तूफान खड़ा करने लगे हैं। यह सच है कि कभी-कभी भारत के चुनावों में इस तरह के मुद्दे तैर जाते हैं और चुनावों को प्रभावित भी कर देते हैं। मगर राहुल गांधी ने केवल यही कहा था कि गोहाना की जलेबी अगर इस कस्बे की पहचान है तो इसके उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे जलेबी बनाने की बड़ी फैक्टरीनुमा उत्पादन इकाई खुल सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। खाने-पीने की चीजों की फैक्टरियां भी होती हैं।

मैं जिला बिजनौर के छोटे से कस्बे नजीबाबाद का रहना वाला हूं। मेरा बचपन और किशोर अवस्था इसी कस्बे में बीते। शहर के चौक बाजार में एक प्रसिद्ध कृष्णा हलवाई की दुकान हुआ करती थी। इस दुकान की मिठाई पूरे जिले में अव्वल मानी जाती थी। वैसे तो कृष्णा हलवाई की दुकान की सारी मिठाइयां ही लजीज समझी जाती थीं, मगर इसकी बनाई हुई सोहन पापड़ी की ख्याति दूर-दूर तक के शहरों में थी। इसकी बनाई सोहन पापड़ी धीरे-धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में जानी जाने लगी। बेसन से बनने वाली सोहन पापड़ी इतनी नफासत भरी होती थी कि वह मुंह में रखते ही घुल जाया करती थी। इस दुकान के कारीगर बेजोड़ समझे जाते थे।

इन्हीं कारीगरों में एक कारीगर इन्दर ने दुकान की नौकरी छोड़ कर अपनी पृथक एक छोटी सी दुकान केवल सोहन पापड़ी की ही खोली। उसकी सोहन पापड़ी भी खूब बिकने लगी। उसकी देखा-देखी कुछ और लोगों ने भी यह धंधा शुरू कर दिया। मगर इस बीच कृष्णा हलवाई की दुकान थोड़ी हल्की पड़ती गई और एक समय ऐसा भी आया कि कृष्णा हलवाई की अगली पीढ़ियां दुकान पर बैठने लगी। बाद में हालत यह हो गई कि तीसरी पीढ़ी के पुत्र अशोक ने दुकान को नामचारे के लिए ही चलाया। अशोक कुमार की मृत्यु के बाद अब यह दुकान पूरी तरह से बन्द हो चुकी है।

दूसरी तरफ सोहन पापड़ी के कारोबार में अन्य लोग घुस गये। थोड़ी पूंजी लगा कर ही सोहन पापड़ी का व्यापार करने वाले लोग अब नजीबाबाद के करीब के कस्बे सहारनपुर समेत अन्य कई गांवों में फैले हुए हैं। इन लोगों की उत्पादन इकाइयों को यहां के लोग 'सोहन पापड़ी की फैक्टरी' कहते हैं। नजीबाबाद से इन्हीं फैक्टरियों में बनने वाली सोहन पापड़ी अब प्रदेश के लगभग हर राज्य में नजीबाबाद की सौगात के रूप में जानी जाती है। इस कारोबार में कार्यरत लोगों की संख्या भी अच्छी-खासी मानी जाती है। भारत की यह विशेषता है कि इसके हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ जरूर बनता है जिसकी शोहरत दूर-दूर तक फैली हुई होती है।

उदाहरण के तौर पर हम आगरा को ही लें। आगरा में पेठे का कारोबार बहुत जोर- शोर से होता है। इस शहर के इस उत्पाद को बनाने के लिए आगरा व उसके आस-पास के इलाकों में पेठा तैयार करने की इकाइयां लगी हुई हैं। पेठे के बड़े उत्पादकों को यहां भी पेठे की फैक्टरी के मालिक नाम से जाना जाता है। असल में जब किसी भी उत्पाद का उत्पादन बड़ी मिकदार में होता है तो स्थानीय जनता उसे फैक्टरी के रूप में ही पहचानती है। याद कीजिये भारत के बंटवारे से पहले पंजाब के स्यालकोट शहर की पहचान क्रिकेट का बल्ला बनाने वाले शहर के रूप में होती थी। इस शहर में खेल का सामान उत्पादित करने वाली सैकड़ों फैक्टरियां थी।

अत: बहुत स्पष्ट है कि जिस किसी भी उत्पाद का उत्पादन थोक में होने लगता है तो भारत के लोग उसके उत्पादन स्थल को फैक्टरी ही कहने लगते हैं। इसी प्रकार पंजाब के जालंधर शहर के बूंदी के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका उत्पादन लवली ब्रांड के साथ होता है। अब इस दुकान के लड्डू व कलाकन्द विदेशों तक में जाते हैं। पंजाब के लोग भी लड्डू उत्पादन केन्द्रों को लड्डू की फैक्टरी ही कहते हैं। इसी प्रकार लखनऊ से पहले संढीला कस्बा आता है। यहां के काशीफल के लड्डू भी दूर-दूर तक प्रसिद्ध हुआ करते थे। इन्हें संढीला के लड्डू ही बोला जाता है और इनके उत्पाद स्थलों को लोग फैक्टरियां ही बोल देते हैं। इसी प्रकार मेरठ शहर में देशी घी की रेवड़ियां या गजक बनाने की सैकड़ों फैक्टरियां हैं।

मध्य प्रदेश के विभिन्न बड़े- बड़े नगरों में 'रतलामी सेव' बनाने की फैक्टरियां हैं। बेशक इन्हें हलवाई और कारीगर ही बनाते हैं मगर ऐसी इकाइयों में सैकड़ों अन्य लोग भी काम करते हैं। अगर हम गौर से देखें तो पंजाब सरकार का एक उपक्रम वर्का भी खाद्य सामग्री का उत्पादन करता है। यह डिब्बा बन्द सरसों का साग तक बनाता है। यह सारा काम फैक्टरियों में ही होता है।

अब यदि गोहाना की जलेबी का उत्पादन थोक में किसी बड़ी फैक्टरी में होता है तो उसमें किसी को क्यों गुरेज होना चाहिए। नहीं भूला जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर जिले के एक उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के प्रयासों में जुटी हुई है। अगर आप कभी सड़क मार्ग से दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून गये हैं तो मार्ग में एक छोटा सा कस्बा 'पुरकाजी' पड़ता है। एक जमाने में इस कस्बे की गुप्ता जी की चाट बहुत प्रसिद्ध थी। हर यात्री इस दुकान की चाट खाने से खुद को रोक नहीं पाता था। अब पुरकाजी में दर्जनभर चाट की दुकानें खुल चुकी हैं और सभी अपने को असली गुप्ता जी चाट वाले का वंशज बताते हैं।

भारत जितनी विविधताओं से भरा देश है उसकी कल्पना महानगरों में पले-बढ़े लोग नहीं कर सकते। यह ऐसा देश है जहां पेड़े भी फैक्टरी में बनते हैं। मथुरा वृन्दावन में पेड़े बनाने के थोक केन्द्रों को पेड़े बनाने वाली फैक्टरी ही कहा जाता है। वैसे भी जब सरकार 'वोकल फार लोकल' का उद्घोष करते हैं तो जलेबी की फैक्टरी होने पर किसी को ऐतराज क्यों हो सकता है। फिर चाहे व बनारसी साड़ी का मामला हो या यहां कि दूध, जलेबी, कचौरी या रबड़ी का। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमें खाद्य पदार्थ की फैक्टरी की जरूरत है। हल्दीराम की मिठाई व नमकीन भी विदेशों में निर्यात होती है और अमेरिका तक में जाती है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। मसलन मसालों को ही ले लीजिये। कितने उद्योगपति इस कारोबार में लगे हुए हैं। सभी के उत्पादन स्थलों को फैक्टरी ही बोला जाता है।

किसी को न करना पड़े ये 'सिग्नेचर': अनुपम खेर

बुजुर्ग सामान होते हैं, क्या एक उम्र बीत जाने के बाद वो किसी लायक नहीं रह जाते? जिन्होंने हमारी जिंदगी बनाने में उम्र बिता दी उनकी जिंदगी क्या महज कागज पर एक सिग्नेचर की मोहताज रह गई है, कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, एक जबर्दस्त अहसास होती हैं, वो आपको बदलने का मादा रखती हैं, जी-5 पर आई सिग्नेचर वैसी ही फिल्म है और ये फिल्म बताती है कि हम किस्मत वाले हैं जो अनुपम खेर जैसे शानदार एक्टर के दौर में जी रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, ये अपने आप में खुशकिस्मती ही है, वहीं पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत में अनुपम खेर ने अपनी आने वाली फिल्म को लेकर कई खुलासे किए।

फिल्म सिग्नेचर के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लेकर अनुपम खेर ने बताया कि जब इस तरह से ऑडियंस का प्यार मिलता है और मूवी को इतनी प्रशंसा मिलती है तो इससे एक एक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि यह फ़िल्म लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी और वो इस फ़िल्म से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आख़िर उन्होंने कहानी के बारे में बात करते हुए कहा कि यह कहानी एक कॉमनमैन के बारे में है जिसकी पत्नी भी वेंटिलेटर पर होती है और कैसे ज़िंदा रखने के लिए डॉक्टरों को पैसे देने के लिए और हॉस्पिटल्स का बिल भरने के लिए अपनी पूरी ज़मीन-जायदाद बेचकर उनके पैसे चुकाता है।

आप जब कोई रिलेटिव करैक्टर प्ले करते हैं तो उसके बाद ऑडियंस आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं तो उस तरह का प्यार जो आपको ऑडियंस से मिलता है तो आपको कैसा महसूस होता है ?

कॉमनमैन को पोर्ट्रे करना स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब आप किसी कॉमनमैन का करैक्टर प्ले कर रहे हों और ऑडियंस से कनेक्ट करना हो।

उन्होंने कहा कि वह भी एक मिडल क्लास फ़ैमिली से आते हैं वो एक आम आदमी रह चुके तो उससे उनको ऐसे में काफ़ी आसानी होती है। मैंने कई फ़िल्मों में कॉमनमैन का किरदार किया है तो मैं जानता हूं और अच्छे से समझता हूं कि आम आदमी को किस तरह से स्क्रीन पर उभार कर दिखाना है।

आजकल की जनरेशन जिस तरह से रिश्तों को निभाती है उसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं?

इस पर बात करते हुए अनुपम खेर ने बताया कि आज की जनरेशन का सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा लगाव है अपने इमोशंस को शुरू करने के लिए आज की जनरेशन सोशल मीडिया की हेल्प लेती वहीं पहले की जनरेशन इसे सामने से बयान करती थी।

पंजाब केसरी के पाठकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ?

पंजाब केसरी की सीएमडी श्रीमती किरण चोपड़ा उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं और आगे उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता किस तरह शुरू से ही पंजाब केसरी के अख़बार को पढ़ा करते थे और साथ ही उन्होंने पंजाब केसरी के सभी पाठकों को यह मैसेज दिया कि उनकी फ़िल्म 'सिग्नेचर' को ज़रूर देखें और फ़िल्म को ही अपना ख़ूब सारा प्यार दें।

कहां देख सकते हैं फ़िल्म सिग्नेचर ?

सिग्नेचर जी-5 पर प्रीमियर हो चुकी है और सभी ऑडियंस उसे देख सकते हैं और उसके साथ अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे।

जलवायु परिवर्तन : दोस्ती चाहती हैं आक्रामक प्रजातियां

डॉ. सत्यवान सौरभ

आक्रामक प्रजातियों को अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र के हानिकारक विघटनकारी के रूप में देखा जाता है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कुछ आक्रामक प्रजातियां पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सकती हैं। हालांकि वे मूल जैव विविधता के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं लेकिन नई परिस्थितियों में जल्दी से अनुकूलन करने की उनकी क्षमता कभी-कभी पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने या कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। विश्व प्राणी समुदाय में आक्रामक प्रजातियों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है जिससे देशी पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के बारे में व्यापक स्तर पर गलत धारणा बन जाती है। इस श्रेणी में गैर-देशी 'खरपतवार' से लेकर कीड़ों और जलीय आक्रमणकारियों तक की कई प्रजातियों को गलत समझा जाता है और अक्सर उनका गलत प्रबंधन किया जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जानबूझकर या अनजाने में पेश की गई अधिकांश प्रजातियां देशी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा नहीं करती हैं।

आक्रामक प्रजातियां वे पौधे, कीड़े और जलीय जीव हैं जो अपने वर्तमान आवासों के मूल निवासी नहीं हैं। वे अक्सर नए पारिस्थितिकी तंत्रों में फैल जाते हैं जिससे स्थानीय जैव विविधता बाधित होती है। इन प्रजातियों को गैर-देशी या पेश की गई प्रजातियां भी कहा जाता है। आक्रामक प्रजातियों के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। एक आम गलतफ़हमी है कि सभी आक्रामक प्रजातियां नए पारिस्थितिकी तंत्र में आने पर हानिकारक हो जाती हैं। जबकि कुछ महत्वपूर्ण ख़तरे पैदा कर सकती हैं, यह सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है। कई पेश की गई प्रजातियां अपने नए वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती हैं और वास्तव में लाभकारी भूमिका निभा सकती हैं।

आक्रामक प्रजातियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली आकस्मिक आगमन प्रजातियां अक्सर अचानक व अनजान तरीके से आती हैं जैसे कि ज़ेबरा मसल, जिसे ब्लैक सी से दूसरे क्षेत्रों में जहाजों में बैलस्ट पानी के माध्यम से पहुंचाया गया था, जहां यह तब से स्थानीय बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। दूसरी आक्रामक प्रजातियां जानबूझकर पेश की जाती हैं, जैसा कि लैंटाना के मामले में देखा गया है, जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा दक्षिण अमेरिका से भारत लाया गया था। लैंटाना का तेजी से प्रसार हुआ है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आदि जैसे कई राष्ट्रीय उद्यानों में देशी वनस्पतियों को मात देकर और कृषि फसलों को नुक्सान पहुंचाकर एक खतरा बन गया है जिससे स्थानीय जैव विविधता को खतरा है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि के साथ ही आक्रामक प्रजातियों के साथ हमारे संबंध भी विकसित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने में आक्रामक प्रजातियों के लाभ देखें तो कार्बन पृथक्करण में इनकी भूमिका है।

कुछ आक्रामक पौधों की प्रजातियों में महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा भारत में एक आक्रामक प्रजाति, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है जो निम्नीकृत भूमि में कार्बन भंडारण में योगदान करती है। स्पार्टिना अल्टरनिफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियां तटीय मिट्टी को स्थिर कर सकती हैं, कटाव को रोक सकती हैं

एवं समुद्र के बढ़ते स्तर के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा कर सकती हैं। कुछ आक्रामक प्रजातियां जैसे साइबेरियाई एल्म, अधिक सूखा-प्रतिरोधी हैं एवं जहां देशी प्रजातियां विफल हो जाती हैं, वहां वनस्पति आवरण प्रदान करती हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखा जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण देशी पौधों की कमी होने पर आक्रामक पौधों की प्रजातियां परागणकों के लिए खाद्य संसाधन प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी अमेरिका में लोनीसेरा जैपोनिका (जापानी हनीसकल) कुछ मौसमों के दौरान मधुमक्खियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। उन क्षेत्रों में जहां मूल जैव विविधता पहले ही नष्ट हो चुकी है, आक्रामक प्रजातियां पारिस्थितिक अंतराल को भर सकती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में आक्रामक नीलगिरी के पेड़ ने स्थानीय प्रजातियों के लिए आवास की मुहैया करते हुए वनों की कटाई वाले क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में मदद की है।

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन बंजर क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण पहल का समर्थन करता है। समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए आक्रामक प्रजातियों के प्रसार एवं प्रभाव को ट्रैक करने के लिए निरंतर निगरानी प्रणाली स्थापित करना। उदाहरण के लिए भारत की आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना विभिन्न राज्यों में फॉल आर्मीवर्म जैसी प्रजातियों की आवाजाही पर नजर रखती है। सार्वजनिक जागरूकता से संभावित प्रभावों के बारे में शिक्षित करते हुए आक्रामक प्रजातियों की निगरानी एवं नियंत्रण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए केरल में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में जलकुंभी, एक आक्रामक जलीय पौधा, को हटाने में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के लिए जानकारी एवं रणनीतियों को साझा करने के लिए सीमा पार सहयोग को मजबूत करना। उदाहरण के लिए जैविक विविधता पर कन्वेंशन में भारत की भागीदारी आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन पर जोर देती है। जबकि आक्रामक प्रजातियां महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लाभ प्रदान कर सकती हैं जैसे पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करना एवं कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना।

एक संतुलित दृष्टिकोण जो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभावों पर विचार करता है, पारिस्थितिक लचीलापन एवं जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देते हुए आक्रामक प्रजातियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किए गए कई प्रयास अप्रभावी और अत्यधिक समय की मांग करने वाले साबित हुए हैं। ये प्रजातियां अक्सर अपने पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई से समा जाती हैं जिससे उनका उन्मूलन मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए आक्रामक पौधों की प्रजातियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शाकनाशी अनजाने में देशी वनस्पतियों को नुक्सान पहुंचा सकते हैं जिससे तितलियों जैसी लाभकारी प्रजातियों में गिरावट आ सकती है।

...भर-भर कर शराब बंटवाते हैं

वो नशे के खिलाफ मुहिम चलाते हैं,
पर चुनाव आने पर भर-भर कर शराब बंटवाते हैं,
अब चुनाव पहले जैसे कहां नज़र आते हैं,
कितने मिलनसार हैं नेताजी जनता से, ये अब हमें उनके-
सोशल मीडिया के पोस्ट बताते हैं...!!

गीता पाढा

आरक्षण पर से 50 प्रतिशत की सीमा हटानी चाहिए : शरद पवार

सांगली (महाराष्ट्र), (भाषा): राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मौजूदा सीमा 50 प्रतिशत से अधिक करने के लिए संवैधानिक संशोधन लेकर आने की अपील की। हालांकि, शिवसेना ने सवाल किया कि पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले क्यों यह मुद्दा उठा रहे हैं? पार्टी ने जानना चाहा कि पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया ?

पवार ने यहां पत्रकारों से कहा कि आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मराठाओं को आरक्षण देकर इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के कदम से अन्य समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण की सीमा में कोई व्यवधान नहीं पड़े। उन्होंने कहा-अगर तमिलनाडु (विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण) 78 प्रतिशत कर सकता है तो महाराष्ट्र में 75 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं किया जा सकता।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

CMYK

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

आरक्षण की सियासत

अपने देश में आरक्षण पर ऐसी दुखद सियासत होने लगी है, जिसका तथ्य और तर्क से कोई लेना-देना नहीं है। मुंबई में राज्य सचिवालय में शुक्रवार को उस समय अजीब दृश्य सामने आया, जब विधानसभा के उप-सभापति नरहरि झिरवाल और तीन अन्य विधायक तीसरी मंजिल से कूद गए। यह तो भला हो कि नीचे पहले से ही जाल लगाकर सुरक्षा इंतजाम किया गया था। सुरक्षा इंतजाम न होता, तो आत्महत्या की यह कोशिश भारतीय विधायिका पर एक स्याह धब्बा लगा जाती। अगर एक विधायक को अपनी मांग मनवाने के लिए आत्महत्या करने की नौबत आ जाए, तो फिर विधायिका की समग्र व्यवस्था की मजबूती के बारे में क्या कहा जाए? हालांकि, यह सियासत है और विधायक कूदे, क्योंकि उन्हें पता था कि नीचे जाल है। वास्तव में, आत्महत्या की कोशिश का यह दिखावा कोरी सियासत है, उसके अलावा कुछ नहीं। विधायकों के इस कृत्य की सिर्फ निंदा हो सकती है। यह विधायिका को भी शर्मसार करने वाला पल है और इस पर सभी दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर वे देश के सामने कैसी जानलेवा सियासत पेश कर रहे हैं?

आत्महत्या का बहाना तो और भी दुखद है। यह सियासी कोशिश वास्तव में आरक्षण मांगने के लिए नहीं है, बल्कि एक जाति विशेष को मिलने जा रहे आरक्षण के विरोध में है। धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध विचारणीय हो सकता है, पर उसके लिए ठोस तर्क या विमर्श की जरूरत है। इन विधायकों को जब लगा कि उनका विरोध काम नहीं कर रहा है और धनगर समुदाय को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा, तब उन्होंने कूदने का दुस्साहस दिखाया। अब यह सोचने की बात है कि धनगर समुदाय के नेताओं और लोगों को कैसा लग रहा होगा? झिरवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट के सदस्य हैं। वास्तव में, यह पूरी पार्टी इन दिनों बहुत बेचैन है। सियासी लाभ और चुनाव जीतने के लिए इसके नेता हरसंभव दांव आजमा रहे हैं। उनका यह नया दांव पता नहीं कितना कारगर होगा, पर इससे सत्ता पक्ष और एकनाथ शिंदे की सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है। सरकार में भाजपा भी शामिल है और कूदने वालों में एक भाजपा विधायक भी शामिल बताए जाते हैं। वास्तव में, यह सत्ताधारी विधायकों की बेचैनी है। उन्हें इसी महीने चुनावी मैदान में जाना है। जहां आरक्षण मांगने वालों और आरक्षण का विरोध करने वालों, दोनों के भाग्य का फैसला होगा।

आरक्षण का सवाल वाकई अपने देश में बहुत गंभीर होता जा रहा है। कोई आरक्षण की मांग करता है, तो कोई उसके विरोध में आत्महत्या तक की कोशिश कर बैठता है।

वैसे सियासत से अलग आरक्षण का सवाल वाकई अपने देश में बहुत गंभीर होता जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, जब किसी को आरक्षण देने या किसी खास श्रेणी में आरक्षण देने का विरोध हो रहा है। राजस्थान में जब गुर्जरों ने अनुसूचित जनजाति में आने के लिए साल 2007 में रेल रोको आंदोलन किया था, तब भी एक दबंग अनुसूचित जनजाति के नेताओं ने विरोध किया था। उस त्रासद आंदोलन में 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे, नतीजा क्या हुआ, आज भी गुर्जरों को कमोबेश ओबीसी वाला ही लाभ मिल रहा है। गुर्जरों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो चुका है, पर गुर्जरों की मांग अभी भी जिंदा है। ऐसी अनेक जातियां हैं, जो अपने आरक्षण में बदलाव चाहती हैं, तो क्या तमाम पार्टियां मिलकर आरक्षण के मसले को हमेशा के लिए सुलझाएंगी?

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 05 अक्तूबर, 1949

राजस्थान का बजट

संयुक्त राजस्थान का १ अक्तूबर १९४९ से ३१ मार्च १९५० तक का प्रथम छमाही बजट हमारे सामने है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के बाद यह पहला बजट तैयार हुआ है। राजस्थान में धारासभा तो है नहीं, इसलिये मंत्रिमंडल ने ही उस पर अपनी मंजूरी दे दी है। यह सन्तोष का विषय है कि यह घाटे का बजट नहीं है। उसमें आय ८,८३,५३,००० रुपये और व्यय ८,२३,५०,००० रुपये अनुमान किया गया है। इस प्रकार बजट में ६० लाख रुपये की बचत बताई गई है। राजस्थान के प्रधानमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री ने (तब राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था) पिछले दिनों अपने भाषणों में अनेक बार ऐसे उद्गार प्रकट किये थे, जिनसे यह आशंका हो गई थी कि संयुक्त राजस्थान को अपने जीवन के प्रारंभ काल में खासा घाटे का सामना करना पड़ेगा। यह आशंका अकारण नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में शामिल होने वाली अधिकांश रियासतों की आय कम और व्यय बढ़ा हुआ था। यह आशंका सच नहीं निकली और राजस्थान मंत्रिमंडल ने अगले ६ मास का बजट संतुलित कर दिया, इसके लिए वह बधाई का पात्र है।

किंतु राजस्थान के प्रधानमंत्री ने साथ ही एक चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ६० लाख की बचत को वास्तविक बचत मानना ठीक न होगा; क्योंकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना होगा। आकस्मिक खर्चों की उससे पूर्ति की जायेगी। राष्ट्र-निर्माणकारी विभागों की नई योजनाओं और विकास की सामान्य योजनाओं के लिए भी इसी बचत का उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार राजस्थान सरकार यदि सब की सब बचत को खर्च भी कर दे, तो भी बजट संतुलित ही रहेगा। संयुक्त राजस्थान की स्थापना को लगभग ६ महीने हो चुके हैं। इस काल में करीब ४० लाख रुपये का घाटा होगा। घाटे में यह कमी, प्रधानमंत्री का कहना है कि खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखने के कारण संभव हो सकी है। कई मर्तबा ऐसा अनुमान होता है कि सार्वजनिक पैसे को बेदर्दी से खर्च किया जाता है। हमारी राय में यह सर्वथा अनुचित है। व्यक्ति अपने पैसे खर्च करने में जितनी सावधानी बरतता है, उससे कहीं अधिक सावधानी सार्वजनिक कोष को खर्च करने में बरती जानी चाहिए।

भारत एक शांतिप्रिय देश है। दुनिया में कहीं भी युद्ध की स्थिति बनती है, तो यहां चिंता हावी हो जाती है। आजादी मिलने के बाद 1950 के दशक में भी बार-बार महायुद्ध की स्थिति बनती थी। 17 दिसंबर, 1957 को लोकसभा में वैश्विक स्थिति पर हुई चर्चा आज भी राह दिखाती है।

हमें दुनिया में कमजोरों के लिए लड़ना चाहिए

यहां स्कैन करें

श्रीपाद अमृत डांगे | सांसद व वरिष्ठ वामपंथी नेता

- विशिष्ट स्वार्थ ही दुनिया में युद्ध को जन्म देते हैं, जनता नहीं।
- शांति के लिए सोवियत संघ तैयार है, लेकिन अमेरिका नहीं।
- प्रधानमंत्री ने अफ्रीका की समस्या का उल्लेख तक नहीं किया है।

प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर पर शस्त्रों की वर्तमान होड़ की परिस्थिति में शांति के प्रश्न पर उचित ही जोर दिया है, लेकिन इस संबंध में जनता को यह बताना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का दो विभिन्न देशों में किस प्रकार का अर्थ लगाया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक देश ने तो अणु के विखंडन से अणु बम बनाकर उसका प्रयोग भी संहार के लिए कर दिया था, दूसरी ओर, सोवियत संघ ने उसी अणु विखंडन से अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया है और उसका उपयोग अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजने के लिए किया है...। जनता को यह बताना जरूरी है कि युद्ध इन यंत्रों के कारण नहीं होता, युद्ध छेड़ने के पीछे कुछ निहित स्वार्थ रहते हैं। ये विशिष्ट स्वार्थ ही युद्ध को जन्म देते हैं, जनता नहीं। ...जनता को इस चीज को देखना चाहिए कि कौन यंत्रों का उपयोग युद्ध और कौन शांति के लिए करता है। ...सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक उपग्रह का छोड़ा जाना एक महानतम घटना है। उसका प्रभाव केवल वैज्ञानिक क्षेत्रों पर ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा है। इंग्लैंड के *इकोनॉमिस्ट* ने लिखा है कि उसने अरब देशों और मध्य पूर्व की जनता को बल दिया है और उन्हें पश्चिमी देशों के विरुद्ध खड़े होने का अधिक साहस प्रदान कर दिया है।

स्पुतनिक ने कम विकसित देशों की जनता के स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया है। स्पुतनिक ने शांति की भावना को बल दिया है। उसने युद्ध की गुहार मचाने वालों का उत्साह ठंडा कर दिया है। ...सोवियत संघ के पास अंतर्महाद्वीप प्रक्षेपास्त्र होने से शांति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ...अमेरिका के पास इतनी दूर मार सकने वाले प्रक्षेपास्त्र नहीं हैं। ...युद्ध समर्थकों का मोर्चा नाटो टूटता जा रहा है और उसका मूल कारण स्पुतनिक है।

...आइजनहावर (अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष) और बुल्गानिन (सोवियत राष्ट्राध्यक्ष), दोनों ही अणु परीक्षणों को स्थगित करने के लिए तैयार दिखते हैं, पर... अमेरिका केवल इसी शर्त पर उन्हें स्थगित करने को तैयार है कि पहले निःशस्त्रीकरण-समस्या का हल कर लिया जाए, पर बुल्गानिन ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। आशा है, अमेरिका भी हमारे प्रधानमंत्री की बात शीघ्र मान लेगा।

...हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम डच साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में इंडोनेशिया का पूरा साथ देंगे। यह इसलिए कि पेट्रोल आदि के एकाधिकारी इंडोनेशिया की आजादी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ... हमें भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने यहां के मजदूर वर्ग की शक्ति को अनदेखा नहीं करना चाहिए।...

प्रधानमंत्री ने अफ्रीका का उल्लेख तक नहीं किया है। हमारा दल अल्जीरिया की जनता के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने वाली भारत सरकार की नीति का समर्थन करता है, पर अल्जीरिया के निकट ही दक्षिण अफ्रीका भी स्थित है, जो अफ्रीकी जनता पर जातिवादी नीति थोपने की कोशिश कर रहा है। ...हमें सर्वदा यह याद रखना चाहिए कि हमने अभी यह निश्चित नहीं किया है कि अफ्रीका के बारे में भारत की क्या नीति होनी चाहिए। ...तीस वर्ष पहले हमारी नीति थी कि नीग्रो व सरकार के झगड़ों के बीच कोई भाग न ले। अब हमारी नीति बदल गई है। ...कश्मीर के बारे में मैं तथा मेरा दल, सरकार समर्थक है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर ग्राहम की आवभगत अवश्य करें, पर इस बारे में कोई और बातचीत न करें। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करना उचित नहीं था, परंतु यदि गिरफ्तार किया भी गया था, तो चार वर्ष बहुत होते हैं और अब उनको छोड़ दिया जाना चाहिए।

गोवा के बारे में कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए व शांति से काम लेना चाहिए। परंतु जब इंडोनेशिया आदि की जनता स्वतंत्रता के लिए लड़ सकती है, तो हमें भी एक अवसर दिया जाना चाहिए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

आमने-सामने

सबको युद्ध से बचाना अभी ज्यादा जरूरी

यहां स्कैन करें

जवाहरलाल नेहरू | तत्कालीन प्रधानमंत्री

- दुनिया की समस्याएं सशस्त्र शक्ति से हल नहीं की जा सकतीं।
- हमने सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों से ही शांति की अपील की है।
- अफ्रीका के संबंध में नीति स्पष्ट है, हम अफ्रीका से जंग नहीं छेड़ सकते।

मैंने वर्तमान समय के दो सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के नाम की गई अपील का जिक्र किया था, क्योंकि युद्ध और शांति व मानवता का भविष्य इन्हीं दो देशों पर अधिकतर निर्भर है। उन्होंने उस अपील का विस्तृत उत्तर दिया है और औचित्यपूर्ण तर्कों से अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके उत्तरों के लिए कृतज्ञ हूं और मैं समझता हूं कि सभा को भी कृतज्ञ होना चाहिए। ... हम भारत के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, पर आज विश्व का इतिहास अन्य देशों की तरह भारत के इतिहास से इस प्रकार संबंधित है कि हम अपने दायित्व से बचकर नहीं जा सकते। ...हम ऐसे माननीय सदस्य की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं, जो अपनी ही निराली दुनिया में रहते हैं और अपने 30 वर्ष पुराने विश्व भ्रमण के आधार पर बोलते हैं। हम वर्तमान संसार में रहते हैं, भूतकाल में नहीं और वर्तमान के आधार पर हम भविष्य का निर्माण चाहते हैं। ...

विश्व की वर्तमान स्थिति बहुत नाजुक है और यदि यही प्रवृत्ति कायम रही, तो स्थिति बहुत गंभीर और खतरनाक हो सकती है। हमें इस स्थिति के संबंध में जागरूक रहना है और इस उत्तेजना या वर्तमान प्रवृत्ति को रोकना है। इसीलिए मैंने इन सब बातों का जिक्र किया, क्योंकि इसकी तुलना में अन्य बातें अपेक्षाकृत कम महत्व रखती हैं। ...संभव है, हमें कश्मीर के संबंध में कोई लाभ न हुआ हो, अपितु हानि ही हुई हो, तथापि हमारी नीति से अन्य रूप में पर्याप्त लाभ हुआ है। ...

फिलहाल, सारा प्रश्न ही निःशस्त्रीकरण के चारों ओर केंद्रित है। मैंने रूस और अमेरिका से किसी खास चीज पर प्रतिबंध लगाने पर जोर नहीं दिया था। इतना जरूर था कि इसके पहले कदम के रूप में मैंने आणविक परीक्षणों को रोकने का जिक्र किया था। ...दुनिया के लोग युद्ध से घबराते हैं, विनाश से डरते हैं। ...अब समय आ चुका है कि जब इस मामले का संबंधित देशों द्वारा सीधे ही आपसी बातचीत से एक-दूसरे की आलोचना न करके, जैसा वे करते रहे हैं, हल करना चाहिए। ...अब दुनिया ऐसी स्थिति में है, जहां समस्याएं सशस्त्र शक्ति से हल नहीं की जा सकती। प्रायः कहा जाता है कि रोटी अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु केवल रोटी से ही सारी मानव जाति की प्रगति नहीं होती है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि खाली फौजी ताकत काफी नहीं है। उल्टे यह बड़ा जबरदस्त खतरा बन गई है। ... श्री डांगे ने कहा कि आप लोगों को क्यों कार्रवाई की अनुमति नहीं देते? इसका उत्तर यही है कि हम उस पहलू में स्वयं आए बिना लोगों को ऐसा करने की मंजूरी नहीं दे सकते। ...जो लोग गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए वहां गए हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, वह बहुत बुरा हुआ है और हम नहीं समझते कि हम अपने नवयुवकों को ऐसे कार्य के लिए आगे बढ़ावा दें। ...एक समय आ सकता है, जब हम कोई कार्रवाई करें, यह अलग बात है।...

श्री डांगे ने अफ्रीका के लोगों के संबंध में जो कहा है, उस पर मैं कहना चाहता हूं। मैं उनकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अफ्रीका आदि देशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में हमारी नीति स्पष्ट रही है।... माननीय सदस्य पूछ सकते हैं, सरकार क्या करने जा रही है? ...हम अफ्रीका से जंग तो नहीं छेड़ सकते। हमें यह काम संयुक्त राष्ट्र संघ में ही करना है और वहां अपनी ताकत बढ़ानी है। ...हमें पाकिस्तान मामले में तथा शेष संसार के अन्य देशों के साथ भी व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए। आज संसार भर में जो अशांति फैली हुई है, उसे हटाने के लिए हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने अपनी अपील में प्रेसीडेंट आइजनहावर और बुल्गानिन से भी प्रार्थना की है कि हमें इन आणविक शस्त्रों पर कुछ रोक लगानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें महात्मा बुद्ध की बात याद रखनी है कि हमें इस प्रकार की विजय चाहिए, जिसमें किसी की भी पराजय न हो।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

हमें परस्पर जोड़ते नवरात्रि जैसे अखिल भारतीय त्योहार

यहां स्कैन करें

जवाहर सरकार | पूर्व सांसद और पूर्व संस्कृति सचिव

कई लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है कि प्राचीन भारतीय धर्म- हिंदू, बौद्ध और जैन (सिख इतना पुराना नहीं है) कैसे हजारों सालों से जीवित हैं और समृद्ध होते रहे हैं? वह भी *बाइबिल* या *कुरान* जैसे पवित्र धर्मग्रंथों और मक्का, वेटिकन या येरुशलम के मार्गदर्शन के बिना। दरअसल, किसी एक केंद्रीय सत्ता या समान प्रारूप का न होना ही इसकी वास्तविक वजह है। हिंदू धर्म में निहित सहिष्णुता और इसके संघीय स्वरूप ने ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग भूगोल में बिखरी 'राष्ट्रीयताओं' को बिना किसी जोर-आजमाइश के एक किया है। इसमें अखिल भारतीय त्योहारों ने मुख्यतः छतरी का काम किया है, जिसके नीचे स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को सार्वभौमिक स्वीकृति मिली। नवरात्रि से इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं।

सभी हिंदू शरद ऋतु के इन नौ दिनों और दस रातों पर एकमत हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इनका पालन अलग-अलग होता है। मोटे तौर पर हम नवरात्रि की व्याख्या तीन क्षेत्रों में बांटकर कर सकते हैं- उत्तर व पश्चिम, पूर्व व कुछ पूर्वोत्तर और तीसरा हिस्सा, दक्षिण। उत्तर और पश्चिम में नौ दिनों तक उपवास व संयमित खान-पान का प्रचलन है, लेकिन यहां दशहरा का जश्न रावण पर राम की जीत के रूप में मनाया जाता है। पूर्व व पूर्वोत्तर राम का नहीं, बल्कि दुर्गा का, वह भी उनके सबसे उग्र रूप का उल्लास मनाता है और बुराई (महिषासुर) पर उनकी जीत की विजयादशमी मनाता है। मगर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश व मैसूरु में न तो राम और न ही दुर्गा, बल्कि पांडवों की जीत का जश्न है नवरात्रि।

दक्षिण में नवरात्रि के दौरान अलग-अलग देवियों की पूजा भी की जाती है। तमिल पहले तीन दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अगले तीन दिन पार्वती या दुर्गा की। आखिरी के तीन दिन सरस्वती का पूजन होता है। हमें लकड़ी के तख्तों पर रखी गई कई गुड़ियों की आकर्षक प्रदर्शनी देखने को मिलती है, जिन्हें बोम्बई कालू या इसी तरह के अन्य नामों से पुकारते हैं। नवरात्रि के अंत में महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे दक्षिणी राज्यों में अस्त्र पूजा की जाती है, जिसमें औजारों व यंत्रों की पूजा होती है, ठीक गंगा के मैदानी इलाकों, बंगाल और पूर्वी हिस्सों में मनाई जाने वाली विश्वकर्मा पूजा की तरह। उत्तर और दक्षिण भारत नौ दिनों में देवी के नौ रूपों की समान पूजा करते हैं, लेकिन पूर्व में बंगाल व उसके पड़ोसी राज्यों में सिर्फ अंतिम तीन दिन और दसवें दिन का जश्न मनाया जाता है। वे खान-पान में कोई प्रतिबंध नहीं रखते, लेकिन मछली-मांस ज्यादा पसंद करते हैं। राजस्थान के कुछ राजपूत परिवार तो बकरे और भैंसों की बलि भी देते हैं।

हिंदू धर्म में निहित सहिष्णुता और इसके संघीय स्वरूप ने ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग भूगोल में बिखरी 'राष्ट्रीयताओं' को बिना किसी जोर-आजमाइश के एक किया है।

स्थानीय रीति-रिवाज अखिल भारतीय त्योहारों में किस कदर रच-बस जाते हैं, इसे भी नवरात्रि मनाने के तरीके से समझा जा सकता है। मसलन, महाराष्ट्र में इसे घटस्थापना उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मिट्टी के एक घड़े में पानी भरकर उसे गीली मिट्टी के आधार पर रखते हैं और उस पर सात प्रकार के खाद्यान्न बोते हैं, जो इन नौ दिनों में अंकुरित होते हैं। गुजरातियों को पता है कि घड़ा उर्वरता का प्रतीक है और वे इसे गर्भ कहते हैं। उनका प्रसिद्ध नृत्य गरबा घड़े के चारों ओर ही होता है, जिसमें एक जलता दीपक रखते हैं। हालांकि, डांडिया रास से मिलन के बाद गरबा का ज्यादातर हिस्सा बदल गया है। गोवा में बर्तन तांबे का होता है और कई अन्य समुदायों ने भी इस दौरान दाल, अनाज, जौ या अन्य बीज बोना शुरू कर दिया है। बंगाल में भी नवपत्रिका, यानी केला, हल्दी, बेल, अनार और धान जैसे नौ पौधों की पत्तियों को दुर्गा पूजा के पहले दिन (सप्तमी) घुटने भर पानी में पवित्र किया जाता है और केला के पौधे व अन्य पत्तियों को साड़ी में लपेटकर कोला बौ (एक हरी दुल्हन) के रूप में देवी के साथ पूजा जाता है।

जाहिर है, विविधता को समेटने की यही भावना लाखों लोगों को एक साथ लाती है। अलग-अलग क्षेत्रों के अनुष्ठान और त्योहार किस कदर एक-दूसरे के करीब आते गए, इसकी पड़ताल मानव विज्ञानी कर सकते हैं। मगर धर्मांतरण सैद्धांतिक रूप से हिंदू धर्म का घटक नहीं है, बल्कि इसमें मतों व रीति-रिवाजों को एकरूप बनाने वाली भावना का लगभग अभाव ही रहा है। लिहाजा, हिंदू धर्म को एकरूप बनाने का कोई भी प्रयास विरोधाभासी ही साबित होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

दोस्ती की आग

अली नाम के एक व्यक्ति को पैसों की जरूरत थी। उसने अपने मालिक से मदद मांगी। मालिक ने उसके सामने एक चुनौती रख दी कि अगर वह एक पूरी रात पहाड़ की चोटी पर बिताएगा, तो वह उसे बहुत बड़ा इनाम देगा; लेकिन यदि वह असफल हुआ, तो उसे मुफ्त में काम करना होगा।

दुकान से बाहर निकलते समय अली ने देखा कि बर्फीली हवा चल रही थी। उसे डर लगा और उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त ईदी से सलाह-मशविरा करने का फैसला किया कि कहीं मालिक की शर्त मानकर उसने पागलपन का मुजाहिरा तो नहीं किया?

अली की पूरी बात पर कुछ पल विचार करने के बाद ईदी ने उससे कहा : 'चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल रात, जब तुम पहाड़ की चोटी पर बैठो, तो बिल्कुल आगे की ओर देखना। मैं सामने वाले पहाड़ की चोटी पर रहूंगा, जहां पर मैं तुम्हारे लिए पूरी रात आग जलाए रखूंगा। तुम आग को देखना और हमारी दोस्ती के बारे में सोचना; और यह तुम्हें गरम रखेगा। तुम आसानी से रात निकाल लोगे, और बाद में मैं तुमसे इसके बदले में कुछ मांगूंगा।'

ठीक वैसा ही हुआ। अली के सामने वाले पहाड़ की चोटी पर ईदी ने रात भर अलाव सुलगाए रखा और अली भी एकटक उसे निहारता रहा। उसने शर्त जीत ली। मालिक से इनाम की रकम लेकर वह अपने दोस्त ईदी के घर पहुंचा और बोला, 'तुमने कहा था कि तुम बदले में कुछ मांगोगे, मांगो?'

ईदी ने कहा, 'हां दोस्त, मगर वह पैसा नहीं है। वादा करो कि अगर कभी मेरी जिंदगी में ठंडी हवा चली, तो तुम मेरे लिए दोस्ती की आग जलाओगे।'

पाउलो कोएल्हो

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

पाली और प्राकृत भाषाओं को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा देकर सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण-संवर्द्धन के प्रति कटिबद्धता दर्शाई गई है। ये भाषाएं भारतीय ज्ञान परंपरा को फिर दुनिया भर में ले जाने का माध्यम बनेंगी।

तीसरे महायुद्ध की कोई आशंका नहीं

जो लोग इस जंग को विश्व युद्ध की शुरुआत समझ रहे हैं, उनको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल पर ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। नाराज इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपने यहां प्रतिबंधित कर दिया है। यानी, संयुक्त राष्ट्र मौन रूप से ईरान का समर्थन कर रहा है! ऐसी परिस्थिति में विश्व युद्ध की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। हां, इजरायल समर्थक देशों द्वारा मध्यस्थता का प्रयास किया जा सकता है! ईरान को पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पश्चिम एशिया में इस समय अमेरिका के लगभग एक लाख सैनिक अलग-अलग देशों में तैनात हैं और अगर कोई अनहोनी होती है, तो उसके सैनिकों व अड्डों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है!

अली जमीर रिजवी, टिप्पणीकार

सभी नुकसान से वाकिफ

ईरान और इजरायल के बीच अभी जो तनाव बढ़ा है, उसमें कई बुद्धिजीवी तीसरे विश्व युद्ध के बीज ढूंढ़ रहे हैं। मगर यह फिलहाल असंभव है, क्योंकि लगभग सभी देश यह जानते हैं कि विश्व युद्ध मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध चाहे किसी भी युग में क्यों न हो, हमेशा बर्बादी ही लाता है। हकीकत यही है कि जब कभी कुछ सत्ताधारियों ने अपने अहं के कारण युद्ध छेड़ा है, तो उसमें बेकुसूर और निहत्थे लोगों को ही सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। फिर, दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो, उसका बुरा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि सभी देश एक-दूसरे पर किसी न किसी रूप में थोड़े-बहुत निर्भर हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनातनी का दायरा यदि बढ़ता है, तो विश्व को आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि एक तरफ तेल की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी, तो दूसरी तरफ कारोबारियों का माल अटक सकता है। यही नहीं, अब जिस तरह से मिसाइलों से हमले किए जाते हैं, इनका पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ना तय है। ऐसे में, सभी जिम्मेदार नेताओं को इजरायल-ईरान के आपसी तनाव को कम करने की दिशा में सक्रिय हो जाना चाहिए। अभी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जिससे जलती आग में घी पड़ जाए। विश्व युद्ध कितना भयावह होता है, वह कोई जापान से पूछ ले। बेशक इस देश ने आज अच्छी-खासी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके सीने पर लगे महायुद्ध के घाव अब भी टीस देते रहते हैं, जबकि वह तो दूसरा विश्व युद्ध था। आज कई देशों के पास मानव संहारक हथियार हैं, इसलिए तीसरा महायुद्ध कहीं अधिक विध्वंसक होगा।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

तीसरा महायुद्ध

इसे महायुद्ध की पटकथा ही कहेंगे

ईरान के बहुप्रतिक्षित हमले के बाद संभवतः तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। अभी तक टुकड़े-टुकड़े में जंग जारी थी, लेकिन अब ईरान आर-पार की मुद्रा में सामने आ गया है। इजरायल पर मिसाइल दागने के बाद उसने कहा भी कि वह हमास व हिजबुल्लाह नेताओं की मौत का बदला ले रहा है और अगर अब इजरायल ने कोई प्रतिक्रिया दी, तो तनाव और बढ़ेगा। शनिवार का उसका बयान भी आक्रामक था। वास्तव में, यह लड़ाई यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व और शिया मुस्लिम बहुल देश ईरान व उसके छद्म गुटों के बीच वर्चस्व की जंग है। इजरायल के साथ अमेरिका और उसके मित्र देश हैं, तो हमास के साथ इस्लामिक दुनिया के देश। वैसे, इस यहूदी और शिया की लड़ाई में हम हिंदू बहुल देश का क्या काम, लेकिन यह चिंता तो बनी ही हुई है कि अगर इस युद्ध का विस्तार हुआ, तो हमारा रुख क्या होगा? सवाल महाशक्तियों पर भी है। विशेषकर रूस करीब-करीब तीन साल से यूक्रेन से उलझा हुआ है, जबकि अमेरिका परोक्ष रूप से कीव की मदद कर रहा है। ऐसे में, यूरोपीय राष्ट्र, अमेरिका और पश्चिम एशियाई देश, सभी युद्ध में उलझे हुए दिख रहे हैं। तो, जब इतनी बड़ा क्षेत्र जंग में शामिल है, तो इसे विश्व युद्ध की पटकथा नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे?

पवन सिंह, टिप्पणीकार

संयम बरतें नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों कुछ ज्यादा आक्रामकता दिखा रहे हैं, इसलिए वह कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। मगर उनको भारत से सीख लेनी चाहिए और अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। इसमें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनका कद तो बढ़ेगा ही, इजरायल के लोगों को भी राहत मिलेगी। इससे तीसरे विश्व युद्ध के सज चुके मंच पर भी परदा गिर सकेगा। जो लोग इस मुगालते में हैं कि अहिंसा से क्या हो सकता है, तो उनको भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए कि कैसे सिर्फ धोती पहनने वाला एक नंगा फकीर अपनी लाठी से अंग्रेजों की बंदूकें खामोश कर गया और उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए अब तय नेतन्याहू को करना है कि वह इतिहास के पन्नों में किस रूप में जगह पाना चाहते हैं- एक ऐसे नेता के रूप में, जो तीसरे विश्व युद्ध का कारक बना, या ऐसे नेता के रूप में, जिसने महायुद्ध को होने से रोक दिया? उम्मीद है, इजरायल के प्रधानमंत्री पर अंतरराष्ट्रीय दबाव तेज किया जाएगा और अलग-अलग मोर्चे पर चल रहे उसके युद्ध को खत्म करने में सफलता हासिल की जाएगी। मानवता का यही तकाजा है।

आशुतोष, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

संवाद से ही विवाद का समाधान संभव है

प्रसाद की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बीयुक्त घी का इस्तेमाल किए जाने के मामले में विशेष जांच दल का गठन करके आंध्र सरकार की ओर से की जाने वाली जांच को लेकर उठ रहे संदेह को खत्म करने का काम किया है। आशा की जानी चाहिए कि पांच सदस्यीय विशेष जांच दल इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने में सफल होगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को तैयार करने में अशुद्ध घी का इस्तेमाल किए जाने का आंध्र के मुख्यमंत्री का आरोप बहुत ही सनसनीखेज था। इस आरोप ने हिंदू समाज को विचलित किया, क्योंकि कोई यह सोच भी नहीं सकता कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल होता है, उसमें पशुओं की चर्बी प्रयुक्त होती है। ऐसा होने की आशंका इसलिए गहरा गई थी, क्योंकि यह सामने आया था कि घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी उसे लगभग चार सौ रुपये प्रति किलो में उपलब्ध कराती थी। इतना सस्ता घी तो तभी मिल सकता है, जब उसमें कोई मिलावट की जाए, क्योंकि दूध की औसत कीमत 45-50 रुपये प्रति लीटर है और एक किलो घी तैयार करने में 20 से 25 लीटर दूध चाहिए होता है। स्पष्ट है कि यह जानने की जरूरत है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए इतना सस्ता घी कैसे उपलब्ध कराया जा रहा था और यदि उसमें मिलावट की जा रही थी तो किस चीज की? यदि देश में कहीं पर भी पांच-छह सौ रुपये में एक किलो घी उपलब्ध हो रहा है तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। प्रश्न यह है कि इसकी जांच कौन करेगा कि विभिन्न कंपनियां पांच-छह सौ रुपये में घी कैसे उपलब्ध करा रही हैं?

अपने देश में खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट कोई नई बात नहीं है। खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट रुके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विभिन्न एजेंसियां खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए सक्रिय रहती हैं, क्योंकि उनकी सक्रियता निष्प्रभावी ही साबित हो रही है। तिरुपति मंदिर का मामला केवल यह जानने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि उसके प्रसाद में पशुओं की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल होता था या नहीं? इस मामले ने यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि आखिर हिंदुओं के मंदिरों का संचालन सरकारों को क्यों करना चाहिए? यदि अन्य समुदायों को अपने धार्मिक स्थलों के संचालन का अधिकार मिला हुआ है तो ऐसा ही अधिकार हिंदू समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह वह प्रश्न है, जो अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि राज्य सरकारों की ओर से संचालित हिंदू मंदिरों की देख-रेख सही तरीके से नहीं हो रही है।

अमानवीय व्यवहार

बिहार सरकार पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बेहतर पुलिसिंग के लिए हर स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का सोच है कि आमजन को आवश्यकता पड़ने पर जल्द से जल्द पुलिस से मदद मिल सके। किंतु, कुछ घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस अपने रवैये में सुधार के लिए शायद तैयार नहीं है। हाल ही में कैमूर जिले में खेत में सांप काटने के बाद भागकर घर जा रहे व्यक्ति को गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उससे पैसे वसूलने के लिए इतना समय जाया किया कि जहर उसके शरीर में फैलता चला गया और अंततः उसकी मौत हो गई। वह उनसे बार-बार कहता रहा कि उसे सांप ने काट लिया है। यहां पुलिसकर्मियों की नजर में यदि वह गलत भी था, तो मानवता के नाते उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। एक अन्य घटना राजधानी पटना में हुई, जिससे साफ है कि किसी भी थाने में आज भी प्राथमिकी कराना आसान नहीं है। जल संसाधन विभाग के एक कर्मचारी से फरवरी में साइबर ठगी हुई। उस वक्त वह व्यक्ति तमाम संबंधित जगहों पर दौड़ता रह गया, लेकिन उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। उसी के साथ फिर सितंबर में फ्राड हुआ, तब उसने वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई तो दोनों ही मामलों की प्राथमिकी दर्ज की गई। जाहिर है, जब आम आदमी इतना परेशान हो जाएगा तो पुलिस कतई उसका भरोसा नहीं जीत सकती। वरीय अधिकारियों तक बात पहुंचने पर भले ही कार्रवाई हो जाती है। जाहिर है, पुलिस के कामकाज की व्यवस्था पारदर्शी करने के साथ-साथ उसकी विभिन्न स्तरों पर कड़ी मानीटरिंग करनी होगी तथा घोर लापरवाह कर्मियों को बर्खास्त करने के साथ कठोर दंड भी देना होगा।

> जब तक लोग थाना जाने पर सहज महसूस नहीं करेंगे, तब तक स्वस्थ पुलिसिंग की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती

विश्व शांति के लिए खतरा बना ईरान

दिव्य कुमार सोती

खोमैनी ने इस्लामिक शासन का जो कट्टरवादी माडल मुस्लिम जगत के सामने पेश किया, उससे दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावित हुए हैं

हिजबुल्ला के मुखिया हसन नसरुल्ला की इजरायली हमले में मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव की आग और भड़क गई है। नसरुल्ला की मौत के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला बोला। इजरायल ने इन मिसाइल हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। इससे पहले इजरायल ने ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ढेर किया था, लेकिन तब ईरान ने इजरायल पर कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। इस बार लेबनान में विभिन्न इलेक्ट्रानिक उपकरणों में विस्फोटों के जरिये हजारों हिजबुल्ला आतंकियों के घायल होने और कई के मारे जाने और फिर नसरुल्ला की मौत के बाद ईरान अत्यंत मजबूर दिखने लगा और उसके द्वारा समर्थित विभिन्न आतंकी गुटों के भीतर ही ईरान की इजरायल नीति को लेकर आवाजें उठने लगी थीं।

ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के चलते आयतुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में बनी कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार ने पूरे पश्चिमी एशिया में आतंकी संगठनों का जाल बिछाया। इस्लामिक जगत का नेतृत्व शिया वर्ग के हाथ में लेने के लिए खोमैनी के नेतृत्व वाले ईरानी शासनतंत्र ने पूरे विश्व के मुस्लिम मानस को प्रभावित करने वाले फलस्तीन के मुद्दे को चुना और इजरायल के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के लिए हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। शिया और सुन्नी इस्लाम के समीकरणों की एक खास बात यह है कि कोई सुन्नी मुसलमान शिया भी बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम जगत में शिया अल्पसंख्यक हैं। इसलिए खोमैनी के कठमुल्ला तंत्र के लिए यह आवश्यक था कि वह सुन्नी अतिवादियों के भी एक तबके को अपने साथ ले। चूंकि अधिकांश सुन्नी अतिवादी शिया इस्लाम के कट्टर विरोधी हैं और आर्थिक रूप से सुन्नी अरब देशों पर निर्भर रहे हैं, इसलिए ईरान के लिए यह चुनाव आसान नहीं था। ऐसे में सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड की फलस्तीन इकाई यानी हमास ईरान का औजार बनी।

खोमैनी ने इस्लामिक शासन का जो कट्टरवादी माडल मुस्लिम जगत के सामने पेश किया, उससे दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावित हुए। इसका एक परिणाम यह हुआ कि अरब जगत की तमाम सेक्युलर सरकारें और तानाशाह धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता खोते गए और इस्लामिक कट्टरपंथी मजबूत होते गए। जो सुन्नी राजशाहियां इस लहर में बच भी पाईं, उन्होंने अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए दूसरे देशों में सुन्नी जिहादी संगठनों का समर्थन करना शुरू किया, जिसकी परिणति अलकायदा से लेकर तालिबान जैसे तमाम सुन्नी आतंकी संगठनों के उदय के रूप में हुई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तो खोमैनी के कठमुल्ला शासन का सुन्नी संस्करण ही थी। तालिबान सरकार के 1996 में सत्ता में आने पर उसे तीन देशों से ही मान्यता मिली थी-सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान। इनमें से पहले दो देशों का उद्देश्य ईरान से सटे अफगानिस्तान में खोमैनी के शिया इस्लामिक राष्ट्र जैसा ही एक प्रतियोगी सुन्नी शासनतंत्र खड़ा करना था, जिसका प्रमुख भी एक कट्टरपंथी मौलाना हो और जहां सुन्नी कट्टरपंथियों को इकट्ठा रखकर उनकी शक्ति को दूसरे देशों की ओर निर्देशित रखा जा सके। खोमैनी की इस्लामिक क्रांति का एक और प्रभाव यह भी हुआ कि दुनिया भर के अशांत मुस्लिम क्षेत्रों के लोगों को लगा कि हिंसा के माध्यम से सत्ता को पलटा जा सकता है। खोमैनी ने मुस्लिम जगत में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इस भावना को खूब हवा भी दी और फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक के मुसलमानों को अपने भाषणों के जरिये उकसाया। ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सुन्नी देशों ने आतंकी संगठनों की सहायता की। इस प्रकार यह एक दुष्चक्र बन चुका है, जिस कारण लाखों लोग जान गंवा चुके हैं।

अवधेश राजपूत

भारत के ईरान के साथ संबंध ठीक-ठाक ही रहे हैं और सुन्नी पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए दोनों देशों ने कई स्तरों पर साथ काम भी किया है, लेकिन ईरान की ओर से ये संबंध बस यहीं तक सीमित रहे हैं। वह पाकिस्तान के सुन्नी कट्टरपंथियों को बस खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता। खोमैनी के कठमुल्लावाद में भी भारत के लिए इससे अधिक जगह नहीं है। अभी हिजबुल्ला पर इजरायली हमलों से कुछ दिन पहले ही भारत में मुसलमानों की दशा की फलस्तीन से तुलना करते हुए खामनेई ने एक भड़काऊ ट्वीट (पोस्ट) किया था। परंपरागत रूप से ईरान भारत और उसके भागों में सक्रिय रही कट्टरपंथी शक्तियों के संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। भारत से उखाड़ फेंके जाने पर हुमायूं ने ईरान के शाह की सहायता से ही मुगल साम्राज्य को भारत में फिर से स्थापित किया था। जब औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर पड़े तो नादिर शाह भारतीयों से लूटी गई अपार धन-संपदा को ईरान ले गया। नादिर शाह के बाद उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई हमले कर मराठों के विस्तार को रोका और मुगलों को पतन से बचाया।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले ईरान के शाह ने कराची बंदरगाह की रक्षा के लिए पाकिस्तान से गुप्त समझौता कर रखा था। भारत को यह संदेश भी भिजवाया गया था कि अगर उसने पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया तो ईरानी फौजें आगे बढ़कर पाकिस्तान की रक्षा करेंगी। बलूचिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा ईरान पाकिस्तान की तरह ही उसके स्वतंत्रता आंदोलन का निर्ममता से दमन करता आया है। ईरान को परमाणु तकनीक उपलब्ध कराने में भी पाकिस्तान के एक्यू खान का हाथ रहा है। अगर ईरान भारत का भरोसेमंद मित्र देश होता तो पाकिस्तान के सुन्नी जनरल कभी ईरान को परमाणु तकनीक उपलब्ध न कराते। स्पष्ट है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भारत के हित में भी नहीं और इजराइल के साथ मौजूदा संघर्ष में यदि ईरान का पलड़ा भारी रहा तो वह विश्व शांति के लिए और बड़ा खतरा होगा। ईरान में उपजे कठमुल्लावाद की भू-राजनीतिक परछाई भारत तक पड़ती है। यह परछाई पूरे विश्व को प्रतिस्पर्धात्मक इस्लामिक उग्रवाद की आग में झुलसा रही है। अच्छा यही होगा कि खोमैनी द्वारा स्थापित मध्ययुगीन कट्टरपंथी शासन का वर्तमान सैन्य संघर्ष के फलस्वरूप पतन हो जाए।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

लोक से संवाद का अनूठा प्रयोग

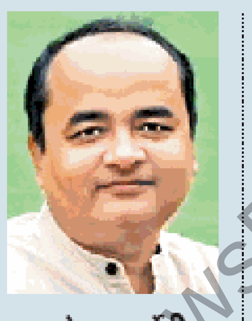

उमेश चतुर्वेदी

लोक से शासक का संवाद लोकतंत्र के लिए जरूरी है। 'मन की बात' इसी जरूरत को पूरी करता है

महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम् का एक दृश्य है, जहां एक व्यक्ति न्याय की अपेक्षा में राजा दुष्यंत के महल में तीन बजे भोर में पहुंचता है। वह द्वारपाल से राजा से मिलने की अनुमति मांगता है। वह कुछ संकोच भी कर रहा है कि राजा कहीं विश्राम कर रहे होंगे। तब द्वारपाल उस व्यक्ति को समझाता है कि यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपने राजा से कभी भी मिल सकते हैं। ऐसा अधिकार उस राजतंत्रिक व्यवस्था में था, जिसे हम पुरातनपंथी मानते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की जटिलताओं के चलते आज के शासक से मिलना आमजन के लिए संभव ही नहीं है। कहीं-कहीं जनता दरबार जैसी संकल्पनाएं हैं भी तो उनमें भी दुष्यंत जैसा लोकतांत्रिक सोच नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र की पहली शर्त है, लोक का चुने हुए शासक से सीधा संवाद। इस संवाद के माध्यम और तरीके पर हमेशा से चिंतन होता रहा है। इन अर्थों में आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे 'मन की बात' कार्यक्रम को लोक संवाद की आधुनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। रेडियो के इतिहास में 'मन की बात' संभवतः पहला कार्यक्रम है, जो इतना नियमित है। हाल में इसने एक दशक का सफर पूरा कर लिया। सबसे अहम बात यह है कि यह कार्यक्रम तब रेडियो पर आया, जब संचार माध्यमों की क्रांति अपने उफान पर थी।

इंटरनेट के विस्तार और विकास ने दो मोर्चों पर संचार माध्यमों को प्रभावित किया है। उसने खुद में सारे माध्यमों मसलन प्रिंट, रेडियो और टीवी को तो आत्मसात किया ही, खुद को सभी रूपों में एक साथ विस्तारित भी किया। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' के जरिये देश को संबोधित करना शुरू किया, जिसकी वजह से दूसरी पीढ़ी के माध्यम यानी पारंपरिक रेडियो की लोकप्रियता को नई गति मिली। हालांकि इसकी वजह से मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर भी रहे। उन्हें अक्सर यह उलाहना भी सुनना पड़ा कि उन्हें 'जन की बात' करनी चाहिए। सार्वजनिक माध्यम के जरिये जनता को संबोधित करने की पहली कोशिश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध की आहट की वजह से जहां अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था चरमराने लगी थी, वहीं जर्मनी के हिटलर प्रशासन की ओर से खूब प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा था। ऐसे माहौल में रूजवेल्ट को लगा कि अमेरिकी लोगों को सांत्वना देने और दुनिया को अफवाहों से बचाने के लिए उनके सामने सही बात रखी जानी चाहिए। इसके लिए रेडियो उन्हें ज्यादा प्रभावी माध्यम लगा, जिसके जरिये अपनी बात तुरंत लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। रूजवेल्ट ने इस कार्यक्रम का नाम फायरसाइड चैट दिया, जिसके जरिये उन्होंने अमेरिका और दुनिया को अमेरिका के रुख से न सिर्फ परिचित कराया, बल्कि ध्वस्त होने के कगार पर पहुंची अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था को बचाने के लिए की जा रही अपनी सरकार की कोशिशों की जानकारी भी दी। फायरसाइड चैट के जरिये उन्होंने लोगों की राय बदल दी। 1933 में शुरू हुआ उनका यह रेडियो संवाद 1944 तक जारी रहा। वैसे उसमें रुकावट भी आती थी। इसकी तुलना में 'मन की बात' नियमित है।

मन की बात कार्यक्रम सुनते भाजपा कार्यकर्ता। फाइल

'मन की बात' के पहले एपिसोड का प्रसारण तीन अक्टूबर, 2014 को हुआ, जिसका विषय एक दिन पहले ही शुरू हुआ 'स्वच्छता अभियान' था। उस दिन शुक्रवार था और दशहरा का पावन त्योहार भी। तब से लेकर मार्च 2015 तक महीने के आखिरी शुक्रवार को ही इसका प्रसारण होता रहा, लेकिन बाद में महीने के आखिरी रविवार का दिन तय हुआ। तब से प्रसारण का यही दिन नियत है। इस कार्यक्रम में सामाजिक बदलाव ला रहे स्थानीय नायकों का खूब उल्लेख होता है। बिहार की किसान चाची हों या कश्मीर का शिकारा चलाकर परिवार पालता बच्चा या फिर वाराणसी के गंगा घाट की सफाई का अभियान शुरू करने वाली छात्राएं हों, ऐसे तमाम लोगों की इस कार्यक्रम में चर्चा हुई है। इनके जरिये सामाजिक बदलाव लाने वाले लोगों को समाज के सामने प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में उस महीने विशेष के त्योहारों के जरिये भी सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों को प्रस्तुत किया जाता है। मेक इन इंडिया, लोकल के प्रति वोकल, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, खेती-किसानी में नवाचार, खिलौना उद्योग का विस्तार, स्टार्टअप, अंगदान की महत्ता जैसे तमाम विषय हैं, जिन पर पीएम ने खुलकर चर्चा की और उन पर लोगों का ध्यान भी गया है। जल संरक्षण, त्योहारों पर भारतीय वस्तुओं की खरीद, खादी का कम से कम एक वस्त्र जरूर खरीदने की अपील हो या फिर नवीकरणीय ऊर्जा की बात, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने वाले ऐसे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक दशक में खुलकर चर्चा की है।

गत दिनों 'मन की बात' की एक सौ चौदहवीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने 'नारी शक्ति', अमेरिका से वापस आ रही सैकड़ों कलाकृतियों की चर्चा के साथ ही मातृभाषा में शिक्षा की चर्चा की। इसके ठीक पहले के एपिसोड में उन्होंने प्रतिभाओं की राह में आने वाली बाधाओं में परिवारवाद को भी जिम्मेदार बताया था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विषयों के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगते रहे हैं। लोक से शासक का संवाद लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है। इस लिहाज से देखें तो 'मन की बात' इसी संवाद प्रक्रिया का तरीका है, जो रूजवेल्ट के संवाद से कुछ अलग है। रूजवेल्ट ने राजनीति को जवाब के तौर पर फायरसाइड चैट का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी इसके जरिये समाज को ही सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव को लेकर हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन की स्थिरता

कहते हैं कि यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो मन ही हम पर नियंत्रण करने लगता है। मन पर हमारा नियंत्रण उसे स्थिरता प्रदान करता है। मन की स्थिरता ही हमारी सद्प्रवृतियों को पोषित करती है। जीवन की प्रगति का कारक बनती है। लक्ष्यों के निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। स्थिर एवं नियंत्रित मन से ही योग और ध्यान किया जा सकता है। भगवत भक्ति, ईश साधना स्थिर मन द्वारा ही संपन्न हो पाती है। मन को स्थिर रखना भी स्वयं एक साधना है। जिनका मन स्थिर होता है वे जीवन में प्रगति के नित नए आयाम गढ़ते चले जाते हैं। मन में स्थिरता होने पर ही हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कार्य कर पाते हैं।

महाभारत में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख को भेदकर अपनी प्रवीणता का परिचय दिया था। ठीक ऐसा ही एक प्रसंग पढ़ने को मिलता है, जिसमें एकलव्य द्वारा स्वान का मुंह तीरों से भर दिया जाता है। बावजूद इसके स्वान को अन्य भाग में कोई शारीरिक क्षति नहीं होती। हम समझ सकते हैं कि इन धनुर्धरों को ये सिद्धियां कितने अधिक परिश्रम के बाद मिली होंगी। यदि इसके मूल में जाकर देखेंगे तो यही पाएंगे कि दोनों का अपने मन पर नियंत्रण रहा होगा। मन की स्थिरता से ही वे इस विद्या में पारंगत हुए होंगे।

चंचल मन का कोई भी स्थिर मत नहीं है, अतः इसके मत पथ पर न चलो। इसकी जो अज्ञानतापूर्ण बुरी आदतें हैं, उन्हें स्वाध्याय-साधना से छुड़ाओ। बेहतर यही है कि दौड़ते हुए मन को दुष्कामनाओं से बचाकर बार-बार भक्ति-साधना में लगाओ। मन की स्थिरता ही हमें सुमार्ग पर चलने को प्रेरित करेगी। चंचल मन बार-बार मूर्खतापूर्ण विचार पैदा करता रहेगा। हमें उन विचारों पर चलने को प्रेरित करता रहेगा। इसलिए मन की स्थिरता के लिए हमें निरंतर स्वाध्याय एवं श्रेष्ठ जनों का सान्निध्य प्राप्त करते रहना चाहिए।

ललित शौर्य

चांद के लिए तेज होती दौड़

प्रदीप

> चांद पर मानव बेस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है

चांद पर जाने और उसे अंतरिक्ष अन्वेषण के केंद्र में लाने की होड़ पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज हो गई है। 20वीं शताब्दी के मध्य में अंतरिक्ष की दौड़ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन अब यह 21वीं सदी में एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां कई देश और निजी कंपनियां चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। इस बार दौड़ मनुष्य को चंद्रमा पर दोबारा उतारने का ही नहीं है, बल्कि एक 'मैराथन' है जिसके लिए चंद्र सतह पर दीर्घकालिक उपस्थिति की आवश्यकता होगी। दुनिया की दो बड़ी शक्तियां चीन और अमेरिका इस प्रतियोगिता के शीर्ष दावेदार हैं। जहां आर्टेमिस मिशन के जरिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी 'नासा' मनुष्यों को लगभग 50 साल बाद फिर एक बार चांद पर उतारने की योजना बना रहा है, वहीं चीन का दावा है कि वह 2030 से पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर पहुंचा देगा।

हाल ही में चीन की मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने वाली एजेंसी 'सीएमएसए' ने 2030 में चंद्र मिशन पर जाने वाले अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नए स्पेससूट का अनावरण किया किया है। इसे विशेष रूप से चंद्रमा के वातावरण और तापमान में आने वाले उतार-चढ़ाव, रेडिएशन और धूल से बचाव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चीन का दावा है कि यह स्पेससूट इतना लचीला है कि चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्री किसी भी क्रियाकलाप और प्रयोग को आसानी से पूरा कर सकते हैं। चीन के चांग'ए मिशनों की श्रृंखला ने विशेष रूप से चंद्र विजय की दिशा में एक मजबूत नींव रखी है, जिसका अंतिम लक्ष्य चांद पर मानव मिशन भेजना और वहां एक स्थायी अनुसंधान शिविर स्थापित करना है।

आज चांद पर जाने की होड़ न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का प्रतीक है, बल्कि विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और शक्ति प्रदर्शन का भी केंद्र बन चुकी है। इस दौड़ चीन और अमेरिका के अलावा रूस, भारत, जापान और अन्य देश भी शामिल हैं। निजी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक भी चांद और अंतरिक्ष अन्वेषण में अहम भूमिका निभा रही हैं। फिर भी, इस दशक में लांच होने वाले बड़े चंद्र मिशनों में से अधिकांश अमेरिका और चीन के इर्द-गिर्द ही केंद्रित हैं। अमेरिका और चीन के बीच चांद को लेकर होड़ छिड़ती दिखाई दे रही है। कई अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि चंद्रमा की ओर अमेरिका की वापसी चीन के इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाने की वजह से हो रही है। चीन तकनीक के स्तर पर स्वयं को ताकतवर दिखाकर महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ जाना चाहता है, वहीं अमेरिका दिखाना चाहता है कि वैश्विक महाशक्ति का खिताब उसी के पास है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी

'सेवा भाव पर हावी होता स्वार्थ' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि आम जनता के जीवन में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है, जब सरकारी तंत्र सेवा भाव को अपनी प्राथमिकता बनाए। जबकि आज स्थिति ऐसी है कि सेवा भाव दिखना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ स्वार्थ का बोलबाला है। आखिर, जब स्वार्थ के रास्ते पर ही सफलता के पुल बनते हैं, तो सेवा का महत्व किसे याद रहेगा? पराली जलाने की समस्या की ही बात करें तो इसकी आग हर साल धुआं उठाती है, मगर समाधान कहीं नजर नहीं आता। सरकार और किसान दोनों एक-दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठता। किसान पराली जलाते हैं, क्योंकि उनके पास सस्ती एवं सुलभ तकनीक का अभाव है और सरकार कागजी योजनाओं में उलझी रहती है। अगर सरकार किसानों को सही उपकरण और सब्सिडी प्रदान करे, तो इस समस्या का निदान भी संभव है। किसानों को जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि पर्यावरण और उनकी आजीविका दोनों सुरक्षित रह सकें। स्वच्छ भारत अभियान ने भले ही कुछ सफलता प्राप्त की हो, लेकिन गांव और छोटे शहरों में आज भी सफाई की हालत दयनीय है। यहां समस्या सिर्फ सरकारी तंत्र की ही नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता की भी है। जब तक लोग खुद सफाई को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक सरकार अकेले इस अभियान को सफल नहीं बना सकती। समाधान के लिए जागरूकता का प्रसार करना ही होगा, जिसमें लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो और समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए, तभी सेवा भाव को पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

चिंताजनक राजनीतिक विमर्श

राहुल वर्मा का 'निराश करता राजनीतिक विमर्श' आलेख सचमुच में हमारे राजनीतिक महारथियों के लिए पठनीय एवं विचारणीय है। आजकल के अधिकांश राजनीतिक महारथी 'लाइक्स' युग के राजनीतिज्ञ हैं, जो उथली मानसिकता से ग्रस्त हैं। वे भूल जाते हैं कि असली राजनीतिज्ञ देश और समाज को दिशा देने का कार्य करता है। चिंता की बात यह है कि इस प्रयास में वे जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा आदि की विभाजक रेखाओं को इतना लंबा और गहरा खींच देते हैं कि इससे हमारे देश की छवि पर तुषारापात होता है। अपने विमर्श में इनसे मर्यादा की आस रखना दूर की कौड़ी लगती है। परंतु उन्हें कुछ तो सोच-विचार करना होगा। हमारे समाज में इनकी विष-वमन करती टिप्पणियों से केवल और केवल आपसी वैमनस्य ही फैलता है। ऐसे महारथी न भूलें कि सत्य जब सामने आता है तो फिर इनके अप्रासंगिक होने में भी देर नहीं लगती है। सभी राजनेता मर्यादित राजनीतिक विमर्श की दिशा में सोचें जिससे हमारी आर्थिकी सुदृढ़ हो, समाज में एका हो, देश हित के मुद्दों पर मतैक्य हो व असहमति के लिए सहमति की गुंजाइश बनी रहे।

योगराज, खरड़, पंजाब

नशे का बाजार

समय-समय पर भारत के विभिन्न राज्यों में नशीले पदार्थों का पकड़ा जाना इस बात का संकेत देता है कि यह जहर भारत के युवाओं को देकर उनको कमजोरी करने का काम हो रहा है। देश और समाज में इस प्रकार का कारोबार करने वाले अंतरराष्ट्रीय माफिया हमारे देश की युवा पीढ़ी को गलत दिशा दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने पांच हजार करोड़ रुपये मूल्य की जो खेप पकड़ी है, वह अब तक की सबसे बड़ी मात्र बताई गई है। इससे पहले भी 2022 में मुद्रा पोर्ट पर 500 करोड़ रुपये की 56 किलो कोकेन बरामद हुई थी। तमिलनाडु के पोर्ट पर 300 किलो कोकेन पकड़ी गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत दो हजार करोड़ रुपये बताई गई थी। कुछ समय पहले गृह मंत्री ने कहा था कि भारत को जल्दी ही नशीले पदार्थों से मुक्त कर दिया जाएगा। पुलिस अपना कार्य कर रही है, हमें भी सहयोग करना चाहिए, ताकि नशे के सौदागर समय-समय पर पकड़े जा सकें।

मीना धानिया, सिरसपुर, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण
(12) शनिवार, 5 अक्टूबर, 2024 : आश्विन शुक्ल - 3 वि. 2081

संवाद से ही विवाद का समाधान संभव है

प्रसाद की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बीयुक्त घी का इस्तेमाल किए जाने के मामले में विशेष जांच दल का गठन करके आंध्र सरकार की ओर से की जाने वाली जांच को लेकर उठ रहे संदेह को खत्म करने का काम किया है। आशा की जानी चाहिए कि पांच सदस्यीय विशेष जांच दल इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने में सफल होगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को तैयार करने में अशुद्ध घी का इस्तेमाल किए जाने को आंध्र के मुख्यमंत्री का आरोप बहुत ही सनसनीखेज था। इस आरोप ने हिंदू समाज को विचलित किया, क्योंकि कोई यह सोच भी नहीं सकता कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल होता है, उसमें पशुओं की चर्बी प्रयुक्त होती है। ऐसा होने की आशंका इसलिए गहरा रही है, क्योंकि यह सामने आया था कि घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी उसे लगभग चार सौ रुपये प्रति किलो में उपलब्ध कराती थी। इतना सस्ता घी तो तभी मिल सकता है, जब उसमें कोई मिलावट की जाए, क्योंकि दूध की औसत कीमत 45-50 रुपये प्रति लीटर है और एक किलो घी तैयार करने में 20 से 25 लीटर दूध चाहिए होता है। स्पष्ट है कि यह जानने की जरूरत है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए इतना सस्ता घी कैसे उपलब्ध कराया जा रहा था और यदि उसमें मिलावट की जा रही थी तो किस चीज की? यदि देश में कहीं पर भी पांच-छह सौ रुपये में एक किलो घी उपलब्ध हो रहा है तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। प्रश्न यह है कि इसकी जांच कौन करेगा कि विभिन्न कंपनियां पांच-छह सौ रुपये में घी कैसे उपलब्ध करा रही हैं? अपने देश में खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट कोई नई बात नहीं है। खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट रुके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विभिन्न एजेंसियां खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए सक्रिय रहती हैं, क्योंकि उनकी सक्रियता निष्प्रभावी ही साबित हो रही है। तिरुपति मंदिर का मामला केवल यह जानने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि उसके प्रसाद में पशुओं की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल होता था या नहीं? इस मामले ने यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि आखिर हिंदुओं के मंदिरों का संचालन सरकारों को क्यों करना चाहिए? यदि अन्य समुदायों को अपने धार्मिक स्थलों के संचालन का अधिकार मिला हुआ है तो ऐसा ही अधिकार हिंदू समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह वह प्रश्न है, जो अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि राज्य सरकारों की ओर से संचालित हिंदू मंदिरों की देख-रेख सही तरीके से नहीं हो रहा है।

बाढ़ के बाद पुनर्वास

राज्य में बाढ़ की स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। इस समय भी बड़ी संख्या में लोग विस्थापितों की जिंदगी जी रहे हैं। अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से सचमुच कितनी बर्बादी हुई है, इसका आकलन पानी घटने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन, पहली नजर में जिस बर्बादी को हम देख पा रहे हैं, उसकी भरपाई के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ेगी। प्रारंभिक आकलन में बताया जा रहा है कि बाढ़ का प्रभाव राज्य के डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों की आंशिक या पूर्ण आबादी पर है। धान की फसल बर्बाद हुई है और इसकी भरपाई वैकल्पिक खेती से हो सकती है। सरकार इसकी भी योजना बना रही है। फसल क्षति की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा भी देना होगा। यह ध्यान देने की बात है कि इसबार धान की खेती के लिए किसानों को पानी का प्रबंध अतिरिक्त स्रोतों से करना पड़ा। बोचड़े डालने के बाद फसल को बचाने के लिए बोरिंग का सहारा लेना पड़ा। कुल मिलाकर किसानों को अधिक श्रम और धन का व्यय करना पड़ा था। मुआवजे के निर्धारण में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाए तो किसानों को राहत मिलेगी। फसल और घर के अलावा आधारभूत संरचना की बर्बादी भी हुई है। खासकर सड़कों का बड़ा नुकसान हुआ है। पटना सहित बीस जिलों में सड़कों की बर्बादी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। राज्य सरकार क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त धन की मांग करेगी। राज्य सरकार ने राहत और बचाव का अच्छा प्रबंध किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि सरकारी खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।

इसबार धान की खेती के लिए किसानों को पानी का प्रबंध अतिरिक्त स्रोतों से करना पड़ा। मुआवजे के निर्धारण में इस तथ्य को ध्यान में रखना किसानों के हित में होगा

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या हरियाणा में मतदान के ठीक पहले अशोक तंवर का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए झटका है?

आज का सवाल

क्या वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में रखने से विवाह संस्था को नुकसान होगा?

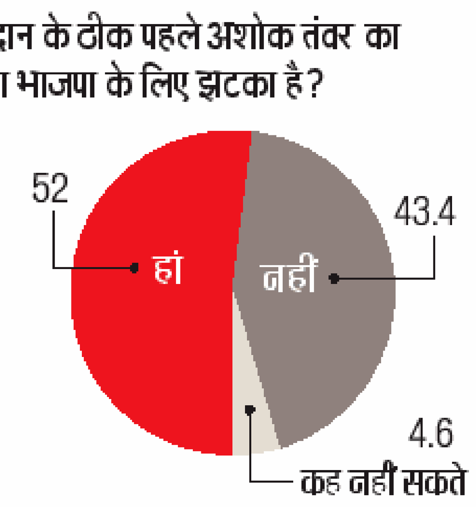

परिणाम जागरण इंटरनेट सर्वेक्षण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विश्व शांति के लिए खतरा बना ईरान

दिव्य कुमार सोती

खोमैनी ने इस्लामिक शासन का जो कट्टरवादी माडल मुस्लिम जगत के सामने पेश किया, उससे दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावित हुए हैं

हिजबुल्ला के मुखिया हसन नसरुल्ला की इजरायली हमले में मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव की आग और भड़क गई है। नसरुल्ला की मौत के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला बोला। इजरायल ने इन मिसाइल हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। इससे पहले इजरायल ने ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ढेर किया था, लेकिन तब ईरान ने इजरायल पर कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। इस बार लेबनान में विभिन्न इलेक्ट्रानिक उपकरणों में विस्फोटों के जरिये हजारों हिजबुल्ला आतंकियों के घायल होने और कई के मारे जाने और फिर नसरुल्ला की मौत के बाद ईरान अत्यंत मजबूर दिखने लगा और उसके द्वारा समर्थित विभिन्न आतंकी गुटों के भीतर ही ईरान की इजरायल नीति को लेकर आवाजें उठने लगीं थीं।

ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के चलते आयतुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में बनी कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार ने पूरे पश्चिमी एशिया में आतंकी संगठनों का जाल बिछाया। इस्लामिक जगत का नेतृत्व शिया वर्ग के हाथ में लेने के लिए खोमैनी के नेतृत्व वाले ईरानी शासनतंत्र ने पूरे विश्व के मुस्लिम मानस को प्रभावित करने वाले फलस्तीन के मुद्दे को चुना और इजरायल के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के लिए हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। शिया और सुन्नी इस्लाम के समीकरणों की एक खास बात यह है कि कोई सुन्नी मुसलमान शिया भी बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम जगत में शिया अल्पसंख्यक हैं। इसलिए खोमैनी के कठमुल्ला तंत्र के लिए यह आवश्यक था कि वह सुन्नी अतिवादियों के भी एक तबके को अपने साथ ले। चूंकि अधिकांश सुन्नी अतिवादी शिया इस्लाम के कट्टर विरोधी हैं और आर्थिक रूप से सुन्नी अरब देशों पर निर्भर रहे हैं, इसलिए ईरान के लिए यह चुनाव आसान नहीं था। ऐसे में सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड की फलस्तीन इकाई यानी हमास ईरान का औजार बनी।

खोमैनी ने इस्लामिक शासन का जो कट्टरवादी माडल मुस्लिम जगत के सामने पेश किया, उससे दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावित हुए। इसका एक परिणाम यह हुआ कि अरब जगत की तमाम सेक्युलर सरकारें और तानाशाह धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता खोते गए और इस्लामिक कट्टरपंथी मजबूत होते गए। जो सुन्नी राजशाहियां इस लहर में बच भी पाईं, उन्होंने अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए दूसरे देशों में सुन्नी जिहादी संगठनों का समर्थन करना शुरू किया, जिसकी परिणति अलकायदा से लेकर तालिबान जैसे तमाम सुन्नी आतंकी संगठनों के उदय के रूप में हुई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तो खोमैनी के कठमुल्ला शासन का सुन्नी संस्करण ही थी। तालिबान सरकार के 1996 में सत्ता में आने पर उसे तीन देशों से ही मान्यता मिली थी-सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान। इनमें से पहले दो देशों का उद्देश्य ईरान से सटे अफगानिस्तान में खोमैनी के शिया इस्लामिक राष्ट्र जैसा ही एक प्रतियोगी सुन्नी शासनतंत्र खड़ा करना था, जिसका प्रमुख भी एक कट्टरपंथी मौलाना हो और जहां सुन्नी कट्टरपंथियों को इकट्ठा रखकर उनकी शक्ति को दूसरे देशों की ओर निर्देशित रखा जा सके। खोमैनी की इस्लामिक क्रांति का एक और प्रभाव यह भी हुआ कि दुनिया भर के अशांत मुस्लिम क्षेत्रों के लोगों को लगा कि हिंसा के माध्यम से सत्ता को पलटा जा सकता है। खोमैनी ने मुस्लिम जगत में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इस भावना को खूब हवा भी दी और फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक के मुसलमानों को अपने भाषणों के जरिये उकसाया। ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सुन्नी देशों ने और बढ़-चढ़कर आतंकी संगठनों की सहायता की। इस प्रकार यह एक दुष्चक्र बन चुका है, जिसके चलते लाखों लोग जान गंवा चुके हैं।

भारत के ईरान के साथ संबंध ठीक-ठाक ही रहे हैं और सुन्नी पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए दोनों देशों ने कई स्तरों पर साथ काम भी किया है, लेकिन ईरान की ओर से ये संबंध बस यहीं तक सीमित रहे हैं। वह पाकिस्तान के सुन्नी कट्टरपंथियों को बस खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता। खोमैनी के कठमुल्लावाद में भी भारत के लिए इससे अधिक जगह नहीं है। अभी हिजबुल्ला पर इजरायली हमलों से कुछ दिन पहले ही भारत में मुसलमानों की दशा की फलस्तीन से तुलना करते हुए खामेनेई ने एक भड़काऊ ट्वीट (पोस्ट) किया था। परंपरागत रूप से ईरान भारत और उसके भागों में सक्रिय रही कट्टरपंथी शक्तियों के संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। भारत से खदेड़ फेंके जाने पर हुमायूं ने ईरान के शाह की सहायता से ही मुगल साम्राज्य को भारत में फिर से स्थापित किया था। जब औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर पड़े तो नादिर शाह भारतीयों से लूटी गई अपार धन-संपदा को ईरान ले गया। नादिर शाह के बाद उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई हमले कर मराठों के विस्तार को रोका और मुगलों को पतन से बचाया।

कम ही लोग जानते हैं कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले ईरान के शाह ने कराची बंदरगाह की रक्षा के लिए पाकिस्तान से गुप्त समझौता कर रखा था। भारत को यह संदेश भी भिजवाया गया था कि अगर उसने पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया तो ईरानी फौजें आगे बढ़कर पाकिस्तान की रक्षा करेंगी। बलूचिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा ईरान पाकिस्तान की तरह ही उसके स्वतंत्रता आंदोलन का निर्ममता से दमन करता आया है। ईरान को परमाणु तकनीक उपलब्ध कराने में भी पाकिस्तान के कुख्यात परमाणु वैज्ञानिक एक्यू खान का हाथ रहा है। अगर ईरान भारत का भरोसेमंद मित्र देश होता तो पाकिस्तान के सुन्नी जनरल कभी ईरान को परमाणु तकनीक उपलब्ध न कराते। स्पष्ट है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भारत के हित में भी नहीं है। यदि इजरायल के साथ मौजूदा संघर्ष में यदि ईरान का पलड़ा भारी रहा तो यह विश्व शांति के लिए और बड़ा खतरा होगा। ईरान में उपजे कठमुल्लावाद की भू-राजनीतिक परछाई भारत तक पहुंचती है। यह परछाई पूरे विश्व को प्रतिस्पर्धात्मक इस्लामिक उग्रवाद की आग में झुलसा रही है। अच्छा यही होगा कि खोमैनी द्वारा स्थापित मध्ययुगीन कट्टरपंथी शासन का वर्तमान सैन्य संघर्ष के फलस्वरूप पतन हो जाए।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

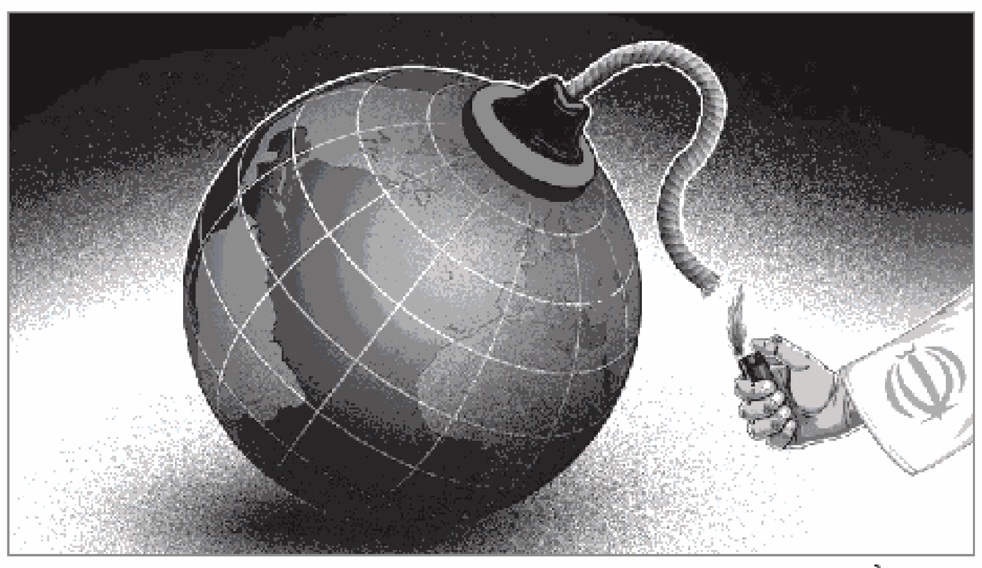

आर केश राजपूत

लोक से संवाद का अनूठा प्रयोग

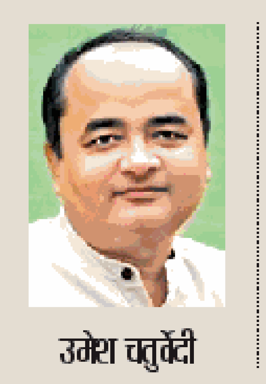

उमेश चतुर्वेदी

लोक से शासक का संवाद लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है। 'मन की बात' इसी जरूरत को पूरी करता है

महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम् का एक दृश्य है, जहां एक व्यक्ति न्याय की अपेक्षा में राजा दुष्यंत के महल में तीन बजे भोर में पहुंचता है। वह द्वारपाल से राजा से मिलने की अनुमति मांगता है। वह कुछ संकोच भी कर रहा है कि राजा कहीं विश्राम कर रहे होंगे। तब द्वारपाल उस व्यक्ति को समझाता है कि यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपने राजा से कभी भी मिल सकते हैं। ऐसा अधिकार उस राजतंत्रिक व्यवस्था में था, जिसे हम पुरातनपंथी मानते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की जटिलताओं के चलते आज के शासक से मिलना आमजन के लिए संभव ही नहीं है। कहीं-कहीं जनता दरबार जैसी संकल्पनाएं हैं भी तो उनमें भी दुष्यंत जैसा लोकतांत्रिक सोच नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र की पहली शर्त है, लोक का चुना हुआ शासक से सीधा संवाद। इस संवाद के माध्यम और तरीके पर हमेशा से चिंतन होता रहा है। इन अर्थों में आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे 'मन की बात' कार्यक्रम को लोक संवाद की अनूठी व्यवस्था कहा जा सकता है। रेडियो के इतिहास में 'मन की बात' संभवतः पहला कार्यक्रम है, जो इतना नियमित है। हाल में इसने एक दशक का सफर पूरा कर लिया। सबसे अहम बात यह है कि यह कार्यक्रम तब रेडियो पर आया, जब संचार माध्यमों की प्रति अपने उफान पर थी।

इंटरनेट के विस्तार और विकास ने तो मोर्चों पर संचार माध्यमों को प्रभावित किया है। उसने खुद में सारे माध्यमों मसलन प्रिंट, रेडियो और टीवी को तो आत्मसात किया ही, खुद को सभी रूपों में एक साथ विस्तारित भी किया। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' के जरिये देश को संबोधित करना शुरू किया, जिसकी वजह से दूसरी पीढ़ी के माध्यम यानी पारंपरिक रेडियो की लोकप्रियता को नई गति मिली। हालांकि इसकी वजह से मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर भी रहे। उन्हें अक्सर यह उलाहना भी सुनना पड़ा कि उन्हें 'जन की बात' करनी चाहिए। सार्वजनिक माध्यम के जरिये जनता को संबोधित करने की पहली कोशिश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध की आहट की वजह से जहां अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था चरमराने लगी थी, वहीं जर्मनी के हिटलर प्रशासन की ओर से जबरदस्त प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा था। ऐसे माहौल में रूजवेल्ट को लगा कि अमेरिकी लोगों को सांत्वना देने और दुनिया की अफवाहों से बचाने के लिए उनके शासन सही बात रखी जानी चाहिए। इसके लिए रेडियो उन्हें ज्यादा प्रभावी माध्यम लगा, जिसके जरिये अपनी बात तुरंत लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। रूजवेल्ट ने इस कार्यक्रम का नाम फायरसाइड चैट दिया, जिसके जरिये उन्होंने अमेरिका और दुनिया को अमेरिका के रुख से न सिर्फ परिचित कराया, बल्कि ध्वस्त होने के कगार पर पहुंची अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था को बचाने के लिए की जा रही अपनी सरकार की कोशिशों की जानकारी भी दी। फायरसाइड चैट के जरिये उन्होंने लोगों की राय बदल भी दी। 1933 में शुरू हुआ उनका यह रेडियो संवाद 1944 तक जारी रहा। हालांकि उसमें रूजवेल्ट कभी-कभी ही आ जाती थी। इसकी तुलना में 'मन की बात' नियमित है।

'मन की बात' के पहले एपिसोड का प्रसारण तीन अक्टूबर, 2014 को हुआ, जिसका विषय एक दिन पहले ही शुरू हुआ 'स्वच्छता अभियान' था। उस दिन शुक्रवार था और दशहरा का पावन त्योहार भी। तब से लेकर मार्च 2015 तक महीने के आखिरी शुक्रवार को ही इसका प्रसारण होता रहा, लेकिन बाद में महीने के आखिरी रविवार का दिन तय हुआ। तब से प्रसारण का यही दिन नियत है। इस कार्यक्रम में सामाजिक बदलाव ला रहे स्थानीय नायकों का खूब उल्लेख होता है। बिहार की किसान चाची हों या कश्मीर का शिकारा चलाकर परिवार पालता बच्चा या फिर वाराणसी के गंगा घाट की सफाई का अभियान शुरू करने वाली छात्राएं हों, ऐसे तमाम लोगों की इस कार्यक्रम में चर्चा हुई है। इनके जरिये सामाजिक बदलाव लाने वाले लोगों को समाज के सामने प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम में उस महीने विशेष के त्योहारों के जरिये भी सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों को प्रस्तुत किया जाता है। मेक इन इंडिया, लोकल के प्रति वोकल, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, खेती-किसानी में नवाचार, खिलौना उद्योग का विस्तार, स्टार्टअप, अंगदान की महत्ता जैसे तमाम विषय हैं, जिन पर प्रधानमंत्री ने खुलकर चर्चा की और उन पर लोगों का ध्यान भी गया है। जल संरक्षण, त्योहारों पर भारतीय वस्तुओं की खरीद, खादी का कम से कम एक वस्त्र जरूर खरीदने की अपील और सांस्कृतिक बदलाव लाने वाले ऐसे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक दशक में खुलकर चर्चा की है।

गत दिनों 'मन की बात' की एक सौ चौदहवीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने 'नारी शक्ति', अमेरिका से वापस आ रही सैकड़ों कलाकृतियों की चर्चा के साथ ही मातृभाषा में शिक्षा की चर्चा की। इसके ठीक पहले के एपिसोड में उन्होंने प्रतिभाओं की राह में आने वाली बाधाओं में परिवारवाद को भी जिम्मेदार बताया था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विषयों के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगते रहे हैं। लोक से शासक का संवाद लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है। इस लिहाज से देखें तो 'मन की बात' इसी संवाद प्रक्रिया का तरीका है, जो रूजवेल्ट के संवाद से कुछ अलग है। रूजवेल्ट ने राजनीति को जवाब के तौर पर फायरसाइड चैट का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी इसके जरिये समाज को ही सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव लेकर हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

मन की बात कार्यक्रम सुनते भाजपा कार्यकर्ता ● फाइल

ऊर्जा

मन की स्थिरता

कहते हैं कि यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो मन ही हम पर नियंत्रण करने लगता है। मन पर हमारा नियंत्रण उसे स्थिरता प्रदान करता है। मन की स्थिरता ही हमारी सद्प्रवृत्तियों को पोषित करती है। जीवन की प्रगति का कारक बनती है। लक्ष्यों के निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। स्थिर एवं नियंत्रित मन से ही योग और ध्यान किया जा सकता है। भगवत भक्ति, ईश साधना स्थिर मन द्वारा ही संपन्न हो पाती है। मन को स्थिर रखना भी स्वयं एक साधना है। जिनका मन स्थिर होता है वे जीवन में प्रगति के नित नए आयाम गढ़ते चले जाते हैं। मन में स्थिरता होने पर ही हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कार्य कर पाते हैं। अन्यथा मन में भटकाव होने पर लक्ष्य से विचलित होने की भरी-पूरी आशंका होती है।

महाभारत में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख को भेदकर अपनी प्रवीणता का परिचय दिया था। ठीक ऐसा ही एक प्रसंग पढ़ने को मिलता है, जिसमें एकलव्य द्वारा श्वान का मुंह तीरों से भर दिया जाता है। बावजूद इसके श्वान को अन्य भाग में कोई शारीरिक क्षति नहीं होती। हम समझ सकते हैं कि इन दोनों धनुर्धरों को यह सिद्धियां कितने अधिक परिश्रम के बाद मिली होंगी। यदि इसके मूल में जाकर देखेंगे तो यही पाएंगे कि दोनों का अपने मन पर नियंत्रण रहा होगा। मन की स्थिरता से ही वे इस विद्या में पारंगत हुए होंगे।

चंचल मन का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, अतः इसके मत पथ पर न चलो। इसकी जो अज्ञानतापूर्ण बुरी आदतें हैं, उन्हें स्वाध्याय-साधना से छुड़ाओ। बेहतर यही है कि दौड़ते हुए मन को दुष्कामनाओं से बचाकर बार-बार भक्ति-साधना में लगाओ। मन की स्थिरता ही हमें सुमार्ग पर चलने को प्रेरित करेगी। चंचल मन बार-बार मूर्खतापूर्ण विचार पैदा करता रहेगा। हमें उन विचारों पर चलने को प्रेरित करता रहेगा। इसलिए मन की स्थिरता के लिए हमें निरंतर स्वाध्याय एवं श्रेष्ठ जनों का सान्निध्य प्राप्त करते रहना चाहिए।

ललित शौर्य

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी

'सेवा भाव पर हावी होता स्वार्थ' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि आम जनता के जीवन में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है, जब सरकारी तंत्र सेवा भाव को अपनी प्राथमिकता बनाए। जबकि आज स्थिति ऐसी है कि सेवा भाव दिखना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ स्वार्थ का बोलबाला है। आखिर, जब स्वार्थ के रास्ते पर ही सफलता के पुल बनते हैं, तो सेवा का महत्व किसे याद रहेगा? पराली जलाने की समस्या की ही बात करें तो इसकी आग हर साल धुआं उठाती है, मगर समाधान कहीं नजर नहीं आता। सरकार और किसान दोनों एक-दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठता। किसान पराली जलाते हैं, क्योंकि उनके पास सस्ते एवं सुलभ तकनीक का अभाव है और सरकार कागजी योजनाओं में उलझी रहती है। अगर सरकार किसानों को सही उपकरण और सब्सिडी प्रदान करे, तो इस समस्या का निदान भी संभव है। किसानों को जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि पर्यावरण और उनकी आजीविका दोनों सुरक्षित रह सकें। स्वच्छ भारत अभियान ने भले ही कुछ सफलता प्राप्त की हो, लेकिन गांव और छोटे शहरों में अभी भी सफाई की हालत दयनीय है। यहां समस्या सिर्फ सरकारी तंत्र की ही नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता की भी है। जब तक लोग खुद सफाई को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक सरकार अकेले इस अभियान को सफल नहीं बना सकती। समाधान के लिए जागरूकता का प्रसार करना ही होगा, जिसमें लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो और समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए, तभी सेवा भाव को पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

awanishg30@gmail.com

युद्ध समस्या का समाधान नहीं

संपादकीय आलेख 'खतरे में विश्व शांति' में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस्लामिक देशों और इजरायल से उचित अपेक्षा की गई है कि युद्ध का त्याग कर विश्व शांति बहाल करने के लिए आगे आएं। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध देश को विनाश की ओर ले जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रूस और यूक्रेन में वर्षों से छिड़ा युद्ध है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अहम के टकराव के कारण दोनों देशों का विकास बाधित है। इन सबके बावजूद दुनिया पर तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान-इजरायल के बीच शुरू हुई जंग के बाद मिडिल ईस्ट गंभीर तनाव से गुजर रहा है। हिजबुल्लाह के मारे गए सर्वोच्च नेता नसरल्लाह को गुप्त स्थान पर दफनाया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो इजरायल पर फिर हमला किया जाएगा। इधर, इजरायल ने बेरुत में जबरदस्त बमबारी कर दावा किया कि इस बमबारी में हिजबुल्लाह के गढ़ को नष्ट कर दिया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह के नए चीफ को भी मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वह ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने इजरायल से उतनी ही कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जितनी आवश्यकता है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव आवश्यक

शिवकांत शर्मा का आलेख 'संयुक्त राष्ट्र में सुधार का इंतजार' पढ़ा। यह वैश्विक संगठन के मौजूदा ढांचे और उसकी विफलताओं पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 में विश्व शांति और सुरक्षा के लिए एक मंच देने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में असमर्थ है। इसे अधिक प्रासंगिक और सशक्त बनाने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हाल ही में कहा था, 'संयुक्त राष्ट्र को आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अनुसार खुद को बदलने की जरूरत है। स्थायी सुरक्षा परिषद में सुधार न होने से संगठन की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।' यह साफ संकेत है कि सुधारों के बिना, संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, 'अगर संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है, तो उसे अपनी संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार करने होंगे।' भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 में इस मुद्दे पर कहा था, 'संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों में सभी देशों की आवाज सुनी जानी चाहिए, और इसमें सुधार के लिए हमें एक साथ काम करना होगा।' संयुक्त राष्ट्र के ढांचे का पुनर्गठन और सुधार करना आवश्यक है।

डा. पवन कुमार, जनकपुर, गया

X पोस्ट

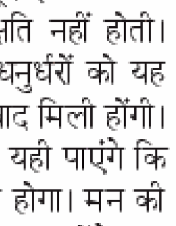

चाहे कोई संघर्ष हो या युद्ध, महामारी या आपदा, उनमें महिलाएं और बच्चों को ही सबसे अधिक खामियाजा उठाना पड़ता है।
रवीना टंडन@TandonRaveena

दुनिया भर में फैले यहूदियों के प्रति सम्मान का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये लोग अपने पैसों, प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल इजरायल को समर्थन प्रदान करने में कर रहे हैं। विश्व भर में बसे भारतवंशियों को भी हमेशा ऐसा ही करना चाहिए।
ईशकरण सिंह भंडारी@ishkarnBHANDARI

इंटरनेट मीडिया ऐसी जगह है, जहां कोई भी किसी विषय का ज्ञाता बन जाता है। जैसे दिल्ली में बैठे लोग एकाएक सैन्य विशेषज्ञ बन गए और इजरायल में गिरती मिसाइलें देख आयरन डोम को नकाम करार दे दिया।
मधुरेंद्र कुमार@Madhurendra13

अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ी और पार्टी नेतृत्व पर करोड़ों रुपये में टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने दुष्यंत चौटाला की जजपा को समर्थन दिया और अपना खुद का भारत मोर्चा बनाया। पिछले पांच वर्षों में उन्होंने चार बार राजनीतिक दल बदले। वह भारतीय चुनावी राजनीति में 'आया राम गया राम' के उदाहरण हैं।
प्रमोद कुमार सिंह@SinghPramod2784

जनपथ

कहीं जलेबी बंट रही कहीं चरस का डोज,
चले मुहब्बत की दुकां और चुनावी भोज।
और चुनावी भोज लगे वादों का तड़का,
वैद रहा है स्वप्न आय पूरी का लड़का!
राजनीति में लोग आ गए गजब फरेबी,
सीधा-सादा देश बना ना कहीं जलेबी!!
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक- संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प्र.झारखंड) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ सिंक. नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 174

युद्ध एक विचारशील प्राणी के रूप में इन्सान की विफलता को दर्शाता है। -जॉन स्टीनबेक

युद्ध और तेल

पिछले कुछ वक्त से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन इस्राइल-हिजबुल्ला-ईरान संकट की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पर गहराता संकट भारत समेत दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं को बढ़ा रहा है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयातित तेल पर निर्भर हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ईरान ने जब इस्राइली ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई थीं, तभी कच्चे तेल की कीमत में कुछ तेजी दिखने लगी थी। लेकिन बाइडन के इस बयान के बाद कि इस्राइल ईरान के तेल के ठिकानों को निशाना बना सकता है, कच्चे तेल की कीमतों में करीब पांच फीसदी की वृद्धि हो गई, जिसमें पिछले चौबीस घंटों में कुछ और इजाफा हुआ है। हालांकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल व गैस विपणन कंपनियों ने अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन पश्चिम एशिया में हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, ऐसा होने की पूरी आशंका बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि ईरान दुनिया में तेल का सातवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो अपने तेल उत्पादन का करीब आधा निर्यात करता है। भारत ने पिछले कुछ समय से रूस से तेल के आयात को बढ़ाया जरूर है, लेकिन इसकी तेल व गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब भी पश्चिम एशिया से ही पूरा होता है। लिहाजा अगर इस्राइल और ईरान में युद्ध पूरी तरह से भड़कता है, तो लाल सागर और हारमुज की खाड़ी जैसे विश्व के प्रमुख तेल मार्गों में बाधा पहुंचेगी, जिससे कतर से होने वाले तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और रूस, इराक व सऊदी अरब से तेल के आयात में दिक्कतें आएंगी। ओमान और ईरान के बीच स्थित हारमुज की खाड़ी को वैश्विक तेल व्यापार का चौराहा कहा जाता है, और इसी वजह से यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अहम है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू स्तर पर भी तेल की कीमतों और तदनुरूप महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यह देखते हुए कि हर बार तेल की कीमतों में उछाल हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देता है, वैश्विक समुदाय को पश्चिम एशियाई संकट का शांतिपूर्ण हल और वैश्विक आपूर्ति को सुरक्षित रखने की कोशिश तो करनी ही होगी, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देते हुए तेल पर निर्भरता के दौर से उबरने के प्रयास भी करने चाहिए।

युद्धों के पीछे के वैश्विक पैटर्न को समझें

इस्राइल के साथ हिजबुल्ला, हमास और ईरान की लड़ाई हो या रूस-यूक्रेन का युद्ध, इनके पीछे के पैटर्न को समझने के लिए हमें इन्हें उस व्यापक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा, जो आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शीतयुद्ध का स्थान लेते हुए दुनिया को दो धड़ों में विभाजित करने की दिशा में बढ़ रहा है।

इस्राइल द्वारा हिजबुल्ला पर किया गया विनाशकारी हमला क्यों और कैसे ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और यहां तक कि चीन के लिए भी दुनिया को हिला देने वाला खतरा बन गया है, यह समझने के लिए हमें इसको उस व्यापक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा, जिसने आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शीतयुद्ध का स्थान ले लिया है। पिछले वर्ष सात अक्तूबर को इस्राइल पर हमास के हमले के बाद मैंने कहा था कि अब हम शीतयुद्ध या शीतयुद्ध के बाद के दौर में नहीं हैं। हम 'शीतयुद्ध के बाद के दौर के बाद के युग' में हैं। इसमें सभ्य देशों के अस्थायी समावेशी गठबंधन और रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के नेतृत्व में एक 'प्रतिरोधी गठबंधन' के बीच संघर्ष चल रहा है।

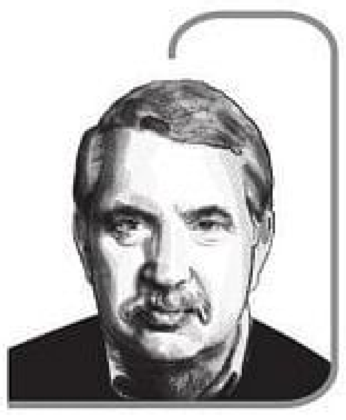

थॉमस एल. फ्रीडमैन

समावेशी गठबंधन में शामिल सभी देश लोकतांत्रिक नहीं हैं, पर अपने भविष्य को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा सुरक्षित मानते हैं, जो जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को आर्थिक एकीकरण, खुलेपन और सहयोग के लिए प्रेरित कर रहा है। जबकि प्रतिरोधी गठबंधन में शामिल देशों का शासन क्रूर और अधिनायकवादी है, जो समावेशी दुनिया के प्रति अपने विरोध का उपयोग अपने समाजों के सैन्यीकरण को उचित ठहराने और सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए करता है। चीन दोनों खेमों में बंटा हुआ है, क्योंकि समावेशी गठबंधन तक पहुंच पर ही उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जबकि सरकार का नेतृत्व प्रतिरोधी गठबंधन की अधिनायकवादी प्रवृत्ति और हितों को साझा करता है।

यूक्रेन, गाजा और लेबनान में चल रहे युद्धों को इस वैश्विक संघर्ष के संदर्भ में देखना होगा। यूक्रेन यूरोप की समावेशी दुनिया में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। वह रूस के दायरे से आजाद होकर यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता था। इस्राइल और सऊदी अरब संबंधों को सामान्य बनाकर पश्चिमी एशिया में समावेशी दुनिया का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। रूस ने यूक्रेन को पश्चिम (यूरोपीय संघ और नाटो) में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया और ईरान, हमास और हिजबुल्ला ने इस्राइल को पूर्व (सऊदी अरब के साथ संबंध) में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो जाता है, तो यूरोप के 'संपूर्ण और स्वतंत्र' होने की समावेशी दृष्टि लगभग पूरी हो जाएगी और रूस में व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर इस्राइल को सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की अनुमति दी गई, तो इससे न केवल उस क्षेत्र में समावेशी गठबंधन का व्यापक विस्तार होगा, बल्कि यह ईरान और लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक में ईरान समर्थक शिया लड़ाकों के दुस्साहसी प्रतिनिधियों को लगभग पूरी तरह से अलग-थलग कर देगा, जो सभी अपने मुल्कों को विफल राष्ट्र में तब्दील कर रहे हैं। वास्तव में, यह कहना कठिन है कि हिजबुल्ला और उसके नेता हसन नसरल्ला, जो इस्राइली हमले में मारे गए, से लेबनान और सुन्नी व ईसाई अरब जगत के कई हिस्सों में लोग कितनी नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने लेबनान का अपहरण कर उसे ईरानी साम्राज्यवाद का अड्डा बना दिया था।

पिछले दिनों मैं ओरिट पेर्लोव से बात कर रहा था, जो इस्राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के लिए अरब सोशल मीडिया पर नजर रखती हैं। उन्होंने बताया कि लेबनानी लोग नहीं चाहते कि बेरूत को गाजा की तरह नष्ट कर दिया जाए और वे वास्तव में गृहयुद्ध की वापसी से डरते हैं। लेकिन नसरल्ला के अंत को लेबनानी, इस्राइली और फलस्तीनी लोगों के लिए स्थायी रूप से बेहतर भविष्य में तब्दील करने के लिए अभी बहुत सारे कूटनीतिक कार्य किए जाने बाकी हैं। बाइडन-हैरिस प्रशासन अस्थायी समावेशी गठबंधन को रणनीतिक महत्व देने के लिए एक नेटवर्क बना रहा है। पूरी परियोजना का मुख्य बिंदु इस्राइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का बाइडन टीम का प्रस्ताव है, जिसके लिए सऊदी अरब तैयार है, बशर्ते इस्राइल पश्चिमी तट में फलस्तीनी प्राधिकरण के साथ द्वि-राष्ट्र समाधान पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो। और समस्या यहीं पर आती है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण पर बारीकी से ध्यान दें, तो वह 'प्रतिरोधी' और 'समावेशी' गठबंधनों के बीच संघर्ष को अच्छी तरह समझते हैं। वास्तव में, यह उनके संयुक्त राष्ट्र भाषण का केंद्र बिंदु था।

उन्होंने अपने संबोधन के दौरान दो नक्शे दिखाए, एक का शीर्षक था 'आशीर्वाद' और दूसरा 'अभिशाप'। अगर आप 'अभिशाप' वाले नक्शे को ध्यान से देखें, तो इसमें इस्राइल तो दिखाया गया है, लेकिन गाजा और इस्राइली कब्जे वाले पश्चिमी तट के साथ कोई सीमा नहीं दिखाई गई है (जैसे कि इसे पहले ही जोड़ दिया गया हो, जो इस्राइल का लक्ष्य भी है)। और यही समस्या है। नेतन्याहू दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि ईरान और उसके समर्थक यूरोप से लेकर पश्चिम एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक फैले समावेशी दुनिया की मुख्य बाधा हैं। मैं इससे असहमत हूं। इस पूरे गठबंधन का आधार सऊदी-इस्राइल सामान्यीकरण है, जो इस्राइल और उदारवादी फलस्तीनियों के बीच सुलह पर आधारित है।

यदि इस्राइल अब आगे बढ़ता है और एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण, जिसने ओस्लो शांति संधि को पहले ही स्वीकार कर लिया है, के साथ दो राष्ट्रों पर बातचीत शुरू करता है, तो यह कूटनीतिक झटका होगा, जो इस्राइल द्वारा हिजबुल्ला और हमास को दिए गए सैन्य झटके को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में 'प्रतिरोधी' ताकतें पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाएंगी और उनकी झूठी ढाल छीन ली जाएगी कि वे फलस्तीनी मुद्दे के रक्षक हैं। ईरान, हमास, हिजबुल्ला एवं रूस और यहां तक कि चीन के लिए भी इससे बड़ा कोई झटका नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए नेतन्याहू को हिजबुल्ला, जिसे पार्टी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, के नेतृत्व को खत्म करने के सैन्य जोखिम से भी बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना होगा। 'समावेशी दुनिया' और 'प्रतिरोधी दुनिया' के बीच संघर्ष कई बातों पर आधारित है, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेतन्याहू लेबनान में 'पार्टी ऑफ गॉड' पर किए गए प्रहार के बाद इस्राइल में उनको समर्थन दे रही 'पार्टी ऑफ गॉड' के जॉर्डन नदी से लेकर भूमध्य सागर तक संपूर्ण भू-भाग पर इस्राइली नियंत्रण के इरादों पर भी वैसा ही राजनीतिक प्रहार करें।

©The New York Times 2024

आर्थिकी

जटिलताएं पेश करता सीबीएएम

यूरोपीय संघ का सीबीएएम आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन शुल्क लगाता है, जो भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात के लिए जटिलताएं पेश कर सकता है।

वैश्विक व्यापार को नया आकार देते हुए यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) विकासशील देशों के लिए नई जटिलताएं भी पेश कर रहा है, विशेषकर भारत सरीखे विकासशील देश के लिए। सीबीएएम एक नियामक ढांचा है, जो यूरोपीय संघ में आयात पर कार्बन उत्सर्जन शुल्क लगाता है। सीबीएएम वर्ष 2026 से लागू होगा। इसमें 2023 से 2025 तक एक ट्रांजिशन यानी बदलाव कालीन चरण होगा। यह खास तौर से सीमेंट, लोहा, एल्यूमीनियम और स्टील जैसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन से बनने वाले सामान पर लागू होगा। सीबीएएम की वजह से यूरोपीय संघ के देशों में भारत द्वारा होने वाले निर्यात पर असर पड़ेगा। लोहा, स्टील और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं पर सीबीएएम के चलते कार्बन शुल्क 19.8 फीसदी से बढ़कर 52.7 फीसदी तक हो सकता है।

ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा थिंक टैंक एंबर ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यूरोपीय संघ के साथ सीबीएएम के अनुपालन के लिए भारत की रणनीतियों को रेखांकित करते हुए कहा है कि भारत के भारी उद्योगों के अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 17 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण से 2030 तक टाला जा सकता है। भारत के भारी उद्योगों को 2030 तक अपनी ऊर्जा खपत को पूरी तरह से डीकार्बोनाइज करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए 120 गीगावाट की समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमीनियम और अमोनिया क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उत्सर्जन-गहन 'भारी' उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन न केवल भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है। वर्तमान में, इन भारी उद्योगों में ऊर्जा की खपत का 11 प्रतिशत बिजली से आता है, जबकि बाकी जीवाश्म ईंधन-आधारित थर्मल ऊर्जा से आता है। उद्योग विकास अनुमानों के अनुसार, भारी उद्योगों के लिए बिजली की मांग में 45 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। इस बढ़ी हुई मांग को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने पर 18 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, जो नीदरलैंड के कुल वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। यदि नई प्रौद्योगिकियां और सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सफल होते हैं, तो 2050 तक औद्योगिक ऊर्जा मिश्रण में साफ बिजली का हिस्सा तीन गुना हो सकता है, और 73.7 करोड़ टन के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा।

सीमा जावेद

सीबीएएम नियमों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले सामान पर कार्बन उत्सर्जन के लिए उचित मूल्य निर्धारित करना है। सीबीएएम को यह सुनिश्चित करना है कि आयात किए गए सामान का कार्बन मूल्य, घरेलू उत्पादन के कार्बन मूल्य के समान हो। साथ ही कार्बन उत्सर्जन पर कमजोर विनियमन वाले गैर-यूरोपीय संघ देशों में उत्पादन स्थानांतरित करने से कंपनियों को हतोत्साहित कर स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। एल्यूमीनियम, उर्वरक, सीमेंट इत्यादि जैसे कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिन्हें यूरोपीय निर्यात के मामले में संभवतः अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली की कल्पना करता है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पहली बार बड़े पैमाने पर कार्बन समायोजन की पहल है और इसलिए भविष्य में कई देशों के लिए यह परीक्षा की कसौटी बन सकता है।

edit@amarujala.com

एआई इन्सानों और मशीनों को करीब लाता है। यह इन्सानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाएगा। -रॉबिन बॉर्दोली

अगर आप एआई की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं, तो होना चाहिए। यह उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। -एलन मस्क

तुच्छ नहीं होती छोटी-छोटी शुरुआतें

जब विज्ञान को अपनी आजीविका बना लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन सभी बेमतलब की बातों और ईर्ष्याओं को पीछे छोड़ दिया है, जो मनुष्य की नैतिक प्रगति में बाधा डालती हैं। कुछ समय बाद मैंने अपने भीतर एक अलग तरह की उन्नति देखी।

मैं जीवनयापन के लिए पहले पुस्तकें बेचता था, जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी लंदन से बारह किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं की थी। छह महीने तक एक अप्रिय मालिक के यहां दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम किया। इस दौरान मैंने मनोरंजन के तौर पर रसायन विज्ञान और दर्शन की कई पुस्तकों से काफी कुछ सीखा और इस दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा हुई। मैं हमेशा से चुंबकीय-विद्युत पर निर्भर नए तथ्यों और विचारों की खोज का इच्छुक रहा हूं, न कि पहले से मौजूद शक्तियों की शक्ति को बढ़ाने की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद इसका पूर्ण विकास हो जाएगा।

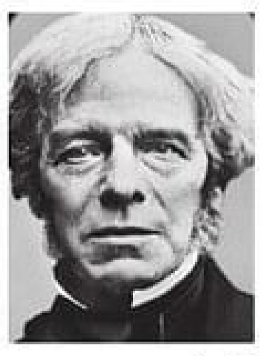

माइकल फैराडे

जब मैंने पुस्तकें बेचने का काम छोड़ दिया और विज्ञान को अपनी आजीविका बनाया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन सभी बेमतलब की बातों और ईर्ष्याओं को पीछे छोड़ दिया है, जो मनुष्य की नैतिक प्रगति में बाधा डालती हैं। कुछ समय बाद मैंने अपने भीतर एक अलग तरह की उन्नति देखी। एक उन्नत व्यक्तित्व और समाज के लिए आत्म-शिक्षा जरूरी है। आत्म-शिक्षा वह बिंदु है, जिसमें मन को अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करना सिखाया जाता है। इसी आत्म-शिक्षा का परिणाम है कि मेरे अधीन कभी भी कोई ऐसा सहायक नहीं रहा, जिसने मेरी सहायता की हो।

जीवन धारा

मैंने हमेशा खुद से ही विचार करते हुए अपने प्रयोग किए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तब किसी कंपनी में काम कर सकता था या खुलकर सोच सकता था या अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता था। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा होता, तो अपने किसी सहायक के साथ घंटों और कई दिनों तक प्रयोगशाला में काम कर रहा होता या सफाई कर रहा होता। लेकिन आज मैं जो भी हूं, यह सब एकांत का परिणाम है। जीवन के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है अगर इसे समझा जाए, तो पाएंगे कि शिक्षा में मन के सुधार से संबंधित सब कुछ शामिल है, चाहे यह दूसरों से ज्ञान प्राप्त करके हो या स्वयं के प्रयासों से हो। यह हमें कभी भी किसी चीज की उपेक्षा करने की शिक्षा नहीं देती और छोटी-छोटी शुरुआतों को तुच्छ नहीं समझती है। कोई भी चीज इतनी अद्भुत नहीं है कि वह सच न हो सके, अगर वह प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो।

चैटजीपीटी से एक लेखिका की मुठभेड़

चैटजीपीटी ने लेखिका को पीछे छोड़ते हुए कहानी तो सिर्फ 17 सेकंड में लिख दी, लेकिन क्या उसमें वह भावनात्मक रस था, जो आपको भिगो दे।

कर्टिस सिटेनफील्ड
उपन्यासकार

इन गर्मियों में, मैं एक अलग तरह के साहित्यिक प्रयोग का हिस्सा बनी। प्रयोग का विषय था कि एक इन्सान द्वारा रचित कहानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई द्वारा लिखित कहानी में क्या फर्क है? यह तय हुआ कि मेरे और चैटजीपीटी के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, यह देखने के लिए कि कौन बेहतर लिखता है। मैंने यह सोचकर प्रयोग के लिए हामी भर दी कि मशीन के साथ आमने-सामने की लड़ाई में हमें एआई के बारे में कुछ स्पष्ट जवाब मिल सकेंगे।

प्रतियोगिता के आयोजकों के सामने अगली समस्या विषय के चुनाव की थी, जिसके बारे में यह निर्णय लिया गया कि पाठकों के बीच एक सर्वे आयोजित किया जाएगा, जिसके जरिये ही विषय का चुनाव होगा। वैसे मैं बता दूं कि मैं उन कई लेखकों में से हूं, जिनके उपन्यासों का उपयोग बगैर मेरी अनुमति के और बगैर मुझे मुआवजा दिए, चैटजीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। खैर, विषय तय हुआ और मुझे व चैटजीपीटी को प्रतियोगिता की शर्तें भी समझा दी गईं। हम दोनों ने कहानी लिखी। चैटजीपीटी की कहानी का

48 वर्षीय नायक बहुत शर्माता है और किशोरावस्था वाली पत्रिकाएं पढ़ता है। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन इतनी जल्दी कहानी का आकलन नहीं कर सकते। मैंने चैटजीपीटी की पूरी कहानी पढ़ी। मैं दावे के साथ कह रही हूं कि इतनी उबाऊ थी कि अगर प्रतियोगिता का सवाल न होता, तो शायद मैं कभी पूरी नहीं पढ़ती। कुल मिलाकर मुझे लगा कि वाक्य रचना की दृष्टि से तो चैटजीपीटी बेहद कुशल है, लेकिन मानवीय भावनाओं के स्तर पर बहुत उथला है। अगर आपको खूब पढ़ने की आदत है, तो चैटजीपीटी का लेखन आपको काफी घिसा-पिटा भी लग सकता है। कुछ कमी है, जो आपको चैटजीपीटी की कहानी में

इमोशन एआई

इसे इमोशनल एआई या प्रभावशाली एआई भी कहते हैं। एआई के क्षेत्र में उभरती हुई इस इमोशन एआई तकनीक का उद्देश्य मानवीय भावनाओं का पता लगाना, उनका विश्लेषण करना और फिर उन पर अपनी प्रतिक्रिया देना है। मानवीय भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए यह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

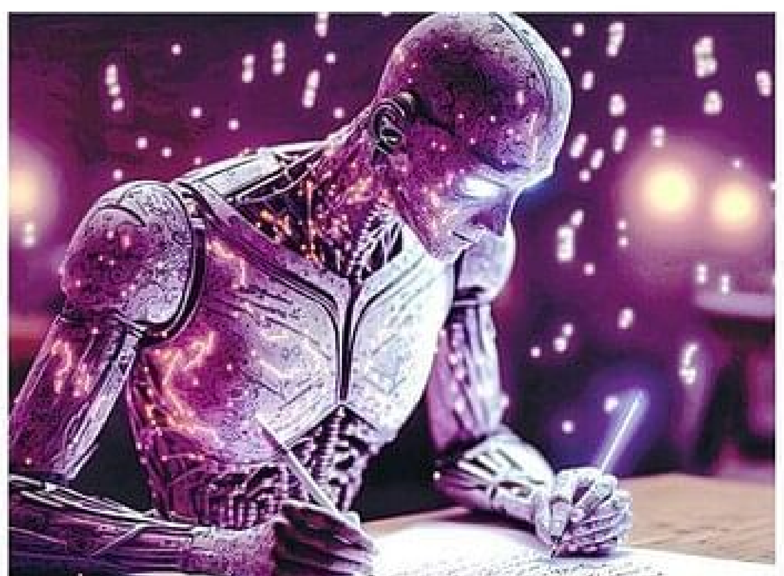

कंपोजिट एआई

एआई ने बिजनेस के कई क्षेत्रों में विविधताओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अवसर बढ़े हैं, तो जटिलताएं भी हैं। इन्हीं जटिलताओं का समाधान करने और एआई की मदद के लिए एआई तकनीक में कंपोजिट एआई का प्रयोग किया जा रहा है। कंपोजिट एआई वह तकनीक है, जो कई तकनीकों की विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग कर बिजनेस में आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। कंपोजिट एआई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और नॉलेज ग्राफ के उपयोग से समस्याओं का हल करती है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि एआई अनुप्रयोगों में बड़े डाटा शीट की जरूरतों को पूरा करता है।

लगेगी, जो मुझे भी लगी। मैं निष्पक्षता का दिखावा करते हुए इसकी तारीफ नहीं कर सकती। चूंकि प्रतियोगिता की थीम में यह शामिल था कि कहानी ऐसी हो, जो लोग समुद्र तट पर बैठकर पढ़ना चाहें, मैंने अपनी कहानी में कुछ चीजें जोड़ीं, लेकिन उन पर चैटजीपीटी ने ध्यान नहीं दिया।

- मैंने धीरे-धीरे लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि जल्दबाजी से चीजों को बेहतर बनाने का मौका खोता है।
- मैं कई दिनों तक समुद्र तट पर टहलने गई, यह महसूस करने के लिए कि उस वक्त मनोविज्ञान किस चीज को पढ़ने की इच्छा करता है।
- मैंने अपनी कहानी के पहले ड्राफ्ट पर अपने भरोसेमंद मित्रों व परिवारजनों से फीडबैक लिया।
- कहानी जिस शहर की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, मैंने वहां जाकर उन जगहों को देखा और वहां के रेस्तरां की मेन्यू सूची भी देखी, ताकि मैं मौलिक ढंग से इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकूं।

एक चीज ऐसी है, जो मैंने की और जिसे चैट जीपीटी भी कर सकता था। चूंकि कहानी 1970 के दशक की है, मैंने सरकारी आंकड़ों की छानबीन की, ताकि मैं उस वक्त लोगों के नाम कैसे होते थे, यह जान सकूं। कहानी के चरित्रों के मैंने वैसे ही नाम रखे। एक चीज ऐसी जरूर थी, जो मैंने नहीं की और चैटजीपीटी ने की। चैटजीपीटी ने अपनी कहानी 17 सेकंड में लिखी, जबकि मुझे काफी वक्त लगा। एआई का यह गुण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इसकी कीमत भी हम चुकाते हैं। कहानी का नायक जब सोफे पर अपना हाथ रखकर कपड़े को महसूस करता है, या जब वह कॉफी का पहला घूंट पीता है और अपनी जीभ पर उसके स्वाद को फैलते हुए महसूस करता है, वह अनुभव जब कहानी में पाठक पढ़ते हैं, तो शब्द, चित्र बन जाते हैं। चैटजीपीटी की कहानी में ये अनुभव क्यों नहीं होते। मनुष्य और मशीन की लड़ाई में फिलहाल मेरा दांव तो मनुष्य पर ही है।

©The New York Times 2024

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

जब आप सहर्ष वही बने रहने पर राजी होते हैं, जो आप हैं और तुलना, प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते हैं, तो सभी आपका सम्मान करते हैं और आपको इज्जत देते हैं।

- लाओत्से

खेती की सुध

बढ़ती आबादी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव सबसे अधिक खेती-किसानी पर देखा जा रहा है। हर वर्ष अन्न उत्पादन बढ़ाने की राह में मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन की दरकार महसूस की जाती रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की दो नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से स्वाभाविक ही इस क्षेत्र में कुछ बेहतरी की उम्मीद जगी है। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना नामक दो नई योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि इस क्षेत्र के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं। कृषि कर्ज और फसल बीमा को सुविधाजनक बनाया गया है। किसानों की प्रोत्साहन राशि बढ़ा कर छह हजार से दस हजार रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। इनके बीच दो नई योजनाएं शुरू होने से खेती-किसानी में कुछ बेहतरी की संभावना बन सकती है। सरकार ने इस वर्ष तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। वह वादा पूरा तो नहीं हो पाया, पर कुछ तरक्की के संकेत जरूर मिले हैं। देखना है, नई योजनाएं इस वादे को पूरा कर पाने में कितनी और कहां तक मददगार साबित होती हैं।

सरकारी दावों के बरक्स जमीनी हकीकत कुछ अलग है। स्थिति यह है कि खेती लंबे समय से घाटे का उद्यम बन चुकी है। बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां किसानों की मानसून पर निर्भरता है। फिर, खेती में लागत काफी बढ़ गई है। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों आदि की कीमतें बहुत सारे किसानों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। लागत और लाभ में काफी अंतर है। कुछ फसलें लागत से भी कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं। सरकार हर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो करती है, मगर उस कीमत पर भी अनाज बाजार में नहीं बिक पाता। बिचौलिए उससे काफी कम कीमत पर फसल खरीदते हैं। नगदी फसल उगाने वाले किसानों को अक्सर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम की मार से फसलें चौपट हो जाती हैं, तो कभी बाजार में उतार और मांग कम होने के कारण उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। हर वर्ष किसानों को प्रतिरोध में फसलें सड़कों पर फेंकते देखा जाता है। इस स्थिति से पार पाने में ये योजनाएं कितनी सफल होंगी, यही उनकी कसौटी होगी।

किसान लगातार मांग करते रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए और इसके दायरे में और फसलों को लाया जाए। इस मांग को लेकर किसान लंबे समय तक आंदोलन भी कर चुके हैं। मगर इस पर सरकार का रुख सकारात्मक नहीं देखा गया। सरकार कृषि को व्यवसाय का दर्जा देने की बात सैद्धांतिक रूप से तो करती रही है, मगर व्यावहारिक स्तर पर उसकी कृषि नीतियां प्रश्नों के दायरे में बनी रही हैं। दरअसल, किसानों की समस्या तदर्थ उपायों से दूर नहीं होने वालीं। टिकाऊ कृषि के लिए व्यापक स्तर पर और व्यावहारिक उपाय करने की जरूरत है। इसके लिए उत्पादन, भंडारण, विपणन आदि खेती-किसानी के हर पहलू पर भरोसेमंद कदम उठाने होंगे। नई योजनाएं इस जरूरत को कहां तक पूरा कर पाएंगी, देखने की बात है।

बेखौफ अपराधी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने कामयाब शासनकाल के प्रचार में सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में अपराध पर काबू पाने के लिए जो अभियान चलाए गए, उससे वहां आपराधिक मानसिकता वाले खौफ से भरे हुए हैं और अपराध रुक गए हैं। मगर हकीकत यह है कि कुछ प्रचारित मामलों को छोड़ दिया जाए तो राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया लगता है। वे अब सामूहिक कत्लेआम करने से भी बाज नहीं आ रहे। अमेठी जिले में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या से जाहिर है कि राज्य में संगठित अपराधी हों या आपराधिक मानसिकता वाले लोग, उनके भीतर पुलिस या कानून का कोई खौफ नहीं है। खबर के मुताबिक, हत्या के आरोपी ने रायबरेली से अपनी मोटरसाइकिल से अमेठी पहुंच कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें उसने न केवल दंपति, बल्कि उनके दो छोटे बच्चों को भी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी और फरार हो गया। हालांकि इस मामले में एक से अधिक अपराधियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी, मगर अपराधियों और अपराध का खात्मा करने के सरकारी दावे के बरक्स यह हत्याकांड क्या दर्शाता है?

सवाल है कि सरकार और पुलिस अब जिस सख्ती का दावा कर रही हैं, उसमें ऐसी निरंतरता क्यों नहीं होती, जिससे अपराधियों के भीतर कानून का खौफ पैदा हो! गौरतलब है कि करीब डेढ़ महीने पहले महिला ने छेड़छाड़, विरोध करने पर पति से मारपीट, जान से मारने की धमकी और जातिसूचक टिप्पणियां करने को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में मुख्य रूप से उसी व्यक्ति के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अब स्वाभाविक ही ये सवाल उठ रहे हैं कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में समय रहते ठोस कार्रवाई की गई होती तो क्या चार लोगों की जान बचाई जा सकती थी? किसी अपराध के आरोपी को मुठभेड़ में मारे जाने की सुर्खियां इस हकीकत का जवाब नहीं हो सकतीं कि राज्य में आए दिन होने वाली आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी बेखौफ दिखने लगे हैं।

वास्तविक के बरक्स आभासी दुनिया

एक सर्वेक्षण के मुताबिक तेरह से सत्रह वर्ष के किशोर औसतन हर दिन नौ से दस घंटे और आठ से बारह वर्ष के बालक औसतन आठ घंटे मोबाइल के साथ गुजारते हैं। आनलाइन मित्रता करना, परिवार और समाज से हर समय कटे रहना तथा केवल मौज-मस्ती करना उनकी जिंदगी का मकसद हो गया है।

अखिलेश आर्येंदु

सोशल मीडिया पर रोजाना न जाने कितने वीडियो, चित्र और समाचार साझा किए जाते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि इस तरह के वीडियो और समाचार किशोरों और कम उम्र के बच्चों में आत्महत्या, हिंसा, यौन अपराध और संवेदनहीनता पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के बाद समाज, संस्कृति और सोच में जिस तरह के बदलाव की आशंका जताई जा रही थी, वह अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। बीसवीं सदी के अंतिम दशक में मोबाइल, इंटरनेट और इससे जुड़ी साइटों और नए-नए साफ्टवेयरों के इस्तेमाल तथा उसके असर पर तब बहुत कुछ ऐसा लिखा जा रहा था, जिस पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही थीं, लेकिन मोबाइल के ऐस नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, किसी ने सोचा न होगा।

समाजशास्त्रियों और शोध संस्थाओं के सर्वेक्षण बताते हैं कि पिछले तीन-चार दशक में भारतीय समाज, खासकर युवाओं में एक नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। बहुत सारे अवसाद का शिकार हो रहे हैं। उनमें चिड़चिड़ापन, अकेले रहने की प्रवृत्ति गहरी हो रही है। माता-पिता, आस-पड़ोस, रिश्तेदारों से उनका लगाव तेजी से कम हो रहा है। पढ़ाई-लिखाई में भी रुचि तेजी से घट रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना और जो कुछ देखा-सुना उसे हासिल करने के लिए हद से गुजर जाने की भावना का लगातार बढ़ते जाना है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक तेरह से सत्रह वर्ष के किशोर औसतन हर दिन नौ से दस घंटे और आठ से बारह वर्ष के बालक औसतन आठ घंटे मोबाइल के साथ गुजारते हैं। आनलाइन मित्रता करना, परिवार और समाज से हर समय कटे रहना तथा केवल मौज-मस्ती करना उनकी जिंदगी का मकसद हो गया है। इससे परिवार और समाज दोनों पर गहरा असर पड़ रहा है।

मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल करने से इसकी लत लग जाती है। जब मोबाइल पर कोई खेल रहा होता है या कोई काम पूरा कर रहा होता है, तो उसे जितना हो सके, बेहतर करने की कोशिश करता है। एक बार जब इसमें सफलता मिल जाती है तो यह धीरे-धीरे आदत में बदल जाती है। यह आदत फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया मंचों पर आठ-दस घंटे लगातार रहने से स्वभाव में बदल जाती है। सोशल मीडिया की तमाम साइटों के जरिए लोग हिंसा, प्यार, नफरत, वेदना और विश्वासघात जैसी प्रवृत्तियों से गुजरने लगते हैं। आज मोबाइल स्क्रीन पर महज एक स्पर्श से सभी कुछ उपस्थित हो जाता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक पचासी फीसद लोग संदेश भेजते हैं। इसी तरह चित्र साझा करने और उन्हें देखने में बयासी फीसद लोग शामिल होते हैं। मित्रों के साथ संपर्क में रहने के लिए अस्सी फीसद लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो/ फिल्म और संगीत के लिए सोशल मीडिया का लगभग पचहत्तर फीसद लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने निकटतम लोगों के संपर्क में बने रहने के लिए लगभग छिहत्तर फीसद लोग, तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए साठ फीसद से अधिक लोग इसका

प्रयोग करते हैं। 'साइट एप्लीकेशन' लगभग पैंसठ फीसद लोग और जीवन साथी की जानकारी रखने के लिए पचास फीसद लोग प्रयोग करते हैं।

पिछले दशकों में सोशल मीडिया के दुरुपयोग की वजह से कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम सहित तमाम कई

> **सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को एक तरह से सम्मोहित कर लिया है। इससे उनमें भटकाव, नकारात्मकता, नफरत, बदले की भावना, कामुकता, अविश्वास, जीवन के प्रति लापरवाही, अच्छे कार्यों के प्रति अरुचि, संवदेनहीनता, क्रूरता, बदपरहेजी, विकृत मनोरंजन, मानसिक तनाव, धूर्तता और विश्वासघात जैसी तमाम प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं। मानवीय, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में बिखराव पैदा करने में सोशल मीडिया की भूमिका से हम सब परिचित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विश्व समाज और प्रकृति की अज्ञात चीजों के बारे में जानने में सोशल मीडिया के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।**

इलाकों में दंगे-फंसाद हुए। हत्या, अपहरण, नफरत, यौन अपराध, बदले की भावना और स्वार्थ की अतिशय प्रवृत्तियों को बहुत बढ़ावा मिला। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर सब कुछ बुरा है, लेकिन मानव मन अच्छाइयों की तरफ न जाकर बुराइयों की ओर ही लपकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फूहड़ सामग्री, वीडियो, आपत्तिजनक संवाद और भावना भड़काने वाले कार्यक्रमों के लेख और वीडियो कुछ ही मिनट में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। दरअसल, सोशल मीडिया अब महज सूचनाओं के आदान-प्रदान का मंच नहीं रह गया है। यह एक बड़ा कारोबार बन चुका है। इसलिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए इसमें बहुत कुछ ऐसी सामग्री भी डाली जाने लगी है, जो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कतई उचित नहीं कही जा सकती।

ऐसा भी नहीं कि सोशल मीडिया का असर केवल शहरी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। इसने ग्रामीण इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गांव की सहजता, मौलिकता, आतिथ्य सत्कार, कृषि-संस्कृति, लोक धर्म, लोक संवाद, लोक चर्चा, लोक साहित्य, लोक संवाद और लोक धुनों की मीठी गूंज गुम होती जा रही है। गांवों के चौपालों पर जो महफिलें सजती थीं, उसको सोशल मीडिया ने अपने आगोश में समेट लिया है। गांवों का स्वस्थ मनोरंजन अब यू ट्यूब, फेसबुक और वाट्सऐप के आने के बाद कहीं गायब हो गए हैं। महज तीन दशक में सोशल मीडिया ने भारतीय समाज को हर स्तर पर पतन की ओर धकेला है। संस्कृति, भाषा, स्वदेशी, शाकाहार, स्वावलंबन और मूल्य परक साहित्य की अहमियत सोशल मीडिया ने खत्म कर दी।

सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को एक तरह से सम्मोहित कर लिया है। इससे उनमें भटकाव, नकारात्मकता, नफरत, बदले की भावना, कामुकता, अविश्वास, जीवन के प्रति लापरवाही, अच्छे कार्यों के प्रति अरुचि, संवदेनहीनता, क्रूरता, बदपरहेजी, विकृत मनोरंजन, मानसिक तनाव, धूर्तता और विश्वासघात जैसी तमाम प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं। मानवीय, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में बिखराव पैदा करने में सोशल मीडिया की भूमिका से हम सब परिचित हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विश्व समाज और प्रकृति की अज्ञात चीजों के बारे में जानने में सोशल मीडिया के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हम इस बात से इनकार नहीं सकते है कि तमाम खामियों के बावजूद सोशल मीडिया समाज, ज्ञान-विज्ञान, प्रकृति और अद्यतन को जानने समझने का सबसे बेहतर जरिया है। गांवों की लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक साहित्य और लोक संगीत भले संकट में दिखते हों, लेकिन सोशल मीडिया ने इन्हें जीवंत और संरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। विश्व स्तर पर आतंक, पलायन, सांप्रदायिकता, क्रूरता, भ्रष्टाचार, व्याभिचार आदि विकृतियों को पोषित कर सोशल मीडिया ने ऐसी कई समस्याओं और संकटों को जन्म दिया है, जिन्हें दो दशक पहले तक कोई नहीं जानता था। इसी तरह अंधविश्वास, पाखंड और कुप्रथाओं को बढ़ाने में भी सोशल मीडिया योगदान कर रहा है। इससे व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों में कमजोरी आई है।

सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से अनेक तरह के शारीरिक और मानसिक रोग असमय ही पैदा होने लगे हैं। दूसरी ओर, कई बीमारियों के बढ़ने की बड़ी वजह सोशल मीडिया की लत है। नई पीढ़ी अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल के संग बिताने में अधिक मशगूल दिखाई पड़ती है। इससे उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति और सहजता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल भले जिंदगी का हिस्सा बन गया हो, पर इसने रातों की नींद और दिन का चैन छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दुनिया मेरे आगे

रिश्तों की डोर

मोनिका राज

हर अगले रोज थोड़ा ज्यादा मशीनी होती जिंदगी में यह एक सामान्य अनुभव है कि रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या फिर एक प्रेम संबंध, सभी रिश्तों की नींव विश्वास और आपसी समझ पर टिकी होती है, लेकिन कई बार इन्हीं रिश्तों में उपेक्षा का दंश और विश्वास की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो संबंधों को कमजोर कर देती हैं। आजकल जिंदगी की भाग-दौड़ में लोगों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। किसी से उपेक्षित होना किसी भी रिश्ते में सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यह वह स्थिति है जब किसी एक व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उसका साथी उसकी भावनाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को महत्त्व नहीं दे रहा है। उपेक्षा धीरे-धीरे रिश्ते को अंदर से कमजोर कर देती है। कामकाजी जीवन, सामाजिक दायित्वों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इससे संबंधों में समय की कमी होने लगती है, जो आखिर उपेक्षा का कारण बनता है।

कई बार व्यक्ति अपने जीवन में इतना आत्म-केंद्रित हो जाता है कि वह अपने साथी की भावनाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता जाता है। वह अपने सपनों, इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके साथी को महसूस होने लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। एक बात यह भी है कि समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिसका असर कई बार स्पष्ट दिखने लगता है। मसलन, शादी के शुरुआती वर्षों में जो व्यक्ति अपने साथी के साथ अधिक समय बिताता था, वह बाद में अपने करियर या अन्य गतिविधियों में इतना खो जाता है कि उसका साथी उपेक्षित महसूस करने लगता है। अपने कामकाज के लिए हम किसी अपने की उपेक्षा करके उसका दिल तो दुखा देते हैं, पर उसका प्रभाव गहरा होता जाता है। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है और उसे अपने आप में संदेह करने पर मजबूर कर सकता है।

> **संवाद और संचार किसी भी रिश्ते का बुनियादी आधार होता है। अगर रिश्ते में उपेक्षा बढ़ रही हो और विश्वास की कमी हो रही हो, तो सबसे पहले दोनों पक्षों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अपनी भावनाओं, चिंताओं और समस्याओं को एक-दूसरे के सामने रखना चाहिए, ताकि गलतफहमियां दूर हों।**

उपेक्षा से व्यक्ति के भीतर अकेलेपन की भावना पनप सकती है, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है। लंबे समय तक उपेक्षा सहने से व्यक्ति रिश्ते में रुचि खोने लगता है और रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। इस तरह के दरार को पाटने के लिए एक दूसरे पर विश्वास होना आवश्यक है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। यह वह धागा है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है, लेकिन जब इस धागे में दरार आ जाती है, तो रिश्ते का टूटना तय होता है। अक्सर देखा गया है कि कई बार व्यक्ति के अतीत में हुए धोखे और धोखाधड़ी के अनुभव उसे नए रिश्ते में विश्वास करने से रोकते हैं। उसे डर रहता है कि वही इतिहास दोहराया न जाए। और इस डर के कारण वह अपने साथी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता। असुरक्षा की भावना भी विश्वास की कमी का एक प्रमुख कारण है। व्यक्ति को लगता है कि उसका साथी उसे छोड़ सकता है या धोखा दे सकता है। यह भावना उसे अपने साथी पर विश्वास करने से रोकती है और वह संदेह की दृष्टि से अपने साथी को देखने लगता है। कई बार छोटी-छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। जब दो लोगों के बीच संवाद की कमी होती है, तो वे एक-दूसरे के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये गलतफहमियां विश्वास की कमी का कारण बनती हैं। जब रिश्ते में विश्वास की कमी होती है, तो व्यक्ति को अपने साथी के हर कार्य पर संदेह होने लगता है। वह साथी के फोन, संदेश, ईमेल आदि की जांच करने लगता है। यह संदेह और असुरक्षा की भावना धीरे-धीरे रिश्ते को अंदर से कमजोर कर देती है। विश्वास की कमी से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, जो धीरे-धीरे रिश्ते के टूटने का कारण बनती है।

संवाद और संचार किसी भी रिश्ते का बुनियादी आधार होता है। अगर रिश्ते में उपेक्षा बढ़ रही हो और विश्वास की कमी हो रही हो, तो सबसे पहले दोनों पक्षों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अपनी भावनाओं, चिंताओं और समस्याओं को एक-दूसरे के सामने रखना चाहिए, ताकि गलतफहमियां दूर हों और रिश्ते में मजबूती आए। उपेक्षा से बचने के लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे वह कुछ मिनट के लिए फोन पर बातचीत हो या संवेदना के खोए सूत्रों को फिर से जोड़ना। यह महत्त्वपूर्ण है कि एक-दूसरे के साथ समय बिताया जाए। आत्म-जागरूकता रिश्ते में सुधार लाने का एक महत्त्वपूर्ण जरिया है। अगर किसी को लगता है कि वह अपने साथी की उपेक्षा कर रहा है या उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो उसे अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए। कारणों की खोज के बाद उसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दो लोगों के बीच कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन माफी मांगने और माफ करने से रिश्ते में विश्वास की भावना फिर से स्थापित होती है। एक-दूसरे की सराहना करना भी रिश्ते को मजबूत करने का एक कारण बनता है। जब कोई अपने साथी के प्रयासों और योगदान को सराहता है, तब उसे यह महसूस होगा कि उसकी उपेक्षा नहीं हो रही है। यह रिश्ते में सकारात्मकता और प्रेम की भावना को बनाए रखता है।

दरअसल, रिश्ते को निभाने में समझ, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास की कमी रिश्तों को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष समय पर इन समस्याओं को पहचानकर उनका समाधान करें, तो रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ता वही होता है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे की भावनाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं का सम्मान करते हैं और आपसी विश्वास बनाए रखते हैं।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

वादों की सियासत

आज की राजनीति में निरंतर प्रयोग और गठबंधन के खेल ने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया है। हर चुनाव के साथ नए समीकरण बनते हैं, परंतु इसका असर प्रायः नकारात्मक रहा है। राजनीतिक दल जनता के हित के बजाय अपने स्वार्थों को साधने में लगे दिखते हैं, जिससे राज्य और देश के विकास पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार होने वाले गठजोड़ ने प्रशासनिक कार्यकुशलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। चुनावी वादों की लंबी फेहरिस्त अक्सर केवल कागजों तक सीमित रह जाती है, जबकि जमीन पर उन वादों का कार्यान्वयन नदारद रहता है। यह स्थिति न केवल सरकार की विश्वसनीयता पर चोट करती है, बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है। समस्या की जड़ में जनता की निष्क्रियता भी है। मतदाता अक्सर चुनावी वादों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि वे दीर्घकालिक सोच के साथ मतदान करें, ताकि दल भी जनता के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें।

- अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

उपलब्धियों के बरक्स

राजग सरकार के सौ दिन के कार्यकाल में कुछ उपलब्धियां हैं, तो कुछ नाकामियां भी हैं। बीते तीन महीने में अरबों रुपए की परियोजनाओं पर केंद्र सरकार की ओर से कार्य शुरू किया गया है। देश की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने का प्रयास हुआ है। किसान सम्मान योजना की राशि का वितरण किया गया है। खरीफ सीजन की चौदह फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' लागू की गई है। सात लाख तक की आय को कर मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कार्य हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए गए। मगर मणिपुर में हिंसा की आग को रोकने में यह सरकार नाकाम रही है। रेल दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। महंगाई को रोकने में भी सरकार विफल रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी वारदात बढ़ी हैं। राजग के घटक दलों में समन्वय का भी अभाव देखा गया है।

- ललित महालकरी, इंदौर

आस्था के समांतर

हाल के दिनों में बलात्कार से संबंधित दहलाने वाली कई खबरें आईं। इन्हें पढ़ कर और सुन कर बेहद अफसोस होता है। देश में लोग नवरात्रि पर धूमधाम से मां दुर्गा के विविध रूपों की आराधना करते हुए उपवास करते हैं। मां गंगा की कसम खाई जाती है, उसी देश में महिलाओं का अपमान हमारे सभ्य चेहरे पर कालिख के समान है। कई बार यह भी कहा जा सकता है कि हम केवल दिखावे की भक्ति ज्यादा करते हैं। हम जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा-पाठ करते हैं, उसी भावना के साथ बच्चियों को सुरिक्षत माहौल दें। महिलाओं का सम्मान करें तो ही सभ्य समाज कहलाने में गर्व महसूस कर सकते हैं। इस समय नवरात्रि पर पूरी आस्था और भक्ति का भाव दिख रहा है। ऐसे में सभी पुरुषों को संकल्प करना चाहिए कि हम ऐसा आचरण कभी नहीं करें जो हमारे संस्कारों और सिद्धांतों के विरुद्ध हों, तभी इन पर्वों को मनाने की सार्थकता रहेगी ।

- हेमा हरि उपाध्याय 'अक्षत' , उज्जैन

शांतिदूत की जरूरत

विश्व आज महायुद्ध की आशंका से घिरा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन लंबे समय से युद्ध में उलझे हैं, वहीं इजराइल ने अपनी आक्रामकता से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। कब तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क उठे, कोई नहीं जानता। भारत ने बुद्ध और गांधी सरीखे शांति दूत दिए, लेकिन आज वे विस्मृत किए जा रहे हैं। सबको पता है कि राजनीति के कारण आज हम देश के महापुरुषों को रसातल में भेजने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। न विश्व से गांधी खत्म होंगे और न ही उनकी विचारधारा, बल्कि ज्यों-ज्यों उनकी उपेक्षा की जाएगी, लोगों में उनको जानने की इच्छा जागृत होगी। यह देश मूलतः शांति और सह-अस्तित्व का देश है। इसमें गांधी भी रहेंगे और बुद्ध तथा महावीर भी। यहां की मिट्टी की तासीर ही ऐसी है कि नफरत हमेशा हारी है। वैसे भी देश की तरक्की का रास्ता शांति और भाईचारे में ही है।

- मुनीश कुमार, अलखपुरा भिवानी, हरियाणा

www.readwhere.com

चिंतन

जयशंकर का पाक दौरा एससीओ बैठक के लिए

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा केवल एससीओ बैठक के लिए है। वे 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में शामिल होंगे। 2015 में सुषमा स्वराज के बाद किसी भारतीय नेता का यह पहला दौरा होगा। इस यात्रा को लेकर भारत का रुख साफ है कि इस दौरान भारत की पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। पिछले नौ वर्ष से भारत व पाक के बीच वार्ता पर बर्फ जमी हुई है। भारत एससीओ के चार्टर के नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए इसकी बैठक जहां होगी, वहां भारतीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जयशंकर के इस दौरे का पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान से वार्ता के लिए भारत अपने पूर्व के रुख पर कायम है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा नहीं करता, तब तक भारत वार्ता शुरू नहीं करेगा। भारत वार्ता भी आतंकवाद व पीओके पर करेगा, कश्मीर पर नहीं। जयशंकर की यह यात्रा पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए नहीं है। दरअसल, भारत से रिश्ते सुधारने का दायित्व पाकिस्तान पर है, वह शर्त का पालन करे तो नई दिल्ली के साथ संबंध मधुर हो सकता है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दरम्यान कश्मीर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर होते तो भारत पाक की मदद करता। पाकिस्तान की मेजबानी में राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक हो रही है। चीनी प्रभुत्व वाले एससीओं में चीन, रूस, भारत, ईरान, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान व उज़्बेकिस्तान सदस्य हैं। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ बैठक के लिए न्योता दिया था। न्योता आने के बाद 30 अगस्त को जयशंकर ने दोनों देशों के रिश्ते पर बयान दिया था, जिसमें कहा कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार साल 2015 में एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। तब उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान दौरे पर गई थीं। पर पाक ने पीएम व विदेश मंत्री की यात्रा की कद्र नहीं की, अगले साल ही 2016 में भारतीय जवानों के वेश मंथ 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने 15 से ज्यादा ग्रेनेड कैंप पर फेंके थे। इस हमले में सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। हमले का जवाब देने के लिए 28-29 सितंबर की रात सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। इस हमले में 38 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ती गई है। भारत में पाक कलाकारों और फिल्मों का भी बॉयकॉट हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम भी आखिरी बार 2008 में मैच खेलने पाकिस्तान गई थी। इस साल 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान में हुए एससीओ समिट में भी विदेश मंत्री जयशंकर ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पिछले दो बार से पीएम इस बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे चीन के साथ सीमा पर तनाव व पाक से खराब रिश्ते वजह मानी जा रही है। मई 2023 में पाक के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जब गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे, तब भी भारत व पाक के बीच कोई बात नहीं हुई थी। बिलावल का यह दौरा 12 सालों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला दौरा था। जय शंकर के इस पाक दौरे का कोई भी कूटनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।

आर्थिकी
सतीश सिंह

फेडरल रिजर्व के फैसले का वैश्विक प्रभाव

अमेरिका के फेडरल रिजर्व को दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों का अगुआ माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर का दुनिया के सबसे मजबूत करेंसियों में से एक होना और सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अमेरिका का दुनिया का सबसे मजबूत देश होना है। अमूमन, फेडरल रिजर्व के नक्शे-कदम पर दुनियाभर के केंद्रीय बैंक चलते हैं। हालांकि,सभी देशों की आर्थिक स्थिति अलग-अलग होने के कारण कभी-कभी कुछ देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से इतर निर्णय लेते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो भारत भी फेडरल रिजर्व द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप कदम उठाता है। विगत 4 वर्षों में पहली बार फेडरल रिजर्व ने 18 सितंबर को नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की है, जिसके बाद दुनिया के दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा भी नीतिगत दरों में कटौती करने की संभावना बढ़ गई है। वैसे, इसे अमेरिका में संभावित आर्थिक मंदी को लेकर फेडरल रिजर्व की बढ़ती आशंकाओं के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका में विकास की गति धीमी है, जिसमें तेजी लाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। फेडरल रिजर्व के ताजा निर्णय के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में ज्यादा निवेश किया है। 24 सितंबर को सेंसेक्स और निफ्टी अपने शीर्ष स्तर को छूने में कामयाब रहा। दरअसल, डॉलर के कमजोर पड़ने, उधारी दर में कमी आने, निवेश व कारोबारों में तेजी आने आदि की संभावना बढ़ी है, जिसकी पुष्टि निवेश में तेजी से हो रही है। सवाल का यहां उठना लाजिमी है कि क्या फेडरल रिजर्व की तर्ज पर आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में कटौती करेगा, क्योंकि महंगाई और विकास के बीच के तालमेल को बनाये रखने के लिए फरवरी 2023 के बाद से रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और यह 6.5 प्रतिशत पर बरकरार है। इसलिए, रिजर्व बैंक को रेपो दर में कटौती करने से पहले मौजूदा आर्थिक स्थिति, जीडीपी वृद्धि दर, महंगाई की स्थिति, आर्थिक गतिविधियों की गति आदि बिंदुओं पर गहन विमर्श करना होगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े निरंतर बेहतर हो रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 6.8 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत थी। हालांकि, मूडीज ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा है, जबकि 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.6 प्रतिशत जताया है। भले ही, मूडीज़ ने कैलेंडर वर्ष 2024 की तुलना में कैलेंडर वर्ष 2025 और 2026 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कम जताया है, लेकिन ये आंकड़े विश्व के कई विकसित देशों से बेहतर हैं। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई और अगस्त महीने में 4 प्रतिशत से नीचे रही है और बारिश के खत्म होने के बाद खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी आने का अनुमान है, जिससे आगामी महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति में और भी कमी आने के कयास लगाये जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भी वित्त वर्ष 2025 में मुद्राास्फीति घटकर 4.5 प्रतिशत रह सकती है। एचएसबीसी विनिर्माण पीएमआई सितंबर 2024 में घटकर 56.7 रह गया, जो अगस्त महीने में 57.5 रहा था। सेवा पीएमआई भी सितंबर महीने में घटकर 58.9 प्रतिशत रह गया, जो अगस्त महीने में 60.9 रहा था। बेशक, विनिर्माण और सेवा पीएमआई में अगस्त महीने के मुक़ाबले सितंबर महीने में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। फिर भी, यह 50 से ऊपर है, जो दर्शाता है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तेजी का रुख बना हुआ है। रेपो दर फरवरी 2023 से 6.5 प्रतिशत के स्तर पर कायम है। दिसंबर 2023 की तुलना में ऋण उठाव में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 9 अगस्त 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए क्रमिक रूप से 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निरपेक्ष रूप से, पिछले 8 महीनों में, ऋण उठाव 9.2 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 9 अगस्त 2024 तक 168.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अगर रेपो दर में कटौती की जाती है तो उधारी के उठाव एवं विकास में और भी तेजी आएगी। फिलवक्त जीडीपी में वृद्धि हो रही है और महंगाई भी काबू में है। साथ में, वित्त वर्ष 2025 और 2026 में भी खुदरा मुद्रास्फीति के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के आसार हैं। पुनश्चः डॉलर के कमजोर रहने और निवेश व ऋण उठाव में तेजी आने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, जिसे और भी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अगली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में कम से कम 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है।

(लेखक एसबीआई में एजीएम हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

कश्मीर
मनोज कुमार अग्रवाल

नसरल्लाह की मौत पर घाटी में रोष क्यों

लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उनके चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह चीफ घोषित किया गया है। नसरल्लह की मौत का रोष जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रा ने कहा कि आपने एक हिजबुल्लाह को मारा है, अब हर घर से नसरल्लाह निकलेगा', नसरुल्लाह की मौत पर इजरायल पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर के बडगाम की सड़कों पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने नसरल्लाह के पोस्टर के साथ इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। ऐसा क्यों?

इजराइल द्वारा लगातार हिजबुल्ला आतंकियों को निशाना बनाते हुए उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि अब हसन नसरल्लाह दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। वह 32 साल से संगठन का चीफ था, लेकिन क्या हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह के मारे जाने से आतंकवाद दफन हो जाएगा? दरअसल जरूरत नसरल्लाह के खात्मे की नहीं, उस कट्टरपंथी आतंकी मानसिकता के सफाए की है जो नसरल्लाह को जन्म देती है। आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़े सशस्त्र और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का 32 वर्षों तक नेतृत्व करने वाला नसरल्लाह शुक्रवार के हमले में मारा गया है। अब हिजबुल्ला अपने 42 साल के इतिहास में सबसे भारी हमले के बाद अस्तित्व के लिए कठिन चुनौती का सामना कर रहा है।

लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उनके चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्ला चीफ घोषित किया गया है, उसके भी मारे जाने की खबर है। नसरल्लाह की मौत का रोष जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। यहां विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रा ने कहा कि 'आपने एक हिजबुल्ला को मारा है, अब हर घर से नसरल्लाह निकलेगा', नसरुल्लाह की मौत से इजरादल पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर के बडगाम की सड़कों पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने नसरल्लाह के पोस्टर के साथ इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। कश्मीर में प्रदर्शन कर रही एक छात्रा ने इजरायल पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, 'मैं लेबनान के लोगों को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करें, हम उनके साथ हैं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको मारा है। अब हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा'। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह के अलावा उसकी बेटी जैनब की भी मौत हुई है। इजराइल ने यह हमला तब किया, जब नसरल्लाह और ईरान समर्थित समूह के कई अन्य नेता लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बंकर में जमा हुए थे। ये लोग दक्षिण बेरूत के व्यस्त इलाके में जमीन से 60 फीट नीचे इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इस क्षेत्र को तबाह करने के लिए आईडीएफ ने लगभग 80 टन बम का इस्तेमाल किया था। दहियाह के बेरूत उपनगर में हमला इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने के तुरंत बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कसम खाई थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल का अभियान जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक, विस्फोट से कुछ समय पहले ही इससे पहले हुई स्ट्राइक में मारे गए वरिष्ठ कमांडर सहित तीन हिजबुल्ला सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए लोग जमा हुए थे। सूत्रों ने कहा कि उसके शरीर पर कोई सीधा घाव नहीं था और ऐसा लग रहा है कि मौत का कारण तेज धमाके से हुआ ट्रॉमा रहा होगा। उधर, इजराइली सेना ने कहा कि उसने पिछले कुछ घंटों के दौरान लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमला किया है। सेना का कहना है कि हमलों का उद्देश्य हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्चर और हथियार गोदामों को तबाह करना था। महीनों की योजना और कई

खुफिया सूचनाओं के बाद, इजरायल ने एक अंडरग्राउंड बंकर पर सटीक हमला किया, जहां नसरल्लाह और कई अन्य हिजबुल्ला नेता बैठक कर रहे थे। यह बंकर दक्षिण बेरूत की एक व्यस्त सड़क से 60 फीट नीचे स्थित था। 31 अगस्त 1960 को बेरूत के उत्तरी बुर्ज हम्मूद उपनगर में जन्मे नसरल्लाह का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके आठ भाई-बहन थे। नसरल्लाह शिया समुदाय से ताल्लुक रखता था। उसके पिता अब्दुल करीम एक छोटी सी सब्जी का दुकान चलाते थे। 1975 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ जाने के बाद वह अमल आंदोलन में शामिल हो गया था।

साल 1992 में नसरल्लाह को हिजबुल्ला का महासचिव बनाया गया था। उसने अब्बास अल-मुसावी की जगह ली थी। मुसावी को भी इजरायल ने ही मार गिराया था। हसन नसरल्लाह को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। एक इंटरव्यू में नसरल्लाह ने कहा था कि वो बंकर में नहीं रहते, लेकिन वो समय-समय पर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। जो उसका इंटरव्यू लेने जाते थे, उन्हें ये तक पता नहीं होता कि वे कहां पर मौजूद हैं। दशकों से नसरल्लाह अपने भाषणों को खुफिया स्थान से जाकर प्रसारित करता था। वो न सिर्फ लेबनान में बल्कि पश्चिम एशिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक था। बताया है कि लेबनान के बेरूत में हवाई हमले में हिजबुल्ला नेता सैय्यद हसन नसरल्लाह के मारे जाने से कुछ घंटे पहले एक ईरानी जासूस ने इजराइली अधिकारियों को उनके ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है। इसकी आंच भारत तक पहुंच गई है।

भारत के जम्मू व कश्मीर के बडगाम इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हसन नसरल्लाह की मौत की मुखालफत की। विरोध प्रदर्शन में हसन नसरल्लाह की मौत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए एक रैली निकाली गई, इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हुए। जम्मू व कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हसन नसरल्लाह की मौत के दुख में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का विधानसभा चुनाव अभियान रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लेबनान और गाजा के लोगों के साथ खड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि 'मैं गाजा और लेबनान खासकर हसन नसरल्लाह की शहादत के वास्ते कल का अपना चुनावी अभियान रोकती हूं। इस अपार दुःख और प्रतिरोध की घड़ी में हम लेबनान और गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं।' सवाल उठता है कि भारत में कश्मीर की सड़कों पर हर घर से निकलेगा नसरल्लाह के नारे लगाने के पीछे कौन लोग हैं? इनकी मानसिकता क्या है? दरअसल नसरल्लाह के समर्थक उसे आतंक का सरगना या सरपरस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। अंजुमन-ए-शरी के अध्यक्ष शियान आगा सैयद ने कहा कि हम उनकी मौत पर कितना भी शोक मनाएं, यह हमेशा कम होगा, शांति होनी चाहिए और यही उनका मिशन था। उस पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया था ताकि लोगों को पता न चले कि वह मानवता के लिए क्या कर रहा है और वह क्या चाहता है। वह फिलिस्तीन के लोगों के लिए फिलिस्तीन को आजाद कराना चाहता था। मैं पूरी मानव जाति से और इस्लामिक देशों के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि उनकी शहादत को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन इतना तय है कि उनके खून से हजारों नसरल्लाह पैदा होंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। उधर हमास के आतंकी भी नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इजराइल के कंधे पर अमेरिका का हाथ है और अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रख कर हिजबुल्ला का सफाया करने में मददगार बना है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

साधना से ही मिलता है वास्तविक सुख

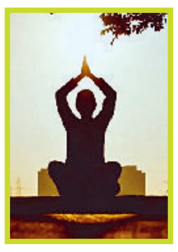

संकलित
दर्शन

अधिकांश व्यक्ति आज भौतिक मूल्यों के उपासक बन गए हैं। इस कारण जीवन के धर्म एवं मर्म को भुला बैठे हैं। उनकी इस उपासना ने दुनिया के बाह्य जगत को बड़ा सुहावना, लुभावना और आकर्षक बना दिया है। जबकि वास्तविक सुख आंतरिक सौंदर्य, अंतर्जगत की जागृति एवं अंतर्यात्रा से ही संभव है। भौतिक आकर्षण के पीछे मनुष्य दौड़ रहा है। यदि वह क्षण भर रुककर गंभीरता से सोचे तो उसे पता चलेगा कि यह सब भ्रम जाल है। जीवन वह नहीं, जिसे वह जी रहा है। संत एकनाथ ने कहा है कि धन जोड़कर भक्ति का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मन में वासना और भी बढ़ जाएगी और जिनका चित्त वासना में फंसा हुआ है, उन्हें अंतरात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। वास्तविक सुख पाने के लिए व्यक्ति भक्ति यानी साधना की ओर प्रवृत्त होता है। स्थायी सुख की प्राप्ति भक्ति पर ही निर्भर है। भक्ति से मन को वश में करना है और मन को वश में करने का सरल उपाय है उसे परमात्मा के हेतु निरंतर भले कार्यो में लगाए रखना। महात्मा गांधी ने प्रेमा बहन के नाम लिखे पत्र में लिखा है-जो लोग कृष्ण-कृष्ण कहते हैं वे उसके पुजारी नहीं हैं। जो उनका काम करते हैं, वे ही पुजारी हैं। रोटी-रोटी कहने से पेट नहीं भरता, अपितु रोटी खाने से ही भरता है। मन को वश में लाने का अभ्यास अनेक प्रकार का होता है। इन अभ्यासों को ही भक्ति यानी साधना कहा गया है।

मृत्यु के बाद के साथी

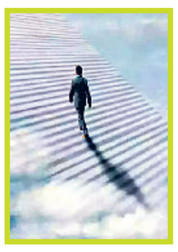

संकलित
प्रेरणा

एक व्यक्ति के तीन घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने जीवन भर उसका साथ निभाया। जब वह मरने की अवस्था के निकट पहुँचा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला- अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है। मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला- मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया। लेकिन अब मैं बेबस हूँ। इससे आगे अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। दूसरा मित्र बोला- मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन तुम्हारा हर परिस्थिति में साथ दिया है। तुम्हारे जाने के बाद, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हारी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यथावत संपन्न हो।

तीसरा मित्र बोला- मित्र! तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूँगा, तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मनुष्य के ये तीन घनिष्ट मित्र हैं- धन, परिवार एवं कर्म। इन तीनों में से मनुष्य के कर्म ही मृत्यु के बाद भी उसका साथ निभाते हैं। धन समय को साथ यहां छूट जाता है। उसे मनुष्य मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकता। यही स्थिति परिवार की होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी नहीं जाता। सिर्फ इस संसार में किए गए अच्छे कर्म ही मृत्यु के उपरान्त उसके साथ जाते हैं।

अंतर्मन

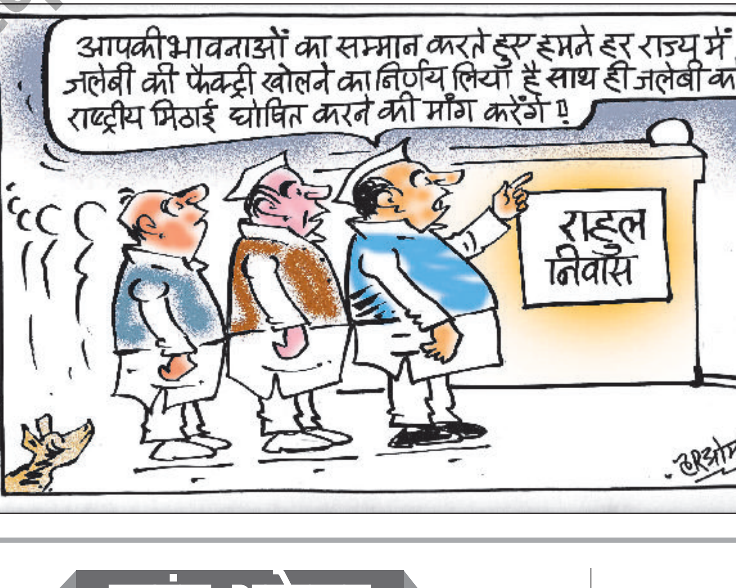

आज की पाती

युद्ध हमेशा नुकसान लेकर आए हैं

ईरान ने इजरायल पर अप्रैल में हमला किया था। उसी समय से इन दोनों में तनाव चल रहा है और अब ईरान ने एक बार फिर से जबरदस्त हमला इजरायल पर किया। इस बार उसने लगभग 180 मिसाइलों से हमला किया और बहुत ज्यादा ताकतवर मिसाइल फतह-2 का प्रयोग किया। यह मिसाइल हाइपरसोनिक मीडियम-रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान-इजरायल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ बुद्धिजीवी और अन्य लोग यह मान रहे हैं कि इन दोनों देशों का यह तनाव विश्व को विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। युद्ध चाहे किसी भी युग में क्यों न हो, हमेशा बर्बादी ही लाता है। लेकिन प्राणी जाति में सबसे समझदार समझा जाने वाला इनसान युद्ध में ही विश्वास रख रहा है। - **देवेंद्र यादव**, राजिम

ट्रेंड

मेरी गहरी संवेदनाएं!

मिर्जापुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जीरो टॉलरेंस की नीति

एक ओर जहां मोदी सरकार 'नशामुक्त भारत' के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

खनन में नीलामी

सरकार ने अधिक पारदर्शिता के लिए खनन में नीलामी शुरू की थी। लेकिन सीमित ब्लॉक ही ऑफर पर होते हैं और इतने सारे स्टील निर्माता कच्चे माल की सुरक्षा चाहते हैं, तो मांग-आपूर्ति में विसंगति होती है और बोली की कीमतें बढ़ जाती हैं।
-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

'पानी' अस्तित्व की लड़ाई

ऐसी दुनिया में जहां पानी दुर्लभ है, प्रेम सबसे बड़ा संसाधन है। यह हमें दिखाता है कि जब जुनून और उद्देश्य एक हो जाते हैं, तो कुछ भी संभव है। फिल्म 'पानी' कहानी से कहीं अधिक अस्तित्व की लड़ाई है।
-प्रियंका चोपड़ा, अभिनेत्री

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अगले हफ्ते से होगी शुरू

दुनिया के कई हिस्सों में छिड़े युद्ध, शरणार्थी संकट, अकाल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में अगले हफ्ते से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो जाएगी। पुरस्कार के ऐलान के सप्ताह में संयोग से सात अक्टूबर की वह तिथि भी आएगी जो हमास की अगुवाई में इजराइल पर किये गये हमले की बरसी भी है। हमास के हमले के बाद से पूरे पश्चिम एशिया में रक्तपात और युद्ध की शुरुआत हो गई जो करीब सालभर से जारी है। साहित्य और विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार को छूट दी जा सकती है। लेकिन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों को मान्यता देने वाला शांति पुरस्कार अगर दिया जाता है तो यह 'अंतरराष्ट्रीय हिंसा' के माहौल में दिया जाएगा। 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' के निदेशक डैन स्मिथ ने कहा, ''मैं दुनिया पर नजर डालता हूं तो बहुत अधिक संघर्ष, शत्रुता और टकराव देखता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह वह वर्ष है जब नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा नहीं की जानी चाहिए।''

ऑफ बीट

हम नहीं जानते सारा ब्रह्मांड अनंत है या नहीं

लगभग 400 साल पहले दूरबीनों के आविष्कार के साथ इंसान कहीं ज़्यादा दूर तक देखने में सक्षम हुए और वहां तक देख पाए जहां सिर्फ आंखों से देख पाना संभव नहीं था। वे आकाश में नई चीजों की खोज करते रहे। उन्हें और भी तारे मिले और फिर अंततः उन्होंने पाया कि वहां अजीब से दिखने वाले बहुत सारे ब्रह्मांडीय बादल थे। खगोलविदों ने इन्हें 'नेबुला' नाम दिया जो लैटिन शब्द 'धुंध' या 'बादल' से लिया गया है। हमने करीब 100 वर्ष पूर्व, पहली बार पुष्टि की थी कि ये ब्रह्मांडीय बादल या नेबुला वास्तव में आकाश गंगाएं हैं ।हालांकि तकनीकी रूप से हमारे ब्रह्मांड का एक छोर है। हम इसे अपना ''अवलोकनीय' ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है या नहीं। दुर्भाग्यवश हम प्रकाश की गति के कारण कभी भी यह नहीं जान पाएंगे। हम केवल वही प्रकाश देख सकते हैं जो हमारे पास आने के लिए पर्याप्त समय ले चुका हो। प्रकाश ठीक 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। इतनी गति से भी हमारे ब्रह्मांड को पार करने में इसे काफी समय लगता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का आकार कम से कम 96 अरब प्रकाश वर्ष है और संभवतः इससे भी बड़ा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a
Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and
receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid